

Wednesday, April 13, 1983
Chaitra 23, 1905 (Saka)

Eleventh Session (Seventh Lok Sabha)



सत्यमेव जयते

Price: Rs. 4.00

CONTENTS

No. 32, Wednesday, April, 13, 1983/Chaitra 23, 1905 (Saka)

		COLUMNS
Oral Answers to Questions :		
*Starred Questions Nos. 618, 619, 623, 624, 626 and 627	...	1—27
Written Answers to Questions :		
Starred Questions Nos. 621, 622, 625, 628 to 639 and 247	...	28—43
Unstarred Questions Nos. 7106 to 7110, 7112 to 7123, 7125 to 7170, 7172 to 7218, 7220 to 7229, 7231 to 7263, 7265 to 7320, 7322 to 7333 and 7335 to 7340	...	43—256
Papers Laid on the Table	...	257
Public Accounts Committee		
Hundred thirty-third and Hundred thirty-fifth Report	...	258
Committee on Public Undertakings		
Sixty-sixth Report	...	258
Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes		
Thirtieth Report	...	258—259
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
Situation arising out of drought, famine and reported starvation deaths in the country :	...	263—299
Shri Ram Vilas Paswan	...	263—278
Shri Arif Mohammad Khan	...	278—283
Prof. Narain Chand Parashar	...	284—285
Shri Jagpal Singh	...	285—289
Shri Ram Singh Shakya	...	290—294
Shri Jaipal Singh Kashyap	...	295—299
Matters Under Rule 377		
(i) Connecting Udaipur and Delhi by a Superfast train :		
Shri Bheekhabhai	...	299—300
(ii) Financial Assistance to Kerala to meet the drought situation in the State :		
Prof. P. J. Kurien	...	300—301
(iii) Bank loans to people of Gujarat whose houses were destroyed in recent cyclone :		
Shri Navin Ravani	...	301
(iv) Need to improve the functioning of telephones at Mathura, Uttar Pradesh :		
Shri Digamber Singh	...	301—302
(v) Working of Telegraph and Telecommunication services in the country :		
Prof. Ajit Kumar Mehta	...	302—303
(vi) Need for early reopening of the Bhashkar Textile Mills Jharsuguda :		
Shri Satyasadhan Chakraborty	...	303—304

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(vii) Need for providing speed boats to Customs Collectorate at Madurai to curb smuggling :

Shri M. S. K. Sathiyendran 304—305

(viii) Problems of opium growers :

Shri Chaturbhuj 305

(ix) Increasing cases of blindness amongst children in the country :

Shri Arjun Sethi 305—306

Demands for Grants, 1983-84

Ministry of Irrigation :	...	...	...	306—414
Prof. Rup Chand Pal	...	...	...	307—315
Shri Arjun Sethi	...	...	...	323—327
Shri Ram Kinkar	...	...	...	327—335
Shrimati Gurbbrinder Kaur Brar	...	...	...	335—344
Shrimati Krishna Sahi	...	...	...	344—351
Shri Chandradeo Prasad Verma	...	...	...	351—357
Shrimati Usha Verma	...	...	...	357—360
Shri Satyanarayan Jatiya	...	...	...	360—364
Dr. Mahipatray M. Mehta	...	...	...	364—371
Shri Nityananda Misra	...	...	...	371—377
Shri Era Mohan	...	...	...	377—383
Shri Birbal	...	...	...	383—384
Shri Maniram Bagri	...	...	...	385—386
Shri D. P. Yadav	...	...	...	386—393
Shrimati Geeta Mukherjee	...	...	...	393—397
Shri Bhubaneswar Bhuyan	...	...	...	397—400
Shri S. T. K. Jakkayyan	...	...	...	400—401 403—405
Shri Beekhabhai	...	...	...	405—407
Shri Banwari La Bairwa	...	...	...	407—411
Prof. Satya Deo Singh	...	...	...	411—414

LOK SABHA

*Wednesday, April 13, 1983/Chaitra 23,
1905 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock*

[MR. SPEAKER in the Chair]

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में पुलिस मालखाने से आतंकवादियों द्वारा हथियार ले जाना चिन्ता का विषय है। हमने नियम 388 में इसका नोटिस भी दिया हुआ है। आप कुछ बता सकेंगे कि इसमें क्या करेंगे ?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : It is serious matter that Parliament should take note of the arms looting at Ganganagar. It is a border area of Rajasthan and Punjab States. Home Minister should make a statement.

अध्यक्ष महोदय : हिसाब से करेंगे।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, we only want that the hon. Minister, after enquiry should make a statement. We just want a statement from the Minister. After going through it we would be know which are the forces behind it.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : We have asked for the report and we have also telephoned to them. As soon as it comes to us, I will make a in position to statement.

(Interruptions)

श्री रामावतार शास्त्री : उससे पता चल जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने सबकी बात ध्यान से सुन ली हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात हथियारों की चोरी से ही संबंधित नहीं है। गंगानगर, फिरोजपुर, जम्मू-कश्मीर तक भारत की सीमा पर एक किस्म की साजिश, एक किस्म के हथियारों की चोरी

(व्यवधान)

आप कुछ तमीज सीखो। राष्ट्रीय बात चल रही है, यह कोई तरीका है क्या ?

(व्यवधान)

इस तरह से कर के आप में से कोई भी मुझे चुन नहीं करा सकता है। आप की ओकात ही क्या है ? आप शांति से रहिये। आप ही लोग इस तरह से देश को तबाह कर रहे हैं। आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि राष्ट्र को कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसे आप करोगे तो मुझे खामाखाह गुस्सा दिलाकर जो बात का तत्व है वह सही देश के और कौम के सामने नहीं आयेगा।

लोगों की ज़िन्दगी जा सकती है जो आधी गई और आधी नहीं गई।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया मैंने।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात सुन लें।

अगर आप ज्योतिषी हैं तो अखबारों में यह खबर आई हुई है, फिर हमारे कहने की जरूरत नहीं। लोक-सभा में जो बातें आती हैं, वह सब अखबारों में आई हुई होती हैं; लोक-सभा में जो बात आपके माध्यम से आती है, सारे राष्ट्र को उसका ज्ञान होता है।

इस लिए ये बातें यहां पर कहनी पड़ती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं समूचे राष्ट्र की बात कह रहा हूं। गंगानगर, फिरोजपुर...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको कैसे एलाऊ करूंगा ?

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आप मेरी आधी बात सुनेंगे और आधी नहीं सुनेंगे, तो

एलाऊ करने या न करने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसका मतलब तो यह है कि आप मुझे मरवाएंगे। फिरकापरस्त लोग, जो हिन्दुओं और सिखों को लड़ाना चाहते हैं, जो हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मारेंगे। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो पाएगी। उन लोगों ने गांधी को कत्ल करवाया।

मेरी बात सुन लीजिए। जब शुरू में खालिस्तान की बात चली थी, तो मुझे मजबूरन यहां घरना देना पड़ा था। ये लोग कहते थे कि यह कुछ नहीं है। वही बात अब कितनी बड़ी हो गई है। लाला जगत नारायण के कत्ल के बाद यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। आज मैं सिर्फ एक चेतावनी देना चाहता हूं। आज आप राष्ट्र के लोगों से कहिए कि अगर सरकार अपने हथियारों की रक्षा नहीं कर सकेगी, तो वह देश की रक्षा कैसे करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस बारे में बयान देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपसे पूछना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको नियम 388 में एलाऊ नहीं किया है। फिर भी हाउस में इतना समय लग रहा है। अगर मैं सब माननीय सदस्यों को इस तरह एलाऊ करूंगा, तो कैसे गाड़ी चलाऊंगा?

श्री मनीराम बागड़ी : क्या आप सब बातों को एक जैसा समझ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सब माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : इन्होंने गांधी को मरवाया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के महत्व को समझते हुए ही मैंने आपकी बात सुन ली है यह देश की रक्षा की बात है। मंत्री महोदय इस बारे में बयान देंगे। उन्होंने सूचना मंगवाई है। अगर इस पर बहस करनी है, तो मुझे

कोई एतराज नहीं है। मैं तो आपके बनाए हुए रूलज के मुताबिक काम करता हूं। अगर आप सहायता नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा?

श्री मनीराम बागड़ी : क्या सारा देश इस बारे में चिन्तित है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : चिन्तित है, इसीलिए तो मंत्री महोदय ने कहा है कि वह बयान देंगे।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह राष्ट्रीय महत्व की बात है और ये हंस रहे हैं। देश की अखंडता को खतरा है और चुने हुए लोग मजाक कर रहे हैं और हंस रहे हैं।—प्रधान मंत्री जी आ गई हैं। खुद प्रधान मंत्री इस पर बयान दें। यह कोई मामूली बात नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश की एकता सब से प्यारी है। देश की सीमा पर मुतवातिर साजिशें और हथियारों की चोरी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Functioning of Industrial Licensing System

*618. SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA : With the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the work of Indian Institute of Public Administration in respect of functioning of Industrial Licensing System ;

(b) if so, whether the report has mentioned about under-utilisation of licensed capacity, production far in excess of licensed capacity and companies which have not actually secured licences from Government ; and

(c) if so, action taken on these points ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Optimum utilisation of the installed capacity is the corner stone of Government's

policy and has been stressed as such in the Industrial Policy Statement of July 23, 1980. Being fully aware of the external as well as internal and management constraints on fuller utilisation of capacities, Government have announced a series of policy decisions during the past three years to improve performance in this behalf. Some of these are :

- (i) Installation of a monitoring system in each Ministry/Department to watch performance and to take action to revoke licences where satisfactory progress has not been achieved ;
- (ii) Constitution of a Cabinet Committee on Infrastructure Industries to look into the problems of industries in the key sector ;
- (iii) Setting up of a Control Room in the Ministry of Industry to monitor and remove external constraints in respect of identified key sector industries ;
- (iv) Introduction of schemes to regularise installed capacities on licences and registration certificates under prescribed conditions ;
- (v) Re-endorsement of capacities on the basis of highest production achieved during the past five years .

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA : From the statement it appears that the Government has taken a series of policy decisions to improve the performance of the industries. It has been said that the Government have installed a monitoring system in each Ministry and Department to watch the performance and take action to revoke licences where satisfactory performance has not been made. May I know if Government are aware that there are many industries in which there is idle capacity due to over-licensing ? Has any study been made to see whether this over licensing was done deliberately, just to siphon off the raw materials, by these industries for profit to themselves and to the detriment of the economy ? Have government taken any action against any industry which has been found to have unsatisfactory progress ?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : This question which was asked by the hon. member covers a vast area and I would require a specific example, because we do not have any detailed information regarding over-

licensing of capacity just now. We ourselves are very careful so that we do not over-licene of course there has been under-utilization of capacity in many sectors. But under-utilization has been because of many factors, factor of infrastructural constraints, lack of power etc. And then, I would repeat, I would require more information. from the hon. member before I can answer, the question regarding over-licensing. because I cannot agree that there has been over-licensing.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA : The general practice is that they are keeping their factories under utilized and they are selling all the raw materials in the black market to make profit. I hope this will be brought to the notice of the Minister. Have government taken any action to revoke the licences of some of the factories which have not been showing satisfactory progress ? Has any action been taken so far against any industry ?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I am advised there is no specific provision to revoke licences just because they have not been showing satisfactory results. The state Governments are also there in the picture. We have to consider specific cases. Then this specific power is not there under the Industrial Development and Regulations Act ; and we ourselves are considering amendments to the Industrial Development and Regulations Act to further streamline the functioning of the Act.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA : In the policy decision you have said that monitoring system has been restored to take action. It is there in the statement. In the statement, they have said that there is a monitoring system to watch performance and to take action to revoke licence where satisfactory progress has not been achieved." What does that mean ? If the government does not have the power, why should they have said it ?

SHRI NARAYAN DUTT TIWARI : The individual administrative Ministries have been asked to look after the monitoring and implementation of letters of intent and licences ; and to make matters more specific, we are proposing necessary amendment in the Industrial Development and Regulations Act. We have also advised by the Law Department in this respect.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA : How many industrial units belonging to MRTTP companies and FERA companies are having capacity in excess of licensed capacity ? If this excess has been regularised, in how many cases has such action given monopolistic or near monopolistic hold of the market to these units ?

SHRI NARAYAN DUTT TIWARI : This is a general question and it should be addressed to the Ministry of Company Affairs. As far as this particular report is concerned, I would like to say that we have received this report. It is under detailed study. Correctives in terms of system of policy application as are considered necessary will be applied.

PROF. MADHU DANDAVATE : I would like to know from the hon. Minister whether his attention has been drawn to the report of Indian Institute of Public Administration in which they have tried to show grouping if violators of licensed capacity ; and whether it is true that in this report, they have actually given the range of excess capacity utilization as per-centage of licensed capacity in which they have said : between 100 and 200, the percentage total is 37, between 20 and 300, it is 8, between 300 and 400, it is 50 between 400 and 500, it is 3 and 500 and above, it is 9. The total comes to 62.

These are the 62 cases mentioned in this report, which are violators of licenced capacity. If this report is correct and in case through mistake you have studied it, will you be able to tell us the concrete actions that are going to be taken to see that these violators are taken to task and at least, it does not become a precursor for further violation in future.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : It is exactly this report which is the subject matter of the original question. And I have already replied to that. As a matter of fact, while answering the last question put by the hon. senior Member, I mentioned that the report was received in February. It is under detailed study. Corrections in terms of systems or policy applications as are considered, will be applied.

PROF. MADHU DANDAVATE : I asked a specific question that these are the ranges in which the increased capacity has been given. Therefore, what concrete, steps are being

taken ? You say that the report is under study. During your study, having applied your mind, have you at least come to some tentative conclusions as to what steps can be taken ? The report was available long time back. That is why, I asked this question.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : The report was presented in this year itself. I have got the report. I can send a copy of it to the hon. Member.

PROF. MADHU DANDAVATE : These statistics are already available with you. This is only compilation. They have only compiled and placed before you. In fact, they have collected this information from the agencies available to you.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : This information has been compiled in this study by quoting the annual reports of individual companies. We have to go into this and then only we can give a firm opinion. For example, the report itself says at page 16 that there are many aspects which require further investigation.

PROF. MADHU DANDAVATE : Other aspects all right. But what about this aspect ?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Therefore, I just cannot say that everything that has been said in this report is correct.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : There is the question of relevance of the whole industrial licensing system which is what the original question is about. The government is always studying reports, but does not come to any conclusions. Before this, there was the Wadilal Dagli Committee on licensing, then H.P. Nanda Committee on licensing system. All are under study, permanent study. Only yesterday, the Ministry of Law and Company Affairs gave the answer that the assets of the MRTTP companies rose from Rs. 12,000 crores to Rs. 18,000 crores in just two years i.e. from 1979 to 1981. In view of the fact that the report says that many companies are having capacity of 200 to 300 per cent in excess of what is licenced, the relevancy of the licensing system is under question. Is the Government considering a comprehensive review of the licensing system, which is more honest and one which can be implemented ?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : We are not considering a comprehensive review as

suggested by the hon. Member. Whatever lacunae are there, we will rectify those lacunae. The broad objectives of our licensing system are: optimal utilisation of industrial capacity, need-based requirement of the industry in accordance with the national priority, prevent concentration of economic power, secure balanced development in various parts of country. I think, the past history of industrial licensing system has rightly sub-served the national objective.

विदेशी नागरिकों का निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहरना

* 619. श्री मोतीभाई आर० चौधरी
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिक अपनी ठहरने की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी देश के विभिन्न नगरों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RAJAN LASKAR): (a) to (c) Arrival and departure of foreigners is a continuing process. Many of them get their visas extended on compassionate or other compelling grounds. The problem of overstays has been particularly noticed in respect of Pakistani nationals. Action including prosecution and deportation, if necessary, is taken against foreigners who continue to stay unauthorisedly. The State authorities are exercising vigilance to detect overstays.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : आप ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि अधिक अवधि तक ठहरने वाले जो लोग हैं उन के प्रति पता लगाने के बारे में सतर्कता बरती जा रही है। यह कैसी सतर्कता है जहां हजारों की संख्या में ऐसे लोग हमारे देश में बस रहे हैं ? मैं

जानना चाहता हूं—सतर्कता के बारे में आप की मशीनरी कैसी है, किस तरह से इनको पकड़ा जाता है ? पिछले तीन सालों में ऐसे कितने लोग इस देश में आये, अवधि पूरी हो जाने के बाद कितने यहां ठहरे हुए हैं, कितनों का पता चला है, कितनों पर मुकदमा चलाया गया है और कितनों को वापस भेजा गया है ? ऐसा भी बतलाया जा रहा है कि ये लोग रहम-दिली के कारण ठहरते हैं, उनका आना-जाना हर रोज का हो गया है। प्रश्न के उत्तर से ऐसा पता चलता है कि इस के बारे में जितनी सतर्कता होनी चाहिये, सरकार की ओर से उतनी सतर्कता मालूम नहीं हो रही है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या गुजरात में 3924 है। उनमें से ओवर-स्टे के केसेज की संख्या 613 है, इनमें से जो पेंडिंग डिस्पोजल बचे हैं उनकी संख्या 168 है। 81 ने सिटिजनशिप की एप्लीकेशन दी है जो अप्रॉपर कन्सीडरेशन है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Why don't you straight forwardly reject it?

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि आने वालों की संख्या जरूर ज्यादा है। लेकिन ओवर स्टे के जो केसेज हैं उनको पकड़ने और डिपोर्टेशन के भी काफी मामले हैं। एक्चुअली 1981 में 427 आदमियों को डिटेक्ट कर के डिपोर्ट किया गया 1982 में 348 को डिपोर्ट किया गया। इस प्रकार इस मामले में निरन्तर कार्यवाही की जाती रही है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं है। मैंने प्रश्न में पूछा था कि विभिन्न देशों से इस देश में कितने लोग आये हैं, मुझे सभी के आंकड़े चाहिये, केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा है।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : So far as the nationals of other countries are concerned, this is a very negligible proportion. There are a very few cases.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : बहुत थोड़े हैं—इसका क्या मतलब है ? कितने हैं जो दूसरे देशों से आये हैं, उनमें से कितने ठहरे हुए हैं, कितनों का वापस भेजा गया है, सभी के आंकड़े दिये जाने चाहिये ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : At the moment I do not have those figures but I say their number is very few.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन लाल पटेल ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : मेरा पूरा सवाल बाकी है । अभी तक तो पहले सवाल का ही पूरा जवाब नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूँ सरकार की सतर्कता के बावजूद लोग अवधि के बाद भी यहां ठहरते हैं, यह हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है । आज बंगला देश से बिना परमिट लिये हुए हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं—मैं जानना चाहता हूँ इनके बारे में क्या सतर्कता बरती जा रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या मशीनरी है, सरकार क्या करने जा रही है और अब तक क्या किया गया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बंगला देश से आने वालों के लिये नियम थोड़ा सा भिन्न हैं । वहां से आने वाले लोग 180 दिनों तक यहां ठहर सकते हैं, उसके पश्चात् उन को वापस जाना पड़ता है । जहां तक पाकिस्तानी नेशनल्ज का सवाल है वे वीजा लेकर आते हैं और हमारी एम्बेसी स्कूटिनी करके उनको वीजा देती है । जो पहले ओवर-स्टे कर चुके हैं उनको वीजा नहीं दिया जाता है । इस प्रकार से वीजा के एक्सटेंशन की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरत और कम्प्लेनट ग्राउण्ड पर मंजूर की जाती है, हालांकि तीन महीने के एक्सटेंशन का अधिकार राज्य सरकारों को दिया हुआ है, लेकिन बहुत से आदमियों को बीमारी के कारण या शादी या इसी प्रकार के अन्य कारणों से उन का यहां ठहरना जरूरी है उन्हीं को वीजा का एक्सटेंशन दिया जाता है, दूसरे लोगों को यहां रहने की इजाजत नहीं दी जाती है ।

SHRI MOHAN LAL PATEL : I would like to draw the attention of the hon. Minister to an article, which has appeared in *The On-*

looker dated 31st March 1983, where it is stated :

“Senior police officers and Collectors of the districts bordering Pakistan met here recently to discuss the problem...The meeting urged the Chief Minister sanction a new post in the Police Department to deal with the influx of foreigners. A senior police officer said that if no remedial steps are taken immediately, the problem may become highly explosive.”

In view of this, I would like to know whether it is a fact that a large number of Pakistani nationals are entering India without passports through the Rajasthan border and setting there permanently ? If it is so, I would like to know whether the hon. Minister is aware of the fact that many of them are working as spies of Pakistan, the Border Security Force is conniving in this matter and no action is taken to stop that. If it is true, it is very dangerous to the safety and security of the country. In view of this, what action do the Government propose to take ?

SHRI P.C. Sethi : Sir, it is rather unfair that charges are levelled against the Border Security Force. Both the army authorities and the Border Security Force are very vigilant. But the hon. Member should realise that the Rajasthan border is an open border, which opens up into miles and so sometimes.. DR. SUBRAMANIAM SWAMY : “Open border” is a wrong term; you have to withdraw it. You can say it is a long border, but not open.

SHRI P. C. STHI : Yes, it is a long border.

PROF. N.G. RANGA : Even then our security forces should be there.

SHRI P.C. SETHI : Our security forces and sometimes even the army is there. The Defence Ministry is taking steps to see that infiltration all along the border of Pakistan is completely stopped and nobody is allowed to enter India without visa and valid documents.

SHRI MOHAN LAL PATEL : Without passports the Pakistanis come to India, live here without passports and work as spies of Pakistan.

SHRI R. L. BHATIA : It has become a regular practice for all those people who come from Pakistan to normally overstay. Whenever their term is about to be over, they simply put up an application. Since their

applications are generally accepted, either on compassionate or other grounds, they overstay. May I know from the hon. Minister whether the same is made available to Indian nationals who go to Pakistan and overstay there, on compassionate grounds ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Refer it to the Pakistan External Affairs Minister.

SHRI P.C. SETHI : I cannot say what facilities are available in Pakistan. But, according to the agreement signed between the two countries, a similar provision should be applied in both the countries.

PROF. MADHU DANDAVATE : Are the Indians allowed to vote in Pakistan ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : There is no right to vote in Pakistan; so, he is wrong.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Like Russia, there is no vote in Pakistan.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I want to educate my friend, Dr. Swamy. There is right to vote in Russia. People vote there. I want to educate him... (interruptions)

SHRI RATANSINGH RAJDA : Is the hon. Minister aware of the press reports that appeared in the *Janma Bhoomi* of Bombay recently that Bangladesh people have come down to Bombay and that they have been staying in Bombay illegally ? If the Government are aware of this, what have they taken to remove them from the city of Bombay before any turmoil or disturbance is created in the public life of Bombay ? There are thousands of them in Bombay.

SHRI P.C. SETHI : As far as Maharashtra is concerned, the number is 838.

SHRI RATANSINGH RAJDA : I am asking merely about the city of Bombay, where more than 10,000 people from West Bengal have come illegally and resettled there... (interruptions) Not from West Bengal.

It is from Bangladesh they have come and it is a front page news item of the press report. Sir, this is a very serious matter about which I am asking. About 10,000 or more than 10,000 people have come to Bombay from Bangladesh. They have been staying over there illegally. I want to know whether the Government is aware of it and if not,

would you get a report from the Maharashtra Government and what steps do you contemplate to take?

SHRI P.C. SETHI : I was only giving the figures of the people who have come from Pakistan. As far as West Bengal people are concerned..... (Interruptions). I am sorry, Bangladesh.

(Interruptions)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Is West Bengal out of India?

(Interruptions)

SHRI P.C. SETHI : I stand corrected, I mean Bangladesh.

(Interruptions)

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY : Under a Communist system you have an internal passport system also. So they should be able to understand that.

SHRI P.C. SETHI : We have no information, but I can assure the hon. Member that we will try to get—not only try, to get, the full facts from the Maharashtra Government, but if there are any unauthorised people from Bangladesh staying there, we shall take suitable action to remove them.

श्री भीमसिंह : मैं राजस्थान बाडर के बारे में पूछना चाहता हूँ। बगैर परमीशन के जो लोग आते हैं उनका तो रिकार्ड आपको पता नहीं होगा लेकिन जो लोग परमीशन लेकर चैक पोस्ट पर एंट्री करके आते हैं और फिर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचते और यहीं रह जाते हैं, उनकी जानकारी तो आपके पास होगी। चैकपोस्ट पर यह एंट्री करनी होती है कि किस गांव के किस मोहल्ले में जाकर रहेंगे

—Check post is supposed to send that record to the police station.

उस गांव में वे जाते ही नहीं हैं। इस तरह के फिगर 1972 के बाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इस तरह से क्या राजस्थान की स्थिति भी आसाम जैसी होने वाली है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : चैकपोस्ट पर एंट्री होती है और उसकी एक कापी संबंधित एस. पो. को भेजी जाती है जहाँ पर उस व्यक्ति को

जाना होता है। अगर वह व्यक्ति एस. पी. को रिपोर्ट नहीं करता है तो एस. पी. चेंकपोस्ट को इनफार्म करता है और सच शुरू करता है। इसके बाद डिटेक्ट करके कार्यवाही शुरू करते हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान बार्डर के बारे में हम काफी स्टैप्स ले रहे हैं और आसाम जैसी स्थिति आने का सवाल ही नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि से लोग हिन्दुस्तान आ रहे हैं। एक हिन्दुस्तान में कितने देशों के लोग आकर बसेंगे यह मैं पूछना चाहता हूँ। जो भी बाहर से आते हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे हो जाते हैं। क्या इनको यहां रखने का इरादा है? क्योंकि मन्त्री जी ने कहा है कि मामला विचाराधीन है। इसका मतलब है कि वे यहां पर कुछ लोगों को परमीशन देने वाले हैं।

MR. SPEAKER : Shri Anantha Ramulu Mallu—Absent. Shri Zainul Basheer—Absent. Question No. 623—Shri Ramavtar Shastri.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

(Interruptions)

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र

* 623. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अन्तर्गत कुल कितने और कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) उन प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं;

(ग) उपरोक्त कितने प्रशिक्षण कोर्सों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिया गया है;

(घ) क्या इन प्रशिक्षण कोर्सों की परीक्षाओं में भी हिंदी माध्यम का विकल्प दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा विकल्प कब तक देने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) एक (सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद)

(ख) 45

(ग) यह विकल्प सारे 45 प्रशिक्षण पाठशालाओं में उपलब्ध है हालांकि इसे बहुत ही कम इस्तेमाल में लाया जाता है।

(घ) जी, हाँ

(ङ) ऊपर भाग 'घ' में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, राजभाषा अधिनियम अपनी जगह पर और सरकार की गति अपनी जगह पर है। मैं उसी गति में आपकी गति को मिलाना चाहता हूँ। राजभाषा अधिनियम की छीछालेदर आपके विभिन्न विभाग के लोग एवम विभिन्न मंत्रिमण्डल के लोग करते रहते हैं। खैर, वह तो एक अलग बहस का विषय है। आपने कहा कि पूरे हिन्दुस्तान के आपके लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केवल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने बड़े देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र को आप यथेष्ट या पर्याप्त समझते हैं? अगर नहीं तो क्या और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए आपके यहां कोई योजना है? अगर है, तो वह क्या है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसमें थोड़ा सा खुलासा देना जरूरी हो गया है। साइन्स और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन बहुत सारी संस्थाएं आती हैं। उनको आटोनामी दी

गई है। इसलिए, प्रश्न का उत्तर ऐसा दिया गया है कि हमारी संस्था जो साइन्स और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसके अन्दर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। दूसरी जो संस्थाएँ हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। साइन्स और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित जो संस्था है, उसी के संबंध में उत्तर दिया गया है। अगर, ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें से अलग-अलग प्रश्न निकल सकते थे। यह जो सर्वे ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट है, उसकी ओर से यहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। दूसरी जो संस्थाएँ हैं, उनमें जो कुछ होता है उनको ट्रेनिंग ही कहा जायेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ रिसर्च, सेमीनार्स और चर्चाएँ होती हैं। सर्वे ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है। उसके कोर्सेज कितने हैं, यह भी बताया गया है। उन कोर्सेज में हिंदी भाषा का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। वे चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक ही इन्स्टीट्यूट है और एक ही इन्स्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा, उसका अर्थ नहीं निकलता।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, 45 कोर्स इनके उत्तर के मुताबिक चल रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन 45 कोर्सेज के पाठ्यक्रम हिंदी में हैं या नहीं या केवल अंग्रेजी में हैं? जो पढ़ाते हैं वे किस भाषा में लैक्चर देते हैं? सिर्फ अंग्रेजी में देते हैं या हिंदी में भी देते हैं? अगर सारे पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हैं और लैक्चर भी अंग्रेजी में दिए जाते हैं तो आप किस आधार पर उम्मीद कर सकते हैं कि जो हिंदी भाषी हैं वे हिंदी में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे? इसका अन्दाज बता दीजिए। आप पढ़ाते हैं अंग्रेजी में और यह उम्मीद करें कि वे हिंदी में उत्तर पुस्तिका लिखें, तो क्या यह तमाम लोगों के लिए सम्भव है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है?

श्री शिवराज बी० पाटिल : यह जो प्रशि-

क्षण होता है, इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग आते हैं। प्रशिक्षण के समय अंग्रेजी भाषा में लैक्चर देते हैं। यदि, कोई विद्यार्थी या प्रशिक्षण लेने वाला कोई बात हिंदी में कर दे और लैक्चर देने वाले हिंदी जानते हैं तो उसका उत्तर भी हिंदी में दिया जाता है। इसके साथ-साथ यदि किसी की इच्छा हो कि किसी प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया जाए तो उसके लिए भी इजाजत दी जा सकती है। कुछ किताबें हैं हिंदी में छपी हुई, उसका भी वह उपयोग कर सकते हैं। मगर यह जो इन्स्टीट्यूट है जहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। उनके लिये, अगर कोई खास विद्यार्थी आये, तो उसको प्रशिक्षण हिंदी में ही देने का विचार किया जा सकता है। उसमें कोई बाधा नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी भाषियों के लिए मैंने सवाल पूछा है। जो अहिन्दी भाषी हैं वह अंग्रेजी में लिखें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हिन्दी भाषी लोगों के लिये आप कहते हैं कि हो सकती है। तो डेफिनेट बताइये कि हिन्दी के कोर्स आपके चलते हैं कि नहीं? मैंने साफ पूछा है, और हिन्दी में लैक्चर होते हैं कि नहीं हिन्दी भाषियों के लिये? यह तो बता नहीं रहे हैं। मैंने अहिन्दी भाषियों के लिये सवाल नहीं पूछा है।

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैंने कहा है कि हिन्दी भाषा का उपयोग करने की व्यवस्था है। मगर हिन्दी भाषा का उपयोग करने के लिये कोई सामने नहीं आये, जैसा मैंने (ग) के उत्तर में बताया...

श्री रामावतार शास्त्री : वहाँ व्यवस्था है कि नहीं? लोग पढ़ाते हैं कि नहीं इसका स्पष्ट उत्तर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि कोई पढ़ने वाला ही नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : पढ़ाते ही नहीं है तो कैसे कोई पढ़ेगा?

अध्यक्ष महोदय : कोई ऐसा आदमी है ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैंने कहा है कि 45 कोर्सेज जो हैं उसमें हिन्दी की व्यवस्था हो सकती है।

श्री रामावतार शास्त्री : 'सकती' की बात कह रहे हैं। इसी से हमारा संदेह है कि अभी कोई व्यवस्था वहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकती "नहीं"। है कि नहीं।

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैंने कहा हिन्दी में किताबें लिखी गई हैं। अगर कोई कहे कि मैं हिन्दी में उत्तर देना चाहता हूं तो हम उसको इजाजत देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी पढ़ने वाला है कोई, लेकिन कोई हिन्दी जानने वाला न हो जो कि पढ़ाने वाला है, तो उसके लिये हिन्दी का कोई प्रबन्ध है कि नहीं ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैंने कहा है कि हिन्दी में किताबें हैं, उसको उत्तर देने की इजाजत है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सरकार राजभाषा के प्रति कितनी सजग है यह इससे स्पष्ट होता है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, I want to throw some light. The problem is this. In India on various subject, particularly on Science and Technology the quality books in Hindi or in other Indian languages are not generally available. That is why, most of the students, even if they very much like to learn in Hindi or any other Indian language, they do not generally offer because of the lack of books.

I would like to know from the Minister, because of this difficulty what steps the Government is contemplating so that the quality books on Science and Technology in Hindi and other Indian languages are made available to the students whereby they can learn the subject in their own language and the lectures can also be delivered through Hindi or any other Indian languages ?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, we have to make distinguish between the basic literature and the literature which is available for the training purposes. The material which is available for the training purposes, to some extent has been translated into Hindi and other Indian languages and it is available.

But the translation of the basic literature has to be done by those who are well-versed in Science and Technology as well as in Hindu or other Indian languages. This is our difficulty and if it is possible to get well-versed persons, it will be done. But without looking into all the details and the difficulties, it would not be possible to give any assurance or promise on the floor of the House.

For a question that to what extent the training information is available in Hindi and other Indian languages, I have already said that we have pamphlets, book-lets and the books which are available for the purpose of training and if anybody is coming forth asking for instructions in Hindi, that kind of instructions can be made available to him. But if nobody is coming forth, why should be spend the money on all these arrangements ?

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी, यह जो, उत्तर दिया गया है, अभी तो मंत्री जी सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर दिया गया है वह तथ्यों से परे है। आपने (ग) में कहा है कि 45 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध है लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इस्तेमाल होता ही नहीं है। अगर कुछ इस्तेमाल होता तो आपने नाग (घ) में यह कहा है कि जो हिन्दी माध्यम से ही परीक्षा देना चाहते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बतायें कि वहां हिन्दी माध्यम से कितने परीक्षार्थियों को मौका दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दिया गया है। That is what he has said, he has already replied.

श्री बी० डी० सिंह : एक भी नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं आपसे यह कहना चाहता था कि प्रधान मंत्री ने इससे आगे बढ़कर बात कही है और यह कहा है कि सरल संस्कृत हमारी भाषा का एक अच्छा माध्यम

बन सकती है। इसलिए मेरा कहना था कि हिन्दी माध्यम के उपयोग को अधिक हतोत्साहित मत कीजिए, इसके उपयोग को जितना करा सकते हैं, कराइये।

परमाणु बिजली की अघिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन

*624. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु बिजली की अघिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : The installed capacity of nuclear power stations in operation is 860 MWe. The first unit of the Tarapur Atomic Power Station is shut down for refuelling and maintenance, and unit II is operating at about 160 MWe. The first unit of the Rajasthan Atomic Power Station is shut down for maintenance and repairs, and unit II is operating at about 180 MWe.

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मूल प्रश्न किया था, उसको तोड़-मरोड़ कर 2, 3 भागों में कर दिया जाता है और उसकी भावना नष्ट कर दी गई है जो मैं जानना चाहता था।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम काम करना चाहते हैं, लगातार परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हास हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उड़जा कह रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : उड़ जा नहीं ऊर्जा।

अध्यक्ष महोदय : खुरजा की बात तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा हूँ।

हमारे देश में कुल ऊर्जा के उत्पादन का अनुपात 1974 में ताप विद्युत से 54, जल विद्युत से 42 और परमाणु ऊर्जा से 4 था। इसका मतलब यह है कि जो 4 का अनुपात था वह 1983 में आते-आते ताप का 61, जल का 37 और परमाणु ऊर्जा का 2 रह गया।

परमाणु ऊर्जा के विकास की दृष्टि से 1974 में जो स्थिति थी वह 1983 में आधी रह गई जिसका कि विकास होना चाहिए था।

जो राजस्थान के आंकड़े आपने दिये हैं, उसमें आपने कहा है कि हम उस इकाई को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि राजस्थान के परमाणु बिजली घर की एक इकाई 4 मार्च 1982 से बन्द है। सारे देश में जितने परमाणु ऊर्जा घर हैं, वह अपनी उत्पादन क्षमता का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा घर कोटा की इकाई उत्पादन नहीं कर रही है। ठीक से वहाँ एफी-शियेट उत्पादन हो सके, इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : कोटा के परमाणु बिजली घर की मशीनरी में कुछ बिगाड़ आया है। इस ऊर्जा घर को हमारे साइंटिस्टों और हमारे देश के लोगों ने अपने बल-बूते पर बनाया है। इसमें 80 प्रतिशत अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी और ज्ञान का उपयोग किया गया है। पहले तारापुर का बनाया गया और दूसरा यह बनाया गया है।

इसके अन्दर कुछ मशीन में कमियाँ हैं जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। वहाँ के टरबाइन में प्ले के बिगाड़ जाने की वजह से और दूसरी जगह पर मशीन में कुछ बिगाड़ होने की वजह से इसे बन्द किया है। जो ज्ञान हमको इस बारे में प्राप्त हुआ है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं। इसके लिये अगर बाहर से टरबाइन वगैरह लाने की जरूरत हुई तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आगे चलकर जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग करने के बाद

इस का को हम अच्छी तरह से कर सकेंगे।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You are not giving the real reason, lack of heavy water.

श्री सत्यनारायण जटिया : जो उत्तर दिया गया है, उससे सारी बात स्पष्ट नहीं हैं। तारापुर का परमाणु ऊर्जा घर हमारे पावर जर्नीरेशन के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई बन्द होने के बाद वह बहुत दिनों तक उलझा पड़ा रहा और अब फ्रांस ने यूरेनियम सप्लाई किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रांस ने तारापुर ऊर्जा घर के लिए जो यूरेनियम सप्लाई किया है, उसमें अब कोई बाधा आने की स्थिति तो नहीं है। हमारे जितने परमाणु ऊर्जा घर हैं, उनकी ओवर-आल एफिशेंसी स्थापित उत्पादन-क्षमता कितनी है और वास्तविक उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग यूनिट के बारे में अलग अलग रूप से देना पड़ेगा। तारापुर का अलग उत्तर होगा और राजस्थान का अलग होगा। तारापुर पावर स्टेशन की एफिशेंसी ज्यादा है और राजस्थान की कम है और वह वक्त पर कमी मशीन खराब होने की वजह से, कभी दूसरी वजहों से कम या ज्यादा होती रहती है। लेकिन वह 40 से 60 प्रतिशत तक प्लक्वुएट होती नजर आती है। बीच में कहा गया कि हैवी वाटर वहाँ पर न होने की वजह से राजस्थान पावर स्टेशन बन्द हुआ। हैवी वाटर न होने की वजह से नहीं, बल्कि मशीनों में बिगाड़ होने की वजह से राजस्थान के पावर स्टेशन में बिगाड़ आया हुआ है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये डिफेक्ट्स दूर हों।

श्री सत्यनारायण जटिया : इस रिपोर्ट में जो छपा है, मन्त्री महोदय उसके विपरीत कह रहे हैं।

SHRI ERA ANBARASU : I learnt that USSR offered to set up a big atomic power generation plant in India and, in fact, it

appears that the Government has also suggested to have four small such units instead of a big one. If this information is true, I would like to know whether the atomic power generation plant offer by USSR has been accepted or not. If it has been accepted, may I know whether one such unit will be set up in Tamilnadu in view of the acute power shortage ?

The Madras atomic power project in my Constituency, even though after 15 years of instalment has not started producing power and, therefore, I also request the Hon. Minister to let me know when it will start generating power.

MR. SPEAKER : Please consider his request.

SHRI ERA ANBARASU : What has happened?

MR. SPEAKER : He will consider your request.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : It is a pertinent question, whether the Soviet Union's offer has been evaluated to augment the capacity.

MR. SPEAKER : We will be requesting him.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : That part of the question is an essential one. Don't make a mistake.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : The question is not very germane to the main question and if you hold that it is relevant.

MR. SPEAKER : No. It is not.

PROF. K. K. TEWARI : The Hon. Minister has stated that the unit of Tarapur plant is shut down and we read in the newspapers that very often it happens.

I would like to know whether it is a fact these arise because of want of spare parts which are supplied by America. They have not supplied the fuels. France has now replaced the fuel supply. I would like to know whether after the contract, the Americans are dragging their feet in the matter of supply of spare parts which has resulted in frequent closing down of these plants.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : That is true.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Tarapur unit one is under maintenance now and the spare

parts which are required for that purpose have not always been readily* available. But I would not say that they have been, all the time refused and those spare parts which have not been readily available, have been manufactured by us locally indigenously.

*626. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some persons/officers have arrested who have issued fake certificates particularly for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to unauthorised persons; and

(b) if so, number of such cases brought to the notice of Government of India during last two years and the action taken against such persons ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) This Ministry has not kept any record of persons/officers proceeded against for issuing false Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

SHRI K. PRADHANI : It has been noticed in the past that in some cases fake certificates of Scheduled Caste and Schedule Tribe are produced by candidates to get the jobs reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes May I know from the hon. Minister what steps are taken by the Government to prevent production of such certificates ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : As I have said in my main answer, we have no records with us. But whenever we get any complaint from anybody, then through State Governments we have those cases investigated. We have issued several guidelines to the State Governments. The State Governments also have been requested to take strict measures to detect such cases of non-Scheduled Castes and Scheduled Tribes holding false certificates, deprive them of the benefits that they are not entitled to and impose appropriate penalties and take legal action against those who are responsible for issue of such certificates. We are very vigilant about this and so far as my knowledge goes, these cases have already been taken care of. As soon as we get some complaint from hon. Members or from any person, we get it investigated through the State Government.

SHRI K. PRADHANI : Production of fake Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates to get the jobs reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is an offence under the Indian Penal Code. It is an offence under section 419 of the I.P.C.—cheating by impersonation—and the person using that certificate is an abettor of this offence. May I know from the hon. Minister whether any action has been taken in the past to prosecute such persons, persons producing such false certificates and the persons who have issued such false certificates. He has stated in his original reply that the record is not available. I want to know whether he will call for such information for production in the House, for the information of the Members.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : I have already said that strict actions are being taken on all these cases. The State Governments have also been advised to set up special courts for expeditiously trying the cases relating to the issue of bogus certificates with deterrent rapidity and give wide publicity to the names of persons who are convicted of these offences by the courts. So, all these actions have been taken.

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने कहा है कि गलत तरीके से जो प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और जो शिकायतें आती हैं उन पर वे कार्यवाही करते हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट डी एम इत्यादि ही ऐसा प्रमाण-पत्र देते हैं ? क्या किसी शिकायत पर अब तक कभी कोई कार्यवाही की गई है ? यदि की गई है तो क्या ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : The State Governments must have the cases with them. We have no case records with us.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : I would like to add that we have recently written to the State Governments to send a quarterly report about any such certificates which have been issued and the actions taken by them against such officials.

‘इन्टोग्रेटेड सर्किट’ संबंधी नीति बनाने के लिए कृतिक बल

*627. श्री बापूसाहेब सिंह पहलेकर
श्री भीम सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ‘लार्ज स्केल’ इन्टीग्रेटेड सर्किट्स और ‘बेरो लाज स्केल’ इन्टोग्रेटेड सर्किट्स के उत्पादन तथा विकास के संबंध में नीति बनाने और सुझाव देने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कृतिक बल के सदस्यों को कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कृतिक बल को रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो रिपोर्ट पर क्या चार्य-वाही की गई ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) A Task Force on LSI/VLSI technology has been set up by the Department of Electronics not to formulate policies but to review the current status of R&D and production in the country and to suggest various measures, strategy and policy with regard to the further development of LSI/VLSI over the decade 1983-1992.

(b) The total number of members (including Chairman) of the said Task Force is nine.

(c) and (d) Part I of the report of the Task Force was submitted to Government in December, 1982 and is under the consideration of Government.

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सी और डी के संबंध में जो उत्तर दिया है, मैं उसी के संदर्भ में सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार उस रिपोर्ट को कब तक अपना कंसीडरेशन समाप्त करके फरदर एक्शन ले लेगी।

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : Mr. Speaker, Sir...

MR. SPEAKER : Question Hour over.

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Visit of Pak Nationals

*621. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Pak nationals who visited India during 1981 and 1982 and in 1983 (so far) separately; and

(b) how many of them have since returned to Pakistan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b)

The requisite information is as follows :—

Year	Arrival	Departure
1981	2,22,066	2,16,516
1982	2,19,511	1,14,848
1983 (upto 2/83)	30,539	33,594

अरबों के साथ भारतीय युवतियों की शादी पर रोक

*622. श्री जैनुल बशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1983 के “दैनिक हिन्दुस्तान” में प्रकाशित “अरबों से भारतीय युवतियों की शादी-मुखी दाम्पत्य जीवन या बरबादी” शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता है अनेक भारतीय युवतियाँ शादी के नाम पर घोखाघड़ी की शिकार बन जाती हैं;

(ग) क्या इस घोखा घड़ी को रोकने के लिए सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है; विशेष कर उन मामलों में जिनमें शादी के कुछ दिनों बाद अरब लोग विदेशी पत्नियों को छोड़कर भाग जाते हैं ? और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, श्रीमन् ,

(ख) कुछ अरब आगंतुक जिन्होंने विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में गरीब परिवारों की स्थानीय मुसलमान लड़कियों को प्रलोभन में देकर उनसे विवाह किया था देखने में आये थे ।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य प्राधिकारी स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग हैं और ऐसी बुरी प्रथा को रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं । ये उपाय हैं : —

(1) वक्फ बोर्डों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से ऐसे विवाहों के विरुद्ध जनमत तैयार करना ।

(2) दलालों और होटल वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई करना जो ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों में ग्रस्त हैं ।

(3) जो अरब राष्ट्रिक सऊदी अरेबिया सरकार द्वारा जारी किये गये पूर्वा-नुमति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनसे विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोध नामंजूर करने हेतु वक्फ बोर्डों को कहना ।

Legislation to Ban Advertisements Discriminating Against Women

*625. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether there is any proposal under consideration of Government to bring legislation banning discrimination against women in advertising in view of the world-wide celebration of International Women Day; and

(b) if so, the policy of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Industries in 'No industry Districts of Gujarat

*628. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether "No-industry districts" have been identified in Gujarat by the Centre;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed for development of industries, incentives proposed and other measures taken for the development of these districts ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) :

(a) to (c) Dangs District has been identified as a "No-Industry District" in Gujarat. In accordance with the policy of giving overriding preference for grant of Licences in favour of "No-Industry Districts", three letters of intent have been granted for locations in Dangs District. A Central package of incentives for "No-Industry Districts" is being finalised. Dangs is also declared as a backward district by the State Government and is eligible to the incentives and subsidies as determined by them from time to time.

Killer Liquor Plant Busted in Delhi

*629. SHRI SUBHASH YADAV :

SHRI M. RAM GOPAL REDDY :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press reports appearing in the Indian Express dated 19 March, 1983 under the heading "Killer Liquor Plant busted";

(b) if so, whether one of the largest plants ever used to manufacture illicit liquor in the Capital was busted and a huge quantity of illicit liquor seized;

(c) whether any arrest has been made; and

(d) action Government have taken to remove this evil from the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) Yes Sir.

(b) The premises of a firm located in the industrial complex Nangloi were raided and 3 drums of rectified spirit, 24 drums of dena-

tured spirit and 25 litres of mixture of denatured spirit and caustic soda used for distilling rectified spirit were seized.

(c) Three partners of the firm and another person engaged in the manufacture of illicit inkuor were arrested.

(d) Intelligence is collected and raids conducted as and when any useful information is received.

Formation of Tribes Advisory Councils in States

*630. SHRI PIYUSH TIRKI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether under clause (4) of the Fifth Schedule of the Constitution, there is provision for establishment of Tribes Advisory Councils in those States which have Scheduled Areas ;

(b) if so, whether Tribes Advisory Councils in those States have been formed;

(c) whether Government propose establishing Tribes Advisory Councils in those States also which have Scheduled Tribes but not Scheduled Areas;

(d) if so, by what time; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir, The Councils have been constituted in eight States having Scheduled Areas.

(c) to (e) Tribes Advisory Councils have also been constituted in Tamil Nadu and West Bengal not having Scheduled Areas. Presently, there is no proposal to form such Councils in other States.

Introduction of Anti Defection Bill

*631. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the reasons for delaying the introduction of anti-defection legislation in Parliament ;

(b) whether it is a fact that due to failure of the Government to introduce Central

legislation against defections, States like Karnataka are planning to introduce State legislation against defections ;

(c) if so, whether to ensure uniform approach on the question, Government will expeditiously introduce Central legislation against defections ; and

(d) what will be the time limit for introducing such a legislation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKUTASUBBAIAH) : (a) to (d) The problem of defections forms part of the larger issue of Electoral Reforms and it cannot be viewed in isolation. This problem is, therefore, being considered by the Central Government along with other issues connected with Electoral Reforms. While the matter is under active consideration and appropriate decisions will be taken as early as possible, no time-limit for introducing a Central Legislation against defections can be given at this stage. The considerations, which weighed with certain State Governments for planning to introduce State Legislation against defections, without waiting for a Central Legislation in this regard are not known.

Budget Estimates and Actual Expenditure NALCO

*632. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of STEEL AND MINES : be pleased to state :

(a) the total amount budgeted so far for National Aluminium Company Limited and the actual funds spent up-to-date ;

(b) whether the progress of the project is not satisfactory ; if so, the reasons therefore ;

(c) whether bureaucratic delay results from everything being centralised in New Delhi even in the day-to-day policy decisions ; and

(d) the agency set up so far in Orissa to take appropriate action in recruitments and other decisions on the project for expending the process of commissioning the project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE) : (a) The Orissa Alumina/Aluminium Complex of National Aluminium Company Ltd. (NALCO) is being financed partly through

	(Rs. in crores)				(B.E.)
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	
Budget (Revised estimated)	52.00	64.06	64.43	75.68	
Euro-currency loan	—	4.74	86.75	289.00	
Total	52.00	68.80	151.18	364.68	

budgetary support and partly through loans obtained from a Consortium of International Banks. The year-wise provisions from each of these sources, has been as under :

The figures for 1983-84 are the proposed budget estimates. The total year-wise expenditure is given below :

1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
47.64	33.57	139.49	—
(Provisional)			

(b) to (d) The organisation of the company is adequately decentralised to implement the project. The registered head-quarters of the Company is at Bhubaneswar. The Director (Projects) and Adviser, (Technology) are posted there. All 3 General Managers are posted at the respective sites. A substantial part of supervision of work on sites has been entrusted to Consultants, who have also deployed their technical personnel at the sites. An adequate number of personnel from NALCO are at each of the sites to oversee the work of the Consultants. The senior management personnel of NALCO, as well as those of the consultants, have been delegated wide financial/administrative powers to meet the requirements at the project level. Independent Personnel and Finance Divisions of NALCO are operating from Bhubaneswar, as also the sites which inter-alia, look after recruitment. In sum, the organisational structure existing is appropriate for timely implementation of the project. The progress of implementation is satisfactory and on schedule.

Pokharan Blast Site

*633. SHRI N.K.SHEJWALKAR :

SHRIJAI NARAYAN ROAT :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

- (a) whether Government have seen the news item appearing in the "Indian Express", dated 17 January, 1983 under the heading "Pokharan blast site remains unprotected";
- (b) if so, the details of reasons for not taking appropriate steps to protect the site ; and
- (c) whether it has come to the notice of Government that the Naves oozing out of the site have an adverse effect on the surroundings, particularly human beings, animals and plants ?

THE PRIME MINISTER SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Yes, Sir.

- (b) and (c) The Pokharan site is in the protected area. No further protection is considered necessary as there is no residual radioactivity on the surface.

Expansion of Instrumentation Ltd.

*634. SARI V.S. VIJAYARAGHAVAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

- (a) whether there is any proposal to expand the Instrumentation Limited at Palghat ; and

- (b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Proposals are under the examination of the company.

- (b) The Company proposes to diversify the product range at the Palghat Unit of Instrumentation Limited by addition of the following items :-

- (i) H.P. Angle Valves, Flowing Valves, Low Noise Valves, Double Seated Control Valves, Field Mounted Controllers, Magnetic Flow Meters.

- (ii) Power Cylinders.
- (iii) De-Superheaters.
- (iv) Safety Relief Valves.

Production of Vehicles by TELCO and Ashok Leyland

*635. SHRI CHINTAMANI JENA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

- (a) whether the production of vehicles has been cut by the TELCO and Ashok Leyland ;
- (b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that there is a demand of our vehicles in foreign countries also ;

(d) if so, the names of those countries and the number of such vehicles exported during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83 ; and

(e) the steps being taken to increase the production to meet the demand indigenously and for export ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The production of vehicles by Ashok Leyland and Telco during 1981-82 and 1982-83 was as follows :

	1981-82	1982-83
Ashok Leyland	15,872	15,020
Telco	46,280	44,252

(b) The production of commercial vehicles has been regulated by manufacturers in relation to the demand thereof. The sales of Ashok Leyland vehicles in 1982-83 were 15,400 approximately and of Telco 45,500 approximately.

(c) and (d) The details of exports made by Ashok Leyland and Telco in the last two years are as follows :

	TELCO	LEYLAND
	Qty	Qty
1981-82	3000	135
1982-83	2364	645

These vehicles have been exported mainly to Sri Lanka, Ghana, Nepal, Mauritius, Fizi, Algeria, Malayasia Somalia and Kuwait.

(e) Government have taken several measures, both long-term and short-term, including the creation of additional capacities, provision of input support for increase the production of commercial vehicles and also for availability

of bank loans to purchasers. The production of commercial vehicles in the country increased from a level of about 57,000 in 1979-80 to over 91,000 in 1981-82

Clearance of Yamuna Nagar Thermal Power Project

*636. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has cleared the Yamuna Nagar Thermal Power Project; and

(b) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN): (a) No, Sir,

(b) The Central Electricity Authority and the Department of Power recommended the scheme to the Planning Commission in July, 1982 on condition that the investment on Yamunanagar Thermal Power Project during the Sixth Plan would not in any way be prejudicial to the progress of on going projects and new projects already committed to. Keeping these conditions in view, the Planning Commission has requested the State Government of Haryana to furnish the financing pattern of this scheme which is awaited.

Poaching of Wild Life

*637. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the numbers of incidents of poaching of wild life by the army officers brought to the notice of Government during last one year;

(b) the details of each case;

(c) whether the animals like neelghai and chinkara have been killed by these officers in a very cruel manner ;

(d) if so, the reasons that Government could not provide proper protection to the wild life;

(e) the action taken against the defaulters; and

(f) steps taken to ensure proper security of the wild life?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Steps taken to ensure protection of wild life

Action taken

Details of the case

Name and designation of Army Officers responsible for poaching

1 2

3

4

5

6

1. Rajasthan

Major David K. Onni and Jawans of 3/11 Gorkha Rifles presently attached to 20 Infantry Brigade, Itarana, Alwar.

On 15.2.83 Major David along with some Jawans of his Company is reported to have shot and later stoned to death a Nilgai in Tatarpur Plantation on Behror-Alwar Road, Alwar District. On being confronted by the plantation workers, he left the area but returned in the same evening with more jawans in two trucks and forcibly took away the carcass of the animal.

The case has been registered under the Wild Life (Protection) Act, 1972, and prosecution is to be launched in the Court of Law. The case was also reported immediately to the concerned Army authorities for appropriate action according to army procedures. The Defence authorities have informed that a Court of Enquiry has been started and is in progress.

The following steps have been taken:

(1) The Wild Life (Protection) Act, 1972, is now applicable to all States and Union Territories except Jammu & Kashmir which has a similar law of its own. The Act *inter alia* provides for the protection of wild animals and birds their habitats, the constitution of protected areas, regulations on trade and commerce and lays down penalties for contravention of the provisions of the Act.

Col. J.S. Toor, Major R.P. Singh and Driver Dalip Singh of the College of Combat, Mhow.

In the early hours of 23.12.82 the flying squad of the Indore Forest Division apprehended a Military vehicle with four carcasses of Chinkaras with gun shot wounds.

The case has been challaned in Court on 13.1.83 under the Wild Life (Protection) Act, 1972. The matter has also been reported to the Army authorities for appropriate action according to army procedures. The Station Commander, Mhow, has moved the Court on 14.2.83 for transfer of the case for trial by Army Court Martial.

(2) A network of 207 Sanctuaries and 43 National Parks has been set up throughout the country to represent different wildlife ecosystems. No hunting of any form is permissible in such areas.

2. Madhya Pradesh

6

5

4

3

2

1

3. West Bengal
Subedar Major Negi, Subedar Major Jagmir Singh, Havildar I. Ekka, and Signalman R.N. Bala. All from 323 Signal Regiment Mongpong.
On 10.10.82 the four Army officials mentioned in Col. (3) Act, 1972, against the culprits. The matter was also reported to 33 Corps Head Quarters for appropriate action according to Army procedures.
A case has been registered under the wildlife (Protection) Act, 1972, against the culprits. The matter was also reported to 33 Corps Head Quarters for appropriate action according to Army procedures.
(3) The Forest Conservation Act, 1980, provides that no forest land will be diverted for non-forest use without the approval of Central Government. The Act, thereby provides protection to the habitat of wildlife.
4. Uttar Pradesh
Major Shashi Anand 1, Maratha Battalion C/o 56 A.P.O.
On 20.4.82, Major Shashi Anand was apprehended in Khajawar forest block of Siwalik Forest Division for killing a Nilgai. He confessed about having committed the offence.
The case was decided departmentally by the State Wildlife authorities in accordance with the provision of the wildlife (protection) Act, 1972, and a sum of Rs. 6,300 was realised as compensation. The case has since been referred to the Defence Ministry for appropriate action.
(4) 9 States and 3 Union Territories have imposed a total ban on shooting and trapping of wild animals. In 5 other States very restricted hunting limited to only a few common species is permitted.
5. Uttar Pradesh
Captain R.S. Dhillon, Ordnance Factory, Raipur, Dehra Dun.
The Officer was apprehended on 21.11.82 in Chamasari Forest Block of Yamuna Forest Division while trying to shoot a Goral.
The case was decided departmentally by the State (wildlife authorities) in accordance with the provisions of the wildlife (Protection) Act, 1972. A sum of Rs. 4,500 was realised as compensation. The case has since been reported to the Defence Ministry for appropriate action.
(5) The States have been advised from time to time to strengthen their wildlife wings and protection enforcement machinery and to take stringent steps against poachers.

Cement Prepared from Paddy Husk

*638. SHRI A.K. ROY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that good quality cement can be prepared from the Paddy Husk abundantly available in the country ; if so facts in detail and

(b) whether any technology to that effect has been developed in the country and applied for commercial production; if so, facts in detail ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDI) : (a) Yes, Sir. Cementitious binder, which is different from portland cement, can be produced from rice husk. It can be used for several applications such as plastering, masonry and canal lining.

(b) Technology for manufacturing cementitious binder from rice husk and lime was initially developed at Indian Institute of Technology, Kanpur for Small Scale production and based on it NRDC has supported the establishment of a demonstration-cum-training unit of 500 tons annual capacity at Attara (UP). After trials it has started production in Jan., 83. It is found to be of satisfactory quality and conforms to ISI standards. Earlier a technology was developed by Central Building Research Institute based on the use of waste lime with paddy husk. Cement Research Institute had also developed a technology.

गन्धर्व और कुथालिया बौरा जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में मिलाना

*639. श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गन्धर्व (नाच गाने से अपनी आजीविका कमाने वाले) और कुथालिया बौरा दो जातियाँ उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कुल जनसंख्या क्या है और उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कब तक शामिल किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त गणना जाति के आधार पर नहीं की जाती है। अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में गन्धर्व और कुथालिया बौरा जातियों को शामिल करने के सम्बंध में प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित ध्यापक संशोधन के संदर्भ में और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाए गए सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक के साथ परामर्श करके विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। मामले में अन्तिम रूप से विचार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण टिप्पणियों के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में पुनः कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 343(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही किया जा सकता है।

Signing of Antarctic Treaty By India

247. SHRI JITENDRA PRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government contemplates to become a signatory to the Antarctic Treaty ;

(b) If so, whether the reaction of other signatory nations has been ascertained; and

(c) the ways in which the country is going to benefit by becoming a signatory to the Treaty ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) No decision has yet been taken in the matter.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise at present.

Retirement of Supera nnuated Staff in the Department of Science and Technology

7106. **SHRI HARIKESH BHADUR :** Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state :-

(a) whether orders for retirement of superannuated staff and transfer after 5 years enure have been fully implemented in the Department of Science and Technology; and

(b) if not, the details of staff exempted from these orders with reasons ?

THE MINISTERS OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) Yes sir, in the Deptt. of Science & Technology, the Govt. orders for retirement of superannuated staff and transfer after 5 years tenure have been fully implemented.

(b) Not applicable in view of the answer to part (a) above.

Raising Additional Resources From Agricultural Sector

7107. **SHRI MANOHAR LAL SAINI :** Will the Minister of **PLANNING** be pleased to state :

(a) whether there was any proposal to raise additional resources from the agricultural sector besides land revenues to mobilise the resources for the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI (S.B. CHAVAN) : (a) and (b) Yes, Sir. The Sixth Five Year Plan 1980-85 had recommended that additional resources should be raised from the agricultural sector. Attention is invited to paras 5.50, 5.53 and 7.10 of the Sixth Plan Document. In pursuance of these recommendations the Planning Commission has been asking the State Governments from time to time to take appropriate measures to mobilise additional resources from the agricultural sector, particularly through reduction in irrigation losses, etc.

Issue of Industrial Licences

7108. **SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY :** Will the Minister of **INDUSTRY** be pleased to state :

(a) the number of industrial licences issued from January, 1980 to February, 1983 end giving State-wise and Union Territory-wise break up; and

(b) the details of articles to be manufactured and investment particulars ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) A statement is enclosed.

(b) Details of all Industrial Licences including name and address of the undertaking, location of the unit, item of manufacture and capacity, etc. are being published by Indian Investment Centre in their 'Monthly News Letter'. Copies of this publication are available in the Parliament Library. Information regarding investment particulars of industrial licences is not maintained centrally in the Secretariat for Industrial Approvals in the Deptt. of Industrial Development.

Statement

Statement Showing State-wise break-up of Industrial Licences issued during the years 1980 & 1983 (upto Feb.)

State	1980	1981	1982	1983 (upto Feb)
1. Andhra Pradesh	42	39	26	9
2. Andaman & Nicobar	—	—	—	—
3. Arunachal Pradesh	—	—	—	—

4. Assam	5	4	1	2
5. Bihar	4	10	9	4
6. Chandigarh	1	1	3	1
7. Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—
8. Delhi	5	2	7	2
9. Goa, Daman & Diu	2	5	7	1
10. Gujarat	85	79	69	12
11. Himachal Pradesh	2	1	6	—
12. Haryana	20	21	21	6
13. Jammu and Kashmir	1	3	3	8
14. Karnataka	40	25	34	15
15. Kerala	11	15	9	3
16. L.M. & A. Islands	—	—	—	—
17. Madhya Pradesh	18	15	9	5
18. Maharashtra	107	114	95	54
19. Manipur	—	—	—	—
20. Meghalaya	—	—	—	—
21. Mizoram	—	—	—	—
22. Nagaland	—	—	—	—
23. Orissa	8	5	10	2
24. Pondicherry	—	1	1	—
25. Punjab	18	17	14	9
26. Rajasthan	15	26	14	4
27. Sikkim	—	—	—	—
28. Tamil Nadu	37	30	41	11
29. Tripura	—	—	—	—
30. Uttar Pradesh	30	24	22	10
31. West Bengal	23	34	27	5
32. State not indicated/More than one State	1	4	4	—

TOTAL : 475 476 432 133

बेलटेक द्वारा निर्मित टी० बी० सेट

7109. श्री निहाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बेलटेक टेलीविजन, ए-80, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I नई दिल्ली ने राष्ट्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कितनी धनराशि का ऋण लिया, उपरोक्त फर्म के भागीदारों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि लगाई हुई है;

(ख) कम्पनी द्वारा प्रत्येक माह में निर्मित

दूरदर्शन तथा अन्य सेटों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उसने कितने मूल्य के पुर्जों का आयात किया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी ने बिक्री कर के रूप में कुल कितनी धनराशि सरकार के पास जमा की ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) (1) कम्पनी ने सरकार अथवा अन्य संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है। उन्हें बैंकों से ऋण की सुविधा प्राप्त है। 28 फरवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार कम्पनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उप-

लब्ध कराई गई निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का उपयोग करती रही :—

—नकद ऋण (बंधक पर)

47.75 लाख रु०

—बिलों/चैकों को खरीदने की सीमा

19.37 लाख रु०

(ii) कम्पनी के चार निदेशक हैं। उनके नाम तथा उनके द्वारा किया गया पूंजी-निवेश इस प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम	शेयर-पूंजी के रूप में की गई पूंजी-निवेश की रकम (रु०)
1.	श्री कृष्ण सी० कणिक	85,500.00
2.	श्री वाई० पी० वर्मा	82,500 00
3.	श्री सतीश वर्मा	1,71,000.00
4.	श्री आई० एस० सोढी	30,000.00

(ख) (1) दूरदर्शन तथा अन्य मर्दों के मासिक उत्पादन का व्यौरा 1980-81 :

क्र० सं०	माह	श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन	रंगीन दूरदर्शन	वीडियो कैसेट रिकार्डर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अप्रैल, 1980	1309		
2.	मई, 1980	1403		
3.	जून, 1980	1597		
4.	जुलाई, 1980	1643		
5.	अगस्त, 1980	1707		
6.	सितम्बर, 1980	1475		
7.	अक्टूबर, 1980	1908		
8.	नवम्बर, 1980	2027		
9.	दिसम्बर, 1980	2231		
10.	जनवरी, 1981	3006		
11.	फरवरी, 1981	2172		
12.	मार्च, 1981	1715		
		<u>22193</u>	<u>10</u>	<u>शून्य</u>
			<u>10</u>	<u>शून्य</u>

1.	2.	3.	4.	5.
1981-82				
1. अप्रैल, 1981	1430			
2. मई, 1981	1798			
3. जून, 1981	2269		19	
4. जुलाई, 1981	2194		19	
5. अगस्त, 1981	2238			
6. सितम्बर, 1981	2690			
7. अक्तूबर, 1981	2567		1	
8. नवम्बर, 1981	2898		66	
9. दिसम्बर, 1981	3625		1	
10. जनवरी, 1982	4041		22	
11. फरवरी, 1982	3273		13	
12. मार्च, 1982	3295		1	शून्य
	<u>32318</u>		<u>142</u>	<u>शून्य</u>
1982-83				
1. अप्रैल, 1982	2919		43	—
2. मई, 1982	2412		1	—
3. जून, 1982	2619		18	—
4. जुलाई, 1982	2576		129	—
5. अगस्त, 1982	1802		86	50
6. सितम्बर, 1982	2824		155	—
7. अक्तूबर, 1982	2546		1090	—
8. नवम्बर, 1982	3673		4426	88
9. दिसम्बर, 1982	4186		1079	11
10. जनवरी, 1983	4886		275	—
11. फरवरी, 1983	4021		883	—
	<u>34434</u>		<u>8185</u>	<u>149</u>

*इनमें छोटे-मोटे परिवर्तन हो सकते हैं।

(11) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित संघटक पुर्जों का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	आयातित वस्तुओं का मूल्य
1980-81	27.77 लाख रु०
1981-82	133.16 लाख रु०
1982-83	297.50 लाख रु०
(अप्रैल से फरवरी)	

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकार को दी गई बिक्री कर की कुल रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	केन्द्रीय बिक्री कर (लाख रुपयों में)	स्थानीय बिक्री कर (लाख रुपयों में)
1979-80	6.63	1.44
1980-81	10.56	2.96
1981-82	14.88	4.60
	32.07	9.00

Scheme to Strengthen District Level Planning Machinery

7110. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of PLANNING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 158 on 3 March, 1982 and state the progress made so far in evolving the scheme to strengthen the district level planning and share the expenditure by the States in his regard alongwith other relevant details ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : The Scheme for strengthening District Planning Machinery is under implementation from 1982-83. The central purpose of this scheme is to provide assistance or establishing a Planning Cell at the District level.

The scheme envisages the induction of some technical personnel with knowledge and skills required for scientific district planning with minimum supporting staff.

The pattern of sharing of expenditure between the Centre and the States is on a 50: 50 basis.

Requirement Production and Import of Heavy Water

7112. SHRI A.K. ROY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the annual requirement of heavy water in the country and details of its use for the last three years ;

(b) annual production of heavy water in the country for the last three years ;

(c) whether there is any import, if so, the countries from which it was imported in the last three years, facts in detail of the countries and the quantity imported in each year ;

(d) cost of indigenous production and imported heavy water ; and

(e) steps taken to make the country self-sufficient in heavy water and the probable date or period for that, facts in detail ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) During the last three years, heavy water was required for the initial charge for Rajasthan Atomic Power Station II and for make-up

requirements of Rajasthan Atomic Power Station I & II. In the year 1980-81, 250 tonnes were used for the initial charge of Unit-II of Rajasthan Atomic Power Station and approximately 64 tonnes were used as make-up for operational losses from both the units at Rajasthan during the last three years.

(b) The annual production of heavy water for the last three years is as follows :

1980-81	35.75	Metric Tonnes
1981-82	46.07	Metric Tonnes
1982-83	24.49	Metric Tonnes

(c) and (d) Yearwise details of quantities of imported heavy water during the last three years are as follows :

Year	Country	Quantity (Metric Tonnes)
1980	U.S.S.R.	41
1981	U.S.S.R.	40
1982	U.S.S.R.	50

The CIF price of imported heavy water ranged between US \$252 and 277 per kg. The price of indigenous heavy water during these years ranged between Rs. 2513/- Rs. 2820/- per kg.

(e) Efforts are being made to optimise production at the existing heavy water plants by improvements in the on-streaming procedures and efficient operation and maintenance. Two more Heavy Water Plants are scheduled to be commissioned and two more Heavy Water Plants are under construction.

Grant of Autonomous Status to Some Districts of Bihar

7113. SHRI SHIBU SOREN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government consider declaring the Ranchi, Santhal Pargana, Hazaribagh, Singhbhum and Palamau districts of Bihar as tribal area for granting them the status of autonomous districts ;

(b) if so, by what time ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NIHAR RANJAN LASKAR)

(a) For the development of the tribals, Tribal Sub-plan areas predominantly occupied by tribals, have been identified. In Bihar, the tribal sub-Plan area extends to the whole of Ranchi and Singhbhum districts, and part of Palamau sub-Plan areas in Hazaribagh district.

(b) and (c) There is no proposal under consideration of the Ministry of Home Affairs to grant autonomous district status to the above districts.

Strike of Employees of Visakhapatnam Steel Plant

7114. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the employees of Visakhapatnam Steel Project went on a strike from 4 March, 1983 ;

(b) if so, what were their demands ;

(c) whether the strike has since been settled ; and

(d) if so, the terms of the settlement ?

THE MINISTER OF STATE OF THE
MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI
N.K.P. SALVE) : (a) Yes, Sir.

(b) The main demands related to leave and holidays facilities, grant of project construction allowance, free transport and subsidised canteen facilities, supply of uniforms, provision of welfare amenities reimbursement of tuition fee, etc.

(c) Yes, Sir.

(d) The terms of settlement provide : increased casual and earned leave to the ministerial employees, better transport facilities to be arranged through Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, reduction in existing prices of snacks, tea, coffee and meals, supply of dress to certain categories of employees, improvement in welfare amenities, extension of reimbursement of tuition fee facilities to the children reading in registered schools also and review of promotion policy of non-executives.

The settlement is final and binding on the the parties for a period of two years from the date of settlement i.e. 16th March, 1983 and would have no retrospective effect,

Report of Indian Institute of Public Administration

7115. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a study of Indian Institute of Public Administration, New Delhi that about 17 of the biggest industrial houses did not use over 60 per cent of the Industrial Licences issued to them ; and

(b) whether it is a fact that this is being used as a ploy to discourage serious entrepreneurs from entering these fields and continue our imports ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) Government have seen the report which *inter-alia* has brought out that 17 large industrial houses have not utilised 196 licences out of 864 licences issued to them which works to about 22 per cent. With a view to ensure expeditious implementation of the licences Government have already introduced a system under which the concerned Ministry/Department monitors the progress of implementation of licences and takes appropriate action to revoke licences where progress is not satisfactory. It may however be mentioned that it takes some time for the unit to go into production after the licence is issued.

Persons Detained in Assam under NSA

7116. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there have been instructions from the Centre to apply National Security Act in Assam on a wider scale ;

(b) if so, how many citizens in Assam have been detained under NSA ; and

(c) how many among them belong to political parties, trade unions and students, and youth organisations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The State Government is competent to exercise powers conferred under Section 3(2) of the National Security Act, 1980.

(b) According to the Govt. of Assam, 214 persons have been detained since October, 1980 till 31st March, 1983.

(c) According to information furnished by State Government, most of the detenus were members/supporters of the organisations spearheading the agitation. However, a few officers of Government and semi-government organisations were also detained under N.S.A.

पर्यावरण विभाग में अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

7117. श्री राम विलास पांडवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की, श्रेणीवार, संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की, श्रेणीवार, संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी जान बूझकर उनकी नियुक्ति नहीं करते ; और

(च) यदि हां, तो अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ और किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Recent Bomb Blasts in Delhi

7118. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS : be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Police and other agencies investigating the recent spate of bomb blasts in the capital are still groping in the dark with regard to the identity of the culprits; and

(b) the reasons for which Delhi police could not make any headway in this respect and what efforts are being made to identify the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) A joint team of officers drawn from various specialised agencies has been constituted in order to make a thorough enquiry from different angles. The culprits in some of these cases have been identified and efforts are being made to apprehend them.

Reservation of items for Small Scale Industries

7119. SHRI N.E. HORO : Will the Minister of INDUSTRY : be pleased to state :

(a) whether in view of the policy as laid down in the Budget proposals, Government propose to add to the items reserved exclusively for small scale industrial sectors ;

(b) if so, what are these items ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the steps Government are contemplating to make small scale industrial units more viable and successful ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) The Government have adopted a policy of reservation of items for exclusive development in the small scale sector. The policy is under constant review. At present 837 items are reserved for exclusive manufacture in the small scale sector.

(d) Government in order to make small scale units more viable and successful have taken several measures like upgradation of technology, modernisation, extension of insti-

tutional network especially in backward areas ; improvement of workshop and testing facilities, establishment of Process & Product Development Centres, field testing stations for improving the quality of products, increased marketing support and measures to remove raw material and other input constraints.

Report on Mineral Wealth

7120. SHRI BHEEKHABHAI : Will the Minister of STEEL AND MINES : be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former ruler of Dungarpur got prepared a report on mineral wealth of erstwhile Dungarpur state by Mr. Fox, a mineral expert ;

(b) if so, the recommendations made by him ;

(c) the action taken thereon ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) No information on this matter is available with the Ministry.

(b) to (d) Do not arise.

**एक लिपिक और एक पुलिस कर्मों के
वेतनमान में विषमता**

7121. श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में एक पुलिस कर्मों के रूप में नियुक्त होने पर एक मैट्रिकूलेट को 225 रुपए का ग्रेड मिलता है और एक मैट्रिकूलेट को दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधीन किसी कार्यालय में एक लिपिक के रूप में नियुक्ति पर 260 रु० का ग्रेड मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक पुलिस कर्मों पूरे 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए उत्तरदायी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषयता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बरया) : (क) जी हां, यह सच है कि दिल्ली पुलिस में मैट्रिकुलेट/हायर सैकेण्डरी कांस्टेबल का आरम्भिक वेतन 225-308 रु० के वेतनमान में 225 रुपये है और दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय गृह मंत्रालय में निम्न श्रेणी लिपिक का आरम्भिक वेतन 260-400 रुपये के वेतनमान में 260 रुपये है।

(ख) और (ग) पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बिल्कुल अलग प्रकृति की होने के कारण उनको दिन अथवा रात को किसी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। किन्तु सहायक उप-निरीक्षक और नीचे के स्तर के व्यक्तियों को, यदि वे एक दिन में 9 घंटे से अधिक ड्यूटी पर रहते हैं तो उन्हें 4 रुपये प्रतिदिन का खुराक भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को कार्य के लम्बे समय के बदले और पुलिस अधिकारियों द्वारा छुट्टियां और साप्ताहिक छुट्टियां न ले सकने के बदले एक वर्ष में 30 दिन की अवधि के वेतन की प्रतिपूरक अदायगी की जाती है। पुलिस कांस्टेबल और लिपिकों का कार्य समान नहीं है इसलिये विषयता को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली
के कर्मचारियों के लम्बित मामलों

7122. श्री राम तिहू शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के बारे में 14 जुलाई, 1982 के अतारंकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग ने खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के उन पुराने मामलों के बारे में कार्यवाही की है जो इसके पास अनेक वर्षों से लम्बित थे और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है; और

(ख) शेष लम्बित मामलों को अन्तिम रूप से कब तक निपटाये जाने की संभावना है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Setting up of Industries in Rayalaseema, A.P.

7123. SHRI K. OBUL REDDY : Will the Minister of INDUSTRY : be pleased to state :

(a) whether Government would set up industries in backward area of Rayala-seema, Andhra Pradesh, based on the availability of raw materials ;

(b) if so, whether they would be set up as joint ventures with the collaboration of foreigners ; and

(c) whether private entrepreneurs will be encouraged to set up industries in Rayala-seema ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) While the primary responsibility for promotion of industries in a State rests with the State Government, the Central Government have notified four districts in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh as eligible to concessional finance. Besides, a set of 22 blocks from all the four districts have been further identified for eligibility to Central Investment Subsidy.

At the instance of the State Government, Anantapur district has been identified for initiating industrialisation under the nucleus plant programme for which a Task Force was set up who have since submitted their report identifying project possibilities, extent of ancillarisation and minimum infrastructural gaps. The report has since been remitted to State Government to examine the techno-economic feasibility of the viable projects and to initiate action thereon.

Besides, the entrepreneurs setting up industries are also eligible to facilities like tax concessions, hire purchase of machinery by small scale industries, consultancy for technical services, interest subsidy and special facilities for import of raw materials. It is

for the entrepreneurs to come forward to set up industries and avail of the concessions and facilities.

Casual and Muster roll Employees

7125. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether casual labour/muster roll employees are being appointed by his Ministry or Departments/Subordinate Offices under his Ministry ;

(b) if so, the number of such employees employed in his Ministry as well as in each Department and Subordinate offices under his Ministry ;

(c) whether their services are not being regularised even after the lapse of considerable period ; if so, the reasons therefor ; and

(d) the action Government propose to take in respect of regularisation of their services instead of keeping them as casual labour and muster roll workers only for years together ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (d)

The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recovery of dues by B.H.E.L.

7126. SHRI D.S.A. SIVAPRAKASHAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the details of dues by the State Electricity Boards in India to B.H.E.L., for supplies made and services rendered by B.H.E.L. as on 1 March, 1983 ; and

(b) the steps B.H.E.L. has taken to recover the dues from the State Electricity Boards ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The details of dues by the State Electricity Boards to BHEL as on 1 March, 1983 is given in the enclosed statement.

(b) The matter has been taken up by BHEL'S management with State Electricity Boards at various levels and follow-up action is being taken by BHEL to recover these dues. The Government has also taken up the matter appropriately with the States.

Statement

Statement of outstanding against State Electricity Board's

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Electricity Board	Outstanding as on 1.3.1983		Net
		Total	Under reconciliation	
1.	Uttar Pradesh	8226	972	7254
2.	Madhya Pradesh	3765	260	3505
3.	Maharashtra	4643	455	4188
4.	Bihar	2641	332	2309
5.	Andhra Pradesh	788	184	604
6.	Tamil Nadu	2464*	54	2410*
7.	Haryana	3211	121	3090
8.	Gujarat	1194	200	994
9.	Assam	1903	55	1848
10.	Punjab	4287	71	4216
11.	West Bengal	616	58	558
12.	Rajasthan	1099	79	1020
13.	Meghalaya	613	—	613
14.	Orissa	176	3	173
15.	DESU	145	—	145
16.	Kerala	108+	1	107+
17.	Karnataka	52	8	44
18.	J & K	20	1	19
19.	Himachal Pradesh	59	3	56
		36010	2857	33153

* Includes Rs. 970 lakhs progress payment

+ Includes Rs. 81 lakhs progress payments.

Recruitment of Grade IV of Indian Statistical Services

7127. SHRI CHITTA MAHATA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the strength of Indian Statistical Service in Grade IV till 1982 and the number of regular vacancies in each year during the last years;

(b) the number of vacancies notified to UPSC for direct recruitment to Grade IV of ISS during the last three years and number of candidates selected, year-wise for this post;

(c) the number of vacancies year-wise worked out to be filled up by promotion to Grade IV of ISS during the last three years and as a result thereof the number of officials promoted to the post;

(d) the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes appointed year-wise by direct recruitment to Grade IV of ISS during the last three years ; and

(e) Ministry/Department-wise distribution of posts in Grade IV of ISS as on 30 August, 1978 and 30 September, 1982 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) The strength of Grade IV of the Indian Statistical Service as on 31.12.1982 was 273. The number of regular vacancies which had occurred during 1980, 1981 and 1982 was 0 24 and 25 respectively.

(b) The information is given in the Statement attached.

(c) The number of vacancies in Grade IV apportionable to the promotion quota during 1980, 1981 and 1982 was 0.6 and 10. None of these vacancies have so far been filled on a regular basis.

(b) The number of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes appointed during the last three years is as follows :

Year of appointment	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1980	3	1
1981	2	1
1982	8	Nil

(e) The information is contained in the Statement II attached,

Statement-I

Year of IES/ISS Examination	No. of vacancies in Gr. IV of ISS reported to the UPSC				No. of candidates recommended for appointment to Gr. IV of ISS by the UPSC			
	General Category	Sch. Castes	Sch. Tribes	Total	General Category	Sch. Castes	Sch. Tribes	Total
1980	16	18	8	42	38	3	1	42
1981	20	13	7	40	31	8	1	40
1982	20	11	9	40	38	2	—	40

Statement-II

S. No. Ministry/Department	Distribution of post sanctioned in Grade IV of the ISS	
	As on 30.8.1978	As on 30.9.1982

1	2	3	4
1. Works & Housing		5	5
2. Agriculture		10	9
3. Food		1	1
4. Rural Development		1	4
5. Labour		13	13

1.	2.	3.	4.
6. Irrigation	9	20	
7. Mines	6	6	
8. Commerce	6	6	
9. Industry	4	4	
10. Company Affairs	1	1	
11. Health	8	11	
12. Family Welfare	1	1	
13. Revenue	1	1	
14. Shipping & Transfer	2	2	
15. Tourism & Civil Aviation	2	2	
16. Planning Commission	16	9	
17. Statistic	69	66	
18. Home Affairs	10	10	
19. Defence	12	12	
20. Petroleum	1	1	
21. Supply	9	9	
22. Expenditure	—	—	
Total	187	200	

*excluding 73 posts as training, deputation and leave reserves.

Irregularities and Enquiry Into Import of Colour T.V. Kits and Tubes

7128. SHRI B.V. DESAI :

SHRI P.M. SAYEED :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have ordered in enquiry into the manner in which the Development Corporation ordered for TV picture tubes :

(b) whether this has followed due to the allegations of irregularities in the import of colour TV kits and the satellite TVRO stations imports for Doordarshan;

(c) whether enquiry has been ordered as a part of a wider review that Government are likely to make into the alleged state of mismanagement in the public sector electronic units in general and plan projects of the Department of Electronics in particular; and

(d) if so, what was the outcome of the enquiry and what action has been taken against those held responsible ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI

M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (d) On receipt of a complaint from one of the parties responding in a tender by Electronics Trade Technology Development Corporation (ETTDC) for purchase of black and white TV picture tubes, DOE is looking into the matter.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

Promotion of Exports by Small Scale Units of Delhi

7129. SHRI HARISH RAWAT : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has not taken adequate measures for promoting exports by small scale units.

(b) how many small scale industrial units are exporting their products from Delhi ;

(c) the quantum of exports of the small scale units of Delhi during the last three years ; and

(d) whether Government propose to direct and help Delhi Administration to gear up and strengthen their administrative machinery for

co-ordinating and accelerating the pace of exports ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT [TIWARI]) : (a) No, Sir.

(b) There are about 400 small scale manufacturer exporters in Delhi.

(c) Exports made by the manufacturer exporters of Delhi including small scale manufacturer exporters, is estimated as follows :

1978-79	Rs. 75.46 crores
1979-80	Rs. 83.49 ,,
1980-81	Rs. 118.31 ,,

(d) An export promotion cell has been set up in the Directorate of Industries, Delhi by the Delhi Administration for coordinating and accelerating the pace of exports.

Recommendations of the Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Amend Constitution

7130. SHRI GIRIDHAR GOMANG : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission for SC and ST has suggested inclusion of some portions, amendments and new provisos in the constitution in their two reports for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) if so, what are the articles, provisos and portions for inclusion specifically recommended for amendment of the Constitution ;

(c) the steps taken by Government to amend the Constitution as suggested by the Commission ;

(d) whether the recommendations relating to Constitutional provisions for SC and ST have been examined by Government and how many of them have been found feasible and possible and amendment ; and

(e) if there was inordinate delay in formulation and bringing the changes by the concerned ministry ; the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes Sir. The Commission for SC and ST in its 1st and 2nd reports have suggested certain amendments in the Constitution and have also recommended for the inclusion of certain new articles in the Constitution.

(b) Copies of the 1st and 2nd reports of the Commission have already been laid on the table of both Houses of Parliament and the same is available in the Parliament Library. The Amendment proposed by the Commission can be seen therefrom.

(c) to (e) Copies of these reports have been sent to the concerned State Govts/UT Adms and the Central Ministries for their comments. A final view in the matter would be taken after the same is received from them. The amendments in the Constitution as suggested by the Commission in its 1st and 2nd reports can be done only through an Act of Parliament.

Computer Maintenance Corporation Ltd

7131. SHRI AMAL DATTA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Computer Maintenance Corporation Limited has been able to apply Data basis designed by it for the integrated rural development or for the maintenance and utilisation of Railway tracks in the Indian Railway ;

(b) if so, in which area of rural developmental Railway track utilization such application of data has been made ;

(c) what success or achievement has been derived from such application of data ; and

(d) whether it is a fact that the Indian Railway is looking for foreign collaboration for computerisation of maintenance and utilization of railway tracks ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (c) (i) Yes, Sir. Computer Maintenance Corporation (CMC) has designed data base oriented systems for land records. A prototype data base has been successfully developed for 7000 land holdings. The data-base system for land records has opened up possibilities for intending State Governments to expedite their rural development schemes/programmes with the help of computers. (ii) CMC had prepared a detailed design for an information system on various aspects of Railway tracks. The system has not yet been implemented.

(d) No, Sir.

Organisations Opposing Reservation Policy

7132. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the number of organizations opposing reservation policy of the Government for Scheduled Tribes is growing up ;

(b) have Government identified anti-reservationists ; and

(c) action taken against such persons/elements ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Government have no such information.

(b) and (c) No action can be taken against any Organisation Association unless they violate the law or provisions of rules. Government take action on such representations in accordance with Government's own policy on reservation.

Grant of Pen-ion to J & K Persons Imprisoned for Anti-Merger Activities

7133. SHRI R.N. RAKESH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in addition to Central Government Pension Scheme for freedom fighters some of the States such as Jammu and Kashmir have also their own similar pension schemes ;

(b) whether it is a fact that pensions in J&K are being given to those persons who were imprisoned in connection with anti-merger with India and if so, the action proposed to be taken in this regard ; and

(c) whether Government are aware that J&K persons who fought for India's freedom have not been covered by Pension Scheme of Government of India by the J&K Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) Yes, Sir. Various State Governments/U.T. Administrations operate their own pension Schemes for freedom fighters which are complimentary to the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme.

(b) The Govt. of J&K have promulgated a Scheme, apart from their scheme for freedom fighters, which regulates grant of pension to the Political Victims of 1953. The A.G J&K

has, however, not made payment against sanctions under these rules on instructions from Central Government. The constitutional validity of this scheme is under examination.

(c) The Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme is uniformly applicable and is operated all over India and there is no discrimination against freedom fighters of J&K.

Development of Tribal Population in North Eastern Region

7134. SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to undertake a programme for the development of tribal population in the North-eastern region to maintain its rich culture and imbibe modern values alongwith economic and scientific benefits through popular participation ;

(b) whether Government propose to seek support of voluntary organisations and social workers in this regard ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) The States of Nagaland and Meghalaya and the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh consist predominantly of tribal population and, as such, the development plans of those States take care of their tribal population and there is no need for any tribal sub-Plan strategy in those States. However, in the States of Assam, Manipur and Tripura, tribal sub-Plans are also formulated and executed through the concerned State Governments who can take the help of voluntary organisations and social workers for the welfare of Scheduled Tribes in their respective States.

Payment of Fare for 400 Kms for Home Town Under LTC by Central Government Employees

7135. PROF. P.J. KURIEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees who avail themselves of Home-town leave travel concession, have to pay the fare for the first 400 Kms. ;

- (b) if so, the rationale behind this rule;
 (c) whether Government proposes to reconsider it; and
 (d) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAN) : (a) Yes, Sir, in so far as L.T.C. to Home Town once in a block of two years is concerned. Full re-imbursement will, however, be allowed, be allowed if a Govt. servant visit Home Town under the scheme of LTC to any place in India once in a block of four years.

(b) The scheme of Leave Travel Concession to Home Town once in a block of two years was introduced with a view to enable persons living at distant places of the country to enter Central Govt. service. Consequently, persons whose home towns were near their places of work had to be excluded from the scheme. Accordingly, a limit of 400 Kms has been prescribed for all employees except Group 'D' employees while a limit of 160 Kms has been prescribed for Group 'D' employees. Such a limit having been laid-down, persons whose home towns are beyond this limit are required to bear the expenditure for 400/160 kms, as the case may be, to ensure parity of treatment with those who are denied home town LTC on account of their home town being within 400/160 kms.

(c) There is no proposal to reconsider the matter at present.

(d) Does not arise.

बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

7136. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों और पूरे किए गए लक्ष्यों का ब्योरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किस हद तक सफलता अर्जित की गई है और उसका ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :

(क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार का इन सूत्रों के संबंध में प्रत्यक्ष दायित्व है— सूत्र 18 (भाग)—परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का सुनिश्चय करने के लिए उदार निवेश कार्यविधियों/कार्य-प्रणालियों और औद्योगिक नीतियों में सुधार; सूत्र 19—तस्करों, जमाखोरों और करों की चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखना तथा काले धन को रोकना; और सूत्र 20—कुशलता बढ़ाकर, क्षमता उपयोग करके और आंतरिक संसाधन (केवल केन्द्रीय परियोजनाएं) सृजित करके सरकारी उद्यमों के कार्य संचालन में सुधार करना। ये लक्ष्य इतर मर्दे हैं। इन सूत्रों के कार्यान्वयन की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सूत्र संख्या 18—परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उदार निवेश कार्य प्रणालियों और औद्योगिक नीतियों में सुधार

1. "उद्योग रहित जिलों" के लिये पहली बार वर्ष 1982 में 159 आशय पत्र (लैटर आफ इन्टेन्ट) जारी किए गए थे।
2. क्रमशः संयुक्त आवेदनों और एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आवेदनों के लिए 120 और 150 दिन की समय सीमा को कम करके 90 दिन कर दिया गया है।
3. अन्य उद्योग लाइसेंसों के लिए 90 दिन की सीमा को कम करके 60 दिन कर दिया गया है।
4. निर्यातान्मुख उद्योगों के लिए समय सीमा 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दी गई है।

5. 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से स्वतः संवृद्धि की व्यवस्था जिसके लिए 5 वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
6. मूल और सामरिक महत्व के उद्योगों में लाइसेंस/पंजीकृत क्षमता की तुलना में आधिक्य क्षमता को स्वीकार करना तथा निर्यात विकास क्षमताओं को भी स्वीकार करना।
7. 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख इकाइयों के लिए स्कीम बनाना।
8. लघु क्षेत्र को संरक्षण देते हुए क्षमताओं के समर्थन के आधार के रूप में उत्पादन को स्वीकार करना।
9. "उद्योग रहित जिलों" अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।
10. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए स्कीमों को लाइसेंस मुक्त करना।
11. उत्पादन को बाह्य मानते हुए निर्यात के प्रयोजन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता।
12. सरकार ने एक ऐसी स्कीम भी तैयार की है जिसके अन्तर्गत उत्पादकता वर्ष में औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन का निश्चित पूर्वाभिमुखीकरण करना संभव होगा। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु क्षेत्रक आदि को उचित संरक्षण देते हुए इकाइयों द्वारा किए गए उत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं में वृद्धि की अनुमति दी जाती है।

सूत्र संख्या 19—तस्करों, जमाखोरों और करों की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखना और काले धन को रोकना

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो माल/सामान पकड़ा गया है, जो तलाशियां ली गई हैं और जो छापे मारे गये हैं उनके बारे में स्थिति नीचे सारणी में बताई गई है।

तस्कर-निरोधी उपाय	1981	1982	जनवरी-फरवरी, 83
1. (क) पकड़े गए तस्कर माल/वस्तुओं की संख्या	62124	71159	उ० न०
(ख) वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रु०)	39.72	65.89	14.41
2. (क) मारे गये छापों और तलाशियों की संख्या	18974	19512	2554
(ख) मूल्य (करोड़ रु०)	8.47	14.22	1.98
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी	1981	1982	जनवरी, 83
(क) तलाशियों की संख्या	5257	7191	520
(ख) पकड़ी गई कर चोरी मूल्य (करोड़ रु०)	50.06	51.72	2.16
प्रत्यक्ष करों की चोरी	1981	1982	जनवरी-फरवरी, 83
(क) तलाशियों की संख्या	3814	4677	745
(ख) कब्जे में ली गई			

परिसंपत्तियों का मूल्य

(करोड़ रु०)

29.95

27.29

4.44

विदेशी मुद्रा विनियमन

अधिनियम

1981

1982

जनवरी-फरवरी, 83

(क) तलाशियों की संख्या

1700

1867

343

(ख) मूल्य (लाख रु०)

77.67

90.48

5.43

(ग) कब्जे में ली गई विदेशी

मुद्रा का कुल मूल्य

(लाख रु०)

36.71

45.48

6.42

सूत्र संख्या 20—केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रम

(करोड़ रु०)

1982-83 (अनंतिम)

कुल बिक्री

41131.00

निवल लाभ

597.25

आंतरिक ससाधनों का सृजन

वर्ष के लिए बजट में शामिल

1673.00

सृजित संसाधन (दिसम्बर, 82 तक)

2133.73

लगाई गई पूंजी के रूप में सकल लाभ

की प्रतिशतता

13.48%

उ० न०—उपलब्ध नहीं।

Mushroom Growth of Institutions Financed by Arab Petro-Dollars

7137. SHRI P. NAMGYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published in 'Kashmir Times' Jammu, dated 1 February, 1983 captioned "Mushroom growth of Institutions financed by Arab Petro-dollars" ;

(b) if so, the number and names of such Institutions which have come to the notice of Central Government ;

(c) the total amount received by the each organisation ; and

(d) the steps taken by Government to prevent such irregular flow of foreign money in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The only organisation mentioned in the news item which has intimated receipt of foreign contribution is Anjuman Nassrat-ul-Islam. The particulars of amounts received by it during 1979 to 1981 are given below :—

	(in rupees)
1979	800.00
1980	96,455.00
1981	71,925.00

The other organisations mentioned in the news item are being asked to furnish the required information.

(d) The question of amendment of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 to tighten its provisions is under examination.

**Recommendation of Expert Group on
Programme for Alleviation of
Poverty**

7138. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Expert Group on Programme for Alleviation of Poverty made certain recommendations to make the Poverty Alleviation Programme more effective ;

(b) if so, what are their details and also those of the actions taken to implement them; and

(c) the impact of those measures in alleviating poverty and how many people were raised above the poverty line under the Programme ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the main findings of the Report of the Expert Group is enclosed.

Copies of the Report have been sent to all State Governments as also to the Ministry of Rural Development and other concerned Ministries at the Centre. The Ministry of Rural Development is taking necessary follow-up action the recommendation of the Report.

(c) The two important programmes for alleviation of poverty, namely, Integrated Rural Development Programme and National Rural Employment Programme have been in operation in the States and Union Territories from October, 1980. Available evidence of their working shows that a considerable number of people below the poverty line have benefited from the programmes. Evaluation studies to assess the impact of these programmes by way of alleviation of poverty are in progress.

Statement

Main findings of the Report on Programmes for Alleviation of Poverty

(1) The recruitment, training and posting of staff in the District Rural Development Agencies has picked up momentum and most of the agencies are functioning.

(2) The block is the basic unit for rural development. Over the years its role and responsibility for coordinating and implementing different sectoral development programmes had suffered a set back.

(3) Emphasis also need to be laid on adequate training and orientation of the blocks staff for implementing the IRDP and other programmes of poverty alleviation in the rural areas. Needless to mention that these are quite complex projects to implement and administer.

(4) There is need to forge linkages between the Integrated Tribal Development Projects and District Rural Development Agencies.

(5) The fact remains that the support has not been forthcoming in adequate measure from the concerned departments. Coordination too has been weak at the district and weaker still at the block level.

(6) The flow of institutional credit to the IRDP families is beset with a number of problems. Institutional finance has not flowed to the extent expected.

(7) The General Body of the Village i.e. the Gram Seva or the elected body the Gaon Panchayat is not always consulted in the selection of the poorest families. The involvement of the local bodies—statutory and otherwise has not been to the extent desired.

(8) Some arrangements have been made for the involvement of voluntary agencies etc. but these are at best feeble and half-hearted.

(9) The scheme (TRYSEM) as formulated, thus excludes a large number of other rural youths who too are badly in need of acquisition of skill from its purview.

These recommendations of the Expert Group are given in Chapter III of the Report (Pages 31 to 65) copies of which are available in the Library of Parliament. (Index No. 339. 46 RM 2).

"Decimating Rare Wild Life"

7139. SHRI NITYANANDA MISRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of growing incidence of decimating rare wild life in the country by poachers by adopting new methods like poisoning, arrow-trapping and deadly roots and similar techniques;

(b) whether such incidence specially from tiger reserve of Orissa had come to the notice of Government; and

(c) the steps Government propose to take against the killing of the animals through these methods.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINGH) : (a) and (b) Only four cases have come to notice lately and these relate to Simlipal Tiger Reserve in Orissa.

(c) Legal action under the Wild Life (Protection) Act 1972 has been initiated against the offenders. Strict vigilance is being maintained and the State Government has been advised to deal with such cases firmly.

Implementation of E.R.R.P. Programme

7140. SHRI NARAYAN SAHU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state.

(a) whether his Ministry is aware that Government of Orissa has started Economic Rehabilitation of Rural Poor fully financed by the State Government during Sixth Plan Period;

(b) if so, whether it is a fact that the subsidy under E.R.R.P. is cent per cent whereas for other programmes of the Central Government it is 50 per cent;

(c) whether it is a fact that to popularise the E.R.R.P. among the people, more funds for this scheme have been allocated during the years of implementation, neglecting the provision of funds for the centrally sponsored schemes;

(d) if so, whether it is a fact that N.R.E.P. sponsored by the Central Government and other schemes have been some times not fully attended to; and

(e) whether some funds are also being diverted from the State Sector resulting in

non-utilisation of Central Government share in some Blocks, particularly in Dhenkanal district ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) :

(a) Yes, Sir.

(b) The subsidy under the ERRP varies for different schemes. Land based schemes and fishery, lac cultivation and mulberry and tassar development schemes are fully subsidised by the State Government. The subsidy is 75% in the case of animal husbandry and non agricultural schemes including rural industries. It is 50% in the case of the cycle rickshaw scheme. In Centrally Sponsored Integrated Rural Development Programme, the rate of subsidy is 25% for small farmers, 33.1/3% for marginal farmers, agricultural labourers and rural artisans and 50% for tribal beneficiaries.

(c) At the time of the discussions on the Annual Plan, the ERRP and other State Plan schemes are also considered by the Planning Commission in finalising the allocation of funds. It is not a fact that funds are sanctioned for the E.R.R.P. neglecting provision of funds for the centrally sponsored schemes of Integrated Rural Development Programme, National Rural Employment Programme, etc.

(d) No, Sir. Every care is being taken to allocate adequate funds for N.R.E.P. and other Centrally sponsored schemes every year in the Plan.

(e) No instance of such diversion of funds either in Dhenkanal or elsewhere in Orissa has come to the notice of the State Government.

Legislation for the Citizens Access to Official Information Regarding Public Affairs

7141. SHRI CHITA BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact suitable legislation guaranteeing the citizens to official informations regarding public affairs; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b)

The Second Press Commission has made certain recommendations on this subject. These are being examined.

Grant of Industrial Licences Under MRTP Act

7142. SHRI K. LAKKAPPA :

SHRI GULSHER AHMED :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether new industrial licences were granted to any Industrial House, registered under Section 26 of the M.R.T.P. Act 1969 during the last three years and if so, the details thereof;

(b) the reasons and justification for grant of such new licences;

(c) whether the industries for which new licences were granted have been set up;

(d) if not, the reasons therefor and action taken, if any by Government; and

(e) present policy of Government in the matter of sanction of new Industrial licences to Industrial Houses covered under MRTP Act ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes, Sir. 276 licences were issued during the year 1980-82 to the industrial undertakings registered under the M.R.T.P. Act, 1969. The details about these licences are published regularly by Indian Investment Centre and circulated alongwith their Monthly News Letter.

(b) These licences were issued on due consideration of merits of each case and in accordance with the provisions of the I (D&R) Act, 1951.

(c) and (d) The licensed industrial undertaking are required to be set up in accordance with the conditions stipulated in the relevant licence and within the period as specified in each case. Monitoring Cells have been set up in each Ministry to review their progress and steps are taken to revoke licences where progress in implementation is not found satisfactory.

(e) The industrial undertaking covered by the M.R.T.P. Act can set up industries included in Appendix I to the Press Note of 2nd

February, 1973 as amended by Press Note of 21st April, 1982. They can set up industries in areas not included in Appendix I subject to undertaking of prescribed level of export obligation.

CBI Probe Regarding Misappropriation by Top Officials and a Minister of Manipur

7143. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI SURAJ BHAN :

SHRI RAMPRASHAD AHIRWAR :

Will the Minister of Home AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for many months, the C.B.I. has been making investigations into at least seven cases of misappropriation and embezzlement of several crores of rupees involving some top officials and a Minister of Manipur ;

(b) whether it is a fact that some cases involving the Chief Minister have already been withdrawn from the CBI ; and

(c) it so, full facts in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) Yes Sir. Ten cases involving various officials and an ex-Minister of Manipur are under investigation by CBI.

(b) and (c) Yes, Sir. Following the withdrawal of consent under section 6 of the DSPE Act by the Government of Manipur, some cases have been withdrawn from CBI.

Number of IAS/IPS/IFS Posts Manned by Scheduled Casts and Scheduled Tribes in Government of India

7144. SHRI BANWARI LAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of posts manned by IAS, IPS and IFS as on 1 January, 1983 in various Departments/Ministries of Government of India ;

(b) the total number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in (a) above along with their particulars ; and

(c) steps taken by Government to give adequate representation under directives issued by Prime Minister in this regard and the results thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATSUBBAIAH) : (a) and (b) The requisite information in respect of officers belonging to the Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service who were serving at the Centre on tenure deputation (excluding those working in public enterprises or on foreign assignments) as on 1.1.83 is indicated below :

	I.A.S.	I.P.S.	I.F.S.
1. Total	638	27	2
2. Number of SCs/STs out of the total	44	3	—

(c) Posts of and above the rank of Under Secretary at the Centre are normally filled by drawing officers from All India Services and other organised Central Services Group 'A' on the basis of suitability, keeping in view the specific requirements of each post and the qualifications and experience of the officers on offer for central deputation. Since these posts are normally filled on tenure deputation basis, there is no reservation provided for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in these posts. However, recruitment rules in respect of various Services, including the Indian Administrative Service, the Indian Police Service and the Indian Forest Service, from which officers are drawn to man the posts in Central Secretariat provide for reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Moreover, whenever cadre controlling authorities of different cadres are requested to suggest names for central deputation, they are advised to give due consideration to eligible Scheduled Caste/Scheduled Tribe officers and names of Scheduled Caste/Scheduled Tribe officers so recommended are considered while making placements at the Centre.

न्यूज प्रिन्ट कारखानों का समुचित कार्यकरण

7145 श्री रतन सिंह राजदा :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दशनि वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्यूज प्रिन्ट के कुल कितने कारखाने हैं;

(ख) उनमें से उन कारखानों की संख्या कितनी है जो सुचारू रूप से उत्पादन कार्य में संलग्न है;

(ग) उन कारखानों की संख्या और नाम क्या हैं जो सुचारू रूप से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) उनके द्वारा सुचारू रूप से उत्पादन न कर पाने के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):

(क) से (घ) वर्तमान में देश में अखबारी कागज उत्पादन करने वाले तीन एकक हैं। दि नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि० सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। किन्तु, मैसूर मैसूर पेपर मिल्स लि० के अखबारी कागज एकक और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० केरल अखबारी कागज परियोजना को जिनमें उत्पादन क्रमशः 1981 और 1982 में चालू हुआ है, अभी अपना उत्पादन स्थिर करना है। वे 1982 के मध्य से बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं।

Implementation of Reservation Quota of SCs/ STs in Cabinet Secretariate, RAW

7146. SHRI KESHAORAO PARDHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that reservation quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not implemented in the Cabinet Secretariat Research and Analysis Wing in recruitment, departmental competitive examinations and promotions, etc., for the last three years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, the details of the implementation of the reservation quota separately for recruitment, departmental competitive examinations and promotions ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) to (c) In view of the special nature of the work of this organisation, the reservation orders are not applicable to it. However, it has been laid down that the Head of the Organisation shall, subject to the requirements of the organisation, make every effort to observe such orders in spirit.

न्यूज प्रिंट कारखानों की उत्पादन क्षमता

7147. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में न्यूज प्रिंट कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इस समय कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : देश में अखबारी कागज बनाने वाले तीन एककों की वार्षिक क्षमता 2,225 लाख मी०, टन है और 1982-83 के दौरान उनकी क्षमता का कुल उपयोग लगभग 52.4 प्रतिशत रहा है।

Over Utilization of Licenced Capacities

7148. SHRIMATI KISHORI SINHA : Will the Minister of INDUSTRY

be pleased to state :

(a) whether some companies which require special regulations are reported to have flouted the Industrial Licensing System ;

(b) if so, whether some of their production levels are twice their licensed capacities ; and

(c) the names and other details of such industrial units/companies ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATI TIWARI) : (a) to (c) The precise type of information called for in the question is not clear. There are no companies as such requiring special regulation. However there are industries like coal, power-loom textiles, milk foods, oilseeds, leather, matches, brewing industry etc. covered by special regulations under exemption notification issued under the IDR Act. In the absence of any reference to any industry/company engaged in the above mentioned industries, it is not possible to give any worthwhile information.

Employment to Persons Displaced on Account of Acquisition of Land for

VIZAG STEEL PLANTS

7149. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of persons displaced or to be displaced on account of acquisition of land for Vizag Steel Plant ;

(b) the number of displaced persons employed ; and

(c) whether Government are having any plan to employ others ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) According to the information furnished by the Government of Andhra Pradesh, 5803 families have been displaced on account of acquisition of land for the first phase of the land acquisition for the Visakhapatnam Steel Project.

The number of families likely to be displaced in the final phase of acquisition of land is expected to be 5,000.

(b) As on 28-2-83, out of total 1805 non-executives employees, 1054 displaced persons have been appointed. Besides, 6339 displaced persons have been provided employment by various contractors engaged for the project.

(c) It is the policy of the Government of India to provide employment in the steel plants to one able-bodied person from each family, displaced on account of acquisition of land, for the construction of the steel plant. Visakhapatnam Steel Project authorities have been giving preference to displaced persons in matters of employment. In order to facilitate their employment, they are being given relaxation with regard to age. In several cases, they have been trained in order to make them employable.

Vigilance Enquiries Against Indian Police Officers by C.V.C.

7150. SHRI ANAND SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of officers of the Indian Police Service against whom vigilance enquiries are being held by the Central Vigilance Commission ;

(b) how many of the above officers who have had or are having vigilance cases against them are still holding sensitive posts in Central Government Police Organisation; and

(c) what Government propose to do to get these officers transferred back to their States in view of the Prime Minister's recent directive to weed out corruption in Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Two

(b) None of them is holding any post in the Central Police Organisation.

(c) Does not arise.

"Setting up of National Institute for Conservation of Wild Life in Orissa"

7151. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the PRIMA MINISTER be pleased to state:

(a) whether Orissa Government had offered land to the Central Government for location of the National Institute for Conservation of Wild Life; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a), No Sir.

(b) Does not arise.

Report of Indian Institute of Public Administration regarding Small Sector

7152. SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the work of Indian Institute of Public Administration in respect of small sector;

(b) if so, whether the report has mentioned about induction of FERA and LBH companies in the small sector; and

(c) if so, action taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (c) Presumably the reference is to the report "Functioning of Industrial Licences System"

brought out by Indian Institute of Public Administration in January, 1983 wherein a mention has been made about some of the large companies having sought exemptions from the purview of Industries (Development & Regulation) Act claiming that their enterprises were registered as small scale units and/or their products do not fall under the purview of the said Act.

A provisoion has already been added to the definition of small scale industries in 1980 whereby the units which are subsidiary of or owned or controlled by medium and large scale undertakings have been subjected to the normal licensing provisions under the Industries (Development & Regulation) Act.

Chain Snatching in Delhi During March 1983

7153. SHRI G. NARSIMHA REDDY. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a car borne gang had committed a large number of Chain snatching in broad daylight in Delhi during March, 1983;

(b) if so, the number of such incidents that took place;

(c) whether the culprits remained untraced for nearly 15 days despite best police efforts; and

(d) what is the present position of such cases now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATSUBBAIAH): (a) and (b) In the month of March, 1983 6 cases of chain snatching by carborne culprits during day time were reported to the Delhi Police.

(c) and (d) Cases have been registered at various police stations and vigorous efforts are being made to apprehend the culprits.

Cement Plant in Gujarat

7154. SHRI RAMJIBHAI MAVANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of big, small and mini cement plants in public and private sectors have been approved and sanctioned by Government in Gujarat and

other States during 1 April, 1977 to 15 March, 1983

(b) if so, the names and places of the same;

(c) how many applications have been received during the above period from public and private sector from each States and the details thereof;

(d) How many of them have been rejected and the reasons therefor in each case;

(e) What is the capacity production and investment of each of the above ones; and

(f) how many sanctioned and approved plants of the above have started production and the details of each one with yearly production by each one during the above period ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) 167 letters of intent and 44 industrial licences were issued during the period 1977-83 for setting up cement plants in the public and private sectors in different States. Details of letters of intent and industrial licences, including the name of the party, address, location, item of manufacture, etc. are being published by the Indian Investment Centre in their 'Monthly Newsletter'. Copies of this publication are available in the Parliament Library.

(c) to (f) The information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

Fake SC and ST Certificates

7155. **SHRI G.Y. KRISHNAN :**

SHRI N.E. HORO :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some cases of fake Scheduled Caste Certificates have been brought to the notice of Government;

(b) whether Scheduled Castes Certificates are much sought after by students claiming to belong to the Scheduled Castes or Tribes of backward classes or minority communities to get admission to educational institutions;

(c) if so, the number of such cases, State-wise, brought to the notice of Government during last three years; and

(d) the steps Government have taken in this regard to protect welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this regard;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) :

(a) to (c) The requisite information is being selected from the State Governments/U.T. Administrations and will be laid on the Table of the House.

(d) The Ministry of Home Affairs has issued instructions to all the State Governments/UT. Administrations from time to time requesting them to take deterrent action against officials who issued certificates carelessly or deliberately without proper verification. The State Governments/U.T. Administrations were also requested to issue necessary instruction to all officials under their control who are empowered to issue certificates to take proper care before issuing them. Those officials were also to be informed that action would be taken against them under the relevant provisions of the Indian Penal Code if any one of them is found to have issued certificates carelessly and without proper verification in addition to the action to which they are liable under the appropriate disciplinary rules applicable to them.

Promotion of Engineering Industry

7156. **SHRI LAKSHMAN MALLICK :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have taken steps for the promotion of Engineering Industry in the country ;

(b) if so, the steps taken by Government to increase the number of engineering industry in the State of Orissa ; and

(c) the details of the programme proposed to be taken up in 1983-84 in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S. M. KRISHNA) : (a) Some of the steps include removal of infra-structure constraints, encouragement of technology upgradation, modernisation, expansion of capacities as also export development, interaction with other agencies to revive demand for commercial planning investments in

projects using the output of engineering industries and various policy measures.

(b) and (d) A nucleuse industrial complex is in the process of being set up in the State. In 1983-84, an outlay of Rs. 447 crores has been provided for Central projects located in Orissa, in addition to an outlay of Rs. 12.63 crores in the State's plan for large and medium industries. All these would lead to increase of engineering industries also.

Issue of Licences for setting up of Industries in no Industry District, Maharashtra

7157. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are giving priority to the issue of Industrial licences where an industrialist proposes to set up an industry in 'no industry district' over the backward districts ;

(b) whether Government are aware that this is causing a great hardship to the State of Maharashtra because some leading private firms who wanted to set up their industry in the backward areas of Maharashtra have been denied licence and have been requested to set up such industry in 'no industry district, but unfortunately Maharashtra does not have any such district so far where as they have many backward areas as defined by the Planning Commission ;

(c) whether this anomolous situation will retard the industrial growth of rural Maharashtra ; and

(d) if so, whether Government would try to resolve this anomaly and allow licences for the backward areas of Maharashtra ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Dispersal of industries and correction of regional imbalances are two of the prime objectives of industrial licensing policy. Maharashtra is an industrially advanced State. In 1982, Maharashtra has been granted 148 Letters of Intent and 95 Industrial Licences of which 42 Letters of Intent and 21 Industrial Licences are for the Backward Areas of the State. The total number of Letters of Intent and Industrial Licences continues to be the highest compared to any other State in India.

Atrocities on Minorities and weaker Sections during last three years

7158. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of places in the country where atrocities on minorities and weaker sections (specifying minor and weaker section) were committed during the last three calendar years and current year ;

(b) the total loss of life and property sustained by them so far ; and

(c) the places visited by Ministers of Central Government and State Governments on such occasions during this period together with details ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS. (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) During the last three years, some of the major incidents of crime against Scheduled Castes have been reported in Pipra (Bihar), Kafalta (U.P.), Deholi (U.P.) Sadhopur (U.P.), Kestara (Madhya Pradesh), Narayanpur (Bihar), Bira (Bihar), Kutruguda (Orissa), Ayyauram (Tamil Nadu), Gaini (Bihar), Sewanan and Bhagwanpur (Bihar), and Padirikuppam (Andhra Pradesh). Of these places, Pipra, Kafalta, Deholi, Sadhopur and Padirikuppam were visited by Central Ministers. In these incidents, a total of 110 members of Scheduled Castes lost their lives. No separate record is kept of crimes against members of other communities such as minorities etc.

Achievements of Second Antarctica Expedition

7159. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the achievements of the second Antarctica expedition team which returned to Goa after completion of their successful mission on 21st March '83 ;

(b) whether they have collected further information regarding poly-metal nodules in sea bed and availability of hydro carbons in different forms ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): The Second Indian Scientific Expedition to Antarctica left Goa on 1st December, 1982 and returned on 21st March, 1983 after a stay of 56 days on the continent of Antarctica. During the stay in Antarctica and during the voyage to and from Antarctica, significant scientific work done in the disciplines of geology, glaciology, meteorology, marine biology, radio-physics, geo-magnetism, geophysics, oceanography, bacteriology, physiology and acoustics. The report of the expedition is awaited.

(b) No sir, the collection of information regarding polymetallic nodules in the sea bed and the availability of hydro-carbons in different forms did not form part of the objectives of the Second expedition.

(c) Does not arise.

Arrest Under N.S.A.

7160. **SHRI GHUFRAN AZAM :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :—

(a) whether the Central Government have directed State Governments to make maximum use of National Security Act to deal with communal elements;

(3) if so, whether Government are aware that some States are not implementing the directions of the Central Governments in this connection;

(c) the details of persons arrested under this Act during the last six months in each States; and

(d) what steps have been contemplated by Government in this regard for its speedy implementation in this country.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The Central Government have not issued a directive as such through its use in this context has been suggested.

(b) The question does not arise.

(c) A statement is attached.

(d) The provisions of the National Security Act, 1980, are available to all States/U.T. Administrations (except Jammu & Kashmir) to be invoked as situation warrants.

Statement

No. of persons (State-wise) arrested under the National Security Act, 1980, during the period from 1.7.82 to 31.12.82

S.No.	State/U.T.	No. of persons detained.
1.	Andhra Pradesh	20
2.	Assam	9
3.	Bihar	16
4.	Gujarat	28
5.	Karnataka	5
6.	Madhya Pradesh	80
7.	Maharashtra	134
8.	Manipur	29
9.	Orissa	6
10.	Punjab	1
11.	Rajasthan	1
12.	Tamil Nadu	8
13.	Uttar Pradesh	101
14.	Delhi.	2
15.	Mizoram.	16
	Total	456

Note : The Act is not applicable to Jammu and Kashmir. Information about the remaining States/U.T. Administrations is 'Nil'

Shortage of Cement

7161. **SHRI UTTAMBHAI H. PATEL : SHRIMATI GEETA MUKHERJEE :**

Will the Ministry of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great shortage of cement in various parts of the country including Gujarat and due to this various project of roads construction and bridge construction and a number of other important projects and industries have come to standstill in public and private sectors;

(b) if so, what steps Government have taken to reduce the shortage;

(c) whether there is great discontentment in the public that they are not getting the cement as required by them;

(d) if so, what steps Government have taken to supply cement to ordinary and middle class people for their necessity; and

(e) what was the requirement and demand of Gujarat and other States during 1977 to 1982 and how much quantity was given to Gujarat and other States during the above period?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) There is a general shortage of cement in the country including State of Gujarat. To this extent, possibility of some construction works in the State of Gujarat being adversely affected cannot be ruled out. Government are making every effort to increase availability of cement in the country by better utilisation of existing capacity, creation of additional capacity and to some extent through imports.

(d) After introduction of the new policy of partial de-control of cement, allotment of levy cement to public is made by State Governments/Union Territory Administration from the bulk allocations placed at their disposal. The various categories eligible for allocation of levy cement are indicated in the Press Notes dated 27.2.1982, 21.4.1982 and 7.5.1982 copies of which have already been laid on the Table of the House in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 4170 answered on 23rd March, 1983.

(e) The State Governments including Governments of Gujarat do not forward their requirements of cement to the Central Government on a regular basis. It is therefore, difficult to indicate the demand for cement by the various State Governments during this period. However, a statement indicating allocation and despatches of cement to the States/Union Territories during the years 1977 to 1982 is laid on the Table of the House. [Pleased in library. Sec No. LT-6374/83]

Applications for Licences for setting up of Industries in Gujarat

7162. SHRI SHANTUBHAI PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether many prospective entrepreneurs who applied for licences for setting up industries in Gujarat had been advised by his Ministry to opt for other states;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any reply has been sent to Gujarat Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) During the period from 1.1.1980 to 31.3.1983, Gujarat has received 420 letters of intent, which is the second highest for any State in the country.

Only eight applications, out of a Total of 735 received for Gujarat during the period 1.1.1980 to 31.3.83, were approved for locations in 'no industry' districts/centrally backward districts of industrially backward States keeping in view :—

(i) Government's policy of correcting regional imbalances and ensuring industrial dispersal; and

(ii) the type of the products/industry applied for.

(c) Copies of letters of intent/industrial licences are normally endorsed to the State Governments concerned. Letters received from the State Governments are also replied promptly.

"Assistance to State for checking environment problem"

7163. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Central Government have taken decision to assist the States in checking environment problems;

(b) if so, whether any scheme has been evolved by the Centre for this purpose; and

(c) the details of the funds earmarked towards this programme in 1983-84 financial year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINGH) : (a) and (b) Yes, Madam. In addition to on-going and planned schemes for soil conservation, afforestation, wildlife management and such other activities for which central assistance is being offered, a new scheme has been formulated to provide catalytic support to the States for planning, promotion and coordination of environmental programmes at the State level.

(c) A token outlay of Rs. 5.00 lakhs has been earmarked for 1983-84. The details of the programme would be finalised on the basis of specific proposals from the States,

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिकों की भर्ती के लिये टाइपिंग परीक्षा

7164. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने लिपिकों के पद पर भर्ती करने के लिए जनवरी, 1983 में टाइपिंग परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के बाद भी आयोग सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति में एक वर्ष से अधिक समय लेता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) अधिकांश केन्द्रों में कर्मचारी चयन आयोग ने लिपिक ग्रेड परीक्षा 1982 के लिए टंकण परीक्षाओं का आयोजन जनवरी और फरवरी 1983 में किया था।

(ख) लिपिक ग्रेड परीक्षा 1982 के परिणामों के मई 1983 में घोषित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आयोग सभी पात्र उम्मीदवारों के डोजियर प्रयोक्ता विभागों/कार्यालयों को अग्रोषित करता है। इसके बाद, सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कतिपय औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद, सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाती हैं।

Police Strength in Metropolitan Town

7165. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the population in Delhi that a policeman is expected to look after ;

(b) whether the police force in Delhi is considered to be inadequate ;

(c) what are the corresponding figures with respect to other metropolises ; and

(d) what steps are being taken to augment the police strength in different metropolitan towns ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH : (a) No Yardsticks have been laid.

(b) If the strength of the police in Delhi i.e. 30,627 & the population are compared with other metropolitan cities like Bombay, Madras, or Calcutta this cannot be construed as inadequate. However, the capital city has got its own problems of law and order and keeping this in view there is continuous review not merely for increasing the strength of the force whenever found necessary but also for improving its efficiency.

(c) The strength of police force in the Metropolitan cities of Bombay, Calcutta and Madras in the year 1979, for which the figures are available is indicated below :

City	Strength of police force
Bombay	22,305
Calcutta	20,413
Madras	6,624

(d) The strength of the police force in Delhi is reviewed from time to time and appropriate additions made. As regards the other Metropolitan-cities, the Police force is the concern of the respective state Government.

Reprocessing of spent fuel from Tarapur Atomic Power Station

7166. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to reprocess the spent fuel from the Tarapur Atomic Power Station in view of the exchange of draft on the matter between India and France ;

(b) whether supply of enriched uranium for the Tarapur Atomic Power Station has since been commenced, if so, details thereof ;

(c) the details of quantity and quality of first shipment of enriched uranium received by India and the period for which it will continue ;

(d) the capacity and strength of the re-processed spent fuel for use either at Tarapur Atomic Power Station or else-where ; and

(e) how much foreign exchange will be saved as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) :

(a) The decision to reprocess the spent fuel from Tarapur reactors will be taken at the appropriate time.

(b) Enriched uranium supplies under the recently and concluded agreement with France are expected to

(c) commence shortly.

(d) and (e) Do not arise.

Ball Bearing Industries

7167. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names and number of the industries producing ball bearings in the country ; and

(b) the locations of those ball bearing industries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) and (b) The names and locations of the industrial units who are borne on the list of the Directorate General of Technical Development for the manufacture of ball and roller bearings are given below :

Sl. No.	Name of the company	Location
1.	M/s. Associated Bearing Co. Ltd.	Pune (Maharashtra)
2.	M/s. National Engineering Industries Ltd.	Jaipur & Newai (Tonk) (Rajasthan)
3.	M/s. Precision Bearing India Ltd.	Vadodra (Maharashtra)
4.	M/s. Shriram Bearing Limited	Ranchi (Bihar)
5.	M/s. Anti-Friction Bearing Corporation Limited.	1. Lonavala (Mah.) 2. Bharuch (Gujarat)
6.	M/s. H.M.T. Bearing Limited	Hyderabad (A.P.)
7.	M/s. Needle Roller Bearing Company Limited	1. Thane (Maharashtra) 2. Aurangabad (Mah.) 3. Jalna (Man.) Mysore (Karnataka)
8.	M/s. Deepak Insulated Cables Corporation Limited.	
9.	M/s. Metal Box India Limited	Kharagpur (West Bengal)
10.	M/s. Asian Bearings Limited.	Hosur (Tamil Nadu)
11.	M/s. Union Bearing Manufacture Company.	Porbunder (Gujarat)
12.	M/s. Amber Bearing Mfr. Company Private Limited.	Nagpur (Maharashtra)
13.	M/s. Mysore Kirloskar Limited.	Harihar (Karnataka)
14.	M/s. Austin Engg. Company Private Limited,	Junagadh (Gujarat).

Meetings of Tribes Advisory Councils in States

7168. SHRI PIYUSH TIRKI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the particulars of members of the Tribes Advisory Councils set up in the state where there is provision for their establishment under clause (4) of the Fifth Schedule of the Constitution ;

(b) the details of the meetings of the Tribes Advisory Councils convened so far in those States ; and

(c) if no meetings have been held, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House when received.

Setting up of bar and Rod Mill by Tisco

7169. SHRI A.C. DAS : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the bar and rod mill proposed to be set by Tata Iron and Steel Company Ltd. under its modernisation and expansion programme has been cleared by Government ;

(b) if so, what would be the capacity of TISCO after the establishment of the bar and rod mill ;

(c) what was the main criteria in clearing the expansion scheme ; and

(d) what are the other facilities allowed to be installed by the above private sector company ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) Yes, Sir.

(b) 2.1 million tonnes of saleable steel per annum.

(c) The main criteria for clearing the expansion scheme was need for replacement and modernisation of obsolete equipment.

(d) Besides bar and rod mill, other facilities are a new sintering plant with a capacity of about 1.2 million tonnes/annum, technological improvements in the blast furnaces and a second continuous casting machine.

Production of Chrome Ore

7170. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the name of the States producing chrome ore at present ;

(b) the annual production of chrome ore by each of those States in last three years ; and

(c) the details of the grade and quality of the chrome ore available in those States ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) and (b) Details of production of chrome ore State-wise for the last 3 years is as follows :

State	(Qty in tonnes)		
Andhra Pradesh	1980	1981	1982
	50	248	324
Bihar	304	586	594
Karnataka	53,141	54,762	63,554
Maharashtra	2,713	2,568	257
Manipur	976	320	78
Orissa	264,134	277,611	274,389
Total	21,318	336,095	339,196

(c) The grade-wise production of chrome ore in 1982, State-wise was as follows:

State	(Qty in tonne)			Total
	Above 47% Cr203	40-47% Cr203	Below 40% Cr 203	
Andhra Pradesh	—	—	324	324
Bihar	—	594	—	594
Karnataka	—	13,703	49,851	63,554
Maharashtra	—	—	257	257
Manipur	7	71	—	78
Orissa	145,178	71,073	58,138	274,389
	145,185	85,441	108,570	339,196

**Slump in Tractor/Automobile Industry
due to Credit squeeze by RBI**

7172. SHRI R.L. BHATIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether he is aware that the credit squeeze by the Reserve Bank of India has very adversely affected the tractor/automobile industry particularly the small scale entrepreneur ;

(b) whether due to lack of sale of tractors, the industry is facing a great slump and work in entire ancillary industry has come to a standstill ; and

(c) whether with a view to help to the farmers for mechanising the agriculture and at the same time reviving the ancillary industry of tractor manufacturers, Government would take up the matter with the Reserve Bank of India asking it to relax credit squeeze in this respect specifically ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) :

(a) to (c) It is a fact that the tractor industry and its ancillaries were adversely affected to some extent on account of lower production arising out of lower sales in 1982-83 as compared to 1981-82. The manufacture ascribed this phenomenon to inadequate credit availability to the intending customers. Government have been constantly monitoring the position and have also been constantly in touch with the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India have in turn taken some steps to improve the situation. It is hoped

that with the implementation of these measures tractor production will pick up in the country.

As regards the automobile industry, the production in 1982-83 has generally been of a higher order than in the preceding year.

I.S.R.O. Project in Kanya Kumari

7173. SHRI H.N. BAHUGUNA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the serious objections of ecologists on the ill-advised and poorly designed ISRO project in the Mahendragiri Hills in Kanya Kumari district in TAMILNADU (India Today, dated 28 February, 1983); and

(b) if so, whether any corrective steps are proposed to undo the damage to ecology in keeping with Government pronouncements and policies ?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Government are not aware of objections raised by ecologists to the proposed Liquid Propulsion Test Facilities being established at Mahendragiri in Tamil Nadu. The Government's attention has, however, been drawn to an article in a magazine on the subject. The site at Mahendragiri in Tamil Nadu was selected taking into consideration the technical requirements and careful assessment of the environmental aspects.

(b) 1. Special care is being taken not to damage the forest ecosystem.

2. Only thorny bushes coming in the actual alignment of road or building and the bare

minimum number of trees considered necessary will be cut. Fresh saplings/ trees will be planted to improve the ecosystem. Wherever possible, mini-forest will be developed.

3. Elaborate inbuilt safety measures are planned in the facilities being set up to control atmospheric pollution.

4. During the testing of the liquid engine, which will be for a maximum of 200 seconds at any time, the atmospheric pollution and noise level will be below the allowable limit.

5. Steps are being taken to ensure that no pollution occurs to ground water and surface water.

6. Measures for the protection of the environment and safety measures to be taken have been prepared after detailed and in consultation with experts.

7. Necessary watch and ward staff will be engaged by the Tamil Nadu Government for proper protection of wild fauna and flora.

महिलाओं की जलने से मृत्यु

7174. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल कर मरने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) 1977 में उनकी संख्या कितनी थी और 1982 तक प्रतिवर्ष ऐसी मृत्यु की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर):

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने

के लिए उत्तरदायी हैं। इस निष्कर्ष के संबंध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि देशों में जलने से मरने वाली महिलाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है। देश में जलने से मरने वाली महिलाओं की संख्या के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जा रहे हैं, क्योंकि अपराध समेत विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है। परन्तु संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी मौतों की संख्या का एक विवरण अनुलग्नक में दिया है। ऐसे मामलों की तत्परता से और गहराई से जांच की जाती है और यदि किसी घोखाघडी का सन्देह होता है तो आपराधिक मामले दर्ज किये जाते हैं और जहां आवश्यक होता है कानून के अनुसार उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है। 22.7.1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों को व्यापक अनुदेश दिये गये थे कि पुलिस द्वारा युवा विवाहित महिलाओं के विवाह के प्रथम पांच वर्षों के दौरान हत्या के प्रयास अथवा उन की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों को गम्भीरता से लिया जाए। इस अवधि को 13.8.82 को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। ऐसे मामलों की जांच पड़ताल उपयुक्त पद के नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए और जहां शव परीक्षा की जाए वह दो डाक्टरों के दल द्वारा की जानी चाहिए। शव परीक्षा के बिना शव के निपटान की अनुमति, पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अलावा, नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, जब तक शव को माता पिता अथवा अभिभावकों अथवा परिवार के वधू पक्ष के निकट संबंधियों द्वारा न देख लिया जाए।

अनुलग्नक

संघ शासित क्षेत्र का नाम	1977 से 1982 तक की अवधि के दौरान जलने से मरने वाली महिलाओं की संख्या ।					
	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1. अण्डमान तथा निकोबार						
द्वीपसमूह	शून्य	2	1	1	1	5
2. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	2	शून्य	शून्य	3	शून्य
3. चण्डीगढ़	24	28	32	17	40	44
4. दादरा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. दिल्ली	311	327	424	408	535	610
6. गोवा, दमन तथा दीव	27	32	31	36	28	42
7. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9. पांडिचेरी	13	15	13	15	17	24

Loud Speakers Blaring in Mayur Vihar, Delhi

7175. SHRI ERA ANBARASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the residents of Pocket II, Mayur Vihar DDA flats across river Jamuna are the victims of constant blaring of loud speakers early in the morning from an unauthorised construction;

(b) whether the loud speakers have been fixed unauthorisedly on the top of a nearly DDA flats; and

(c) if so, what action has been taken by the police for the violation of loud speaker rules ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBIAH) : (a) to (c) A temple situated in Pocket No. II of Mayur Vihar DDA Flats had pitched, on top of a near by unoccupied Flat, a loud-speaker, which was being played in the morning as well as in the evening. The loud-speaker has been removed since 20.2.1983, and installed inside the temple. The temple authorities have applied for the issue of licence to use the loud speaker inside temple, in accordance with the Rules prescribed in this behalf.

Restriction on Acceptance of Hospital by Big Industrial Houses

7176. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether on the lines of the directive issued by the Finance Ministry to the Chairman and top executives of public sector Banks not to attend private dinners and receptions given by their clients, Govt. propose to issue such a directive to the other public dealing Ministries like Commerce, Industry, Petroleum, Chemicals, Finance and Works & Housing prohibiting their senior officers to accept such hospitalities from businessmen and liaison/ Public Relations Officers of Industrial Houses with whom they deal with as one of the measures to root out any chances of corruption prevailing in these Ministries ; and

(b) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBIAH) : (a) The Central Civil Services Conduct Rules and the corresponding rules for All India Services, Railway Services, etc. contain detailed instructions of the Govt. advising the Govt. servants not to

accept hospitality or invitations from the persons whose cases may be pending before them or from industrial or commercial firms and organisations having official dealing with them.

(b) Does not arise.

Government Reply to Letters Written by Public

7177. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

the details of the steps taken to ensure that due courtesy is extended to the public and letters written by the people are attended to and replied to within a reasonable time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : The Central Secretariat Manual of Office Procedure 8th edition provides, in paragraphs 45 and 46 thereof, that all communications recfrom the public should ebeived acknowledged promptly and that interim replies should be sent indicating wherever possible the approximate date by which a final reply may be expected. Separate instructions have also been issued that communications issued to the public should be politely worded. In addition various Departments, have issued instructions recently that due courtesy should be shown to the public.

"Incentives for Shifting Industries from Metropolitan Cities"

7178. SHRI S.A. DORAI SEBASTIAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of incentives being offered to industries for shifting their factories outside metropolitan cities;

(b) whether an air pollution cess is to be levied for the purpose of providing funds to air pollution boards in different States; and

(c) the steps that have been taken to stop pollution of national rivers in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINGH) : (a) To encourage industries to shift from urban cities and reducing pollution, the capital gains arising from transfer of buildings or lands bused for

the purposes of business is exempt from tax if it is used for acquiring lands or constructing buildings for the purposes of business at the new place. In the 1983-84 budget, this concession has been proposed to be extended to the transfer of machinery and plant also.

(b) No such proposal is under the consideration of the Government.

(c) Under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, the Central and State Boards for Prevention & Control of Pollution have been set up who are entrusted with the task of prevention and control of pollution. The Central and State Boards are conducting a regular stream quality monitoring of the major rivers. Special schemes have also been formulated for containing pollution from industrial and municipal sources. Legal action is being resorted to by the Boards against polluting industries the provisions of the Act.

Complaints Received by CBI and CVC

7179. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to lay a statement on the Table of the House indicating :

(a) the number of complaints received by C.B.I. and C.V.C. during the course of the last five years;

(b) how many of them have been disposed of and how many are still under investigation; and since when; and

(c) what are their details and by when they are likely to be disposed of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) All the 7678 complaints received by the C.V.C. during the last 5 years, (1978-82) have been disposed of.

Out of 45030 complaints received by the C.B.I. during the last 5 years 44741 complaints have been disposed of.

Out of the remaining 289 complaints, 2 are pending since 1980, 11 since 1981 and the rest (276) since 1982.

(c) It will not be in the public interest to disclose the details of the pending complaints.

Every effort is being made to dispose of all the pending complaints at the earliest.

First Ocean Expedition to Antarctica

7180. SHRI R. PRABHU : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have completed scientific studies associated with the First Ocean Expedition to Antarctica;

(b) if so, whether Government's findings have been disclosed to public; and

(c) whether there has been a universal acclaim to the success achieved by India in this regard in international scientific community.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) Reports on the scientific work done during the first Indian scientific expedition to Antarctica are expected to be published in the near future.

(b) and (c) Does not arise.

Central Machinery For Evaluation of Performance of State Sector Enterprises

7181. SHRI RASHEED MASOOD :

SHRI RAJESH KUMAR SINGH :

will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the existing number of the State-Sector enterprises functioning in various States;

(b) whether there is any Central machinery to evaluate their performance;

(c) if so, the details thereof stating when the performance of the State Sector enterprises was evaluated last and with what result; and

(d) if not, why Government do not consider it necessary to have a Central machinery for the assessment of the functioning of the State Sector enterprises ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) The information is not readily available.

(b) There is no Central machinery to evaluate the performance of State Sector enter-

prises: However, in the course of discussions on the State Plan and the monitoring of Plan implementation the functioning of some of the important State Enterprises like the State Electricity Boards and the State Transport undertakings is generally assessed.

(c) Does not arise.

(d) The Planning Commission recognises the need for the regular assessment of the functioning of the State sector enterprises. However, this is the responsibility of the State Governments who are directly concerned with these enterprises.

देश में सीमेंट का उत्पादन और उसकी मांग

7182. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है;

(ख) सीमेंट की कितनी मात्रा का पोर्टलैंड पोजोलाना आदि ब्रान्डों के नाम से ब्रांड बार उत्पादन हो रहा है; और

(ग) देश में सीमेंट की विभिन्न किस्मों की पृथक्-पृथक् मांग क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) 1982-83 में सीमेंट का देशी उत्पादन 230 लाख मी० टन से कुछ अधिक होने की आशा है।

(ख) वर्ष 1982 में तीन प्रमुख प्रकार के सीमेंटों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट	61.9 लाख मी० टन
पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट	34.5 लाख मी० टन
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट	128.2 लाख मी० टन

(ग) इन किस्मों के सीमेंट की अलग-अलग मांग के अनुसार नहीं लगाए गये हैं।

Official of Tihar Jail Confined by Prisoners

7183. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an official of the Tihar Jail in Delhi was confined by the Prisoners recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken to investigate the incident ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Import of Steel

7184. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantity of steel imported last year, give category-wise figures;

(b) whether the steel producers of the country had surplus saleable steel last year, give category-wise figures; and

(c) if so, the reason for import ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) Published data on total imports of steel during 1982-83 are not yet available. Imports by SAIL during 1982-83 (provisional) are given below :

Category	Qty. ('000 tonnes)
Slabs/Blooms	43.7
Spade Ingots	2.0
MS Bars & Rods	44.4
MS/HT Plates	214.9
BQ Plates	3.9
SBQ Plates	20.3
Structurals	682.4
HR Sheets/Coils	25.5
HR/CR Strips	2.2
CR Sheets/Coils	77.8
TMB. Plates	65.3
Tin Plate	16.7
Tin Plate Waste/Waste	0.3
Elec. Sheets	40.7
GP/GC Sheets	74.2
Stainless/Spl. Steel	0.8
Rails	2.1

Total : 1317.2

(b) and (c) The category-wise stocks of saleable steel (provisional) with SAIL Steel plants and home sales stockyards as on 31.3.1983 are given below :

Category	Qty. ('000 tonnes)
Billets/Square	231.7
Other Rerollables	79.0
Rounds (P)	90.6
Rounds (TS)	56.3
Wire Rods (P)	80.9
Wire Rods (TS)	8.3
Lights Structural	39.8
Medium Structural	56.6
Heavy Structural	45.5
Plates	200.2
HR Coils	160.8
Skelp	14.3
HR Sheets	71.3
CR Sheets/Coils	194.2
GP/GC Sheets	41.2
Elec. Sheets	1.0
Tin Plates	8.9
Pipe	12.8
Rly. Material	31.6
Others	2.5
Defectives	37.7

Total : 1465.2

Imports of steel by SAIL are made in those sizes and specifications that are not available in adequate quantity in the country.

Modernisation and Expansion of Cement Units

7185. SHRI JAGDISH TYTLER : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have received intimation from a majority of cement units giving ambitious investment plans for machinery modernisation and capacity expansion :

(b) if so, how many units as against the total units manufacturing cement in India have come forward with these plans ; and

(c) whether Government propose to remove the difficulties relating to the supply of power and coal and also of availability of funds under the soft loans scheme for these units ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) out of a total No. of 79 cement factories in

production at present, Cement Manufacturers Association have reported that so far 54 cement factories have drawn up programmes of machinery modernisation and/or expansion entailing a total investment of over Rs. 2,000 crores.

(c) Every effort is being made by Government to provide infrastructural inputs particularly power and coal, to the extent possible, to maximise production of cement in the country. Cement industries is one of the industries eligible for soft loan assistance from the Industrial Development Bank of India.

Deficit in the Fiscal Year 1982-83

7186. SHRI AJIT BAG : Will the Minister of PLANNING pleased to state :

(a) the volume of Central Government deficit in the fiscal year 1982-83 vis-a-vis the State deficit during the same period ; and

(b) the reaction of Planning Commission to the Central deficit ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) Against the original budgetary deficit of the Central Government of Rs. 1375 crores, the deficit is now estimated at Rs. 1935 crores (revised estimates). This excludes the special loan assistance to States of Rs. 1743 crores to clear their deficit as on 31st March, 1982, which did not have any impact in the year 1982-83. All the State Governments except six States, were expected to end the year without any deficit. In the case of these six States, the deficit was anticipated at about Rs. 85 crores. The actual deficit of the Centre and States for 1982-83 would be available after some time.

(b) The increase in the Central deficit is on account of certain unavoidable factors such as higher budgetary support needed for the Central Plan, larger transfer to States particularly for meeting the expenditure on relief from natural calamities, higher subsidy on indigenous fertilisers and increased defence expenditure, etc.

Employees Protest in the National Small Industries Corporation

7187. SHRI K.A. RAJAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the employees of the National Small Industries Corporation refused to

collect their salaries for December, 1982 in protest against the management's lack of response to their demands ;

(b) if so, the details there of ;

(c) whether the management has unilaterally reduced the house rent allowance paid to the employees ;

(d) if so, the details there of ; and

(e) whether the cut has been restored ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) According to National Small Industries Corporation some of the employees of the Corporation collected their salaries for the month of December, 1982 on 30th December, 1982, the due date for disbursement while others took their pay on 31st December, 1982.

(c) to (e) In order to keep in line with normal procedure, the Corporation reversed their decision to pay house rent allowance on maximum of the scale instead of on the basic pay.

Policy regarding taken-over sick units

7188. SHRI NIREN GHOSH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the policy regarding already taken-over sick industries and the details thereof :

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : The Policy Guidelines for sick industries announced by the Government in October, 1981 provide that, in respect of the industrial undertakings presently being managed under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, it will be decided if the undertakings are to be nationalised, or any other alternatives can provide a solution. If none of the alternatives are considered feasible, the Government may consider de-notification of the unit, in which event the Banks and Financial Institutions will deal with their outstanding dues to the undertaking in accordance with the normal banking procedures.

Allocation of Funds for Ocean Development

7189. SHRI K.A. SWAMI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) The funds allocated for Ocean Development for 1981-82, 1982-83 and 1983-84 ;

(b) the amounts spent in 1982-83 and the details of items of expenditure ; and

(c) the details of amounts spent on the various expeditions financed by Department of Ocean Development, if any ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) Funds allocated to Ocean Development are as under :

Year	Amount in thousands
(i) 1981-82	Rs. 8,38,76
(ii) 1982-83	Rs. 45,51,80
(iii) 1983-84	Rs. 32,26,75
(b) Amount spent in 1982-83 and the details of expenditure are as under :	
(Amount in thousands)	
(i) Salaries and Office Expenses	Rs. 19,42
(ii) Research Expedition to South Indian Ocean	Rs. 192,88
(iii) Acquisition of Oceanographic Research Vessel	Rs. 2006,39
(iv) Fishery and Oceanographic Research Vessel (FORV)	Rs. 1528,89
(v) Polymetallic Nodules	Rs. 463,00
(vi) Studies on Prevention of Coastal Erosion and Wave Energy	Rs. 10,00
(vii) Marine Research and Development	Rs. 6,85
	Rs. 42,27,43

(c) Amount spent in thousands of rupees

	1981-82	1982-83
Research Expedition to South Indian Ocean	1,90,30	1,92,88

Sale of Colour T.V. Sets at Stipulated Price.

7190. SHRI JAGPAL SINGH :
SHRI TRILOK CHANDRA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the T.V. manufacturers had given an undertaking to sell colour TVs with imported kit at a Government stipulated price ;

(b) if so, whether Government are aware that despite such an undertaking the manu-

facturers of colour TV sets are fleecing the customers by adopting various methods ; and

(c) if so, the measures taken by Government to ensure that the manufacturers of colour TV sets do not fleece the customers by adopting "back door" methods and the TV sets are sold at the stipulated price ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir. T.V. manufacturers who were allotted Colour TV kits imported by Electronics Trade and Technology Development Corporation (ETTDC) under the *ad hoc* one-time scheme

for the ASIAD, had agreed that the dealer will sell Colour T.V. sets so assembled in Delhi at a price (including all taxes) given below :

(i) CTV set with turret Tuner
: Rs. 7,500

(ii) CTV set with electronic Tuner.
: Rs. 8,000

In other cities, the prices could vary depending on the magnitude of local taxes such as sales tax, octroi, etc.

(b) and (c) The Government has not received any complaints about high prices. Government would take appropriate action if it finds that this agreement has been violated in any specific case.

Low per Capita Consumption of Steel

7191. SHRI MOOL CHAND DAGA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is today almost at the bottom of ladder with a low per capita consumption of steel i.e. only 14 kg. per annum and if so, the reasons for the same ;

(b) whether India's steel industry has been plagued with problems of low productivity, low capacity utilisation, poor industrial relations, uncertain management and other factors ;

(c) if so, what steps Government have taken to deal with the problems for the last three years ; and

(d) the outcome thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) In terms of crude steel equivalent, the per capita consumption of steel in India in 1982 was 18.7 Kg. It was low compared to the per capita consumption in economically advanced countries. This is an index of the development of steel using industries in a country.

(b) to (d) There has been improvement in the production performance and capacity utilisation of integrated steel plants during the last few years as can be seen from the following figures :

	1980-81	1981-82	1982-83
Production of saleable steel (million tonnes)	6.30	7.26	7.29
Capacity utilisation (percentage)	72.2	84.4	84

This improved production performance was the result of good industrial relations and sound management.

Unemployed Science and Technology Personal in the Country

7192. SHRI HANNAN MOLLAH, Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) the State-wise break up of the unemployed Science and Technology personnel for the last three years ; and

(b) steps, if any, taken to coordinate Science and Technology education and training with the requirement of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) Available information relating to Graduates including Post-graduates with Scientific and Technological qualifications on the Live Register of Employment Exchanges (all of whom are not necessarily unemployed) as at the end of December' 1980, 1981 and June 1982 is furnished in the Statement enclosed.

(b) Fresh Engineers are provided with a minimum period of one year of practical training/industrial experience in various training organisations under the Apprentices Act. The curriculum of the courses in Engineering colleges and Polytechnics are continuously reviewed and updated as per the Scheme of Curriculum Development by the Min. of Education. This review/up-dating takes cognizance of the national needs in the area of technical education and training at these levels of education. Under special programme of assistance, selected institutions all over the country are given 100% assistance in emerging areas of technology as also for modernisation of laboratories and workshops

Statement

Number of Graduates and Post Graduates in Selected Subjects (Science/Engg/Agri/Med/Vet. Sc.) on the Live Register of Employment Exchanges.

Sl. No. Name of the States

No. of Persons Registered (in thousands)
At the end of Dec. '80 At the end of Dec. '81. At the end of June, '82.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Andhra Pradesh	39.3	43.8	51.6
2.	Assam	4.9	5.9	6.2
3.	Bihar	58.1	62.8	60.6
4.	Gujarat	7.3	7.1	7.1
5.	Haryana	2.5	2.9	3.3
6.	Himachal Pradesh	1.3	1.2	1.6
7.	Jammu & Kashmir	2.2	2.3	2.4
8.	Karnataka	19.6	21.1	19.1
9.	Kerala	30.8	30.9	32.5
10.	Madhya Pradesh	22.1	25.2	25.1
11.	Maharashtra	19.5	21.2	21.7
12.	Manipur	1.6	1.9	2.0
13.	Meghalaya	0.1	0.1	0.1
14.	Nagaland	@	@	@
15.	Orissa	10.5	9.4	9.4
16.	Punjab	4.6	5.4	4.6
17.	Rajasthan	8.1	7.5	7.1
18.	Sikkim	*	*	*
19.	Tamil Nadu	40.0	45.3	43.4
20.	Tripura	0.4	0.4	0.4
21.	Uttar Pradesh	29.6	28.9	32.8
22.	West Bengal	63.4	73.7	72.2
UNION TERRITORIES				
1.	Andaman & Nicobar	0.2	0.2	0.1
2.	Arunchal Pradesh	*	*	*
3.	Chandigarh	1.6	1.8	1.8
4.	Dadra & Nagar Haveli	*	*	*
5.	Delhi	16.8	14.5	17.2
6.	Goa	0.6	0.3	0.6
7.	Lakshadeep	@	@	@
8.	Mizoram	@	@	@
9.	Pondicherry	1.2	1.6	1.6

Note :—1. *—No Employment Exchange is functioning

@ 2 ,—Figure less than 50.

निर्धारित योजना कार्यक्रम के अनुसार राज्यों द्वारा कार्य पूरा किया जाना

7193. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने योजना प्रावधानों में नियत राशि का उपयोग किया है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा किया है; और

(ख) ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने निर्धारित योजना के अनुसार काम पूरा नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :
(क) और (ख) राज्यों ने योजना प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग किया है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है :—

(करोड़ रु०)

अनुमोदित परिव्यय वषण

1980-81	7255.59	7340.60
1981-82	8223.86	8427.07

वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में राज्यों की उपलब्धियां वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 के वार्षिक योजना दस्तावेजों में बताई गई हैं जो संसद में पहले ही रखे जा चुके हैं।

पर्यावरण बटालियन

7194. श्री विरम राम फुलवारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेरिटोरियल आर्मी में कोई पर्यावरण बटालियन बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस बटालियन में कितने सैनिक कर्मचारी भर्ती किए जाने हैं तथा इसके लिए कुल कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ग) पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस बटालियन को कितने राज्यों में रखा जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। एक पारि-विकास कार्य बल की स्थापना की गई है।

(ख) पारि-विकास कार्य बल में 100 व्यक्तियों की दो कम्पनियां हैं तथा एक मुख्यालय है जिसमें 43 आदमी हैं। 1982-83 के दौरान इस कार्य बल के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 20.00 लाख रु० था।

(ग) और (घ) कार्य बल केवल उत्तर प्रदेश में मृदा संरक्षण तथा वनरोपण के साथ-साथ अनाच्छादित शिवालिक ढालुओं में संरक्षण कार्यों की संरचना के लिए नियुक्त की जाती है।

Obstacles raised by Italian firm on export of Scooters.

7195. SHRI SUSHIL BHATTACHARYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether India's interest is not hampered by Government's allowing two Indian companies to collaborate with an Italian firm which has stood in the way of our export expansion by putting obstacles in the sale of Indian scooters in other countries ; and

(b) if so, whether Government propose to take immediate steps to make the Italian firm stop its anti-export measures of Indian goods as a precondition for its continuance as a collaboration ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) It is presumed that the reference is to the agreements approved by the Government for technical collaboration with M/s. Piaggio Limited in respect of M/s Lohia Machines and Andhra Pradesh Scooters Limited. These approvals were granted having regard to the merits of the proposals vesting specific manufacturing and export rights with the Indian parties. There is a dispute between M/s. Bajaj Auto Limited, Pune and M/s. Piaggio of Italy which is of a commercial nature involving patent rights. This is now pending in the Court in a foreign country and it will not be appropriate for Government to intervene in the matter.

Power Implementation of Uranium Enrichment Programme

7196. **SHRI M.V. CHADRASHEKHARA MURTHY** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether experts reviewing the nuclear power programme have pleaded for India going in for uranium enrichment technology.

(b) if so, whether the views of the experts have been considered ; and

(c) what steps are being taken for proper implementation of the uranium enrichment programme, details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) and (b) Recently some sugges-

tions have been made to develop uranium enrichment technology as a part of the nuclear fuel cycle strategy. The nuclear fuel cycle strategy has been worked out keeping in mind the requirement of the nuclear power programme of the country and is under constant review.

(c) Laboratory scale studies are presently being carried out in the Bhabha Atomic Research Centre on various uranium enrichment processes.

Per capita income, savings, consumptions and expenditure

7197. **PROF. RUP CHAND PAL** : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the per capita income, savings, consumption and expenditure at 1970-71 prices in the fiscal years 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 till 31 December, 1982 ; and

(a) an analytical comparative narration for the decline amongst the items, if any ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) and (b) A statement is annexed showing the latest available estimates of per capita national income, private final consumption expenditure and net domestic capital formation at 1970-71 prices and net domestic saving at current prices during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 based on the Quick Estimates released by the Central Statistical Organisation in February, 1983. Estimates of savings are made at current prices only. It will be noted that there has been no decline during the period. Corresponding estimates for the year 1982-83 have not yet been compiled.

Statement

Statement showing the estimates of per capita national income, private final consumption expenditure and domestic capital formation at 1970-71 prices and net domestic savings at current prices.

Year	Per-capita national income at 1970-71 prices.	Per capita Private consumption expenditure at 1970-71 prices	Per capita net domestic capital formation at 1970-71 prices	Per capita net domestic saving at current prices
1979-80 (P)	662.5	554.6	116.7	263.2
1980-81 (P)	700.4	586.4	127.1	295.5
1981-82 (Q)	719.9	591.7	134.0	347.5
Note : (P) Provisional Estimates (Q) Quick Estimates				

Maintenance of 40 point rosters

7198. **SHRI ARVIND NETAM** : Will the Minister of **INDUSTRY** be pleased to state :

(a) whether the 40-point rosters are not properly maintained by the Ministry and its attached offices;

(b) whether it is also a fact that these are not allowed to be seen by the Scheduled Castes/Scheduled Tribes officers and signed by Scheduled Castes Scheduled Tribes Liaison officer as required according to the rules; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The rosters are being maintained in accordance with the relevant instructions.

(b) As per Ministry of Home Affairs (Department of Personnel & Administrative Reforms), there are not instructions requiring the Rosters to be seen by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers. However, the officer designated as the Liaison Officer in respect of matters relating to representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, is required to certify the entries made in the rosters annually, as part of his normal duties.

(c) Does not arise.

Nepalese and Bhutane Refugees in Sikkim

7199. **SHRI PIYUSH TIPKI** : Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) whether a large number of Nepalese refugees in Sikkim are going to be granted Indian citizenship in the near future;

(b) if so, the total number of Nepalese and Bhutanese refugees presently residing in Sikkim;

(c) whether Government think of transferring some of the refugees to other parts of the country;

(d) if so, by what time and if not the reasons thereof;

(e) whether it is also a fact that the original inhabitant tribals of Sikkim have threatened to launch Assam-type movement on the refugee issue; and

(f) if so, what steps are being contemplated by the Government considering the grievances of the Sikkim tribals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (d) An order was issued on 16th May, 1975 under Section 7 of the Citizenship Act, 1955 providing that every person who immediately before 26th April 1975 (date when Sikkim became the 22nd State of the Indian Union) was a Sikkim subject under the Sikkim subjects Regulation, 1961 would be deemed to have become a citizen of India. Those who were not registered under the aforesaid Regulation of 1961 or were not eligible to be so registered are among the persons who may be regarded as stateless, unless they have a claim to any other nationality. The State Govt. has not estimated the number of such stateless persons officially. They expect that there may be about thirty thousand such persons.

The State Government had appointed a Committee under the Chairmanship of the Deputy Speaker of the Sikkim Assembly to consider the nationality issue. Its report has since been received and is under consideration.

(e) No.

(f) Every care is taken to protect the interests of Scheduled Tribes in Sikkim. 13 seats are reserved for them in Assembly. Seats are also reserved in services. In matters of development the economic interest of the tribals are kept uppermost in mind.

Report of the Official Language Committee on the Use of Hindi Abroad.

7200. **SHRI BRIJ MOHAN MOHANTY** : Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reports or comments from the Official Language Committee that visited different foreign establishments to check up the work of introduction of Hindi language and adoption and projection of Hindi outside India; and

if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) No.

(b) Does not arise.

Adoption of villages by industrial houses

7201. SHRI PIYUSH TIRKI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total number of Industrial Houses in the private sector who are spending sizeable amount on rural development and adoption of villages;

(b) volume of work these houses have accomplished in West Bengal, Bihar, Orissa and Maharashtra; and

(c) the details of the amount spent and number of persons who got gainful employment out of these rural development projects taken up by the industrial houses ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) Under Section 35 CC of the Income Tax Act, 1961, companies and cooperative societies are allowed to deduct from their taxable profits any expenditure incurred by them on any programme of rural development approved by the prescribed authority. Under Section 35 CCA of the Income Tax Act, deduction is allowed for expenditure by way of the payment on any sum to approved associations and institutions for use in carrying out programme of rural development approved by the prescribed authority which at present is a State Level Committee consisting of the notified Commissioner of Income Tax who exercises jurisdiction over the State/Union Territory in which the programme of rural development is to be carried out as the Chairman and an officer of the rank of Secretary to State Government as a Member. The statistics in regard to concessions granted in individual cases are not available at the Ministry level.

Report of all India Evaluation Study for the Rural Electrification Schemes

7202. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of PLANNING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1660 on 3 March, 1982 and state :

(a) whether Volume-I covering "Organisation, Growth and Coverage" has since been released;

(b) if so, the broad outlines of the Report alongwith the date on which the Report was released; and

(c) the likely dates by which the other volumes of Evolution Report would be released in case they have not been released so far and the main findings of the successive volumes in case they have been released alongwith the dates of release of each volume ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Volume I of the Report was released on 30-4-1982. The broad outlines of the Report are indicated in the enclosed statement.

(c) Volume II of the Report is under finalisation and is likely to be released shortly.

Statement

The Programme Evaluation Organisation conducted an evaluation study of the Rural Electrification Programme in 1979. The study was launched in the field in 19 States and covered 397 electrified villages besides 79 non-electrified villages. This study was planned with the objective of covering spread and coverage, integrated development, and assessment of the impact of rural electrification on agriculture, industry, socio-cultural life etc. The report is being brought out in two volumes. Volume I of the report gives— (i) Background information about the programme and administrative and organisational problems in the implementation of rural electrification programme ; (ii) Evaluation of policy formulation and implementation and spread and growth of rural electrification ; (iii) Coordination among various agencies for rural development ; (iv) Power shortage and its effect on the working of pumpsets ; and (v) Growth of rural industries.

The important findings contained in Volume I were as under :

(i) The State Electricity Boards were suffering from organisational inadequacies. Measures suggested by various expert committees for acceleration of rural electrification had not been implemented in all the States.

(ii) The States, particularly the North-Eastern States and States having hilly areas, faced another problem viz.,

trained, experienced and qualified engineers were not coming forward to work in remote areas and difficult terrains.

- (iii) Acute shortage of construction materials like conductors, RCC poles, transformers etc. was reported to have considerably impeded the construction works in most of the States. Also divisions and sub-divisions of the Electricity Boards in almost all the States were reported to be ill-equipped with transport facilities for timely transportation of materials from stores to divisional headquarters, sites etc. This resulted in delay in completion of works.
- (iv) A suitable system for collection of service-wise data on number of consumers, consumption and load separately for urban and rural sectors which is essentially required for planning and estimating financial return was not evolved in any State.
- (v) While Coordination Committees at State and District levels were constituted in a number of States, very little or no effort was made by these Committees to ensure advance planning for integrated rural development by synchronising the developmental activities of all the concerned departments, so that adequate demand for load development is generated.
- (vi) In terms of policy directive from the Central Government, preferential terms of assistance were introduced by the Rural Electrification Corporation in the year 1970-71 in respect of Rural Electrification schemes in the backward areas. A special programme of electrification of Harijan bastis adjoining electrified villages was also taken up.
- (vii) While concessional tariff for agriculture was available in almost all the States, concessions for non-agricultural power was reported from a few States only.
- (viii) From a meagre figure of 21,000 energised pumpsets existing in 1951, the number of energised pumpsets rose

to 39.5 lakhs in 1980 giving on an average an yearly addition of about 1.1/2 lakh pumpsets.

Procedure RE: Transfer and Promotion of class. IV Employees in C.I.S.F.

7203. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have any definite procedure for the transfer and promotion of Class IV employees working in C.I.S.F in a State to which they do not originally belong so as to mitigate their hardship;

(b) if so, the main outlines thereof and the normal tenure after which the employees are granted the request for transfer to their home/neighbouring States ; and

(c) if not, whether such a procedure would be drawn up in the near future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) Postings and transfers in the C.I.S.F are made in public interest for administrative and operational reasons. Compassionate grounds are given due and adequate consideration. Position regarding promotions is that there are no channels of promotion in their line for Class IV i.e. Group 'D' personnel in the Force. However, they are eligible for consideration, if otherwise qualified, for appointment in the rank of security Guards in Group 'C'.

Setting up of Advisory Committee for Development of Himalayan Regions

7204. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Advisory Committee set up by the Planning Commission for securing the development of the Himalayan Region on systematic and scientific lines has held any meeting and prepared any programme or blueprint for the development of the Himalayan Region ;

(b) if so, the main outlines of the plan and the date (s) on which the Committee held any meeting (s) ; and

(c) if not, the likely date which the Committee would start functioning ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) and (b) An Advisory Committee for securing the development of the Himalayan Region on systematic and scientific lines has been constituted under Chairmanship of Member, Planning Commission. The Committee advises on matters relating to planning for socio and economic development of the Himalayan Region keeping in view (a) the Sub-regional endowments and the diverse agro-ecological features as well as socio-cultural ethos and (b) the threat to the eco-system and the urgency to restore and conserve it. The Committee at its first meeting held on 24th February, 1983 discussed the general problems of the region and it was agreed to focus special attention on programmes relating to bridge paths and foot bridges ; drinking water, fuel and fodder, education, energy efficiency and micro hydel units.

(c) Does not arise.

Issue of Licences for Manufacturing of Colour T.V. sets.

7205. SHRI CHINTAMANI JENA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the names of the Indian firms in public sector and in private sector which have been issued licences for manufacturing or assembling colour T.V. sets;

(b) the number of colour T.V. sets, likely, to be manufactured in India yearly ;

(c) whether it is a fact that the T.V. components are to be imported, if so, the value involved annually ; and

(d) what measures are being taken to manufacture these components in India to save foreign exchange ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) So far, no firms either in public sector or in private sector have been issued licences for manufacture of Colour T.V. Sets. However, some firms both in public sector and private sector were allowed to assemble CTV sets as a one-time *ad-hoc* policy for the 'ASIAD' 82 period only. The

names of these firms are given in *Annexures-I and II* respectively laid on the table of the House [Placed in library, See. No. LT-6375/83]

(b) and (c) As no regular manufacturing licence have been given so far, no meaningful estimates can be given.

(d) A number of units are already manufacturing general purpose passive and active components and are capable of manufacturing such components meeting the technical requirements of Colour T. V. sets. The major imported element would be the colour TV picture tube for which one unit has already been issued a Letter of Intent. Indigenisation of other components specific to Colour TV sets e.g. particular types of integrated circuits, will be taken up as the production of CTV sets picks up.

Companies set up with foreign collaboration

7206 SHRI CHINTAMANI JENA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total number of companies set up in the country with foreign collaboration as on 31st December, 1982 and the name of the countries with whom they have collaborated :

(b) whether any other company has applied for establishing their concern in India during the year 1982, if so, the name of these concerns and the names of the countries to which they belong ;

(c) the action taken by Government in this regard ;

(d) whether any multinational company has applied for the expansion of their trade or establishing new units in India ; and

(e) if so, the name of the concerns and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (e) No centralised information is available about the number of foreign collaborations which have fructified till the end of 1982. During the last three years (i.e., 1980-1982) Government approved 1505 foreign collaboration proposals out of which 243 proposals involved financial participation by foreign companies.

Lists giving details of foreign collaboration proposals approved by Government are issued on a quarterly basis by Indian Investment

Centre as a supplement on the Monthly News Letter. Copies of this publication are sent regularly to the Parliament Library.

No fresh trading activity is allowed to be under-taken in India by any foreign incorporated multinational company. However, Indian Subsidiaries of Foreign Companies have been granted 7 Letters of Intent in 1982 to set up new industrial undertakings.

इस्पात और खान मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और जन- जातियों का प्रतिनिधित्व

7207. श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों का कोटा पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन अधि-कारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का है जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी जान-बूझ कर उनकी नियुक्तियां नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) और (ख) इस्पात और खान मन्त्रालय के दो विभागों में 31.3.83 की स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ग) और (घ) आरक्षित पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरने के लिए हर-सम्भव प्रयास किये जाते हैं। इन पदों को भरने के बारे में जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। इनमें भर्ती के लिए मांग-पत्र भेजते समय आरक्षित पदों का विशेष रूप से उल्लेख करना और जो पद खाली रह जाते हैं उन्हें आगे ले जाना शामिल है।

(ङ) इस प्रकार का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इस्पात विभाग (सचिवालय)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
ए	35	1	-	2.85	-	-
बी	78	1	1	1.28	1.28	-
सी	136	20	-	14.70	-	-
डी	71	29	10	40.84	14.08	-

खान विभाग (सचिवालय)

ए	23	4	-	17.39	-
बी	67	2	1	2.98	1.49
सी	75	8	-	10.67	-
डी	38	11	2	28.99	5.27

Transfer of Assam Refugees to Other States

7208. SHRI PIYUSH TIRKI. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) total number of refugees from Assam who have taken refuge in Jalpaiguri district of West Bengal ;

(b) measures taken by the Union and State Governments for their rehabilitation ;

(c) by what time they will be sent back to their home State Assam and steps taken in this regard ; and

(d) whether Government are considering to transfer some of the refugees to other state's like Bihar, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b) According to the Government of West Bengal, 24963 persons from Assam came to Alipurduar Rly junction of Jalpaiguri District in West Bengal till 28.3.83 as a result of recent disturbances. Out of them about 22,000 are reported to have taken shelter in two camps at Dangi and Buritursha and the remaining still camping at the railway station are being transferred shortly to the relief camps. Central Government have agreed to provide financial assistance in respect of expenditure incurred by the West Bengal Government for running these relief camps initially for a period of one month to begin with.

(c) and (d) The Assam Govt. have been requested to take necessary steps to facilitate their early return to Assam. Two Ministers of the State Govt and senior officers of Govt. of Assam has also visited the camps in order to persuade the refugees to return to Assam.

सहरसा जिला (बिहार) के गांव के विकास के लिये ब्रेड फार दी वर्ल्ड, वेस्ट जर्मनी द्वारा दिया गया अनुदान

7209. प्रो० अजित कुमार मेहता: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सहरसा जिला (बिहार) के गांव (तेगड़ा) का सर्वोन्मुखी विकास करने तथा 20 ग्रामदानी गांवों के अग्रिम कार्यवाही कार्यक्रम के लिये ब्रेड फार दी वर्ल्ड, वेस्ट जर्मनी नामक एक विदेशी स्वैच्छापूर्वक दान देने वाले संगठन से 1978-79 में सोसाइटी फार डेवेलपिंग ग्रामरान्स, बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर (डाकघर), जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश को 2,53,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या उक्त समिति ने उपरोक्त अनुदान की राशि में उपयोग सम्बन्धी प्राक्कलन को स्वीकृत कर दिया है;

(ग) क्या उपरोक्त राशि उपरोक्त संगठन द्वारा सीधी व्यय की जानी थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या वह राशि उपरोक्त प्राक्कलन के अनुसार व्यय की गई और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि वह राशि कहाँ और किस प्रकार व्यय की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) कोशी सेवा सदन, महिषी, जिला सहरसा द्वारा संचालित बिहार के सहरसा जिले में (तेगड़ा गांव) समेत 20 गांवों में विकास कार्यक्रम के लिए ब्रेड फार दी वर्ल्ड वेस्ट जर्मनी द्वारा 1978 में 2,53,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। सोसाइटी फार

डेवलपिंग ग्रामदान्स ने सूचित किया है कि उन्हें 1978 और 1979 के दौरान उपयुक्त अनुदान में से क्रमशः 79, 980/- रु० तथा 80,000/- रु० की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं।

(ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जैसा कि सोसायटी फार डेवलपिंग ग्रामदान्स द्वारा सूचित किया गया है, अनुदान का उपयोग कोशी सेवा सदन, महिषी, जिला सहरसा के माध्यम से किया जाना था।

(घ) कोशी सेवा सदन द्वारा संचालित सहरसा जिले में 20 ग्रामदान गांवों में नियोजित कार्यबाई कार्यक्रम के संबंध में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित 31.22.81 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 89,689/- रुपए की राशि व्यय नहीं हुई।

Centrally Sponsored Scheme for Welfare of Bhuyian Community

7210. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :—

(a) whether any centrally sponsored scheme has been introduced for the welfare of the Bhuyian Community;

(b) if so, the names of the States where welfare schemes have been introduced for the Bhuyian Community;

(c) whether such scheme has been introduced in Orissa; and

(d) if so, since when and what are the welfare measures taken so far in Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) For the Welfare of Paudi Bhuyans two MICRO Projects were started during 1978-79 in Sundargarh and Dhenkanal Districts of Orissa with the help of Special Central Assistance. Development Programmes

like agriculture, horticulture, animal husbandry land reclamation, irrigation, communications and education are implemented through these projects.

Central Assistance for Welfare Schemes [for Tribals in Orissa]

2711. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :—

(a) whether Government have made any assessment regarding the progress so far made in relation to the various schemes launched for the welfare of tribal area in the State of Orissa; and

(b) if so, what is the number of institutions to which Government have given assistance during the year 1981-82 under the Modified Area Development Approach to tribal sub-plan launched recently and the number of persons who have been benefitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) 30 pockets of tribal concentration have been identified for assistance through 32 development blocks under the Modified Area Development Approach to tribal sub-plan. 1446 tribal families have directly benefitted under the individual benefit scheme under the programme in 1981-82.

Distribution of new Industrial units

7212. SHRI N.E. HORO : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the State-wise distribution of new industrial units licensed by Government during the last two years;

(b) the reasons for their concentration in some parts of the country leading to regional imbalance; and

(c) the steps Government propose or have taken to stop further aggravation of this imbalance?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) A statement is enclosed.

(b) and (c) Concentration of industries, in the past, in certain areas has been inter alia due to ready availability of infrastructural

facilities like power, water, transport, skilled manpower; raw materials etc. In view of the Industrial Policy Statement of 1980 Government has asserted a locational policy to disperse Industries to Backward Areas and No-Industry Districts. Government is constantly trying to correct any regional imbalance through its licensing policy and the situation has improved considerably.

Statement

State	Number
1. Andhra Pradesh	24
2. Andaman & Nicobar	—
3. Arunachal Pradesh	—
4. Assam	2
5. Bihar	8
6. Chandigarh	1
7. Dadra & Nagar Haveli	—
8. Delhi	—
9. Goa, Daman & Diu	5
10. Gujarat	43
11. Himachal Pradesh	5
12. Haryana	10
13. Jammu & Kashmir	3
14. Karnataka	15
15. Kerala	7
16. L.M. & A. Islands	—
17. Madhya Pradesh	10
18. Maharashtra	32
19. Manipur	1
20. Meghalaya	—
21. Mizoram	—
22. Nagaland	—
23. Orissa	10
24. Pondicherry	1
25. Punjab	16
26. Rajasthan	18
27. Tamil Nadu	22
28. Tripura	—
29. Uttar Pradesh	18
30. West Bengal	14
31. Sikkim	—
32. State not indicated/More than one State	1
TOTAL :	266

प्रशिक्षण केन्द्रों में कोर्सों में हिन्दी

माध्यम का विकल्प

7213. श्री रामावतार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग तथा मंत्रालय/विभाग से सम्बंध तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में इस समय कुल कितने और कौन-कौन से शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इन कार्यालयों में कुल कितने प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं;

(ग) उपर्युक्त कितने प्रशिक्षण कोर्सों में हिन्दी माध्यम का विकल्प किया गया है; और

(घ) क्या इन प्रशिक्षण कोर्सों की परीक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है, यदि नहीं, तो ऐसा विकल्प कब तक दिए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के अधीन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे अधिकांश पाठ्यक्रमों में सामान्यतः परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों में परीक्षाओं के लिए हिन्दी माध्यम के विकल्प की अनुमति दी गई है। जहाँ तक राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का संबंध है, हिन्दी के प्रयोग को प्रावस्थाबद्ध रूप में अपनाया जा रहा है।

विवरण

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	संख्या	चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या जिनमें हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है
एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेड़ी	1	13	10
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम			
आद्यरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली हावड़ा, राजकोट और मद्रास	4	5	5
विकास आयुक्त (लघु उद्योग)			
लघु उद्योग सेवा संस्थान	26	762	762
शाखा लघु उद्योग	20		
सेवा संस्थान			
लघु उद्योग सेवा	41		
संस्थान विस्तार केन्द्र			
फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र	2		
उत्पादन केन्द्र	5		
परीक्षण केन्द्र	4		
ओजार कक्ष	2		
उत्पादन और प्रक्रिया विकास	1		
दस्ती ओजार संस्थान			
	107	780	777

**राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत
अधिसूचित कार्यालय**

7214. श्री रामावतार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय/विभाग राजभाषा नियम, 1976 की धारा 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) अब तक उनके मंत्रालय/विभाग के कौन-कौन से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय उपयुक्त धारा के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और किन तारीखों से अधिसूचित किए गए हैं;

(ग) उपयुक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने कार्यालय अब तक उपयुक्त नियम की धारा 8 (4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किए जा

चुके हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8 (1) में समाविष्ट उपबन्धों और सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नियमों के नियम 8 (4) के अन्तर्गत अभी तक इनमें से किसी भी कार्यालय को विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं हो सका है।

विवरण

मन्त्रालय के निम्नलिखित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

	कार्यालय का नाम	अधिसूचना की तारीख
1.	सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली	24.1.1979
2.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, नागपुर	24.1.1979
3.	नमक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली	24.1.1979]
4.	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, नई दिल्ली	28.9.1979
5.	तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली	17.7.1980
6.	विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली	17.7.1980
7.	औद्योगिक आकस्मिकता का कार्यालय, नई दिल्ली	17.7.1980

Criteria for Allocating Funds to States for Plan For SCs/STs.

7215. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the criteria followed by Government while allocating funds to various States, particularly for the plans for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : The Special Component plans and the Tribal Sub-plans form part of the State plans.

The Government of India give Special Central Assistance to the Special Component Plans and Tribal Sub-Plans on the following criteria :—

Special Central Assistance to the Special Component Plans for Scheduled Castes

40% of the Special Central Assistance is allocated among States on the basis of the Scheduled Caste population; 10% on the basis of relative backwardness; 25% on the basis of the coverage of Scheduled Caste families for enabling them to cross the poverty line; 10% on the basis of the size of the Special Component Plan outlay; 10% on the basis of programmes for Specially Vulnerable Groups among the Scheduled Castes; and 5% on the basis of performance in implementing the Special Component Plans.

Special Central Assistance for Tribal Sub Plans

The criteria followed in allocation of Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan to various State are :—

(a) Fifty per cent on the basis of Scheduled Tribes population in the Tribal Sub-Plans areas.

(b) Thirty per cent on the basis of geographical area of the tribal Sub-Plans; and

(c) Twenty per cent on the basis of inverse ratio of net State domestic product with weightage to tribal population in the Tribal Sub-Plan area.

Establishment of Newsprint Factory in the Country

7216. SHRI NAVIN RAVANI : Will the

Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of applications pending with the Government for clearance for establishing newsprint factories in the country;

(b) steps Government have taken to clear them to manufacture more newsprint to meet the demand of the country;

(c) whether there is any proposal to set up a newsprint factory in public sector in near future; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Three applications for grant of Licences under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for setting up units for manufacture of newsprint and other varieties of paper, received during the year 1983, are awaiting final disposal.

(b) The existing procedures already provide for expeditious disposal of such applications.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिक श्रेणी परीक्षा हिन्दी में आयोजित किया जाना

7217. श्री जेनुल बशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिक श्रेणी परीक्षा के अन्तर्गत दिए गए विकल्प के अधीन हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों को कि केन्द्रीय सरकार तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त हैं, अंग्रेजी में कार्य करने या अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन आधारों पर बाध्य किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार तथा आयोग द्वारा

उक्त विकल्प के विपरीत उन्हें बाध्य करने वाले आज तक जारी किए सभी आदेशों की एक एक प्रति सरकार द्वारा सभा पटल पर रखी जायेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) से (ग) हिन्दी टंकण के साथ लिपिक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे या तो अंग्रेजी में टाइप-कार्य करें अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करें। तथापि, केवल हिन्दी टंकण अथवा अंग्रेजी टंकण में अर्हताप्राप्त, लिपिक ग्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तथा मन्त्रालयों/विभागों में नियुक्त किए जाने वाले लिपिकों को अंग्रेजी/हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशासनिक सुविधानुसार उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

Manufacturing of Video Cassette Tape Recorders by Keltron

7218. SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of approvals/letters of intent issued for the manufacture of Video Cassette Tape recorders in the country during 1980, 1981 and 1982;

(b) whether there was any application from Keltron in 1975 for the manufacture of Video Cassette Tape recorders and if so the reasons for its rejection;

(c) whether Government issued 30 licences for the manufacture of the same in 1982;

(d) whether the Keltron had applied for issue of licence to manufacture the same during 1982;

(e) whether its application was rejected; and

(f) if so, the reasons for rejecting it ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) The number of parties approved during the year 1980, 1981 and 1982 for the manufacture of Video Cassette Recorders (VCR) in the large and small scale sectors is given below :—

	1980	1981	1982
(1) Organised Sector	Nil	6	5
(2) Small Scale Sector	20	18	22

(b) M/s KELTRON had applied for an Industrial Licence for the manufacture of Video Tape Recorders in 1975. The application was rejected at that time because the application involved a very heavy import of components and the company had not done any development work in this field.

(c) No, Sir.

(d) to (f) M/s KELTRON did apply for an Industrial Licence in June, 1982. Their application was deferred and not rejected. The deferralment was done because the policy regarding the licensing of units for VCR manufacture was under the consideration of Government and all applications received after January, 1982 were being kept pending.

राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां

7220. श्री वृद्धि चंद्र जैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां और प्राप्त किये गये लक्ष्यों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) उपयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी हटाने में किस सीमा तक सफलता मिली है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्यों की तुलना में फरवरी, 1983 तक राजस्थान में 20

सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में 20-सूत्री कार्य-

क्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 2,15,746 है जिसे नीचे दिखाया गया है:—

	(इकाइयों की संख्या)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
	1982-83	अप्रैल, 82—फरवरी, 83
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए	22,000	24,915
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए	52,500	57,468
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,41,000	1,33,363

विवरण

राजस्थान

सूत्र/श्रेणी	इकाई	लक्ष्य	अप्रैल 1982 से फरवरी, 83 तक उपलब्धियां	उपलब्धियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5

श्रेणी-क

मकान बनाने के लिए स्थान	संख्या	50000	105766	211.5
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रहने के लिए मकान	संख्या	7099	10955	154.3
गंदी बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	31500	44761	142.1

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम श्रम दिवस	(हजार संख्या)	3120	4283	137.3
पेय जल	(गांवों की संख्या)	2700	3433	127.1
अनुसूचित जनजातियों के परिवार	संख्या	22000	24915	113.3
अनुसूचित जातियों के परिवार	संख्या	52500	57468	109.5
बेशी भूमि	(हजार एकड़)	10.0	10.38	103.8
लगाए गए पेड़	(हजार संख्या)	40000	41527	103.8
उप-केन्द्र	संख्या	250	250	100.0
एकीकृत सामुदायिक विकास स्कीम खण्ड	संख्या	13	13	100.0
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-परिवार	संख्या	141000	133365	94.5
पंप सैट	संख्या	110000	8397	84.0
श्रेणी-ग				
नसबंदी	संख्या	215000	133136	61.9
बंधुआ मजदूर	संख्या	200	114	57.0]
विजली लगाए गए गांव	संख्या	1000	501	50.1
प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	6	2	33.3]
बायो गैस संयंत्र	संख्या	5000	1436	28.7
निर्माण सहायता	संख्या	30000	6408	21.4
खोली गई उचित दर की दुकानें	संख्या	2000	1479	74.0
ग्राम और लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	26900	32906	122.3

श्रेणी क : निष्पादन-लक्ष्य का 80 प्रतिशत या अधिक

श्रेणी ख : राष्ट्रीय औसत से अधिक निष्पादन

श्रेणी ग : राष्ट्रीय औसत से कम निष्पादन

Allotment of cement to Gujarat State

7221. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat State Government has requested the Central Government to allot one lakh MT of cement as an additional quota for cyclone relief works;

(b) if so, how much quantity of cement has been allotted to the State so far for the purpose; and

(c) Whether this quantity represents the full demand made by the State Government; if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) 40,000 (Forty thousand) tonnes of levy cement has been allotted/released to the State Government of Gujarat for cyclone relief works during the period of October, 1982 to March, 1983.

(c) Due to shortfall in domestic production of cement because of sustained power cut of varying degree in the major cement producing States during the year 1982-83, it has not yet been possible to meet the entire additional requirement of cement.

Suspension of Government Employees

7222. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Government employees working in his Ministry and its attached and subordinate offices who are under suspension as on date and what are the reasons of their suspension;

(b) what safeguards are available to a suspended employee if he is neither informed of the reasons of suspension nor a charge sheet is served on him; and

(c) the circumstances under which an employee can be suspended under the clause 'disciplinary proceedings are contemplated'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI

NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) 368 Government employees are under suspension as on 1.3.1983. The reasons for their suspension broadly are alleged mis-appropriation/embezzlement of Government money, insubordination, theft, serious negligence/irregularities, misconduct and moral turpitude; and criminal proceedings.

(b) A suspended Government employee has right of appeal against the order of suspension under Rule 23 (i) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

A suspension order would generally contain the reasons for suspension of a Government employee. Where, however, a Government servant is placed under suspension on the ground of 'Contemplated' disciplinary proceedings, the existing instructions provide that every effort would be made to finalise the charges, against the Govt. servant within three months of the date of suspension. If in some cases it is not possible for one reason or the other to issue a charge sheet within this period; the reasons for suspension are required to be communicated to the Government servant concerned immediately on the expiry of the aforesaid time-limit prescribed for the issue of a chargesheet, so that he may be in a position to effectively exercise the right of appeal available to him.

(c) Public interest is the guiding factor to place a Government servant under suspension. A Disciplinary Authority may consider it appropriate to place a Government servant under suspension under the following circumstances:

(i) Cases where continuance in office of the Government servant will prejudice the investigation, trial or any inquiry (e.g., apprehended tampering with witnesses or documents ;

(ii) Where the continuance in office of the Government servant is likely to seriously subvert discipline in the office in which the public servant is working;

(iii) Where the continuance in office of the Government servant will be against the wider public interest e.g., if there is a public scandal and it is necessary to place the

Government servant under suspension to demonstrate the policy of the Government to deal strictly with officers involved in such scandals, particularly corruption;

(iv) Where allegations have been made against the Government servant and the preliminary inquiry has revealed that a prima facie case is made out which would justify the prosecution or his being proceeded against in departmental proceedings, and where the proceedings are likely to end in his conviction and/or dismissal, removal or compulsory retirement from service, and

(v) Where the public servant is suspected to have engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State.

Planning Units for Development of Tribal Areas

7223. SHRI JAI NARAYAN ROAT : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the extent to which the tribal areas have been developed in the country;

(b) whether Government propose to set up planning units at the district level/division level for the development of tribal areas and rural areas; and

(c) if so, the details thereof and if not, what steps Government would take so that the tribal areas are developed in accordance with the target fixed in the Sixth plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Though data from all States are not forthcoming, as per available information, irrigated area increased to 6,69,993 hectares in six states, area under soil conservation increased to 1,92,264 hectares in six States, area under horticulture increased to 1,15,604 hectares in six States, forest plantation increased to 1,94,179 hectares in six States, 88,811 hectares alienated land were restored to tribals in six States, 9,147 villages were provided with water supply in six States, and 7,816 villages were electrified in seven States. However, the States mentioned in the foregoing are not the same in all cases.

(b) The unit of planning and implementation of tribal sub Plan areas is the integrated tribal development project (ITDP) which functions at district or below level. In the tribal sub-plan areas, 181 ITDPs have been functioning.

(c) The project reports for I.T.D.Ps. are expected to be prepared by the project Administrators having regard to the natural resources, local needs and targets set forth.

Proposal to Repeal Section 5 of Official Secrets Acts

7224. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) whether Government have under consideration any proposal to repeal the Sec 5 of the Official Secrets Act; and

(b) if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) The Second Press Commission has made certain recommendations on this subject. Those are being examined.

Formation of Chief Ministers Council on Centre-State Relations

7225. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is fact that at a meeting of the Chief Ministers of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry held on 20 March, 1983 a Chief Ministers' Council has been formed;

(b) if so, whether the meeting has suggested to the Centre the setting up of a fiscal commission with adequate State representation and statutory powers to review State-Centre relations over fiscal matters and recommend amendments to the Constitution and other enactments in the interest of a more equitable distribution of resources of the State; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI

NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) According to information received from the Government of Karnataka, the Chief Ministers of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondichery in a meeting held on 20.3.1983 agreed to form a Council of the Chief Ministers of Southern States to discuss matters of common interest from time to time. The Chief Ministers decided to recommend to the Government of India the setting up of a fiscal commission to review the Centre-State relations in fiscal matters.

Government of India have recently announced the setting up of a commission to review the existing arrangements between the Centre and the States.

Setting up of Bagasse Based Newsprint Projects

7226. **PROF. P.J. KURIEN** :
SHRI HARIHAR SOREN :
SHRI LAKSHMAN MALLICK :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government intends to set up bagasse based newsprint projects in the country;

(b) whether any detailed plan has been formulated;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether there is any proposal to set up such a factory in Kerala;

(e) The names of States where sites for bagasse-based newsprint projects have been selected; and

(f) the estimated cost of each of those projects ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) The Hindustan Paper Corporation have prepared pre-feasibility reports for bagasse-based newsprint/paper projects in the States of Bihar and Uttar Pradesh. Detailed Project Reports giving complete details of the estimated cost, exact location, etc. are yet to be prepared.

(d) No, Sir,

(e) and (f) An Industrial Licence has been granted for establishment of a bagasse-based paper unit in the State of Tamil Nadu at an estimated cost of Rs. 119.08 crores.

Amendments and Notifications Under I.D.R.A.

7227. **SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA** : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a large number of amendments and notifications have issued under Industrial Development and Regulations Act, 1951 and the rules framed under the Act till date.

(b) if so, the number of amendments in the notifications of 1973 relating to exemption of companies from Industrial Licensing System;

(c) whether these have resulted in making the rules under the notifications cumbersome, complicated and confusing; and

(d) if so, the steps taken to remedy the situation ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) (a) Yes, Sir.

(b) 47, Sir.

(c) and (d) No, Sir. The various amendments issued since 1973 were with a view to streamlining and rationalising the exemptions given under the notifications and also with reference to the situation changing from time to time in the development of various industries.

Setting up of Industries on the Basis of Raw Materials

7228. **SHRI AMAR ROYPRADHAN** : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the names of the places where the industries have been set up on the basis of availability of raw materials during the Sixth Plan period;

(b) the names of the places where the industries are to be set up on the basis of availability of raw materials during the remaining period of Sixth Plan;

(c) whether Government have received

representations/applications from the aspirant parties for setting up industries on the basis of availability of raw materials and;

(d) if so, the details thereof and action so far taken in the matter by the Central Government ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (d) The decisions in regard to setting up of the Public Sector Projects are based on techno-economic feasibility including availability of raw materials within the proximity of the project.

The particulars of the Central Industrial and Mineral Projects to be set up during the Sixth Plan period (1980-85) are given on pages 277-293 of the Sixth Plan Document, copies of which are available in the Parliament Library.

Report of Minorities Commission for the Years 1979 and 1980

7229. **SHRI AMAR ROYPRADHAN :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the main recommendations contained in the Second and Third Annual Reports of the Minorities Commission for the years 1979 and 1980 respectively;

(b) whether the recommendations of these reports have so far been implemented by Government; and

(c) if so, the details thereof and if not the reasons therefor and the time by which the recommendations would be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) Attention in this connection is invited to the Action-Taken-Memoranda on the Annual Reports of the Minorities Commission for the year 1979 and 1980 which were laid on the Table of the House on 22nd December, 1980 and 3rd August, 1982 respectively.

Assent to Bihar Press Bill, 1982

7231. **SHRI BHOGENDRA JHA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament had submitted to the Prime Minister a memorandum signed by about 30 MPs demanding refusal of President's assent to the Bihar Press Bill, 1982 ;

(b) if so, salient features of the Bill and main points of the memorandum relating thereto ;

(c) whether it has been decided to refuse assent to the Bill ;

(d) if so, details there about ; and

(e) if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) to (e) Some members of Parliament had written to the Prime Minister on 28-2-1983 stating that the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1982 popularly known as Bihar Press Bill has neither been returned to the Government of Bihar by the Central Government nor the Bihar Legislature have rescinded it. It has been requested by them that the President's assent may be withheld from the Bill.

The Bill seeks to introduce a new Section 292-A in the Indian Penal Code 1860 to prevent the printing etc. of grossly indecent or scurrilous matters or matters intended to blackmail the public servants. It also provides for amendment of Cr. P.C. to make such offences cognizable and non-bailable.

The Bill is under consideration of the Government.

Assent to Cr. P.C. (Bihar Amendment) Bill, 1982

7232. **SHRI BHOGENDRA JHA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether some Members of Parliament had submitted to the Prime Minister a memorandum signed by about 30 MPs demanding refusal of Presidents' assent to the Cr. P.C. (Bihar Amendment) Bill, 1982 ;

(b) if so, salient features of the Bill and

main points of the memorandum relating there to ;

(c) whether it has been decided to refuse assent to the Bill ;

(d) if so, details there about ; and

(e) if not reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) to (e) Some members of Parliament had written to the Prime Minister on 28-2-1983 stating that the Criminal Procedure Code (Bihar Amendment) Bill, 1982 is against the accepted policy of separation of executive and judiciary, and such the assent of the President may be withheld from the Bill.

The Government of Bihar have stated that some of the provisions of new Cr. P.C. have created certain administrative difficulties. With a view to maintaining law and order and for expeditious disposal of criminal case, it is essential to empower Executive Magistrates to take cognizance and transfer cases to the Courts of Judicial Magistrates for trial. Executive Magistrates are being empowered to try petty offences under Indian Penal Code and offences under other Acts. Therefore, it is imperative to make certain amendments in Cr. P.C. to enable Executive Magistrates to discharge their responsibility in regard to maintenance of law and order effectively.

The Bill is under consideration of the Government.

Assent to Bihar Land Reforms (Amendment) Bill 1982

7233. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament had submitted to the Prime Minister a memorandum signed by about 30 MPs demanding refusal of President's assent to the Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1982 :

(b) if so, salient features of the Bill and main points of the memorandum relating

thereto ;

(c) whether it has been decided to refuse assent to the Bill ;

(d) if so, details thereabout ; and

(e) if not reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) to (c) Some members of Parliament had written to the Prime Minister on 28.2.1983 stating that the Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1982, seeks to turn thousands of Persons and societies owning land, houses and other buildings, industries etc. in Jamshedpur area into sub-tenants of the Tatas. The provisions of the Bill are against the accepted national policy and as such the assent of the President may be withheld from the Bill.

In view of the Industrial Development of the Jamshedpur area and to safeguard the land from encroachment, the Bihar Land Reforms (Amendment) Bill seeks to lease out the land, which had vested in the State of Bihar under the provisions of the Bihar Land Reforms, Act, 1950 to the Tata Iron and Steel Company on certain terms and conditions.

The Bill is under consideration of the Government.

Installed Capacity and Actual Atomic Power Generation During Past Five Years

7234. SHRI SATYANARAYAN JATIYA : will the PRIME MINISTER be pleased to state the position in regard to installed capacity and actual atomic power generation for the past five years ending in March, 1983, year-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : The installed capacity of nuclear power stations in operation is 860 MWe. The details of power generated in the last five years are :—

S. No.	Name of Power Station.	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
(million units)						
1.	Tarapur Atomic Power Station	2286.68	1745.61	1773.70	1963.72	1470.30
2.	Rajasthan Atomic Power Station*	482.75	1130.98	1034.80	1057.20	551.64
Total		2769.43	2876.59	2808.50	3020.92	2021.94

* RAPS-2 has been in commercial operation only since 1st April 1981.

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के त्याग पत्र

कारियों की सेवा अवधि सहित उनका व्यौरा क्या है;

7235. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) उनके त्यागपत्रों के कारण क्या हैं ?

(क) 1982-83 के दौरान सेवा से त्याग-पत्र देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधि-

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना देते हुए एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	संवर्ग, जिससे सम्बद्ध है	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख	त्याग पत्र को तारीख	त्याग पत्र देने के कारण	अभ्युक्तियाँ
1.	श्री ए. एन. केरे	महाराष्ट्र	2.7.68	17.4.82	कोई कारण (अपराह्ण) नहीं दिए गए ।	1967 में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती ।
2.	श्री एस. श्रीनिवासन	तमिलनाडु	1.6.63	1.11.82	व्यक्तिगत कारणों से जो अधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किए गए ।	1962 में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती ।

Central Assistance for Tribal Sub-Plan in Orissa

7236. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the allocation of the special Central assistance for implementing Tribal Sub-plan of Orissa for 1983-84; and

(b) whether the State of Orissa has sought the assistance of Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) As Compared to the allocation of special Central assistance 1982-83, the allocation for 1983-84 has been increased.

(b) Yes, Sir.

Spying by Driver of Amritsar-Lahore Express

7237. SHRI SUBHASH YADAV :

SHRI UTTAMBHAI H. PATEL :
SHRI M. RAM GOPAL REDDY :
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK ;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the driver of the Amritsar-Lahore Samjohta Express has been found spying and passing on Secret information to Pakistan;

(b) if so, whether any other person has also been found in this racket and arrested; and

(c) the action taken by Government in regard there to ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) According to information received from the Government of Punjab no driver of Amritsar-Lahore Samjohta Express has been found engaging in espionage activities.

(b) and (c) Does not arise.

2000 Jhuggis Burns Down Near Badli (Delhi)

7238. SHRI SUBHASH YADAV :

SHRI M. RAM GOPAL REDDY :
SHRI NARAYAN CHOUBEY :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that more than 2000 Jhuggis have been burnt down by antisocial elements near Badli Delhi during the month of March, 1983;

(b) if so, whether any inquiry has since been made ; and

(c) action taken by Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) About 400 Jhuggis were burnt due to fire near Badli, Delhi on 15-3-1983.

(b) and (c) A case under Section 436/304 IPC has been registered at the Police Station Alipur on 15-3-1983 and is under investigation.

Outcome of Visit of the Team to Antarctica During December 1982 to January, 1983

7239. SHRI SUBHASH YADAV : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether twenty eight Member team of Second Indian Scientific Expedition had a visit to the icy continent of Antarctica during December, 1982 to January, 1983 ;

(b) if so, what are the names of the personnel of the team; and

(c) outcome of their visit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS, AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) Yes Sir.

(b) The name of the 28 member team are given in the attached statement.

(c) The report of the expedition is awaited.

Statement

**LIST OF MEMBERS OF THE SECOND
RESEARCH EXPEDITION TO THE
SOUTH INDIAN OCEAN AND ANTARCTICA—1982-83**

S. No.	Name
1. Leader	Shri V.K. Raina
2. Dy. Leader	Shri C.R. Sridharan
3. Member	Shri M.K. Kaul
4. „	Shri S.K. Chakravarty
5. „	Shri A. Sen Gupta
6. „	Shri P.K. Pasricha
7. „	Shri A.K. Sharma
8. „	Shri L.A. D'cruz
9. „	Shri G.S. Mittal
10. „	Shri H.R.S. Sastry
11. „	Shri Prabhu Matondkar
12. „	Shri D.R. Haldankar
13. „	Lt. Cdr. R.S. Gill
14. „	Lt. Cdr. K.S. Randhawa
15. „	Lt. Cdr. Kulwant Singh
16. „	Lt. Cdr. R. Sethi
17. „	Lt. Ujjal Singh
18. „	Shri I. Khan (Ch ELA)
19. „	Shri P.K. Kapur (POELAR)
20. „	Surg. Ldr. Cdr. D.B. Rao
21. „	Sqn. Ldr. H.N. Chaturvedi
22. „	Major D.J. Singh
23. „	Major Jai Bahuguna
24. „	Major P.K. Nair
25. „	Wg. Cdr. Abhay Singh
26. „	Sqn. Ldr. R.S. Tandon
27. „	B.S. Thakur (AM3)
28. „	Shri A.K. Andhare

**Atrocities on Harijans and Tribal Women
During 1981 and 1982**

7240. SHRI AJOY BISWAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cases of torture and molestation of Harijan and tribal women during 1981 and 1982 in the country (State-wise) ;

(b) in how many cases the police personnel are involved ; and

(c) steps Government have taken in this

connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The statistics regarding torture and molestation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe women are not maintained by the Govt. of India. However, a statement showing the number of cases of rape of Scheduled Caste and Scheduled Tribe women, based on the information furnished by the state Governments during the years 1981 and 1982, State-wise is laid on the table of the House.

(b) This information is not maintained by the Government of India.

(c) Comprehensive guidelines covering precautionary preventive, punitive, rehabilitative and personnel policy measures that are required to be taken for checking crimes against Scheduled Castes, including rape of Scheduled Castes women, have been communicated

to the State Governments in the Union Home Minister's D.O. letter dated 10th March, 1980. Similar guidelines have also been reiterated in respect of Scheduled Tribes. A copy of the guidelines dated 10-3-80 has been laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 1077 on 19th march, 1980.

Statement

Statement showing the number of cases of rape committed on Scheduled Caste and Scheduled Tribe women during the years 1981 and 1982
State-wise.

S. No.	Name of State	No. of cases of rape committed on			
		Scheduled*Castes		Scheduled Tribes	
		1981	1982	1981	1982
1.	Andhra Pradesh	22	17	6	11
2.	Assam	Nil	Nil	N.A.	N.A.
			(upto Nov.)		
3.	Bihar	80	97	44	21
4.	Gujarat	3	6	8	2
5.	Haryana	17	59	N.A.	N.A.
6.	Himachal Pradesh	9	2	N.A.	N.A.
			(Upto Oct.)		
7.	Jammu and Kashmir	4	5	N.A.	N.A.
8.	Karnataka	7	6	NIL	1
9.	Kerala	7	7	2	2
10.	Madhya Pradesh	134	148	143	164
11.	Maharashtra	51	48	33	20
12.	Orissa	7	11	6	15
13.	Punjab	12	8	Nil	1
14.	Rajasthan	66	58	9	14
15.	Tamil Nadu	7	2	Nil	Nil
16.	Tripura	Nil	1	N.A.	N.A.
17.	Uttar Pradesh	169	152	N.A.	N.A.
18.	West Bengal	7	4	9	5

Note : Information in respect of other States is 'Nil'.

Loss of Production in Public Undertakings

7241. SHRI AJOY BISWLS ; Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total production of public sector undertakings under the Department of Heavy Industry in 1981-82;

(b) the total loss of undertakings; and

(c) the causes for the loss in these undertakings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) The Public Sector Undertakings under the Department of Heavy Industry achieved a total production of Rs. 1633 crores during 1981-82.

(b) The aggregation of losses and profits of these undertakings led to a net profit of Rs. 18.74 crores during 1981-82.

(c) The causes for losses in the loss making undertakings include shortage of, and inadequate availability of, uninterrupted power, shortage of raw materials particularly steel in matching sections, shortage or free supply items from the customers, lack of adequate orders in the desired product-mix and shortage of funds.

Loss of Production in Public Undertakings

7242. SHRI AJOY BISWAS : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total production of public sector undertakings under the Department of Industrial Development during the year 1981 as against 1982;

(b) the total loss of the public sector; and

(c) the main causes for the fall of production in these undertakings ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The total production the public sector undertakings under Department of Industrial Development during 1981 and 1982 is as under:

Year	Production (Rs. Creres)
1981	299.38
1982	380.92

(b) The undertakings under the Department of Industrial Development taken together earned a profit of about Rs. 866 lakhs during the year 1981-82.

(c) Does not arise.

Car Manufacturing Units

7243. SHRI CHINTAMANI JENA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of the industries which are manufacturing cars and the number of cars manufactured by those companies during the last three years, yearwise and the names of the cars;

(b) whether it is also a fact that the prices of these cars are increasing from time to time;

(c) if so, the price of these cars as on 1 January 1979 and 1 January, 1983; and

(d) the reason for increasing the prices ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The principal manufacturers of cars are M/s. Hindustan Motors Ltd., Calcutta and M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay. The main model manufactured by M/s. Hindustan Motors is the Ambassador petrol vehicle. The company also manufactures a diesel version of this car. The principal model manufactured by M/s. Premier Automobiles is the Premier Padmini. A Deluxe version of this vehicle is also produced by the company. The production details are given below :—

Name of the party	Total Production during		
	1980-1981	1981-82	1982-1983
M/s. Hindustan Motors Ltd. Calcutta	22,000	22,732	20,608
M/s. Premier Automobiles Ltd. Bombay.	9,301	19,764	18,983

(b) and (c) There has been an increase in the prices of cars from time to time, The show-room prices at Delhi of the Ambassador (Pe-rol) car and Premier Padmini car on

1.1.79 and 6.1.83 are as follows :

	1.1.79	6.1.83
	(Rupees)	
Premier	39,183	74,165
Ambassador	38,390	73,525

As a result of Government's dialogue with industry, the prices have, however, remained stable in the last year and a half except for a very recent increase in the price of Premier Padmini car.

(d) The increase in price has been attributed by the manufactures to increase in the cost of raw-materials, components and other inputs, besides increase in Government levies.

Schemes for development of Electronics

7244. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether schemes for development of electronics during Sixth Plan have been finalised ;

(b) if so, the details of the schemes (State-wise) ; and

(c) the amount to be spent thereon (Scheme-wise) ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Representation to SC/ST in the department of atomic energy in the grades of PS/SR, P.A and P.A.

7245. SHRI BHEEKHABHAI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of Private Secretaries/Senior Personnel Assistants and PAs, in the Department of Atomic Energy as on 1 January, 1983 alongwith Roster ;

(b) the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the above grades ;

(c) whether it is a fact that adequate representation has not been given to the Scheduled Castes and Tribes Government employees in the above grades ;

(d) what is the Government policy in this regard to fill the reserved post for SCs and STs ; and

(e) the reasons for not filling the reserved posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) to (e) The information will be collected and laid on the Table of the House.

Adequate representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Department of Atomic Energy in the Grades of Scientists/Technical Engineers.

7246. SHRI BHEEKHABHAI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of Scientists/Technical Engineers in the Grade of Class I and Class II as on 1 January, 1983 in the Department of Atomic Energy alongwith roster ;

(b) whether it is a fact that adequate representation has not been given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Department of Atomic Energy ;

(c) what is the Government policy in this regard to fill the reserved posts for scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Department ; and

(d) the reasons for not filling the reserved posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) to (d) The information will be collected and laid on the Table of the House.

Representation of SCs/STs in the Grade of Scientific officers in the Department of Electronics

7247. SHRI BHEEKHABHAI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of Scientific

Officers as on 1 January, 1983 alongwith roster for SCs and STs candidates in the Department of Electronics ;

(b) the total number of Scientific Officers as on 1 January 1983 belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether it is a fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes representation in the Department of Electronics is not adequate as per Government policy ; and

(d) the Government's policy to fill the reserved posts as mentioned in part (a) above ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) (i) 145 (includes 5 officers on deputation from other Ministries/Departments)

(ii) Reservation for Scheduled Castes (SCs) Scheduled Tribes (STs) according to roster :

	SC	ST	
	19	9	
(b)	SC	ST	Remarks
	4	1	(3 SCs and 1 ST officers left the Department during the previous year)

(c) and (d) Yes, Sir. However, to fill up the reserved vacancies, the Department follows the procedure laid down by Government. The short-fall at any one point of time is taken into account while filling up vacancies at subsequent points of time.

विभागीय परीक्षाओं के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प

7248. श्री रामावतार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके अधीन मंत्रालय/विभाग और उसके सम्बन्ध कार्यालयों में 1982 में कितनी विभागीय परीक्षाएं ली गईं;

(ख) क्या ऐसी विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प दिया गया था और यदि हाँ, तो कितनी परीक्षाओं में;

(ग) उपर्युक्त सभी विभागीय परीक्षाओं

में परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से बैठने की अनुमति कब से दी जाएगी; और

(घ) इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) :

(क) उद्योग मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में वर्ष 1982 में कोई ऐसी परीक्षा नहीं ली गई।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

Recognition to all India Federation of S.C./ S.T. backward classes and Minorities Employees Welfare Associations

7249. SHRI HIRALAL R. PARMAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether All India Federation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities Employees Welfare Associations (Regd) New Delhi had been requesting Government since long for according recognition on the ground that the communities for which it is working are already recognised by the Constitution ;

(b) whether recognition is not being accorded to this Federation only on the plea that it is a caste based organisation although the socially and economically backward castes are classified in the Constitution into four categories i.e. (i) Scheduled Castes, (ii) Scheduled Tribes (iii) Backward Classes, and (iv) Minorities ;

(c) whether Government have recognised other Welfare Associations or Councils etc. of these Communities ;

(d) if so, the reasons for according recognition to these associations or councils etc. and the precise policy of the Government under which these have been recognised ; and

(e) if not, the reasons for not recognising this Federation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) As part of Government policy, however, any association of Government employees formed on the basis of any Caste, Tribe, or Religious denomination or any group or section of such caste, tribe or religious denomination is not recognised by the Government.

(c) and (d) Government have enlisted some outside voluntary welfare associations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only for the purpose of giving wider publicity to the reserved vacancies.

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

7250. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिलों ताड़ीखेत में ब्रॉन्ज फैक्ट्री के बन्द होने से वह “शून्य उद्योग” जिला घोषित हो जाने के कारण जिले को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा; और

(ख) “शून्य उद्योग” जिलों के औद्योगीकरण के लिए अब तक केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):

(क) अल्मोड़ा जिले में निम्नलिखित बड़े और मझौले उद्योग हैं :—

1. कुमार ब्रॉन्ज पाउडर, तारीखेत ।
2. सरस्वती वूलन मिल्स, चेलियानीला (रानीखेत) ।
3. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, माटेला ।

अतएव इस जिले को “उद्योग रहित जिलों” में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार “उद्योग रहित जिलों” में नए एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृत हेतु, सर्वप्रथम अधिमानता दे रही है ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्पदाओं का कार्यकरण

7251. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन औद्योगिक रूप से पिछड़े स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ औद्योगिक सम्पदाएँ हैं और वहाँ इस समय कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन औद्योगिक सम्पदाओं की वर्तमान स्थापित व्यवस्था और प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विकास के लिए दी जानी वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):

(क) से (ग) औद्योगिक बस्तियों का विषय मुख्यतः राज्य सरकारों से संबंधित है । उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 38 पिछड़े जिलों में से 26 जिलों/क्षेत्रों में 34 औद्योगिक बस्तियों की व्यवस्था है । इनमें 770 एककों के कार्यकरण होने की सूचना है । ये हैं अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बांदा, बुलन्दशहर, बस्ती, देवरिया, एटा, इटावा, फँजाबाद, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, पौड़ी गढ़वाल, रामपुर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, मुल्तानपुर और उन्नाव ।

अतएव, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में औद्योगिक बस्तियों की प्रगति की गति संतोषप्रद समझी जाती है ।

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी खनिज

7252. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों में भूगर्भ सर्वेक्षण के दौरान टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी धातुओं के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये भण्डार कहाँ-कहाँ

और कितनी मात्रा में पाए गए हैं;

(ग) इन भण्डारों के दोहन के लिए उनका मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के इस भाग के पर्यावरण सम्बन्धी महत्व को देखते हुए सरकार इन क्षेत्रों में भूमिगत खनन तकनीक अपनाने पर जोर देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) अल्मोड़ा जिले के पटनाल और घौलीचौना क्षेत्रों में टंगस्टन तथा शीशाखानी क्षेत्र में सीसा-जस्ता खनिज होने की सूचना मिली है। इस जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिज मैंगनेसाइट और सोपस्टोन/सैलखड़ी है।

टंगस्टन और सीसा-जस्ता की खोज प्रारंभिक अवस्था में है और अभी इन खनिजों के भण्डारों की आकलन/पुष्टि नहीं हुई है।

मैंगनेसाइट अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के बीच स्थित पट्टी में है। इन जिलों में मैंगनेसाइट के साथ बड़ी मात्रा में सोपस्टोन और सैलखड़ी के भी भण्डार हैं। इन खनिजों के निम्नलिखित भण्डारों की पुष्टि हो गई है :—

मैंगनेसाइट	(मिलियन टन)
ग्रेड—1	15.13
ग्रेड—2	41.03
ग्रेड—3	26.05
सोपस्टोन (पचार पर)	
ग्रेड—1	0.30
ग्रेड—2	2.20
ग्रेड—3	1.60

(ग) और (घ) टंगस्टन और सीसा-जस्ता की खोज प्रारंभिक अवस्था में है और इन खनिजों का दोहन इन भण्डारों की प्रौद्योगिकी उपादेयता की पुष्टि के बाद ही शुरू किया जा सकता है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में मैंगनेसाइट और सोपस्टोन भण्डारों का

विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहले से विदोहन किया जा रहा है।

विदोहन एजेंसियों द्वारा क्षेत्र के पर्यावरण तथा खानों की गहराई को ध्यान में रख कर भूमिगत खनन सहित उपयुक्त खनन विधियों पर विचार किया जा रहा है।

Rajneesh Foundation

7253. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the activities of Rajneesh Foundation, Pune are prejudicial to the public morals and have been affecting civil life of the Indian public ;

(b) whether serious irregularities have also been found in regard to the working of this Ashram during the last five years ;

(c) whether Government of India have inquired into the working of this Ashram ; and

(d) the details of the action Government of India have taken to stop such activities of this Ashram ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) According to information available the Government of Maharashtra had received some complaints in the past about the foreign disciples of the Rajneesh Ashram, including indulgence in alleged obscene activities by them. No such complaints however, had been received by them after the departure of the foreign disciples of the Ashram soon after Acharya Rajneesh left India for the U.S.A. in 1981.

(b) No serious irregularities were reported to have been found in the working of the Ashram during the last five years.

(c) No, Sir

(d) Specific cases had been registered by the State Government under various provisions of law in respect of complaints received by them against the disciples of the Ashram. The Central Government also maintains a general watch on the activities of such organisations for taking appropriate action whenever necessary.

"Extinction of Birds"

7254. DR. KRUPASINDHU BHOI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the species of birds that are facing extinction ;

(b) whether Government have drawn any list of animals facing extinction, if so, the details thereof ;

(c) the steps taken for their captive breeding to save them from extinction and to provide them natural habitats ; and

(d) the factors leading to the fast decline in their numbers with steps envisaged for their preservation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINGH) : (a) and (b) 122 species and sub-species of wild animals and birds found in India are included in Scheduled I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972). Of these, the Cheetah, Mountain Quail, Jerdons Courser, Pink-headed duck and Forest spotted owl are reported to have become extinct. The rest are rare or endangered. However, as a result of conservation action taken in recent years, they are not on the verge of extinction.

(c) For Crocodiles some breeding and rehabilitation centres have been established.

(d) Loss of habitat is the major factor leading to the decline in number of these species. Steps have been taken and are being taken to declare viable habitats of these species as protected areas like National Parks and Wild Life Sanctuaries.

Recommendation of a special group on needs of tribal and backward areas

7255. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that recommendations of a special group which studies the needs of tribal and backward areas have been sent by the Home Ministry to the State Governments ; and

(b) if so, the details of the recommendations

and how far have they been accepted by the State Governments and what has been the salutary effect thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) No.

(b) Does not arise.

Dual pricing policy of Cement

7256. DR. A.U. AZAMI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the measures Government propose to take to export cement and do away with the dual pricing policy ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : Domestic availability of cement being less than the demand estimates, there is no proposal at present to allow export of cement. After the introduction of policy of partial decontrol of cement w.e.f. 28.2.1982, there has been some improvement in the performance of the industry. The production of cement had gone up by 10% over the previous year. Additional capacities of the order of about six million tonnes have been installed of which 3.00 million tonne had commenced commercial production during the year 1982-83. With relatively easier availability of cement in the open market, blackmarketing of cement has been minimised to a considerable extent. The cement factories have also been in a position to earn significant returns and improve their financial strength. Priority areas also continue to get cement at controlled prices.

The implementation of the policy is constantly under review, there is no question, at present, of doing away with the scheme of partial de-control of cement.

Fall in targets of certain Industries

7257. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the targets have fallen short in a number of industries like cement, rubber, footwear, etc. in 1982-83 while there has been appreciable increase in the production in some industries ; and

(b) if so, the steps proposed to remove the impediments which came in the way of

achieving the targets and to make the public enterprises increase efficiency, capacity utilisation, generation of internal resources and productivity ?

THE MINISTER OF INDUSTRY
(SHRI NARAYAN DATT TIWARI) ;

(a) A statement giving 124 selected industries, in various ranges of achievement of target during April, 1982 to January, 1983 is enclosed.

The production of natural rubber in the country during the year 1982-83 is estimated

at 166,000 tonnes as against the targetted production of 162,000 tonnes.

(b) Chapter 19 of the Public Enterprises Survey, 1981-82, Volume I (pages 207-225) and Chapter 28 (pages 311-314) contain information on the performance of public sector enterprises in 1981-82 and for the first six months of 1982-83. Some specific measures taken by Government for upgrading the performance levels of public sector enterprises are detailed at pages 213-216 of the same Report, already placed on the Table of the House.

STATEMENT ACHIEVEMENT OF TARGET (April, 1982 to January, 1983)

Exceeding Target

A. Industries where achievement had exceeded the target.
(29 Industries with total weight 7.99)

Cigarettes, Linoleum, Bicycle Tyres, LDPE, Nylon Filament Yarn, Nylon Tyre Cord, Polyester Filament Yarn, Sulpha Drugs, Tooth Pasts, Tooth Powder, Industrial Explosives, Steel Castings, Structural, Aluminium Sheets and Circles, Razor Blades, Twist Drills, Welding Electrodes, Diesel Engines (Stat.), Sugar Machinery, Mining Machinery, Printing Machinery, Rubber Machinery, Earth Moving Equipment, Cranes, Air Gas Compressors, Typewriters, Domestic Refrigerators, Motor Starters and Contractors, Motor Cycles.

B. (90-100%) Industries where achievement in the range of 90 to 100% of target :
(39 Industries with the total weight 13.82)

Baby Food, Biscuits, Beer, Leather Cloth, Paper and Paper Board, Auto Tyres, Nitrogenous Fertilizers P_2O_5 , Oxygen Gas, Liquid Chlorine, HDPE, Polystyrene, Azo Dyes, Paints and Varnishes, Penicillin, Vitamin 'A', Soaps, Matches, Steel Forgings, Seamless Steel Tubes, Black and Galvanised Steel Pipes and Tubes, C.I. Spun Pipes and Tubes, Lead, Copper/Brass Sheets and Circles, Boilers, Chemical and Pharmaceutical Machinery, Lifts, Road Rollers, Electric Motors, Electric Lamps, Fluorescent Tubes, Winding Wires, VIR/PVC, Dry Cells, Cars, Jeeps, Scooters, Bicycles, Electric Fans.

C. (80-90%) Industries where achievement had been in the range of 80-90% of target :
(33 Industries with total weight 9.39)

Indian Type of Leather Footwear, Western Type of Leather Footwear, Rubber Footwear, Caustic Soda, Soda Ash, D/A Gas, Caprolactum, DMT, Polyester Fibre BHC (Tech.), Streptomycin, Synthetic Detergents, Optical Whitening Agents, Cement, Transmission Towers, Aluminium, Copper Cathodes, Aluminium Foils, Aluminium Extruded Products, Metallurgical Machinery including Steel Plant Equipment, Paper and Pulp Machinery, Power Driven Pumps, Ball and Roller Bearings, Machine Tools, Air Conditioners, Sewing Machines, Storage Batteries, Railway Wagons, Commercial Vehicles, Mopeds, Three Wheelers, Clocks, Wrist Watches.

D. (Below 80%) Industries where target had been achieved less than 80% : (23 Industries with total weight 5.84)

Newsprint, Calcium Carbide, PVC Resins, Synthetic Rubber, Viscose Filament Yarn, Viscose Staple Fibres, Viscose Tyre Cord, DDT, Malathion, Chloramphenicol, Zinc, Bolts, Nuts, and Rivets, Wire Ropes, Cement Machinery, Agricultural Tractors, Power Transformers, ACSR/AAC, Wire Rods for ACSR, Graphite Electrodes and Anodes, House Service Meters, Zip Fasteners, Cellulose Film, Vat Dyes.

Figures are provisional.

Increase in production of Iron Ore non Ferrous metals etc.

7258. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the targets have fallen short in a number of industries like iron-ore, non-ferrous metals, etc. in 1982-83 while there has been appreciable increase in the production in some industries ; and

(b) if so, the steps proposed to remove the impediments which came in the way of achieving the targets and to make the public enterprises increase efficiency, capacity utilisation, generation of internal resources and productivity ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loss due to bomb blast in Palika Bazar New Delhi

7259. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI GULSHER AHMED :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) estimated loss of life and property due to Bomb blast in Palika Bazar on 8 March, 1983 ;

(b) compensation proposed for the loss of life and property ;

(c) preventive measures taken particularly in view of agitations going on in Assam and Punjab ; and

(d) number and details of bomb blasts in the capital since 1 January, 1982 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) In the bomb blast in Palika Bazar on 8th March, 1983, there was no loss of life. However, 8 persons sustained injuries. As regards loss of property, some glass panes of show cases, approximately Rs. 150/- in value were broken.

(b) The Lt. Governor, Delhi has granted

a sum of Rs. 7500/- for disbursement to some of the injured persons.

(c) Armed pickets at strategic points have been posted and patrolling has been intensified. Explosive detectors have been procured by the Delhi Police and they have gone to their staff trained in handling and defusing explosives.

(d) Since January, 1982, there have been 11 incidents of bomb blasts reported to Delhi Police. The details are given below.

1. Explosion at the USSR Embassy on 19-11-1982.
2. Explosion at the Air France Office situated in Scindia House on 4.2.1983.
3. Explosion in the Office of the Iqagi Airways situated in Ansal Bhawan, on 4.2.1983.
4. Explosion at Shanti Path opposite main gate of U.S. Embassy on 11.2.1983.
5. Explosion in Palika Bazar on 8.3.1983.
6. Explosion at I.S.B.T. on 8.3.1983.
7. Explosion at Gole Post Office on 12.3.1983.
8. Explosion in the house of Shri Kishan Chand Sikand, in Sunder Nagar on 2.10.1982.
9. Explosion outside Punjab and Sind Bank, H.C. Sen Road on 12.9.1982.
10. Explosion on 8.1.1983 on road side near C. II Lawrence Road Bus Stop.
11. Explosion in front of flat No. 516, Mukherjee Nagar on 6.4. 1983.

Revision of overtime allowance to staff car drivers

7260. SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the overtime allowance rates have been revised by Government in respect of only staff car drivers ;

(b) if so, the date of issue of these orders ; and

(c) whether these revised rates are applicable to all the drivers of all the Ministries/ subordinate offices or only for persons appointed as drivers with Ministers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) The orders revising the rates of overtime allowance have been issued on 23.12.1982.

(c) The revised rates are applicable to all Staff Car Drivers who are governed by the Staff Car Rules irrespective of whether they are working in the Ministries or in subordinate offices.

Formation of a Council by Southern States

7261. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments in the South have formed a council ;

(b) if so, the objectives of this organisation ;

(c) whether this Council will negotiate with the Centre jointly for the redressal of their common interests ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (d) According to information received from the Government of Karnataka, the Chief Minister of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry in a meeting held on 20-3-1983 agreed to form a Council of the Chief Ministers of Southern States to discuss matters of common interest from time to time. The Chief Ministers decided to recommend to the Government of India the setting up of a fiscal Commission to review the Centre-State relations in fiscal matters.

Government of India have recently announced the setting up of a Commission to review the existing arrangement between the Centre and the States.

Violence in Chandigarh

7262. SHRI G. NARSIMHA REDDY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the incidents of violence in Chandigarh have shown an increase over the last two years ;

(b) how many of them are attributable to political tension and those for others ; and

(c) steps being taken to deal with the situation so as to minimise the impact ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) The U.T. Administration of Chandigarh has reported that there has been no increase in the incidents of violence in the Union Territory of Chandigarh during the last two years.

(b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Preventive measures are being taken by the U.T. Administration to deal with the situation.

Compensation to Police Constables for Work done on Rest Days

7263. SHRI RAMJIBHAI MAVANI :
SHRI UTTAMBHAL H.
PATEL :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some cases in Delhi Police Department ; Police constables and police employees are not given rest day or extra pay for the work taken from them on their rest day ;

(b) if so, what steps have been taken to give them another rest or over time/extra pay for taking work from them on rest day ;

(c) the number of such cases that happened in various police stations and offices where another rest day or over time/extra pay was not given for taking work on their rest day during the last three years ;

(d) the steps taken to give them extra pay/over time for the work/duty taken from

them on their rest days during the above period ; and

(e) the steps taken against Police Officials concerned for violating rules and regulations of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a), (b) and (d) The Government of India have already sanctioned compensatory payment of salary for a period of 30 days in a year in lieu of long hours of work and inability of the Delhi police personnel to avail themselves of all the holidays and weekly off days. In addition to this, Police personnel are entitled to 15 days casual leave.

(d) In view of above, question does not arise.

(e) Does not arise.

Additional allocation of cement to States affected by Flood, Cyclone etc.

7265. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have made additional allocation of cement to States which are affected due to flood, cyclone and other natural calamities ;

(b) if so, whether additional allocation of cement has been made to Orissa in 1983-84 for construction of houses damaged due to flood ;

(c) the original quota of cement allocated to Orissa in 1983-84 ; and

(d) the details of the additional allocation of cement made to Orissa in 1983-84 ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) No request for additional allocation of cement on account of flood/cyclone relief work etc. has been received from any State (including Orissa) during the year 1983-84

which has just commenced. As such no additional allocation on this account has been made so far. However, an additional allocation of 50,000 tonnes of cement was made in favour of the State of Orissa for Cyclone/Flood relief works etc. during the year 1982-83.

(c) and (d) Allocation of levy cement to the States is made on a quarterly basis. An allocation of 57,800 tonnes of cement has been made to the State of Orissa for the quarter April-June, 1983. In addition an allocation of 63900 tonnes of levy cement was also made in favour of Irrigation and Power projects in Orissa State during this quarter. Apart from availability of levy cement, the State also receives cement under the non-levy category free from price and distribution control.

Expansion of cement plants

7266. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal for the expansion of some cement plants ;

(b) if so, the name and the number of cement plants (State-wise) proposed to be expanded ;

(c) the financial outlay involved in such expansion scheme ; and

(d) the period by which the expansion programme is going to be completed ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (d) Details of existing cement factories which have been granted approvals for expansion of their capacity, indicating the location and expansion capacity approved are given in the statement attached.

According to current estimates, capital cost in cement industry is around Rs. 1,000/- per tonne. These schemes are under various stages of implementation.

**STATEMENT
DETAILS OF EXPANSION SCHEMES APPROVED FOR INSTALLATION
BY EXISTING CEMENT FACTORIES**

S. No.	Name of the Unit	Location	Annual capacity lakh/tonnes
1	2	3	4
1.	Cement Corpn. of India Ltd.	Yerraguntla (AP)	11.2
2.	Andhra Cement Ltd.	Vizag & Nadikudi (AP)	5

1	2	3	4
3. Cement Corpn. of India Ltd.		Adilabad (AP)	2.5
4. Raasi Cement		Nalgonda (AP)	2
5. Panyam Cement & Minerals		Buggainipalli (AP)	2
6. A.C.C. Ltd.		Mancherial (AP)	0.85
7. Sone Valley Portland Cement Co.		Japla (Bihar)	3.3
8. Shree Digvijay Cement		Sikka (Gujarat)	4.85
9. Cement Corpn. of India Ltd.		Rajban (H.P.)	2
10. A.C.C. Ltd.		Wadi (Karnataka)	10
11. Cement Corpn. of India Ltd.		Kurkunta (Karnataka)	6.5
12. Visveswaraya Iron & Steel Co.		Bhadravati (Karnataka)	3.8
13. Mysore Cement Ltd.		Ammasandra (Karnataka)	1.9
14. Cement Corpn. of India Ltd.		Neemuch (M.P.)	10
(with grinding units at Delhi and Bhatinda)			
15. Satna Cement Works		Satna (M.P.)	8.0
16. Cement Corpn. of India Ltd.		Akaltara (M.P.)	5
17. Raymond Woollen Mills		Janjgir (M.P.)	5
18. A.C.C. Ltd.		Jamul (M.P.)	2
19. A.C.C. Ltd.		Kymore (M.P.)	0.5
20. I.D.C. of Orissa Ltd.		Bargarh (Orissa)	1.65
21. J.K. Synthetics Ltd.		Nimbahera (Rajasthan)	4.20
22. Hindustan Sugar Mills		Udaipur (Rajasthan)	4
23. Birla Cement Works		Chittorgarh (Rajasthan)	3.3
24. Chettinad Cement Corporation		Karur (Tamil Nadu)	1.8
25. U.P. State Cement Corpn.		Dalla/Chunar (U.P.)	8.4

Cost of rehabilitation of tribals uprooted for setting up various projects

7267. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has asked the concerned Central Ministries/Departments to make the cost of rehabilitation of displaced persons and related matters thereof a part of the Project Report of major and medium industrial and irrigation projects in tribal areas ;

(b) if so, when this policy guideline was issued and the names of the Central Ministries/Departments asked to include in the project estimates provision of adequate funds for proper rehabilitation of affected displaced people therefor ; and

(c) the measures taken by the concerned Ministries and Departments to include the rehabilitation of displaced persons and the cost thereof in the on-going projects and future projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) Yes, Sir. The Planning Commission in December, 1980 have asked the Central Ministries of Industry, Irrigation, Rural

Development and Department of Coal to include in the project estimates provision of adequate funds for proper rehabilitation of affected displaced tribals, scheduled castes and other weaker sections in the tribal sub-Plan areas. The guidelines for preparation of project report was issued to the State Government in February, 1982.

(c) The Central Ministries/departments while examining the project reports ensure inclusion of adequate provisions for rehabilitation of displaced persons.

Linguistic Survey of Tribal Population

7268. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) whether Government have conducted linguistic survey of tribal population of the country to record the number of speakers of different tribal languages ;

(b) if so, tribe-wise and language-wise number of speakers thereof ;

(c) if not, the reasons for the same ;

(d) whether the tribal languages have been included in the list of linguistic Minority Group of Languages by Government ; and

(e) if so, the measures taken by the Linguistic Minority Commission to study the tribal language problems and to recommend to Government to solve them in their last report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir. Information on mother tongue/languages spoken including tribal languages was collected during the 1981 census in all States and Union Territories, except Assam where 1981 census could not be conducted owing to disturbed conditions prevailing in that State then.

(b) The figures of tribe-wise and language wise number of speakers are not available and their tabulation will take quite some time.

(c) Does not arise in view of the reply to (a) above.

(d) and (e) Do not arise in view of (b) above.

Setting up of a High-Power Committee for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes

7269. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his Ministry has constituted a High Power Committee to look into the matter relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes ;

(b) if so, the composition of the Committee and terms of reference given to the Committee ;

(c) whether the Committee has made progress to submit at least an interim report to Government so far ;

(d) when the full fledged report is likely to be submitted by that Committee to Government ; and

(e) if it is being delayed, the reasons therefor, if any ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) The Government of India has set up a High Power Panel on Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections of the Society. The Composition of the Panel and its terms of reference are given in the attached statement.

(c) to (e) The Panel has submitted an interim report on Minorities and are likely to submit its final reports before the 30th June, 1983, when the tenure of the Panel will expire.

STATEMENT

COMPOSITION OF THE PANEL		TERMS OF REFERENCE OF THE PANEL
1. Dr. Gopal Singh,	Chairman	1. To ascertain if the benefits of various fiscal policies of Government, both Union and States, really reach the minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections of Society ;
2. Dr. Rafiq Zakaria, M.P.	Member Secretary	
3. Shri N. Bullayya,	Member	
4. Shri Hokishe Sema,	Member	
5. Shri Arvind Netam, M.P.	Member	2. To identify the constraints or bottlenecks whereby incentives, facilities and other encouragements are not being availed of by them ;
6. Shri N.C. Prashar M.P.	Member	
7. Shri I.D. Jawaharaj.	Member	3. To suggest ways and means by which the benefits of various fiscal policies, incentives, facilities and other encouragements reach them ; and
8. Shri Neon D'souza, M.P.	Member	
9. Shri N.R. Nayak.	Member	4. To make recommendations with regard to other allied matter.
10. Shri Aloo Chibber, MIC.	Member	

Setting up of liaison office between Research Laboratories and Industries

7270. SHRI CHITTA BASU : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have under its consideration any proposal for setting up of an organisation to act as a bridge between research laboratories and industries ;

(b) if so, whether any step has since been taken in that direction ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) and (b) As the National Research & Development Corporation has been set up specifically to act as a bridge between research laboratories, both public and private, and industries, therefore there is no proposal under Government's consideration to set up any other organisation. The objectives of N.R.D.C. include the development and exploitation of inventions, whether patentable or otherwise, including technical and engineering know-how of the processes and to issue exclusive and/or non-exclusive licences on such terms advisable to commercially develop inventions and ensure commercial production of the products of inventions. The NRDC has so far acquired over 2000 processes/technologies from various indigenous R&D institutes since its inception. Over 900 processes have been released to various enterprises in the country.

(c) Question does not arise in view of the answer to (a) and (b).

Modernisation and expansion of Durgapur Steel Plant

7271. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have taken final decision on the modernisation and expansion proposals of the Durgapur Steel Plant ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) and (b) The proposal for modernisation and expansion of Durgapur Steel Plant is under examination. Technical aspects of the proposals and their financial implications are being discussed with the various agencies concerned.

Issue of licences of setting up of industry in Gadchiroli, Maharashtra

7272. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Central Government have been informed by the Government of Maharashtra that the newly created 'Gadchiroli' district is the first 'no industry district' of Maharashtra ;

(b) if so, whether the Central Government would now reconsider the application for industrial licences for industries being set up in the backward areas for being reissued for this new district ; and

(c) if not, the reason for the same and the number of applications that have been held in abeyance because of their being in the backward areas only and not in the no industry district ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) The Government of Maharashtra has requested for inclusion of Gadchiroli District in the list of 'No Industry Districts'. From the map furnished by Government of Maharashtra, there is one large scale industry (under erection) in Gadchiroli. The Government of Maharashtra have been asked to indicate the present status of the Unit under erection.

Under the existing locational policy for Industrial Licences, it has been decided to give preference for issue of licences for setting up of new Industrial undertakings in No Industry Districts and backward areas in the following order :

1. No Industry Districts.
2. Notified backward Districts/Areas in backward States ; and
3. Notified backward areas in other States ;

**Foreign collaboration for setting up
Steel Industry**

7273. SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total anticipated investment in steel sectors both in private and public sectors during Sixth Plan period and the investments made during the year 1980-81, 1981-82 and 1982-83 (upto end of February); the details thereof ;

(b) the number of new steel plants proposed to be installed during the remaining period of Sixth Plan with details ; and

(c) whether there is any collaboration proposal under consideration of Government for establishment of steel industry with any foreign country, with details ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE): (a) The details are as under :

	OUTLAY IN SIXTH PLAN.	RS. CRORES ACTUAL EXPENDITURE		
		1980-81	1981-82	1982-83
Public Sector	3719.72	666.72	730.14	680.17
Steel Plants.				(upto Feb. 1983)
Private Sector (TISCO)		52.50	115.60	142.00
				(estimated for full year).

(b) A steel plant with a capacity of 3.4 million tonnes of liquid steel is under construction at Visakhapatnam.

In addition, proposals for construction of two new plants, one in Orissa and the other at Vijayanagar in Karnataka are under consideration. Details of these projects have yet to be finally decided.

(c) No, Sir.

Ocean Mining

7274. SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether any country is carrying on deep sea mining in Indian Ocean and if so, the specific areas ;

(b) whether India is going ahead with its own technology in Polymetallic Nodules programme or it is receiving any technological know-how from abroad ;

(c) is there any foreign agreement or collaboration in this field ; and

(d) when our deep see mining programme is scheduled to take place ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN

DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL.) : (a) As far as our knowledge goes, no country is carrying out deep sea mining in the Indian Ocean.

(b) India is going on its own for the exploration of polymetallic nodules. We have made significant progress in the survey and analysis of the data.

(c) No Sir, there is no foreign agreement or collaboration in this field.

(d) The mining programme can be started only after the exploration of the area has been completed.

Delivery of Research Vessel "Sagar Kanya"

7275. SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the research vessel named Sagar Kanya had been delivered to India according to the time schedule ; and

(b) the details of the agreement with the Government of West Germany ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. (PATIL.) : (a) Yes Sir, the Research Vessel

named Sagar Kanya has been delivered to India according to time schedule.

(b) This ship has been acquired under a soft loan of the order of 60 million DM and 20.42 DM as a grant from the Federal Republic of Germany. The total cost including the scientific equipment is 80.42 Million DM.

Mid-Team Appraisal of Sixth Plan

7276. SHRI B.V. DESAI : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether the Sixth Five Year Plan will fall short of the targeted growth rate of 5.2 per cent per annum due to a lag in planned investment ;

(b) if so, whether a survey was conducted by the Economic Division of the Birla Institute of Scientific Research on a midterm appraisal of the Sixth Plan ;

(c) if so, whether Government have received the report and examined it ;

(d) if so, whether according to the Study Report the most disturbing feature of the Plan is a slowly growing agricultural sector ; and

(e) what are the other factors that were responsible for the fall in the growth rate ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN): (a) According to the ECONOMIC SURVEY for 1982-83, the average real rate of annual growth during the first three years of the Sixth Plan is estimated at about 5% which is fairly close to the target set in the Sixth Plan.

(b) Yes, Sir.

(c) Government has received a copy of the report referred to.

(d) The report states "that ..in spite of all the investments that have been made, agricultural output during the first three years of the Plan has stagnated at the peak levels attained during the Fifth Plan..."

(e) As stated in reply to (a) above, the average real rate of growth over the first three years of the VI Plan was about 5%.

Visit of French Exploratory Team for modernisation of industries

7277. SHRI B.V. DESAI : Will the

Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a French Exploratory Team for industrial modernisation visited India during the month of November, 1982 to identify areas in the Indian industry which can be modernised with French assistance ;

(b) if so, whether any report has been submitted by them after survey ;

(c) whether the French have stated clearly that they do not have anything to offer to small scale sector ;

(d) if so, the industries that will be revamped with the help and aid of the French Government ;

(e) whether any final agreement in this regard has been reached ; and

(f) if so, the details of the same ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) :

(a) to (f) A team of French experts visited India in November 1982 to examine possibilities of Indo-French collaboration in the field of industrial modernisation. The delegation was sponsored by the French Board for External Trade. The team visited some industrial establishments in the country and held discussion on the scope for French participation in their modernisation. No report has been submitted to the Government by the team. No intimation has been given that the French have nothing to offer to the Small Scale Sector. It is for the concerned industrial units, with whom the French held discussions, to come up with proposals for collaboration, if any. No Agreement between the Government and the French side is envisaged in the matter.

India's assistance to Nepal for setting up of electronic units

7278. SHRI B.V. DESAI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Nepal has sought India's assistance in setting up of electronic units in that country, especially for watches, calculators and radios ;

(b) if so, whether any scheme in this regard has been prepared with the help of the Nepal Government ; and

(c) if so, the details of the same and by

what time the final decision in this regard is likely to be taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Setting up of industries in Badaun, Uttar Pradesh.

7279. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Badaun District of Uttar Pradesh, the biggest district of Rohil khand area, is backward and facing the problems of unemployment, poverty and starvation ;

(b) if so, whether Government propose to set up some medium and big industries in the area ; and

(c) if so, the details of the industries being set up in the district during 1983-84 and 1984-85 ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) Badaun district of Uttar Pradesh is already declared as industrially backward having access to institutional finance, tax relief, hire purchase of machinery by small scale industries, consultancy for technical services, interest subsidy and special facilities for import of raw materials.

During 1980-81 and 1981-82, a total of 391 and 524 Small Scale and artisan units were established in the district. The additional employment provided in the district was 2686 and 2162 persons during 1980-81 and 1981-82.

During the years 1980-82 one industrial licence was issued in the district of Badaun.

Loss to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd.

7280. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the quantum of losses that have been brought down by Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd., New Delhi during last two financial years ;

(b) the advice given by NCCF and whether the same has been implemented ;

(c) whether NCCF had suggested that present structure of the Society should not be disturbed till all losses are liquidated ; if so, the reasons why Government are thinking of changing the present structure and holding elections of the delegates ;

(d) how many branch stores were opened during last two years ;

(e) whether a discussion has been held with DDA and the Ministry of Works & Housing regarding providing accommodation to Society to open their branch stores to provide essential commodities and specified food items including kerosene oil to Government employees ; and

(f) if not, reasons thereof and steps taken in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) After several successive years of incurring losses, 1981-82 was the first year in which the Society made a net profit of Rs. 6.21 lakhs. After apportionment of net profit towards various reserve funds as per statutory requirement, the balance available for adjustment against the accumulated losses of the past years is Rs. 3.09 lakhs. The net losses carried forward is Rs. 46.69 lakhs.

(b) and (c) Some of the recommendations made by the Consultancy Cell of the National Consumer Cooperative Federation, like streamlining the top administration, streamlining the purchase procedure, provision for enough working capital, etc. which were found capable of implementation have been acted upon. The NCCF did not make any suggestion that the present structures of the Society should be disturbed till all the losses are liquidated. No change in the present structure of the Society is involved in the holding of the fresh elections of the delegates which is as per the requirement of the Delhi Cooperative Societies Act and the bye-laws of the Society.

(d) Eight Branch Stores of the Society have been opened during the last two years as listed below :—

1. Chittaranjan Park
2. Pushpa Vihar

3. Archelological Survey of India
4. Patel Dham
5. Central Secretariat, North Block
6. DIZ Area
7. Lodi Colony
8. R.K. Puram, Sector-III

(e) The Delhi Development Authority has neither been approached nor have they provided any accommodation to the Society for running its Branch Stores. The Works & Housing Ministry have however been providing suitable accommodation at a nominal rate of rent for opening the Branches of the Society in Central Government Residential Colonies and some Office Buildings. In one Private Colony (Chitaranjan Park) the Local Residents Welfare Association obtained accommodation from the DDA and handed it over to the Society for running a Branch Store.

(f) Does not arise.

Rohini 300 Rocket

7281. SHRI PRATAP BHANU SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rohini-300 rocket powered by a castor-oil based high performance solid propellant had a successful maiden flight recently; and

(b) if so, the Salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) The IPP-40 propellant based on indigenously developed resin derived from castor oil was recently flight tested on Rohini (RH-300) rocket, as part of the development programme related to advanced solid propellants. The rocket carried a technological payload consisting of magneto sensors, thermocouples and sensors for measuring acceleration, pressure and vibration. The flight was normal.

Manufacturing of Remote Control Equipment/Gadgets

7282. SHRI AMAL DATTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether there is any restriction on manufacture of remote control equipments or gadgets; and

(b) if so, what are the restrictions and under what conditions the manufacture/use of such remote control equipments allowed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO): (a) and (b) While there are no restrictions on manufacture of remote control equipment or gadgets in general, such equipment as require control through wireless signals can be manufactured only by 100% Government-owned companies and their manufacture/use is subject to frequency clearance by Ministry of Communications.

Publication Regarding Khalistan Movement

7283. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has scrutinized the publications of the Khalistan movement produced in India and abroad and arrived at any conclusion regarding the origin, directions and inspiration for this movement;

(b) if so, the nature of the conclusions arrived at; and

(c) if not, whether such a scrutiny would be made so as to place the correct view point before the nation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b) Some such publications have come to notice. These publications relate to anti-national matters and are reported to have been inspired by leaders of organisations of the National Council of Khalistan and Dal Khalsa which have been declared as unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

(c) Does not arise.

Thefts From Cars Parked at Palam Air Port

7284. SHRI NAWAL KISHORE

SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thefts of articles from cars inside the authorised parking area at Palam Airport are on the increase ;

(b) the total number of theft complaints registered with the Palam Police Station during the year 1981 and 1982 regarding thefts from parked cars at Palam Airport ;

(c) how many theft cases have so far been solved ;

(d) what are the reasons for the increase in such thefts ; and

(e) what steps Government have taken or are proposed to be taken to check such incidents of thefts effectively ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) No such increase has been noticed.

(b) In the year, 1981, 3 such cases were reported and in 1982 only 1 such case was reported.

(c) One case of 1981 has since been solved.

(d) Does not arise, in view of reply to parts (a) and (b) of the question.

(e) Patrolling has been intensified and Management of the car park has been alerted.

Import of Construction Equipments etc. for Visakhapatnam Steel Plant

7285. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are pushing through the import of a number of items including construction equipments, structurals and fabricators for the Visakhapatnam steel plant ;

(b) whether it is a fact that these items can be wholly procured domestically and in any quantity ;

(c) what is the total amount involved in the import of the items as at (a) above ; and

(d) what is the justification for importing

these articles when these are available in abundance domestically ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Infiltration of Pakistan National in Jaisalmer of Barmer District of Rajasthan

7286. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at present large scale infiltration of Pakistani nationals is taking place in the place in the bordering districts of Jaisalmer and Barmer in Rajasthan ;

(b) if so, the total number of Pakistani nationals infiltrated during the years 1981 and 1982 ; and

(c) if so, steps taken to check such infiltration and how far their infiltration has been checked ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Government have received no reports about large scale infiltration of Pakistani nationals in the districts of Jaisalmer and Barmer in Rajasthan.

(b) 8 Pak nationals in 1981 and 3 Pak nationals in 1982 were apprehended.

(c) Patrolling along the international border has been intensified and strict vigilance is kept to check any infiltration from across the border.

Development of backward areas of Orissa

7287. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK :

SHRI RASA BEHARI BEHERA :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant special assistance for the development of backward areas of Orissa ;

(b) if so, the amount of Central assistance proposed to be provided to the State of Orissa for that purpose in 1983-84 ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) Government is already granting Special Assistance for development of the backward areas of Orssa. These schemes are for accelerated development in tribal areas, drought prone areas and industrially backward areas of the State.

(b) and (c) The Special Central Assistance provided for the schemes in the year 1983-84 is as follows :—

(Rs. lakhs)

(1) Tribal Areas	1387.34
(2) Drought Prone Areas - Programme	130.00
(3) Industrially Backward Areas	*

*No fixed provision is made. The amount is reimbursed according to needs and eligibility.

The Special Central Assistance for tribal areas is for the development of 23 Integrated Tribal Development Projects and tribal pockets in the State. The Drought Prone Areas Programme is in operation in two districts viz. Kalahandi and Phulbani. The industrially backward districts in the State numbering 8 (Balasore, Bolangir, Dhenkanal, Kalahandi, Keonjhar, Koraput, Mayurbhanj and Phulbani) are eligible for concessional finance from the financial institutions, while 6 districts (Kalahandi, Mayurbhanj, Bolangir, Dhenkanal, Keonjhar and Koraput) are eligible for Investment Subsidy for setting up industries.

Licence for Manufacture of T.V. Picture Tubes

7288. **SHRIMATI JAYANTI PATNAIK :** Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether applications have been received from different States for issue of licences for manufacture of T.V. picture tubes ; if so, from which States ; and

(b) when will these be granted ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) As

for Black and White TV picture tubes, three applications for industrial approvals have been received and are being processed for decision. These applications are from units located in Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa. Regarding colour TV picture tubes conversion to an industrial licence of the letter of Intent already issued to M/s Punjab Display Devices Limited, a public sector company of the Government of Punjab is being processed for decision. In addition, two new applications, one each from the Andhra Pradesh Electronics Development Corporation and the Uttar Pradesh Electronics Corporation, have been received and are also being processed for decision.

Execution of Death Sentences

7289. **SHRI MADHAVRAO SCINDIA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons condemned to death sentence and awaiting execution as on 31 March, 1983, in different jails in the country for more than five years ; and

(b) the main reasons for not executing them for so long ; especially in view of the dehumanising factor involved in the prolonged delay in the executions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Losses suffered by Hindustan Tractors due to dumping of Czech Tractors

7290. **DR. VASANT KUMAR PANDIT :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have seen the news item appearing in the "Current" dated 13 November, 1982 under the caption "Czech lobby Ruins Hindustan Tractors" ;

(b) if so, how many tractors of Gujarat Tractor Corporation of 50 H.P. capacity are lying unsold as on 31 December, 1982 ;

(c) whether import of Czech made 45 H.P. tractors have rendered the Gujarat Tractor Corporation as a sick unit ;

(d) whether there is discontentment among the farmers who had earlier purchased

the 50 HP Gujarat tractors in U.P. and other States ; and

(e) how Government are trying to save Hindustan Tractors from lockout and heavy loss suffered due to dumping of 45 HP Czech tractors in the country ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) 86

(c) GICL have not imported any Czech made 45 HP tractors except 2 nos. which were imported for development purposes. Hence the question of its becoming sick on this account does not arise.

(d) No such instance has come to notice.

(e) Does not arise in view of the answer to part (c) above.

खादी आयोग के कार्यालयों और विक्रय केन्द्रों में कर्मचारी

7291. श्री राम सिंह शाक्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी आयोग के कार्यालयों और विक्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है, वे कहाँ कहाँ पर है और उनमें से प्रत्येक में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) खादी द्वारा आयोग उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assistance to States for Strengthening Police Force

7292. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his Ministry has offered assistance to States for strengthening police forces ;

(b) if so, what sort of assistance is proposed to be provided by Centre to help the States in strengthening their police force ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) The Seventh Finance Commission recommended an outlay of Rs. 168.73 crores for upgradation of standards of police administration in nine States viz. Assam, Bihar, Himachal Pradesh, J & K, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The outlay is intended to enable the States to increase the strength of civil police and to improve staff training, welfare, transportation, equipments and aids to scientific investigation. Further, under the scheme for modernisation of state police forces which has been revived for a period of 10 years from 1980-81 with a total outlay of Rs. 100 crores, Central Assistance is given to the States to meet the non-recurring expenditure on the purchase of vehicles, wireless equipments, computers, scientific aid for investigation and training equipments. 50% of the financial assistance to the States under this scheme is loan repayable over a period of 25 years while the balance 50% is Grant-in-aid. The annual allocation for the States has been determined on the basis of police strength, population and other factors.

Setting up of sea food processing industries

7293. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to set up sea food processing industry in the coastal States ;

(b) if so, the number of sea food processing units proposed to be set up in Orissa by Government ; and

(c) what other steps are proposed to be taken by Government to encourage the setting up of such sea food processing units both in private and public sector in different coastal States ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Discovery of Dolomite and Limestone in Aurnachal Pradesh and some other states

7294. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Geographical Survey of India has undertaken survey and discovered dolomite and limestone in Arunachal Pradesh and some other States recently ;

(b) if so, the expected tonnes of the dolomite reserve at the new places where survey has been conducted in last six months ;

(c) the total area at each place where dolomite and limestone have been discovered ;

(d) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) Yes, Sir. During the last two field seasons (1980-81 and 1981-82) the following reserves of limestone and dolomite have been estimated :—

MINERALS/GRADE	QTY. ESTIMATED (MILLION TONNES)	NAME OF PLACE
Dolomite (flux grade)	185.00	Arunachal Pradesh (Kameng district)
Dolomite (Low grade)	135.00	—do—
Limestone (cement grade)	3.76	Arunachal Pradesh (Subansiri district)
Limestone (cement grade)	500.00	Himachal Pradesh (Simla district)
Limestone (All grades)	900.00	Rajasthan (Jaisalmer district)
Limestone (flux and other grades)	970.00	Madhya Pradesh (Satna, Jabalpur and Rewa districts)
Limestone (SMS grade)	4.00	Andhra Pradesh (Paland Basin)
Dolomite (flux grade)	40.00	West Bengal (Jalpaiguri district)

(b) to (d) The reserves of dolomite and limestone from new places where survey has been conducted in the last six months will be estimated after the data collected by the field parties is processed.

Allotment of cement to plot holders

7295. SHRI R.N. RAKESH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether persons having a maximum area of 200 yards and a maximum planned area of 100 sq feet are entitled to the required quantity of levy cement ;

(b) whether Government are aware that it has brought hardships and it amounts to discrimination against other small plot holders having less than 400 sq. feet plots who are in majority and belong to middle or lower middle class of people ;

(c) whether Government propose to do away with the discrimination by allowing at least that much quantity of cement to each builder equivalent to what is allowed to a

200 yards plot holders upto a plot area of 400 sq. feet ; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) Under the provisions of scheme of partial de-control of cement, supply of levy cement for construction of dwelling units is regulated by the following :—

- (i) For urban agglomerations/towns/cities having a population of one lakh and above as per 1981 census, the limit in regard to plinth area would be upto 100 sq. mts.
- (ii) For urban agglomerations/towns rural areas having a population of less than one lakh as per 1981 Census, the limit in regard to plinth area would be upto 120 sq. mts.

In order that the benefit under the scheme accrues largely to the middle and lower middle class people, Delhi Administration

have, however, prescribed in addition that the size of residential plot should not exceed 205 sq. yds. Plot holders having 400 sq. feet area are thus covered by the existing policy.

(d) Does not arise.

Help to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Families in Andhra Pradesh

7296. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes families proposed to be assisted during the year 1982-83 in Andhra Pradesh ;

(b) the nature of assistance given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under new 20-Point Programme ;

(c) whether the target for the same has been fulfilled upto 31 March, 1983 ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) the target for the year 1983-84 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) The number of Scheduled Castes families proposed to be assisted during the year 1982-83 in Andhra Pradesh is 1,30,917. The corresponding figure for Scheduled Tribes families is 38600. These are according to the Special Component Plan for development of Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan for development of Scheduled Tribes prepared by the State Government. The schemes under Special Component Plan and Tribal Sub-Plan are taken up in various sectors of development.

A Special thrust has been imparted to these schemes by including them under the new 20-Point Programme as Point 7 which concerns with "Acceleration of Programmes for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

(c) and (d) It is expected that the target fixed for the year 1982-83 would be fulfilled.

(e) The target for the year 1983-84 will be finalised after discussion of the Special Component Plan and Tribal Sub-Plan in the Planning Commission shortly.

Production of detergents by M/s. Hindustan Lever at Chindwara

7297. SHRI AMAL DATTA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the installed capacity and market share of Hindustan Lever in manufacture and sale of detergents ;

(b) whether it is a fact that this company has been granted further letter of intent for production of detergents in Chindwara district of Madhya Pradesh ;

(c) whether the M.R.T.P. Commission has been informed/consulted in this respect ; and

(d) if so, what has been its reaction ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) M/s. Hindustan Lever have installed a capacity of 82,520 tonnes detergents and it is about 29% of the total installed capacity in the industry. Government have no information regarding market share of their sales.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Department of Company Affairs examined and approved the proposal under Section 22(3) (a) of the MRTP Act.

Production of sunlight soap by M/s. Hindustan Lever

7298. SHRI AMAL DATA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the licensed capacity of Hindustan Lever for production of Sunlight soap ;

(b) whether it is fact that the company has been sub-contracting manufacture of Sunlight soap to small scale units ; and

(c) if so, the such sub-contracting and what is the production of Sunlight soap inclusive of the manufacture by small scale units ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Sunlight soap is reckoned as laundry soap for statistical purposes. Unit-wise licensed capacity of M/s. Hindustan Lever for the production of laundry soap is as follows :—

GARDEN SEWRI,
REACH BOMBAY
CALCUTTA

(Figures in tonnes)

Laundry soap 17,233 27,796

(b) Government have no information.

(c) Does not arise.

**Director's Grade to Deputy Secretaries
Belonging to Central Secretariat
Service**

7299. SHRI KAMLA MISHRA
MADHUKAR : Will the Minister of HOME
AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that till a few years ago Deputy Secretaries belong to the Central Sectt. Service on inclusion in the Director's panel used to be given the Directors grade by upgrading the post held by them, as in the case of I.A.S. ;

(b) whether it is a fact that while this practice has been stopped in the case of C.S.S. Officers, the officers belonging to I.A.S. are given the benefit, while working in the Secretariat thereby resulting in discrimination between the two Services ; and

(c) whether the Government are aware that discriminatory treatment has added to the already existing stagnation in the Central Secretariat Service ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) to (c) Government did not take any general decision in the past that the posts of Deputy Secretaries held by officers belonging to the Central Secretariat service should be automatically upgraded on their empanelment as Director and they should be promoted against these posts. In respect of officers belonging to the All India Services and Central Services Group 'A', the posts of Deputy Secretaries held by them are re-designated as Directors when they are granted Selection Grade of Rs. 2000/- 2250/- in their respective cadres provided they fulfil the criteria of the requisite length of service. Such re-designation does not involve any promotion in respect of these officers. In the circumstances, the question of any discrimination does not arise.

Reports on Mineral Resources

7300. SHRI BHEEKHABHAI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number and names of princely States in Rajasthan which got prepared expert reports on mineral resources of their States before independence :

(b) whether these reports are available with Government of India ;

(c) the names of authors of these reports ; and

(d) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a to d) No reports on this matter are available with the Ministry.

**Disparity in Pay-Scales of Bhilai Steel
Plant School Teachers Vis-a-Vis
Durgapur and Rourkela Steel Plants**

7301. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Bhilai Steel Plant School teachers have represented to Government several times regarding disparity in scales of their pay with other steelmill school teachers at Durgapur and Rourkela ;

(b) if so, what action has been taken to remove this disparity ; and

(c) if no action has been taken, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) to (c) Yes, Sir. The issue of standardisation of pay scales, leave benefits, working hours, etc. for teachers of steel plants is under consideration of the Standardisation Committee, a sub-committee of the National Joint Consultative Committee for Steel Industry, which includes representatives of Central Trade Unions and also recognised unions of steel plants. The proposals made by management are under discussion of this Standardisation Committee. The Management of Bhilai Steel Plant has granted certain benefits in pay scales to their teachers after discussions with their registered Unions.

**Purchase of Stationery from Central
Government Employees Consumer
Cooperative Store Ltd.**

7302. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of Home AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1850 on 3 March, 1982 regarding purchase of stationery from the Central Government Employees Consumer Cooperative Store Ltd. ; and state :

(a) whether Delhi Administration, Delhi Development Authority, Autonomous bodies, civic bodies, lower formation of Defence are exempted from the purview of the Government order No. 14/14/80-Welfare dated 14 July, 1981 as their names do not appear in the endorsement ;

(b) if not, the steps taken to bring them at par with other departments ;

(c) whether the instructions are being implemented by all Departments of the Central Government ; and

(d) whether a statement will be laid on the Table including the details of local purchase resorted to by Government departments individually during the course of the last three years and whether the same was the barest minimum together with reasons for resorting to local purchases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The Government Office Memorandum No. 14/14/80-Welfare dated 14th July, 1981 covers all Central Govt. Departments, their subordinate and attached offices and other organisations, financed and/or controlled by the Govt. located at Delhi/New Delhi. It does not therefore cover Delhi Administration, Delhi Development Authority, Autonomous bodies, civic bodies etc.

(b) There is no such proposal because as stated in part (a) above the circular covers only the Central Govt. Offices in Delhi and New Delhi.

(c) and (d) The circular was issued on 14th July, 1981. Therefore no information can be furnished for the period prior to 14th July, 1981. The information for the period from 15 th July, 1981 to 31st March, 1983 is being collected and will be laid on the Table of the House.

Mysterious Deaths/Murders in Delhi

7303. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) how many mysterious deaths/murders came to light in Delhi from January, 1982 to March, 1983 ; and what are their details ;

(b) how many of them have been solved and with what results ;

(c) how many people were charged under section 302 IPC and whether any of them were granted bail ; if so, the reasons thereof ; and.

(d) the total number of people arrested in connection with the murders, either directly associated or indirectly, and out of them how many have been released, granted bail together with reasons for doing so ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) A statement containing the requisite information in respect of cases under section 302 IPC is attached.

(c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**STATEMENT
CASES REPORTED UNDER SECTION 302 IPC**

Period	Reported	Admitted	Convicted	Acquitted	Pending Trial	Pending Investigation	Persons Arrested
1982	238	234	2	14	156	43	442
1983							
January	11	11	—	—	2	9	13
February	18	18	—	—	—	18	21
March	25	25	—	—	—	25	24

**Regulation of Casual Labour/Muster
Roll Employees**

7304. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that casual labour/muster roll employees are being appointed by his Ministry or Department/ Subordinate Offices under his Ministry ;

(b) if so, the number of such employees employed in his Ministry as well as in each Department and Subordinate Office under his Ministry ;

(c) whether their services are not being regularised even after the lapse of considerable period ; if so, the reasons therefore ; and

(d) what action Government propose to take in respect of regularisation of their services instead of keeping them as casual labours or only muster roll employees, for years together ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-
जाति के लिए आरक्षित पदों
को भरा जाना**

7305. श्री रामविलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक श्रेणी में उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है जो जान बूझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करते हैं चाहे ऐसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध भी क्यों न हों; और

(च) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी :

(क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के दोनों विभागों के बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:—

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जन जातियां	
		कर्मचारियों की संख्या	कालम सं. 2 कालम सं. 3 का प्रतिशत	कर्मचारियों की संख्या	कालम सं. 2 कालम सं. 5 का प्रतिशत
1.	2.	3	4.	5	6
क	87	7	8.04	1	1.1
ख	549	50	9.1	3	0.5
ग	933	118	12.6	1	0.1
घ (सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त)	240	52	21.6	10	4.1
ङ (सफाई कर्मचारी)	51	51	100	—	—

(ग) तथा (घ) भर्ती करने वाले अभि-
करणों उदाहरणार्थ संघ लोक सेवा आयोग,
कर्मचारी चयन आयोग आदि से अनुसूचित
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधि-
कारियों/प्रत्याशियों में शीघ्रता करके तथा
प्राप्त नामांकनों के सम्बन्ध में आवश्यक औप-
चारिकताओं को पूरा करके पिछले बकाया
पदों को भर कर इस कमी को दूर करने के
प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) इस प्रकार का कोई भी मामला
ज्ञानकारी में नहीं आया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Special Central Assistance for ERRP
Scheme in Orissa**

7306. SHRI GIRIDHAR GOMANGO :
Will the Minister of HOME AFFAIRS be
pleased to state :

(a) whether it is a fact that the special
Central assistance of Home Ministry has
been provided for ERRP scheme of the
State Government of Orissa ;

(b) if so, whether this scheme is only
meant for the tribals of Sub-Plan areas of
that State or for other proper sections of all
districts ;

(c) whether this scheme is to cover all
economically poorer sections including the
poor among the tribals and the Government
for Orissa have prepared their own scheme
from the State Plan outlays ;

(d) whether the financing by the Home
Ministry of the State Plan Scheme instead of
starting the scheme of this type in tribal
areas on the line of micro projects for most
primitive tribes is justified according to
Sub Plan concept ; and

(e) if not, how and why this was agreed
to and the State Government was not
pressed for starting this scheme from the
State Plan outlay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes,
Sir.

(b) and (c) ERRP scheme of Orissa is

meant to cover all economically poor
sections including tribals and scheduled
castes in the Tribal sub-Plan area as well as
outside it in the State of Orissa. This
scheme is State Plan Scheme of Orissa
approved by the Planning Commission.

(d) Yes, Sir.

(e) Does not arise.

**Concessions for manufacturers of Cars
and Scooters**

7307. SHRI BALASAHEB VIKHE
PATIL : Will the Minister of INDUSTRY
be pleased to state :

(a) whether Government have given
some concessions in customs and excise
duty to the manufacturers of small cars and
two wheelers ;

(b) if so, how this concession would be
reflected in the price for each vehicle in the
market ;

(c) whether any step has been taken to
minimise the price of these two types of
vehicles either through duty reduction or
through other means because as they are at
present, they are going beyond the reach of
the common man ;

(d) if so, the steps contemplated in this
direction ; and

(e) what concessions are now being
given to the manufacturing units so that
their products can really become competi-
tive in the foreign market ?

THE MINISTER OF INDUSTRY
(SHRI NARAYAN DATT TIWARI) :

(a) Concessional rates of customs duty for
import of components under an approved
phased manufacturing programme have been
extended by Government for the manufac-
ture of cars upto 1000-cc engine capacity
and for 2-wheelers subject to these satisfying
certain criteria for fuel efficiency which have
been specified. Differential rates of excise
duty have also been introduced.

(b) to (d) Government have established
Maruti Udyog Limited as a public sector
project to take up the manufacture of
passenger cars at economical prices. A
number of new parties have been issued
approvals for the manufacture of 2-wheelers
based on import of the latest technologies

and employing economies of scale in production. These measures alongwith the concessions in customs and excise duties extended by the Government are expected to assist in the availability of passenger cars and 2-wheelers at economical and competitive prices.

(e) A number of incentives of export promotion like 17% cash assistance, 10% REP licences, duty free imports of components and raw-materials and rebate of 11% on customs duty etc. are available to automobile industry also.

Despatch of levy cement quota by cement factories to Punjab

7308. SHRI R.L. BHATIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it has been brought to the notice of his Ministry by the Punjab Government that the cement factories are not despatching levy cement quota in time as per Government's policy ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government will ask the cement factories to complete despatches of cement against quarterly allocations as per Government's policy, before the expiry of the quarter for which the allocation is made ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Bulk of the allocation of levy cement for Punjab is made from cement factories located in Rajasthan. Due to fall in production arising out of imposition of power cuts in Rajasthan, supply of cement (both levy and non-levy) to the States of Rajasthan, Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh has been, to some extent, adversely affected.

(c) Initial validity of release orders is for a period of about 3 months. Shortfalls, if any, in despatches of levy cement are generally carried forward for a further period of about 6 months.

Ashoka Paper Mills Limited

7309. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer : to the reply given to Unstarred Question No. 1731 on 2 March, 1983 regarding Ashoka Paper Mills Limited and state :

(a) whether provision of additional working capital for Rameshwar Nagar Unit of the Ashoka Paper Mills has since been made ; and

(b) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI):

(a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

Defective turbines and generator in B.H.E.L.

7310. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of turbines and generators produced by BHEL which have been found to be defective during 1980, 1981 and 1982 ;

(b) the total cost involved in all these defective machinery and how they were disposed of ;

(c) whether Government have made any inquiry to find out if these defects are real or they are because of some sabotage ; and

(d) the steps being contemplated to eradicate them ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI):

(a) No turbines and generators produced by BHEL for Thermal and Hydro Power Plants during the years 1980, 1981 and 1982 were really defective. However, some problems occurred in respect of some equipments during commissioning which have been rectified.

(b) to (d) Do not arise.

Setting up of Atomic Research Laboratory in Tamil Nadu

7311. SHRI D.S.A. SIVAPRAKASHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that laboratory of the Bhabha Atomic Research Centre is not adequate for research ;

(b) if so, whether there is any proposal to set up new laboratories anywhere in India ; and

(c) if so, will there be one in Tamil Nadu ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) to (c) The existing laboratories of the Bhabha Atomic Research Centre are fully equipped to the research in nuclear sciences. However, there are several frontier areas in nuclear sciences, viz., controlled thermonuclear fusion, lasers, advanced accelerators etc., where it is necessary to initiate research work. BARC is unable to house these programmes mainly for want of space and it is, therefore, proposed to set up a Centre for Advanced Technology at Indore, Madhya Pradesh. The Department of Atomic Energy already have a research centre, viz., the Reactor Research Centre in Tamilnadu at Kalpakkam near Madras.

**Declaration of backward areas in
Tamil Nadu.**

7312. SHRI D.S.A. SIVAPRAKASHAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government of Tamil Nadu had submitted any list of places from Tamil Nadu for declaring as backward areas in the past two years ; and

(b) if so, the places requested by Government of Tamil Nadu and the response of Central Government to that proposal ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) Yes Sir.

(b) The Government of Tamil Nadu have recommended Gandharvakottai added to Pudukottai District for inclusion in the areas to be declared as backward area eligible for Central Investment Subsidy in the last two years.

However, during the year 1980, the Government of Tamil Nadu had also submitted proposals to the Government of India to include the following areas in the list of backward areas in addition to the 33 taluks already declared by Government of India to be eligible for Central Investment Subsidy :

TALUKS

1. Madurantakam
2. Ponneri
3. Gummidipoondi
4. Periakulam
5. Pollur
6. Chengam
7. Wandiwash
8. Cheyyar
9. Aranthangai
10. Avudayarkoil
11. Gingee
12. Tirukkoilur
13. Ulundurpet
14. Kallakurichi
15. Tittangudi
17. Chidambaram
17. Kattumannarkoil
18. Tindivenam
19. Orathanad
20. Peraurani
21. Musiri
22. Ariyalur
23. Vilathikulam
24. Nanguneri

DISTRICTS

- Chingleput
Chingleput
-do-
Madurai
North Arcot
-do-
-do-
-do-
Pudukoottai
Pudukottai
South Arcot
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
Tanjavur
-do-
Tiruchirappalli
-do-
Tirunelveli
-do-

The recommendations of National Committee on the Development of Backward Areas are at present at an advanced stage of consideration and any change in the existing list of selected backward areas/districts would depend on the final decision taken by the Government thereon.

**Implementation of orders/instructions
issued by Ministry of Home Affairs**

7313. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the steps taken to ensure that the orders/instructions issued by the Home Ministry on personnel matters are implemented strictly by all Government Departments ; and

(b) whether the Home Ministry functions as watch dog to ensure compliance of orders issued by it ; if so, the modalities thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : (a) and (b) The Department of Personnel & Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs is inter alia responsible for formulation of policies on various aspects of personnel administration like recruitment, promotion, conditions of service, reservations for scheduled castes/scheduled tribes and other class or categories of persons, discipline, and morale in services including administrative vigilance, staff welfare, training and research in personnel administration. The Department renders guidance and advice to the Ministries/Departments on service matters for ensuring proper implementation of the policies laid down by it. It is, however, for the Ministries/Departments to implement the policies as laid down by the Department of Personnel & A.R. and also to ensure that the various instructions are followed scrupulously. It may also be added that some of the aspects relating to the more important service conditions also take the shape of statutory rules and regulations which are necessary to be followed by Ministries/Departments. Whenever it is considered necessary and appropriate to do so as for example in respect of matters relating to reservations for scheduled castes and scheduled tribes, Ministries/Departments are required to furnish to the Department of Personnel & A.R., information through suitable returns/reports regarding the implementation of the

various orders/instructions relating to the personnel matters.

Equipments and spare parts purchased by Rourkela Steel Plant

7314. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the names of the ancilliary industries from which Rourkela Steel Plant is buying equipments and spare parts ;

(b) how many of these industries are managed by the public sector and private sector ; and

(c) the details of the purchasing bills against buying equipments and spare parts from those industries by Rourkela Steel Plant in last three years ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) to (c) Rourkela Steel Plant purchases equipment and spare parts from 15 ancillary industries all of which are in the private sector. Compilation of details of purchase bills over the last three years will involve voluminous and time consuming work and the results achieved will not be commensurate with the effort that has to be made. The total value of orders placed against each of these industries during the last three years are, however, given below :

S.NO.	NAME OF THE PARTIES.	TOTAL VALUE OF ORDERS PLACED		
		1980-81	1981-82	1982-83
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	M/S Kanak Industries, Rourkela.	6,69,337	15,45,537	2,52,970
2.	M/S Rourkela Construction, Rourkela.	28,13,786	10,95,148	15,18,176
3.	M/S Modern Engg. Works, Rourkela.	16,86,306	16,67,647	6,69,269
4.	M/S Tara Engg. Works, Rourkela.	47,72,237	39,48,508	39,79,258
5.	M/S Zentuc Industries Rourkela.	9,08,896	15,55,368	7,21,047
6.	M/S Techno Engineers, Rourkela.	4,99,654	5,77,130	10,07,928
7.	M/S Precision Engg. Works, Rourkela.	40,36,376	40,94,475	36,24,473
8.	M/S Premier Ind., Rourkela.	15,41,885	24,47,625	2,28,920
9.	M/S Hirakud Enterprises, Rourkela.	37,260	2,73,458	19,800
10.	M/S Steelo Precision Works Rourkela.	65,536	Nil	Nil
11.	M/S Utkal Metal Ind., Rourkela.	2,72,152	3,24,673	4,45,921
12.	M/S Jwala Engg. Works, Rourkela.	11,70,990	4,25,583	6,10,183
13.	M/S East India Engg., Co., Rourkela.	18,08,900	28,78,784	74,81,621
14.	M/S Rourkela Fabrication Rourkela.	20,77,993	21,88,662	5,94,720
15.	M/S Hardman Press Tools, Rourkela.	4,96,721	4,45,014	6,48,625

Exploitation of Tribal Migrant Labour

7315. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some cases have come to the notice of Central Government regarding in-human exploitation of tribals, especially of women, who migrated to other States for the attraction of jobs ;

(b) if so, the assessment of Government in this regard ; and

(c) whether Government propose to evaluate the present programme of tribal welfare to stop trafficking in liquor, drugs and sex, especially in Orissa and Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Cases of exploitation of tribals are got enquired into through the State Governments.

(b) and (c) The tribal welfare programme includes steps to prevent the exploitation of tribals in all spheres. These antiexploitative measures are discussed with State Governments along with the tribal welfare programme under the tribal sub-Plan and it has been impressed upon the State Governments to take necessary steps for this purpose, including strict enforcement of the provision of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. No special evaluation of anti-exploitative measures in Madhya Pradesh and Orissa is contemplated at present.

Committee on problems of industry

7316. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether his Ministry has set up any machinery or constituted any Committee to go into various problems of industries ;

(b) if so, the main factors which have led to hamper the growth of industries ; and

(c) the steps taken to overcome those difficulties ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a)

to (c) While no formal committee has been set up to go into the various problems of the industries, a Control Room comprising of a representative each of the Departments of Heavy Industry, Industrial Development and DGTD has been set up in the Ministry of Industry. This Control Room monitors and liaises with the concerned authorities in finding solutions to the problems reported in respect of identified key sector industries. The production constraints reported are like supply of raw materials, coal, power, railway movement and industrial relations. These constraints are analysed and action is initiated to refer the problems to the concerned authorities and pursue with them till the remedial action has been completed.

Opposition by big industrial houses to set up industries in backward areas

7317. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of the places which Government had selected and decided to establish major/minor public sector units in backward areas/developed areas during Sixth Plan period in the country ;

(b) the basis of the establishment of these units ;

(c) whether it is also a fact that decision of Government for the establishment of these units was opposed by some big industrial houses ; and

(d) if so, the names of the parties with specific reasons and reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) The Central Investments are primarily in large industrial projects of a basic character. The location of such projects has, therefore, to be decided on broad techno-economic considerations. It has been the policy of the Government that subject to techno-economic considerations comparatively backward regions are given preference in the location of Central Projects. Having regard to the inherent limitations in ensuring equal distribution of Central Investments in different regions, balanced regional development of industries has to be achieved by attracting larger investments in the private sector, in

regions which are industrially backward. Therefore, in order to attract investment in backward and less developed areas a number of concessions like Capital investment subsidy, transport subsidy concessional finance from financial institutions are being offered to prospective entrepreneurs.

In the Sixth Five Year Plan, priority has been given to all on-going schemes and for modernisation/replacement programmes. New schemes have been identified and provided for, based on techno-economic feasibility and keeping in view the constraints on resources and the inter-sectoral priorities indicated in the Plan Document. Substantive details of all such projects included in the Sixth Five Year Plan period have been published in the Sixth Five Year Plan Document (Pages 277-293) and copies are available in the Parliament Library.

(c) and (d) In so far as this Ministry is concerned, no big industrial house has so far approached opposing the setting up of any Public Sector Project.

बोकारो इस्पात कारखाने के आसपास के क्षेत्रों में सूखे तथा अकाल से निपटने में योगदान

7318. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना ने आसपास के क्षेत्रों में सूखे तथा अकाल से उत्पन्न स्थिति से निपटने में कहाँ तक योगदान दिया है; और

(ख) क्या अन्य इस्पात कारखानों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ योगदान दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :

(क) बोकारो इस्पात कारखाना बिहार में सूखे तथा अकाल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री के सहायता कोष में एक लाख रुपये दे रहा है। इस कारखाने के बहुत से कामगारों ने भी इस कोष में अपना एक दिन का मूल वेतन दिया है।

इसके अलावा कारखाने के आस-पास के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बोकारो के इर्द-गिर्द के गावों में 22 हैंड पम्प और 4 रिग बोर्ड पम्प लगाए गए हैं। समीपवर्ती क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिए तोपचांची झील में से गाद निकालने का काम भी किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

Deaths of C.R.P. Men in clash with Assam Police

7319. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report in Hindustan Times dated 17 February, 1983 captioned "Three, CRP men die in clash with Assam Police" and if so, what are the facts and details of the incident and Government's reaction thereto ;

(b) whether Government propose to appoint a high level committee in order to determine reasons for the clash and fix responsibility for the unholy incident ; and

(c) if not, how do Government propose to deal with the incident ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir. According to available information, a clash took place between detachments of CRP and Assam Police Battalion on 16.2.1983 at Goalpara in which 4 CRP personnel and one Rajasthan Armed Constabulary personnel were killed.

(b) A court of inquiry is being held by CRP.

(c) Steps have been taken to isolate the incident.

Setting up of Industries in Nepal

7320. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government of Nepal invited Indian entrepreneurs and industrialists to invest in industries in Nepal ;

(b) if so, what is the precise potential for investment by Industrialists in Nepal, indicating the nature and class of industries ; and

(c) the steps taken or being taken by Government to encourage and aid investments by Indian industrialists in Nepal ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) An official level industrial delegation from Nepal visited India in September 1982. Whilst explaining the policies of Government of Nepal for foreign investment, it welcomed investment by Indian entrepreneurs.

It is for the individual enterprises to take initiative in investing in any country, in keeping with the policies of the Government of India guiding the setting up of joint ventures abroad.

Rise in industrial production to achieve Sixth Plan target

7322. **SHRI CHITTA BASU :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether to achieve the Sixth Plan target, industrial production in the next two years would have to be raised by 11% to 12% annually during the remaining period of the plan ;

(b) if so, whether adequate steps have so far been taken to ensure that growth rate ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) The annual rate of growth of industrial production in the next two years of the Plan required for achieving the Sixth Plan target can be worked out after the growth rate for the whole year 1982-83 becomes available.

(b) and (c) Since 1980, Government have taken several important measures to improve industrial production. These include :

1. Provision for automatic growth at the rate of 5 per cent per annum subject to a maximum of 25 per cent over a period of 5 years,

2. Recognition of excess capacity over the licenced/registered capacity in industries of basic and critical importance as also those of export potential.
3. Permitting capacities on the basis of the best production achieved by the units with due protection to small scale sector, etc.
4. De-licensing of schemes for exploitation of alternate sources of energy.
5. Special attention to the development of industries in 'No Industry Districts' and notified backward areas.
6. Creation of a special cell in the Secretariat for Industrial Approvals (Department of Industrial Development) to receive and process industrial investment and licence applications from non-resident Indians.
7. Review of investment policies in order to provide a positive production orientation to the industrial economy is a continuous exercise.

In addition, the Government has taken various steps to ease the industrial situation and to increase the capacity utilisation in various industries. These include :

8. Making sustained effort to improve the performance of the key infrastructural sectors viz., coal mining, Railway transport, port facility and power generation.
9. Announcement of liberalisation of credit policy by the RBI in addition to the earlier announced measures like reduction in cash reserve ratio for banks and provision of greater credit to those sectors of industry where difficulties were being felt.
10. Placing considerable stress on the improvement in the performance of public enterprises with particular reference to improving the efficiency, capacity utilisation and generation of internal resources.
11. Strengthening the machinery for monitoring and improving performance of public enterprises in accordance with the emphasis laid on the revised 20-Point Programme.

12. Effecting reduction in the ceiling rate of interest from 19.5 per cent to 18 per cent.
13. Providing an outlay of Rs. 6469.45 crores in the Annual Plan 1983-84 for the large and medium industries and mineral projects in the central sector (including coal and petroleum,) representing an increase of about 25 per cent over the previous year's outlay.
14. The Union Budget for 1983-84 contains certain proposals aimed to encourage higher production.

Sixth Plan targets in Agricultural and Industrial Sectors

7323. DR. KRUPASINDHU BHOI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

- (a) whether despite a setback due to drought and floods, there has been a steady improvement in the infrastructure sectors of energy and transport and some progress in the main agricultural and industrial sectors ;
- (b) if so, the details thereof, State-wise ;
- (c) the steps taken to ensure that Sixth

Plan targets are achieved in the above fields and the efforts being made in this direction with the progress so far ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to make maximum use of the existing potential and to create additional potential in these fields and how far these will go to meet our requirements ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) and (b) The progress achieved in the first two years of the Sixth Five Year Plan, and that anticipated in 1982-83, in agricultural and industrial growth and in the performance of infrastructure sectors like energy and railway transport is given in the attached statement.

Details of outlays and performance under all heads of development are contained in the Annual Plans which are tabled in both the Houses of Parliament every year.

(c) and (d) Regular monitoring, of the infrastructure sectors of the economy as also implementation of the Sixth Plan, is being undertaken. In the remaining two years of the Plan also such regular monitoring will continue, both for creation of potential and for achievement of Plan targets.

STATEMENT

PROGRESS OF PLAN PERFORMANCE DURING	1980-81 AND 1982-83		
	1980-81	1981-82	1982-83 (Estimated)
1. Percentage of Agricultural Growth (over previous year)	15.3	5.5	NA
2. Percentage of Industrial Growth (over previous year)	4.0	8.6	4.5
3. ENERGY			
(a) Power (generation billion KWH)	119.23	130.93	193.47
(b) Coal (Mill. Tonnes)	113.96	124.90	129.130
(c) Petroleum Crude (Mill. tonnes)	10.5	16.2	21.4*
4. Railway Freight Transport			
(a) Revenue earning originating (mill. tonnes)	195.9	221.2*	227
(b) Net tonne kilo-metres (Billions)	147.6	164.2	165.5

*Provisional.

Complaints against Para Military Forces

7324. DR. KRUPASINDHU BHOI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

- (a) whether there have been serious

complaints about the role of Provincial Armed Constabulary and other para-military forces during the riots and other duties performed by them ;

(b) if so, the nature of complaints and the steps taken or proposed to be taken to

look into them pragmatically ; and

(c) the steps envisaged to ensure that they play their role with a clean record and in a befitting manner and there is no high-handedness on their part in such matters ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) No serious complaints about the role of BSF and CRPF have come to the notice of Government. Complaints against some State Constabularies have been received and they have been brought to the notice of the State Governments.

(c) In a letter dated the 18th January, 1983, addressed to all Chief Ministers, the Union Home Ministers had stressed the need for re-structuring the composition of the armed constabulary to make it broadly representative of the cross-section of the society and also to take a fresh look at the training programmes so that members of police force develop the proper attitude to deal with sensitive situations particularly in the context of communal disturbances.

Incentives for Industrial workers

7325. SHRI N.E. HORO : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce any community or group incentives for industrial workers and labourers to arouse them to work hard and step up the production industries during the current productivity year ; and

(b) if so, the details regarding the programme and the nature of such incentives as have been favoured by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) No, Sir : it is for each individual industrial unit to work out incentive schemes.

(b) Does not arise.

Growth Target in Sixth Plan Period

7326. SHRI A.C. DAS : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) what was the aggregate growth target set for the Sixth Plan ;

(b) whether it is a fact that due to drought, flood and other calamities which prevailed in the existing plan period, the growth rate has been severely hit ; and

(c) if so, what steps Government propose to do to meet the growth target in the current plan period ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) The aggregate growth target set for the Sixth Plan is 5.2 per cent per annum.

(b) As per the latest Quick Estimates, the national income over the first two years of the Sixth Plan has increased, in real terms, by 6.6 per cent per annum. For 1982-83 a firm estimate of growth rate is not yet available. However, the latest Economic Survey has estimated the real increase at 2 per cent for this year. Even taking this growth rate for 1982-83, the average annual growth rate at the aggregate level, despite the set backs due to drought, floods and other calamities, work out to about 5 per cent during the three years of the Sixth Plan.

(c) Every effort will be made to maintain an optimum growth rate in the remaining years of the Plan.

Power equipment manufacturing units

7327. SHRI A.C. DAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of industries manufacturing power equipment ;

(b) the names of those power equipment manufacturing units ;

(c) the places of their location ;

(d) whether guidelines have been sent to those industries to manufacture high standard power equipment ; and

(e) the details of their production performance in the last two years ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a), (b), (c) and (e) The information pertaining to present power equipment manufacturers in the country is contained in the statement attached.

(d) While considering the applications materials and components, care is taken to for industrial licence and particulars for see that quality product would be manufac- import of know-how equipment, raw tured with proven technology.

STATEMENT

Sl. No.	NAME OF THE FIRM	A/c UNIT	PRODUCTION	
	MESSRS		1981	1982
1.	Bharat Heavy Electricals Ltd., (Bhopal) (Hardwar) and (Hyderabad).	Rs. lakhs	10,888	13,101
2.	Kerala Electrical & Allied Engg. Co. Ltd., Mamala, Cochin-682 305.	KVA	5,300	7,000
3.	Voltas Ltd., 19, J.N. Heredia Marg. Ballard Estate, Bombay-400 038.	KVA	6,000	810
4.	Crompton Greaves Ltd., 1, Dr. V.B. Gandhi Marg, Bombay-400 023.	KVA	7,973	13,897
5.	Kirloskar Electric Co., Post Box No. 5555, Malleswaram West, Bangalore S60056	KVA	4,42,046	3,37,424
6.	Jyoti Ltd., Industrial Area P.O. Chemical Industries, Vadodara-390 303.	KVA	1,26,630	1,21,120

Self-Sufficiency in Electronic Goods

7328. SHRI A.C. DAS : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of private and public sector companies which are dealing with the production of various electronic goods in the country ;

(b) whether we have become self-sufficient in electronic goods ;

(c) whether the export of electronic goods has increased in the last few years ; and

(d) if not, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) There are over 2000 units spread over the large scale, small scale and cottage scale sectors which produce electronic items. However, the names of as many of these units as possible will be collected and placed on the Table of the House.

(b) While most electronic goods are manufactured in the country, special types of equipment and components are imported.

Continuous efforts are being made to increase the range and quantum of locally produced electronic goods. However, in this rapidly developing industry, with applications covering diverse areas in the economy, it may not be possible to be entirely self-sufficient.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Argentina's Offer for Collaboration in Study of Antarctica

7329. SHRI R.P. GAEKWAD :
SHRI R.P. DAS

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Argentina has invited India to collaborate and expressed its willingness in the study of Antarctica and its resources ;

(b) whether any programme for exploration of the ice continent jointly has been prepared ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Argentina has expressed willingness to provide support to India in establishing an air link with Dakshin Gangotri, the Indian Station in Antarctica. No offer regarding study of resources has been made.

(b) and (c) Does not arise.

Complaints regarding Non-availability of cement

7330. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints for non-availability of cement from citizens and corporate bodies from various States, from the cement quota allotted to them ; and

(b) if so, what further measures have been taken by Government in this regard to make it available to public ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) A few complaints/requests from corporate bodies and individuals in regard to inadequate availability of cement from the State Governments/Union Territories Administrations were received. These were forwarded to the respective Governments for necessary action. Within the overall availability of cement, wherever possible, additional allocations were made available to the State Governments/Union Territories Administrations.

Technological gap for industrial growth

7331. SHRI RASHEED MASOOD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment with regard to the technological gap for the industrial growth in the country to keep pace with the industrial growth and advanced technology in the developing/developed countries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by Government to bridge the technological gap either by importing or developing the sophisticated technology within the country to make a breakthrough in the technological advancement for rapid economic growth ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (c) The Technology Policy Statement of January, 1983 spells out the policy with regard to import of technology. An illustrative list of industries where no import of technology would normally be permitted has been published in the Guidelines for Industries. Government's policy provides for taking full advantage of technological developments in the rest of the world. Encouragement is also given to industrial units for setting up in-house R&D units with a view to absorbing, assimilating and adapting imported technology, as well as development of advanced technology.

Closure of Kalinga Tubes

7332. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the closure of Kalinga Tubes, Chanduor in Orissa ;

(b) if so, the main factors which led to the closure of Kalinga Tubes factory in Orissa : and

(c) the steps proposed to be taken to start that factory again ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA): (a) Yes, Sir.

(b) The main reasons are stated to be very old plant and equipment, inadequate quality of products, paucity of working capital funds and large accumulated losses, leading to its becoming an economically and commercially unviable unit.

(c) The above unit has since been amalgamated with M/s. Indian Metals & Ferro Alloy Limited who have initiated action for its revival and rehabilitation.

Involvement of Officers of R.R.L.C. Jorhat and I.C.A.R. Delhi in Communal Riots in Assam

7333. SHRI T.S. NEGI :

SHRI ASHFAQ HUSSAIN :

SHRI K. RAMAMURTHY :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that police have arrested top 14 officials of Regional Research Laboratory Complex Jorhat and charged them with inciting communal trouble and waging war against the State ;

(b) if so, the full details thereof ; and

(c) whether there is also involvement of senior officers of ICAR Head-quarters at New Delhi who had recently visited Jorhat etc. in Assam for helping in conducting State election in Assam and if so, full details thereof and action taken/proposed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) According to the information so far available from the State Government, the following personnel of the Regional Research Laboratory, Jorhat, were arrested by the Police in connection with case FIR No. 383/83 under Section 120B/153A IPC of Jorhat PS.

1. Dr. J.N. Barua, Director
2. Shri Dinesh Goswami, Asstt, Director
3. Shri Rebakana Saikia, Electrical Engineer
4. Shri Promode Chandra Tamuli, Scientist
5. Shri Dibeshwar Bora, Fitter
6. Shri. Sadanand Bora, Fitter
7. Shri Gauri Prasad Barua, Sr. Documentation Assistant.
8. Shri Chandra Kanta Pathak, Helper
9. Shri Chandra Saikia
10. Shri Manoj Saikia
11. Shri Manik Bora
12. Shri Kunda Hazarika

(c) Government has no information to this effect.

Setting up of Paper Cement Factories in Assam

7335. SHRI BHUBANESWAR BHU-
YAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is any plan to set up new Paper/Cement Industries in Assam with a view to bring this border State at par with other industrially developed States of India ;

(b) if so, the proposed factories and industries and the names of the places, and whether they are under public sector or under the private sector or under both, alongwith the availability of raw materials like bamboos and lime stone and their allied products ; and

(c) the expected dates by which each of the proposed factories and industries would be set up and start production of paper and cement ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) :

(a) to (c) Hindustan Paper Corporation Ltd., a public undertaking, is implementing two projects for manufacture of paper in Nowgong and Cachar Districts of Assam. They are scheduled for mechanical completion in 1984.

Registration has been granted in March, 1983 by DGTD to a private sector unit for setting up a mini-cement plant at Garampani in Tehsil and District North Cachar in the State of Assam. It is too early to indicate the date by which the unit would go into production.

Financial approval has also been granted in February, 1983 to the North Eastern Council for setting up a mini-cement plant at Umrangso (Garampani), which has a gestation period of 30 months.

Availability of requisite raw materials is taken into account before approval is granted for setting up such units.

लेजर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र

7336. श्री चतुर्भुज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ उचित स्थानों में लेजर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए मार्ग निर्देश तैयार किये गए हैं; और

(ख) यदि हां तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र खोले जाएंगे और ये केन्द्र कब तक कार्य शुरू करेंगे ?

विज्ञान, और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी. पाटिल) (क) और (ख) संलयन, उच्च ऊर्जा वाले प्रगत स्वरूप, लेसर तथा इनसे सम्बन्ध अन्य टेक्नालाजियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास-कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर में एक नया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के बारे में प्रारंभिक कार्य चालू योजना अवधि में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

**Solar Atomic Energy Research Centre
near Indore**

7337. SHRI KESHAO RAO PARDHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up Asia's first and world's third Solar Atomic Energy Research Centre near Indore in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the estimated cost of the Centre, the number of years to be taken in its completion ; and the ratio of expenditure to be borne by the Central and State Government ; and

(c) whether Central Government will bear entire expenditure ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

भारत में प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए निगुंट सम्मेलन का निर्णय

7338. श्री डूंगर सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगुंट देशों के हाल में हुए सम्मेलन में भारत में निगुंट देशों को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने के निर्णय पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस उद्देश्य के निगुंट सम्मेलन निधि से कितने व्यय की राशि मंजूर की गई है और उसमें भारत का अंशदान कितना होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (शिवराज बी० पाटिल): (क) गुट निरपेक्ष देशों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव गुट-निरपेक्ष आन्दोलन (एन० ए० एम०) के विचाराधीन है। भारत सरकार ने मेजबान सुविधाओं को प्रदान करने की पेशकश की है। इन केन्द्र की संविधियों के मसौदे को गुट निरपेक्ष देशों के बीच परिचालित कर दिया गया है। सदस्य देशों द्वारा इन संविधियों को स्वीकार किए जाने के पश्चात् यह केन्द्र अस्तित्व में आ जाएगा।

(ख) अभी तक केन्द्र के खर्चों को पूरा करने के लिए किसी कोष का सृजन नहीं किया गया है संविधियों के अनुमोदित किये जाने के पश्चात् भारतीय योगदान की सीमासहित सदस्य देशों से निधीयन की विधि के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

High Power Committee set up by Development Council for Textile Machinery Industry

7339. PROF. NARAIN CHAND PRASHAR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the High Power Committee (1980-82) set up by the Development Council for Textile Machinery Industry has made certain important recommendations for the promotion of textile industry in India ;

(b) if so, the main recommendations made by the Committee ;

(c) the action/decision taken by Government on the recommendations ; and

(d) if not, the likely date by which a decision would be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) Yes Sir.

(b) The principal recommendations of the Committee are as under :—

- (i) Establishment of a modernisation reserve fund out of pretax profits or out of excise duty paid by the industry. Withdrawals from the fund will be permitted only for purchase of new machinery for modernisation.
- (ii) Soft loan scheme should be continued at the reduced rate of interest and its scope be enlarged to cover other textile sectors like woollen industry and artsilk industry.
- (iii) The Textile Machinery Industry should be treated as a priority industry for purposes of allotment of indigenous raw-materials like steel, pig iron, coke etc.

(c) and (d) The recommendations of this Committee were considered by the Development Council for Textile Machinery Industry in its meeting held on 25th November, 1982 and discussed in detail. The Council decided to set up a Standing Committee headed by the Textile Commissioner to look into the various aspects brought out in the Report and make appropriate suggestions to Government for implementation by different organisations/Departments.

Sittings held by sub committee of National Council of JCM

7340. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) is it a fact that a sub-committee of National Council of JCM was constituted about 3-4-5 years back to look into the matter of granting recognition to Federations and framing rules for the same ; and

(b) if so, how many sittings of the sub-committee have been held till date and what is the progress of work done by them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) A sub-committee of the National Council of JCM was constituted in 1979 *inter-alia* to go into the guidelines for the purpose of recognition of Unions/federations/associations.

(b) Informal discussions with some of the members of the Standing Committee of the staff side of the National Council have taken place from time to time. The staff side has been requested a number of times to furnish their formulations on the subject for consideration in the meetings. Since they were not received the meetings had to wait. A meeting of the Committee had been held on 18th March, 1983. It had been decided to constitute a small group from amongst committee members belonging to both the staff side and the official side to draft the said guidelines/recognition Rules.

— — —

12.00 Hrs.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*.
(*Interruption.*)

PROF. K.K. TEWARY (Buxer) : I have given notice of breach of privilege under Rule 222 against Prof Madhu Dandavate. That motion is still pending before you. In the meanwhile he held a Press Conference and got wide publicity in the matter. The matter is very sensitive.

MR. SPEAKER : It is under consideration.

PROF. K. K. TEWARY : It is a very important issue, Sir.

MR. SPEAKER : I will consider it.

PROF. K.K. TEWARY : He has misled the House.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, 43 children are reported to have disappeared from the Delhi's Children's Home. You might have seen the press reports. Education and Social Welfare Minister should make a statement.

MR. SPEAKER: मेट्रोपोलिटन काउन्सिल करेगी ।

They will take it up.

PROF. K.K. TEWARY : Normalcy is returning to Assam. This will create further complications in Assam. Therefore, this matter is very important...

(Interruptions)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : You see how the Children's Home is functioning.

MR. SPEAKER : There is the elected body. They are responsible people. The Metropolitan Council is a duly elected body. Their representatives have been duly elected by the people of Delhi. They are men of integrity.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कल प्रो० मधुदंडवते जी ने प्रिविलेज मोशन दिया है। हम लोगों ने टेप को सुना है। यह भयंकर चीज है।

... (व्यवधान) ...

MR. SPEAKER : Not allowed. ... You cannot say anything now. It is under my consideration.

श्री रामविलास पासवान : क्या हुआ उस बात का ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचाराधीन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के कर्मचारा और डाक्टर्स तथा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

MR. SPEAKER : Not allowed.

SHRI HARIKESH BAHADUR : 18 crores of people are suffering. And you cannot allow it.

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। 377 दीजिए या और कुछ दीजिए। मैंने आपको डिसएलाउ नहीं किया है। तरीके से करिए।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : दिल्ली की बात हो गई है। मैं यह कह रहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों को जो अपहृत किया गया था, उनका आज तक नहीं पता चला है।

MR. SPEAKER : Not allowed. It is a State subject.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgorh) : I have given notice of a motion about the reported robbery of the armoury at Ganganagar.

अध्यक्ष महोदय : आपके आने से पहले सुबह तय कर दिया।

श्री राम अवतार शास्त्री (पटना) : पटना शहर में पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लोग रास्ता रोक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पानी नहीं मिलेगा, तो यही होगा। क्या करें।

श्री राम विलास पासवान : दिल्ली में भी यही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में बन्दोबस्त हो रहा है।

... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाउ कर दिया। 377 कर दिया और मैं क्या कर सकता हूँ।

... (व्यवधान) ...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY Bombay North East : I want to know what you have decided. In North Bihar sugar cane producers are suffering very much. Have you decided anything ?

MR. SPEAKER : It will be decided by the Business Advisory Committee to-day.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भिलावाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर चावल खरीदने में जो एफ सी आई के अधिकारी लगे हैं, उनकी मिलीभगत और फूड एंड सिविल सप्लाय की मिलीभगत से 80 हजार टन चावल रिजर्वेटेड चावल में शामिल कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : फूड एंड सिविल सप्लाय या एग्रीकल्चर डिमाण्ड्स आ रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : फूड एंड सिविल सप्लाय या एग्रीकल्चर डिमाण्ड्स आ रही है।

... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : नाँट एलाउड ।

... (व्यवधान) ...

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) :
उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्लिंग एटेंशन है और कल परसों डिसकशन होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शोर करने से फायदा क्या है । मिनिस्टरी आ रही है डिसकशन होगा । (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) :
अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना में पिछले पचास घंटों से पानी और बिजली नहीं है ।...

अध्यक्ष महोदय : जो बात शास्त्री जी ने कही है, वही आप कह रही हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : वहां कूओं पर लाखों की भीड़ लगी हुई है । मैं जानती हूं कि भारत सरकार से इस विषय का सम्बन्ध नहीं है, परंतु यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री चतुर्भुज (शालावाड़) : अध्यक्ष महोदय, युवा कांग्रेस (आई) की रैली में आने वाले कार्यकर्ताओं ने अनेक रेलवे स्टेशनों पर खोमचे, टी-स्टाल, और दुकानें लूट लीं । मैंने इस सम्बन्ध में 377 भी दिया है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आँवला) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने बदायूं तथा बरेली जिलों के देहातों से आने वाले दूध पर पाबन्दी लगा दी है, जिस से दूध पड़ा सड़ रहा है । यदि दूध को बाजारों में नहीं लाने दिया जायेगा तो इस से हजारों लोगों का नुकसान होगा । इस पाबन्दी को समाप्त किया जाना चाहिये । ... (व्यवधान) ...

श्री मंगल राम प्रेमी : गाँव के अन्दर 18 जानवरों को जहर दे कर मार दिया गया है तथा आप की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर

पा रही है ।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय यह स्टेट का सब्जैक्ट है ।

श्री मंगल राम प्रेमी : स्टेट का सब्जैक्ट नहीं है । हरिजनों के जानवरों को मारा गया है, 18 जानवरों को मार कर 18 हजार रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई है...

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में से स्टेट को भगा नहीं सकता ।

श्री मंगल राम प्रेमी आप इसे स्टेट सब्जैक्ट बतला रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : मेरा सब्जैक्ट नहीं बतला रहा हूं, स्टेट का सब्जैक्ट बतला रहा हूं ।

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं इस की रिपोर्ट और फोटो सदन के टेबिल पर रख रहा हूं ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Pauskura) : The Children's Home from which the children were missing is run by the Department of Social Welfare ; it should be the concern of the Metropolitan Council...

(Interruptions).

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं जो कहने जा रहा हूं, उस का जवाब भी मुझे पता है, आप यही दोगे...

अध्यक्ष महोदय : ये अंतर्द्वार हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : हां इस सवाल के लिये मैं अंतर्द्वार हूं । गन्ने के बारे में आप कहोगे कि कमेटी में बात हो गई है । लेकिन गुप्त बात को मैं मानने वाला नहीं हूं । गन्ना सड़ रहा हो, जल रहा हो, गन्ने की कीमत मिल न रही हो और आप के नेता...

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी, पहले आप मेरी बात सुनिये । मैं यह कहना चाहता हूं—आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिये बनाई है ?

श्री मनीराम बागड़ी : इस लिये कि सलाह-मशविरा कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : उस में सारी पार्टियों के, सारे ग्रुप्स के प्रतिनिधि होते हैं । मैंने यहां भी और वहां भी, यहां हाउस में जिस मामले

में सारे हाउस का कन्सेन्सस होता है उस का आदर करता हूँ और उसी के हिसाब से काम करता हूँ, उसी तरह से चूँकि सारे हाउस में सारी बात नहीं हो सकती है, इस लिये आप ने एक छोटी कमेटी बनाई है। चूँकि 70 करोड़ जनता हाउस में इकट्ठी नहीं हो सकती, इस लिये उस ने आप 542 सदस्यों को चुन कर यहां भेजा है। चूँकि आप 542 मेम्बर्स इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस लिये आप ने 10 आदमियों की एक कमेटी मेरे साथ बना दी है, उस की राय के अनुसार मैं करता हूँ।

मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आप के किसी सब्जैक्ट को दवाऊ या डिस्कशन न कराऊं। जो वह कहती है उसी हिसाब से करता हूँ। उन्होंने वहां बैठ कर सभी की सलाह से, जिस में सब के नुमाइन्दे हैं, आप का नुमाइन्दा भी वहां है, फैसला किया है। अब मैं आप से हाथ जोड़ कर बिनती करता हूँ—आप मेरे ऊपर दूसरा कानून क्यों लागू करते हैं, जब कि मैं आप के ही बनाये हुए कानून का पालन करता हूँ। अभी एक बात चीत चल रही है, परसों एग्रीकल्चर की डिमाण्ड आयेगी उस में आप बहस करेंगे, सारी बातें होंगी। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जब एग्रीकल्चर की डिमाण्ड आयेगी, उसको न आप रोक सकते हैं और न यह कमेटी रोक सकती है। यह हमारे ऊपर कोई अहसान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा है कि मैं कोई अहसान कर रहा हूँ ?

श्री मनीराम बागड़ी : इस वक्त विशेष बात यह है कि गन्ने के दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : गम्भीरता को समझ कर ही मैंने मीटिंग बुलाई थी।

श्री मनीराम बागड़ी : तब फिर क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री ऐलान करेगा। मैंने करना होता तो कभी का कर दिया होता।

श्री मनीराम बागड़ी : आप नहीं कर सकते हैं तो मंत्री को कहें।

अध्यक्ष महोदय : यही तो कर रहा हूँ। वह परसों ऐलान करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हाथ पर सरसों नहीं जमाई जा सकती है। आप के लिये कोई और कानून नहीं हो सकता है। अगर हाउस आप के लिये कोई नया कानून बनाना चाहे तो बना ले।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात सही नहीं है। मैं कोई नया एम० पी० नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप के कहने से करता हूँ, फिर भी आप नहीं करने देते हैं। किस का कहना मानूँ ? आप का कहना मानूँ या सारे हाउस का कहना मानूँ ?

श्री मनीराम बागड़ी : हाउस का मानो। लेकिन फर्ज करो किसान मर रहा हो, तो फिर यह हाउस किस बात का है...

अध्यक्ष महोदय : हाउस कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं ? यह रनिंग कमेंटरी ठीक नहीं है। I do not agree with you. मैं आप से सहमत नहीं हूँ

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मैं गन्ना किसानों के लिए प्रोटैस्ट करता हूँ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप से साफ कह देना चाहता हूँ कि आप देश के किसानों के परिसंघ के अध्यक्ष भी हैं, आप किसान भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं करता हूँ, इसीलिए करता हूँ। यहां 70 प्रतिशत किसान बैठे हैं। वे भी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आप क्या कर रहे हैं ? गन्ना जल रहा है।

(व्यवधान)

12.10 Hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Explosive Rules, 1983, Review on and Annual Report of Bharat Heavy Electricals Ltd. New Delhi for 1981-82 and a statement for delay.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : On behalf of Shri Narayan Datt Tiwari, I beg to lay on the Table.

(1) A copy of the Explosives Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 248 (E) in Gazette of India dated the 2nd March, 1983 under sub-section (8) of section 18 of the Indian Explosives Act, 1884. [Placed in Library See No. LT 6360/83]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English version) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :

(i) A statement regarding Review by the Government on the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 1981-82.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 1981-82 along with Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library See. No. LT 6361/83].

**Detailed Demands for grants of Department of
[Atomic Energy for 1983-84]**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) :

I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of Department of Atomic Energy for 1983-84. [Placed in Library See No. LT-6362/83]

12.11 Hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

**HUNDRED THIRTY-THIRD AND
HUNDRED THIRTY-FIFTH
REPORTS**

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee :—

(1) Hundred and Thirty-third Report on Paragraphs 26 and 32 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1980-81 Union Government (Posts & Telegraphs) on Local Printing of Inland Letter Cards and construction of staff quarters at Annanagar respectively relating to the Ministry of Communications (P&T Board).

(2) Hundred and Thirty-fifth Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Eighty-second Report on Badarpur Thermal Power Project-Stage II relating to the Ministry of Energy (Department of Power).

**COMMITTEE ON PUBLIC
UNDERTAKINGS**

Sixty-sixth Report

SHRI MADHUSUDAN VAIRALE (Akola) : I beg to present the Sixty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fiftieth Report on Engineering Projects (India) Ltd.

12.12 Hrs.

**COMMITTEE ON THE WELFARE OF
SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES**

Thirtieth Report

SHRI A.C. DAS (Jaipur) : I beg to present the Thirtieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Action Taken by Government on the recommendations contained in their

Twenty-first Report on the Ministry of Home Affairs and Planning Commission Benefits for Scheduled Castes and Schedule Tribes in Fifth and Sixth Five Year Plans.

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है ? आप सब को क्या हो रहा है ? श्री राम बिलास पासवान ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी कमेटी आपका काम करने वाली है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जब नहीं मानते तो मैं आपकी क्यों मानू ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिये । गन्ने की परचेज बंद हो गयी है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आदमियों को क्यों नहीं बताते है ? यह जिम्मेदारी मेरी है क्या ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)**

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Sir, before you speak, I would request you to make cotton pads available to us, to check these take-off sounds... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि सबकी इसमें सहमति है । इसके पहले 6 बार डिसकवान हो चुका है । कल सातवीं दफा और आज आठवीं दफा यहां पर यह बात उठाई गई है । दोनों मंत्री यहाँ हर मौजूद हैं । जिनके पास मिलें हैं वे भी मौजूद हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी मौजूद हैं । फाइनांस मिनिस्टर की कमी बाकी है । लेकिन हर काम व्यवस्था से होता है । घीगामस्ती से कोई काम नहीं होगा । जोर

से चिल्लाने से कोई काम नहीं होगा । इस तरह से सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है । आपके कथनानुसार जो भी हाउस कहता है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ । कमेटी के हिसाब से जो भी डिसकशन यहां पर आप कराना चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ । इसके बावजूद आप इस तरह से करेंगे तो ये लोग भी आपकी बात कैसे मानेंगे । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई गई थी कि यह बहुत जरूरी काम है इसलिए चर्चा होनी चाहिए । किसानों का गन्ना मिलों में जाता रहे, मिलें चलती रहें किसानों को उचित कीमत मिलती रहे और गन्ना खराब न हो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है । इसके लिए उनको दो दिन का समय दिया गया है कि वे आपस में सलाह मशविरा कर लें । पार्लियामेन्टी अफेयर्स मिनिस्टर ने भी उनसे बात की है और वे भी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं । दो दिन में डिमांड्स आएंगी । जो भी आप आश्वासन लेना चाहें ले सकेंगे । अब मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी जगह बैठकर क्यों नहीं सोचते । मेरी जगह बैठकर सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ । क्या नहीं किया है मैंने ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सारी बातें उस वक्त आ जाएंगी । जगपाल सिंह जी आप आए नहीं थे, उससे पहले चर्चा हुई है ।

श्री जगपाल सिंह : जब कस्टोडियन मिलें 21.50 नहीं देंगी तो प्राइवेट मिलों को आप कैसे मजबूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं । आपके आने से पहले यह सब बात हो चुकी है । चिल्लाने से क्या फायदा है ?

(व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) :
स्पेशल डिसकशन होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : बाकी अगर कोई चीज रह जाएगी तो आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहां हूं और सदन भी यहां है । मैंने कब इन्कार किया है । सवाल यह है कि आप व्यवस्था से काम तो चलने नहीं देते । हाउस इस बात से एकमत है ।

श्री जगपाल सिंह : फिर क्यों नहीं हो रहा है ? (व्यवधान) राव बीरेन्द्र सिंह नहीं चाहते । प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कोठी पर यह तय किया है कि कस्टोडियन मिलें भी 21.50 रुपए देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों इतना तेज बोलते हैं ।

श्री जगपाल सिंह : प्रधानमंत्री ने कहा है कि कस्टोडियन फैक्ट्रियां वही दाम देंगी जो प्राइवेट फैक्ट्रियां देंगी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं । सारी बात तय कर ली है फिर क्या फायदा है ।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको देखकर लोग क्या सोचते होंगे । सारी बात हो चुकी है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) :
मंत्री जी से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए । बाकी कार्यवाही वाद में होती रहेगी ।

श्री जगपाल सिंह : इससे बड़ी और क्या बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 21.50 देंगे । (व्यवधान) कस्टोडियन फैक्ट्रियां 21.50 रुपए नहीं दे रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बगैर डिस्कशन के डिस्कशन किए जा रहे हैं । परसों आ रहा है । यह सवाल आप उसमें पूछ लेना ।
(व्यवधान)

श्री कृष्ण चंद्र पांडे (खलीलाबाद) :
अध्यक्ष जी, आरिफ साहब सब कुछ जानते हैं । वित्त मन्त्री जी को भी यहां पर बुलाइए ।

इस पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए । . . .
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान बोलिए ।

. . . (व्यवधान)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : I want to make a suggestion. When the ruling party members and the opposition parties members agree, then it should be announced immediately today in the House,

श्री जगपाल सिंह : हम आपका समर्थन करते हैं । लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी गवर्मेन्ट की फैक्ट्रियां . . .
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

I am very much distressed.

श्री जगपाल सिंह : प्राइवेट फैक्ट्रीज के लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं । . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप काफी दिनों बाद गर्म होकर आते हैं और सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : आप इतना बोल रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे गूंगे-बहरे तो हैं नहीं ।

श्री जगपाल सिंह : यह बात आप सही कह रहे हैं कि वे इस मामले पर गूंगे, बहरे और अन्धे भी हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपने हमारे लिए धींगामस्ती शब्द का इस्तेमाल किया है । यह रिकार्ड में रहेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो मजाक की बात है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं अपना और अपनी पार्टी का कर्तव्य समझता हूं । इतना कहने के बावजूद भी यहां कोई ब्यान नहीं

दिया जाता है तो हमें अपना रोष प्रकट करने के लिए सदन से वाक-आउट करना पड़ेगा। अब मैं और मेरी पार्टी के लोग सदन से वाक-आउट कर रहे हैं।

12.23 Hrs

SHRI MANI RAM BAGRI AND SOME OTHER HON. MEMBERS THEN LEFT THE HOUSE.

श्री जगपाल सिंह : भारत सरकार ने आदेश दिया है कि गवर्मेन्ट की फैक्टरीज भी 21 रुपए 50 पैसे क्विंटल गन्ने की कीमत देगी। मेरे क्षेत्र लक्सर में जो फैक्टरी है वह 21 रुपए 50 पैसे के हिसाब से गन्ने की कीमत रसीद पर नहीं डाल रही है। मैं मांग करता हूँ कि गवर्मेन्ट फैक्टरीज भी 21 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कीमत दें नहीं तो मैं भी सदन से वाक-आउट करता हूँ।

Shri Jagpal Singh and some other hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY SPEAKERS IN THE CHAIR

12.24 Hrs.

CALLING ATTENTION MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of drought, famine and reported starvation deaths in the country.

श्री रामबिलास पासवान (हाजीपुर) : मैं अबिलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

“देश के विभिन्न भागों में सूखा, अकाल और भुखमरी से हुई कथित मौतों से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में किये गये प्रभावी उपाय।”

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Sir,

Hon'ble Members will recall the statement made by me on 18th March, 1983 in response to the Calling Attention Motion moved by Shri Narain Choubey and other members of this House regarding drought conditions in many States. I have already informed the House that the Central Government had sanctioned a record level of assistance to the States during 1982-83 to meet the drought situation. Altogether ceilings of expenditure upto Rs. 409.06 crores were communicated to 12 States and one Union Territory to be utilised by 31.3.1983. Of this assistance, Rs. 207.49 crores were earmarked for employment generation. Works opened with this assistance would have generated enough employment and purchasing power in the hands of the people. A total quantity of 1.13 lakh tonnes of foodgrains have been allotted to States to be utilised for payment of part wages to labour in kind at the rate of 1 kg. of foodgrain per man day. Funds have also been sanctioned under the head 'gratuitous relief' and 'nutritional programme' to sustain the old, the infirm and the indigent, as well as pre-school going children and expectant mothers.

2. Since I last informed the House about the relief measures taken by the Government to meet the drought situation. Central Teams have completed their visits to Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal and Bihar. Reports of the Central Teams in respect of Tamil Nadu, and Karnataka have been considered by the High Level Committee and they are at an advanced stage of processing for release of sanctions. In the meantime, an amount of Rs. 15 crore each for both these States was released last month by way of advance 'on-account' for continuing relief operations. Reports of the Central Teams which visited Bihar and West Bengal for the second and third time respectively have been received and placed before the High Level Committee. Recommendations of the Inter-Ministerial Group in respect of Pondicherry and Madhya Pradesh have also been submitted to the High Level Committee. We have also received a supplementary memorandum on drought from Kerala. A memorandum was

received from Mizoram, where unfavourable conditions have been created by heavy rainfall in the months of February and March last. The case of Mizoram has been considered by the Inter-Ministerial Group on 6th April. Sanction is soon expected to issue from Finance Ministry. A Central Team shall be going to Kerala soon. A request has also been received from Rajasthan to depute a team for assessing its requirements for the period April-September, 1983. Their request is to be considered in a meeting of the inter-Ministerial Group on 20.4.1983. Meanwhile, an amount of Rs. 11 crore has been sanctioned on *ad-hoc* basis for continuing relief measures during the current year. A second memorandum has also been received from the Government of Andhra Pradesh on 7th of this month which is under processing.

3. Providing relief to the people is a continuing exercise and as explained earlier, requests of the States for assistance during the current financial year are also under active consideration. Sanctions to the extent of Rs. 50.38 crores have already been issued to five States for the current year, 1983-84. As the new financial year has just begun, the entire margin money as well as the budgetary provisions under different sectors are available to the States for continuing the relief measures. Central assistance to supplement their efforts in this behalf would be sanctioned as the cases are finalised.

4. The position of drinking water in Madras City is reported to be serious. The city's water supply is from the lake situated in the Red Hills about 15kms. north of Madras. The Cholavaram Tank and Poondi reservoir are the feeder sources to this lake. Because of scanty rainfall in the catchment of these reservoirs, the inflow in the lake has been very poor. Fortunately, the ground water supply is available and the State Government are trying to tap this source to the maximum extent. The supply position is being augmented through tubewells, handpumps and digging of open wells. Areas not served by existing pipelines and wells are being supplied water through lorries and railway wagons. Our Prime Minister visited Tamil Nadu on 28th March and saw some relief works in the interior of North Arcot district. She also

toured Madras city where she was apprised of the drinking water problem. She announced an immediate sanction of Rs. 10 crores for the State by way of 'on-account' advance, Rs. 5 crores had been sanctioned earlier. She also sanctioned Rs. 10 lakhs from the Prime Minister's National Relief Fund.

5. Government's attention was drawn to the reports of starvation deaths which appeared in some newspapers. Upon enquiries made from the State Governments, it has been confirmed by them that no starvation deaths have taken place anywhere. Some Hon'ble Members of the House mentioned about famine conditions in Western Rajasthan accordingly a team of officers was deputed to visit the State. This team visited Jodhpur, Pali, Jaisalmer and Barmer districts and also hold discussions with the State officials. They also called on the Chief Minister. The State Government assured them that foodgrains are available at reasonable price.

6. Government have adequate stocks of foodgrains in the national buffer and I am sure Hon'ble Members will commend the Government's decision to replenish the buffer stocks through imports contracted some time back. Government are making adequate allocations of foodgrains to the States for public distribution system. In the month of February 12.79 lakh tonnes, in March 13.28 lakh tonnes and for the current month 13.93 lakh tonnes of foodgrains have been allotted to the States. It would be seen that Government are alive to the situation and have been continually increasing the allotment.

7. States have been advised to enforce strict monitoring and to keep the Central Government informed about the utilisation of the Central assistance and the foodgrain allotment. They have been particularly advised to monitor the drinking water situation, cattle conservation, employment generation and nutritional status of the vulnerable groups at village level.

8. I wish to assure the House that Government are fully seized of the situation and will extend all possible assistance to the States in this hour of distress.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय,

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : बागड़ी साहब, वापिस आ गये आप ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपको समझाना भी तो है ।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अभी मंत्री जी ने 4 पेज के अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा है, यदि उसमें से कुछ निकाला जाये कि इन्होंने क्या कहा है तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : खोदा पहाड़, निकली चुहिया ।

श्री राम बिलास पासवान : यहां तो कुछ निकला ही नहीं ।

18 मार्च, 1983 का हवाला देते हुए इन्होंने 3,4 बातें मुख्य रूप से कहीं । इस सदन में जहां सबसे बड़ा “सत्यमेव जयते” लिखा हुआ है, इन्होंने स्वयं कहा है कि हमारी केन्द्रीय टीम वहां गई, वहां गई । यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है, सारा सदन और पूरा देश इस बात को जानता है कि पूरे देश में भयंकर दुर्भिक्ष है, सूखा है और इन्होंने जवाब में कहा है कि अभी तक एक आदमी की भी मृत्यु इससे नहीं हुई है ।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : हमने मरने नहीं दिया है किसी को ।

श्री राम बिलास पासवान : आपने मरने नहीं दिया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मृत्यु हो नहीं सकती, इस सरकार के होते हुए ।

श्री राम बिलास पासवान : राव साहब मैं आपको यह बतलाता हूं कि यह अकाल 1943 के अकाल से भी भयंकर है और आप कहते हैं कि एक आदमी भी नहीं मरा है । मैं कहता हूं कि इस साल के अन्त तक लाखों से ज्यादा लोग मरेंगे और हजार से ज्यादा तो मर चुके हैं । आप किस रूप में मौत चाहते हैं ? क्या आपकी कोठी पर लोग लाश लाकर रखेंगे तब आप कहेंगे कि लोग मरे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी स्टेट तमिल-नाडु में रेलवे से पानी पहुंचाया जा रहा है जो कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पानी के बगैर लोग घुट-घुट कर मर रहे हैं । यह सरकार पार्लियामेंट में गर्व से कहती है कि एक आदमी की भी मृत्यु नहीं हुई है । इसका मतलब यह है कि एक भी मृत्यु नहीं हुई है तो आपके फैमिन कोड में कहीं त्रुटि है, उसको आप बदलिये । इस सदन में आप सीधी सी बात कहिये कि देश में दुर्भिक्ष है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम मान रहे हैं ।

श्री राम बिलास पासवान : जब देश में अकाल है तो आपने कितनी जगहों को अकाल क्षेत्र घोषित किया है ? जब अकालग्रस्त क्षेत्र आप किसी को घोषित नहीं करेंगे तो फैमिन कोड कैसे लागू करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो स्टेट गवर्नमेंट करती है । हम तो एसिस्टेंट देते हैं ।

श्री राम बिलास पासवान : ज्यादा से ज्यादा स्कैरसिटी एरिया तो कहिये । मेरा एक प्रश्न था—Whenever large number of persons have died due to the starvation deaths in Santhal Pargana, Navada, Chhota Nagpur and some other districts of Bihar ?

सरकार ने जवाब किया —

“According to the information received from the Government of Bihar no starvation deaths have taken place in any part of the State. The State Government have reported that when the news of starvation deaths appeared in the local press, a thorough enquiry was made and, on verification of the news, all the reported deaths were found to be baseless.”

सरकार से पूछा गया —

“If so, the details of the persons died due to starvation deaths ?”

जवाब दिया गया —

“Does not arise.”

आगे पूछा गया —

“the schemes formulated by the State Government to meet the situation ?”

जवाब मिला —

“The Government of Bihar has reported that three quintals of foodgrains have been kept in reserve in every panchayat.”

सरकार के कथनानुसार तीन क्विंटल अर्थात् 300 किलो एक पंचायत में रखा गया है, जबकि पंचायत की पापुलेशन दस हजार के करीब होती है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्यों में 4.80 करोड़ हैक्टेयर से अधिक फसलें सूख गई हैं, 200 जिले और 27.17 करोड़ लोग प्रभावित हैं। पानी कहीं नहीं है, बिजली की कमी है। जब आधे से अधिक जनसंख्या को सूखे ने प्रभावित किया है, तब मंत्री महोदय बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि एक पंचायत में तीन क्विंटल अनाज रिजर्व रख दिया गया है ! सब लोग मर जाएंगे और तीन क्विंटल घरा रह जाएगा।

उसके बाद उन्होंने कहा है :—

“Foodgrains are being distributed to the needy and indigent persons as gratuitous relief in the affected areas up to one per cent of the population.

पचास परसेंट पापुलेशन एफेक्टिड है, लेकिन देंगे सिर्फ एक परसेंट को ! सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिन्दुस्तान की टोटल जनसंख्या 68 करोड़ में एक करोड़ लोग तो अंधे हैं, दो करोड़ को टी बी की बीमारी है, लूले-लंगड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ड्राउट सिचुएशन को मीट करने के लिए क्या व्यवस्था की है।

उन्होंने यह भी कहा है :—

“Under the National Rural Employment Programme, 14,413 schemes are in progress all over the State in which over 9 lakh agricultural labourers are employed.”

बिहार में हर एक जिले से मजदूर दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। श्री भगवात झा बाबाद बैठे हुए हैं। बिहार के कोई भी माननीय सदस्य, चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के, कह दें कि उनके जिले से मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं भाग रहे हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि 9 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए स्कीम बना दी है। श्री भगत का जिला . . .

श्री बी आर भगत (सीतामढ़ी) : मेरे जिले से एक लाख आदमी पंजाब में गए हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : वे तो हमेशा जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : 14 मार्च, 1983 को अनस्टाई क्वेश्चन नम्बर 2455 में सरकार से पूछा गया कि कितना क्राप एरिया एफेक्टिड है। जवाब मिला, कि कुल मिला कर 428.73 लाख हैक्टेयर जमीन प्रभावित है। अकाल इस सरकार के बस की बात नहीं रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ देश बाढ़ से पीड़ित है और दूसरी तरफ अकाल से। बाढ़ और सुखाड़ इस देश को भून कर खा रहे हैं। यदि आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसके मुताबिक 1953 से लेकर 1982 तक बाढ़ से 11,630 करोड़ रुपए की क्षति हुई है और सूखे से प्रति वर्ष 185 करोड़ की क्षति हुई है। बाढ़ के लिए छठी पंचवर्षीय योजना तक 10,200 करोड़ की राशि रखी गई और 1951 से 1982 तक सिंचाई के लिए 19,081 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

पी. ए. सी. की रिपोर्ट अभी दो दिन पहले ही इस सदन में पेश की गई है। उसको पढ़ने से मालूम होगा कि सिंचाई के मामले में क्या घांघली हुई है, कितने दिनों में सिंचाई की योजनायें तैयार होनी थी और कितने दिन के बाद तैयार हुई और कितना खर्चा बढ़ा, कितना करप्शन है और किसको प्रायर्टी मिलनी चाहिए थी, किसको मिल गई। इस देश में कृषि मन्त्री के अनुसार, 1,430 लाख हैक्टेयर टोटल कृषि भूमि है जिसमें से 1,050 लाख हैक्टेयर केवल

वर्षा पर निर्भर है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात सही है कि एक दिन में बाढ़ और सुखाड़ के लिए कार्यक्रम नहीं बनाए जा सकते लेकिन कुछ ठोस योजनाएँ बनाई जानी चाहिए और सदन को आश्वासन मिलना चाहिए कि कितने दिनों में उनको लागू किया जायेगा।

मैंने पार्लियामेंट में एक प्रश्न किया था जिस मुताबिक 185 मिलियन हैक्टेयर जमीन में से सिर्फ 37 मिलियन हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है और बाकी भूमि इन्द्र भगवान पर आश्रित है। यहां पर तो हम इन्दिराजी के आश्रित हैं और ऊपर इन्द्र भगवान के आश्रित हैं। गवर्नमेंट के अनुसार 60 लाख हैक्टेयर जमीन में वाटरलॉगिंग होती है और जो वर्षा का पानी है उसका केवल 14 प्रतिशत ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं।

मेरे पास स्टेटवाइज फीगर्स हैं। मैं बता सकता हूँ कि कहां पर कितने लोग सूखे से प्रभावित हैं। राजस्थान में राहत मन्त्री के अनुसार 23,572 गांवों में 1 करोड़ 77 लाख आदमी तथा 2 करोड़ 60 लाख मवेशी सूखे की चपेट में हैं और आगे अभी स्थिति और बिगड़ने वाली है क्योंकि मई और जून का महीना बाकी है। 27 जिलों में से 26 जिले बिल्कुल सूखे में हैं।

इसी तरह से केरल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सौ वर्षों में वहां पर कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा है। वहां पर 3 लाख 23 हजार हैक्टेयर घान की फसल नष्ट हो गई है और 400 करोड़ रुपए का फसल में नुकसान हुआ है। 1300 में से 100 गांव बुरी तरह से सूखे से झुलस गए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र से 200 करोड़ रुपए की मांग की है।

पश्चिम बंगाल के साथी भी यहां पर बैठे हैं। रोज हंगामा होता है। एक हजार करोड़ की फसल को वहां पर नुकसान पहुंचा है। पिछली बार जब श्री नारायण चौबे बोल रहे

थे, तो पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ बतलाया था। हमारे यहां बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग भूख से न मर रहे हों और पानी के बगैर न मर रहे हों लेकिन सरकार के पास एक ही जवाब है कि कोई भूख से नहीं मर रहा है। लेकिन भूख से कैसे लोग मरते हैं, यह भी आप जान लीजिए। आप राजस्थान की रिपोर्ट पढ़िए। पत्रिका का रिपोर्ट लिखता है कि जब वह वहां पर जानकारी करने के लिए गया तो लाना जोकि ऊंट के खाने की घास होती है, उसको पीस कर लोग रोटी खा रहे थे। अब्दुल लोहार ने घास की रोटी का टुकड़ा दिखलाया। जब लोग मरने को होते हैं तब जो चीज नहीं खानी चाहिए उसको भी अपनी जान बचाने के लिए खाते हैं। जब वह उसको खाएगा और गन्दा पानी पीएगा, तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी। डाक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नार्मल मृत्यु होती है। जब भी डाक्टर उसको देखेगा तो कहेगा कि उसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई है, इसकी मृत्यु हुई है बीमारी के कारण। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अक्षम सवाल है। इस देश में 35 सालों की आजादी के बाद भी लोग भूख से मरें, लोगों को पानी नहीं मिले, यह कितने शर्म की बात है। लोग एक-दो की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में मर रहे हैं और प्रतिवर्ष मर रहे हैं। यह गांधी जी का देश है, लोहिया जी का देश है और जिस देश में एक-एक चींटी को चीनी खिलाई जाती है और ऐसे चला जाता है जिससे की उसकी हत्या न हो जाए, लेकिन देश के लोग कीड़े-मकौड़े की तरह से मर रहे हैं। यह आजाद भारत और इस सरकार के लिए कलंक की बात है। बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां लोग भूख से नहीं मर रहे हैं और वहां अकाल की छाया न पड़ी हो। मेरे पास हर जिले की रिपोर्ट है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उड़ीसा की स्थिति और भी खराब है। वहाँ सामान्य

उत्पादन 42 लाख टन होता है, जिसमें से 19 लाख चावल की फसल नष्ट हो गई है। 314 प्रखण्डों में से 283 प्रखण्ड सूखे से प्रभावित है। गुजरात में 85 सूखे से प्रभावित है और मध्य प्रदेश की स्थिति भी इसी प्रकार की है।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आपने अपने स्टेटमेंट में यह नहीं बताया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : पहले बताया है।

श्री राम विलास पासवान : आपको स्टेटमेंट में बताना चाहिए था कि वर्तमान समय में किस स्टेट में कितने जिले इससे प्रभावित हैं। आप प्रखण्ड के हिसाब से नहीं चलते हैं। आपने 14 मार्च के लिए कहा है, लेकिन आज 13 अप्रैल है—एक महीने में स्थिति बदल सकती है। एक महीने में, जिस प्रकार से मृत्यु की दर बढ़ रही है, अब मृत्यु की दर बढ़ सकती है और स्थिति और भी बदतर हो सकती है। 13 अप्रैल की जो स्थिति है, वह 13 मई तक नहीं रहेगी और 13 मई को जो स्थिति होगी वह 13 जून को नहीं रहेगी। एक महीना कह दिया तो सदन में डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय ने इसकी गम्भीरता को समझा है। स्पीकर महोदय ने इन्डायरेक्टली आपके ऊपर सेंसर लगाया है। आपने पिछली बार जो कहा, उस पर आपने काम नहीं किया है। आपने स्थिति को गम्भीरता से नहीं समझा है। यही कारण है कि बार-बार अध्यक्ष महोदय इसका डिस्कशन करा रहे हैं। तब तक डिस्कशन होता रहेगा जब तक मन्त्री जी आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि समस्या का निदान आपको तुरन्त करना चाहिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप ठोस कदम बताइए।

श्री राम विलास पासवान : मैं बतलाऊंगा आपका ठोस कदम आखिर में। मेरे पास ठोस कदम है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Supposing the Central Government announces a particular area, say West Bengal, Kerala or Tamilnadu, as a famine-stricken area, but the State Government opposes it. What will happen ?

The State Governments must recommend that these are famine-stricken areas. Otherwise, the Central Government will be found fault with on encroaching upon the rights of the States. Please explain that.

श्री राम विलास पासवान : यहां बात उल्टी है। स्टेटमेंट रिकमेंड करती है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कहती है, कि मेरे यहां अकाल है। लेकिन राव वीरेन्द्र साहब को उस लोकप्रिय सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, इनको विश्वास है अपने आफिसर्स के ऊपर। अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। उनको भेज दिया जाता है कि पता लगाकर आओ कि राज्य सरकार गलत है या सही है।

राव वीरेन्द्र सिंह : क्या उनका सब मान लें ?

श्री राम विलास पासवान : सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिये कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसी के मुताबिक जो एरिया फैमिन-एरिया, स्केअरसिटी एरिया है, उस को डिक्लेअर कर दें।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस का मतलब है कि सारा स्टेट बजट सेंट्रल अपना ले।

श्री राम विलास पासवान : जब आप रेलवे का टैक्स वसूलियेगा, इन्कमटैक्स वसूलियेगा, डाक-तार वसूलियेगा, दूसरे टैक्स वसूलियेगा, और राज्य में जब भुखमरी होगी तो क्या यह कहियेगा कि सारे का सारा रुपया वहां चला जाएगा ? यही तो लड़ाई है।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्टेट का सारा बजट सेंटर अपना ले, सेंटर वहां का बजट पास करे।

श्री राम विलास पासवान : कहां का ?

राव वीरेन्द्र सिंह : सब स्टेट्स का।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके तमिलनाडू की बात बतलाता

हूँ। वहाँ की कृष्णा वाटर योजना को लीजिये। 1976 में प्रधान मन्त्री वहाँ गई थीं और वहाँ आप ही के श्री करुणानिधि मुख्य मन्त्री थे, जिन्हें डिस्मिस किया गया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not know anything about it

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा था कि वर्तमान प्रधान मंत्री वहाँ गई थीं और उस समय इसी सवाल को लेकर श्री करुणानिधि को डिस्मिस किया गया था और घोषणा की गई थी—कृष्णा वाटर के सम्बन्ध में एक 'बीरा' नाम का प्रोजेक्ट था, उस को स्टार्ट किया जायगा। यह घोषणा 1976 में की गई और अब 1983 चल रहा है—उस योजना का क्या हुआ ?

यू० पी० के 57 जिलों में से 46 जिले प्रभावित हैं। आप ने कहा है—मेरे हाथ में क्या है, जिस के लिये सुभाव देना चाहेंगे ? मेरा आग्रह है, मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ—एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा, इन दोनों का समन्वय कर दें। जो अति-रिक्त पानी है, जो एडिशनल-वाटर है, जैसा मैंने कहा है कि 40 परसेन्ट वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, बाकी वेस्ट चला जाता है, इसके उपयोग करने का रास्ता निकालें तो समस्या का 90 प्रतिशत निदान हो सकता है। लेकिन उस के लिये आप के पास कोई दृष्टि नहीं है और आपने यह कह दिया है कि मैं यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ, आजाद साहब का डिपार्टमेंट फलाना काम कर रहा है। आजाद साहब के डिपार्टमेंट के बारे में रोज अखबारों में पढ़ते हैं—फेअर प्राइस शाप्स पर कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आप का व्यूरोक्रेटिक-सेटअप है, आप उस का विश्वास कीजिये, अपने नौकर का विश्वास कीजिए, बी० डी० ओ० का विश्वास कीजिये, डी० एम० का विश्वास कीजिए, लेकिन वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन का विश्वास क्यों करते हैं ? इस भयंकर अकाल और

सूखे के समय में आप उन से भी सहयोग ले सकते हैं। मैं आल पार्टीज की बात नहीं कहता, क्या आप की अपनी पार्टी में भी अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं हैं ? सभी लोगों का सहयोग लेकर आप अपनी योजना को चलाइये।

जहाँ इस तरह की बात होती है, लोग शिकायत करते हैं कि फलां आदमी भूख से मर गया, आप का कोई साधारण कार्यकर्त्ता या प्रेस रिपोर्टर अगर कह दे कि भूख से लोग मरे हैं तो फेमिन कोड के मुताबिक क्या होगा ? तुरन्त उस आफिसर को सस्पेंड किया जायगा। ऐसी हालत में कौन बी. डी. ओ., एस. डी. ओ. या डी. एम. कहेगा कि कोई भूख से मरा है। पूरी आबादी भी भूख से मर जायगी तो कोई नहीं कहेगा कि एक आदमी भी भूख से मरा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप का मतलब है—वहाँ की इलैक्ट्रेड गवर्नमेंट की बात न मानें, आप की बात को सच मानें।

श्री राम विलास पासवान : यहाँ जितने बंटे हैं वे सब सिलैक्ट्रेड हैं और वह इलैक्ट्रेड है ? गजब की बात करते हैं। आप क्या सिलैक्ट्रेड हैं या इलैक्ट्रेड हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The State Government is also elected by the people. It is a popular government. You are also elected. Whom do you want him to follow ?

RAO BIRENDRA SINGH : The State Government or you !

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are also elected by the people. The State Government is also elected by the people. The Chief Minister is elected. Whom do you want the Central Government to follow ?

श्री राम विलास पासवान : I do not want that the Central Government should follow me. जो स्टेट गवर्नमेंट डिमाण्ड करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट देती है, उस पर आप विश्वास करें और उसके मुताबिक दें। मैं चाहता हूँ कि केरल की गवर्नमेंट ने आप से

जितना मांगा है, उतना उसे दीजिए। लेकिन जहां आपकी सरकार रहेगी, वहां आप थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन जहां अपोजिशन की सरकार रहेगी वहां यह भी नहीं करेंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा दिया, वहां क्या हमारी सरकार है ? तमिलनाडु को दिया, आन्ध्र को दिया।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) आपकी सरकार क्या बिहार में नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं देंगे ?

श्री राम विलास पासवान : तमिलनाडु ने जितना मांगा था, उससे बहुत कम दिया। जिस प्रपोरशन में आपने केरल को दिया, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप केरल सरकार को भी खूब दीजिए लेकिन जहां अपोजिशन की सरकार हो वहां भी आप किसी को भूख से और प्यास से मरने नहीं दीजिए। जब आप कृषि मन्त्री भारत सरकार है तो आप के लिए सब लोग बराबर हैं। आपकी बराबर की दृष्टि रहनी चाहिए।

मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्री रामाश्रयप्रसाद सिंह, हमारे यहां बिहार में मन्त्री हैं। उन्होंने एक चिट्ठी हम सभी एम० पी० को भेजी है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से क्या मांग किया था और केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को क्या दिया है।

उन्होंने प्रतिमाह एक लाख मीट्रिक टन अनाज मांगा था, केन्द्रीय सरकार ने 50 हजार टन दिया। यह चिट्ठी उन्होंने मेम्बर आफ पार्लियामेंट के पास इसलिए भेजी है कि पार्लियामेंट में मामला उठा कर हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने चीनी प्रतिमाह 40 हजार टन मांगी थी और आपने 29.625 टन दी है। केरोसीन तेल 30 हजार मीट्रिक टन मांगा था, आपने दिया है 23,750 मीट्रिक टन। पाम आयल उन्होंने 780 मीट्रिक टन प्रति माह मांगा था, आपने 200 मीट्रिक टन दिया है।

सीमेंट प्रतिमाह 200 मीट्रिक टन मांगा था, आपने दिया 1 लाख 29 हजार टन। यह चिट्ठी है आपकी बिहार सरकार की। अब मैं कैसे विश्वास करूं ?

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि देश में जो अभी वर्तमान स्थिति है, उसमें राज्यों में कितनी जमीन सूखे से प्रभावित है, कितने जिले सूखे से प्रभावित हैं ? 1982-83 में रबी फसल के लिए क्या लक्ष्य था और कितने उत्पादन की आशा है ? मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन आप कहेंगे कि आपके पास जो आंकड़े हैं, चूंकि आप अपोजिशन में हैं, इसलिए आप सही नहीं बोलते हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपके पास किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी सहायता मांगी गयी और कितनी-कितनी सहायता आपने दी ? गंगा-कावेरी योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ? अण्डर ग्राउण्ड वाटर यूटिलाइजेशन बोर्ड आपका क्या काम कर रहा है। जो आपका रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, जो आपका पानी का अपव्यय होता है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है ? यह जो आपकी दूरगामी योजना है, अभी जो लोग भूख से मर रहे हैं, अभी जो लोग प्यास से मर रहे हैं, इस सबके लिए सरकार क्या कर रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मिनिस्ट्री की डीमाण्ड्स शुरू हो रही हैं, उस पर सब पूछ लेना।

13.00 Hrs.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय पासवान जी ने मांगी है वह पिछली बार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय दी गई थी। उन्होंने पूछा है कि कितना क्षेत्रफल सूखे से प्रभावित है, कितनी जनसंख्या प्रभावित है। इस बारे में पिछली बार विस्तार से सूचना दी थी। अगर

माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको पढ़कर सुना सकता हूँ।

श्री रामविलास पासवान: लेटेस्ट बताइए।

श्री मनीराम बागड़ी : उससे बड़े नहीं हैं क्या ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is only sufficient that to the questions he has put, you should reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. I do not want any other voice other than that of the Hon. Minister.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने अपनी लंबी टिप्पणी में सूखे से प्रभावित गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया है सरकार का ध्यान इस ओर पहले से ही है। यह बात मैंने अपने लिखित वक्तव्य में भी बताई है और जो सहायता प्रदेश सरकारों को दी गई है उससे भी यह बात स्पष्ट है। अगर पहले दी गई सहायता और इस बार दी गई सहायता को देखें तो इस बात का पता चल जाएगा। इससे यह पता लगता है कि सरकार की नजर में यह कितनी गंभीर समस्या है। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपया और इस बार चालू वित्तीय वर्ष में जून 1983 तक उन राहत कार्यों को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार की गई है। अभी कुछ फँसले करने बाकी हैं। उन पर जल्दी ही निर्णय लिया जाना है।

पासवान जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि इतिहास में कभी ऐसी गंभीर समस्या सूखे की उत्पन्न नहीं हुई। उसी हिसाब से राहत कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे मद्रास में जहां पीने के पानी का संकट है वहां पर रेलवे बैग्स के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार इन समस्याओं के प्रति न केवल जागरूक है बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं।

जैसा कि लिखित वक्तव्य में मैंने बताया है कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं।

जहां तक स्टारवेशन डैथ्स के बारे में ध्यान दिलाया गया है, समाचार पत्रों में छपने वाली इस प्रकार की खबरों की ओर हमने राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है। वैसे भी हम समय-समय पर पूछते रहते हैं। राज्य सरकारों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार किसी भी राज्य में भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

श्री रामविलास पासवान : क्या आपने पता लगाया है कि किस कारण से मृत्यु हुई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमने पता लगाया है।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : हर बीमारी का अलग-अलग थोड़े ही पता लगते रहेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : भूख की बीमारी तो सबसे बड़ी बीमारी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राजस्थान के सोलीनिकिया तेल्ली गांव के बारे में कहा गया था। प्रदेश सरकार से सूचना मंगाई गई है। वहां से जानकारी आई है कि वहां पर भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है। वहां पर फैली किसी बीमारी के कारण कुछ लोग मरे हैं।

श्री रामविलास पासवान : किस बीमारी के कारण ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सामूहिक रूप से जब लोग मरते हैं तो किसी बीमारी की वजह से मरते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister is definite that it is not a starvation death. Their reply is based on the report of the State Governments.

श्री मनीराम बागड़ी : कम खाए, बिना खाए और लगातार कुछ न खाएं तीनों का

मतलब ही स्टारवेशन है। यह आपको समझना चाहिए।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : The State Government is misleading them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is different. You may have your own opinion. But their reply will be based on the State Government's report.

श्री राम विलास पासवान : अफसोस है कि सरकार स्टारवेशन डेथ्स और अकाल को बहुत हलके ढंग से ले रही है, यह बड़े शर्म की बात है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अभी राम विलास जी कह रहे थे कि हम प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास न करके अपने अधिकारियों से जानकारी करवाते हैं। हम प्रदेश सरकार की ही बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना को ही मैं बता रहा हूं। अगर, आप कहें तो राजस्थान सरकार से प्राप्त जो सन्देश है, वह मैं पढ़कर सुना सकता हूं। अगर, आप बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेकर आपको सूचना भेज दी जायेगी।

श्री मनीराम बागड़ी : असल में बात यह है कि इसके लिए राव साहब जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए खाद्य मंत्री जिम्मेदार है। यह तो ऐसी बात हो गई जैसे तीतर का जवाब बटेर और बटेर का जवाब तीतर।

MR. DEPUTY-SPEAKER : M. Mani Ram Bagri is the most privileged Member in the House. He will get up at any time and every time, and the Speaker is also very kind to him.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : प्रदेश सरकार से हमें जो ज्ञापन प्राप्त होते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आपको खुद मोके पर जाना चाहिए था। आप उद्घाटन करने चले जाते हैं लेकिन अकाल पीड़ित क्षेत्र में कोई नहीं जाता।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am seriously thinking why we should not leave the Chair to Mr. Mani Ram Bagri, so that he can conduct the House.

श्री आरिफ मोहम्मद : प्रदेश सरकार से प्राप्त ज्ञापन में शुरूआत यहीं से हुई है कि सूखे से उत्पन्न समस्या गम्भीर है जितनी मांग विभिन्न प्रदेश सरकारों की तरफ से की गई है वह मांग उसी हद तक जितना उन्होंने मांगा है, जितनी उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रभावित हैं पूरी करते हैं। सातवें वित्तीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार हम प्रदेश सरकारों को मार्जिन मनी उनके बजट में देते हैं ताकि वे ऐसी कोई भी दैविक विपदा से निपटने के लिए समर्थ हों और राहत कार्य करने के लिए उनके पास आर्थिक साधन उपलब्ध रहे। इसके अलावा जब भी ज्ञापन प्राप्त होते हैं तो पहले से निर्धारित नियम और मार्ग—निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए यह तय करते हैं कि राहत कार्य करने के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। कोई एक व्यक्ति बैठकर फैसला नहीं करता है बल्कि जो नार्म्स और गाइड-लाइन्स हैं उन्हीं के अनुसार निर्णय लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर हम अपने सरकारी अधिकारियों को यहां भेजते हैं और प्रदेश सरकार का तैयार किया हुआ ज्ञापन भी सरकारी अधिकारियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। हम वहां जाकर अवश्य देखते हैं और सातवें वित्तीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो नार्म्स और गाइड-लाइन्स हैं उसके मुताबिक ही फैसला करते हैं। 40 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल और 7 प्रतिशत पानी बह जाना, यह हमसे सीधे संबंधित नहीं है। सवाल यह है कि जो समस्या है उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राहत कार्य करने के लिए है।

श्री राम विलास पासवान : लांग-टर्म कोई योजना नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आपको शायद दूसरी तरफ यह मामला उठाना पड़ेगा।

इस वक्त तो आपने राहत कार्य के लिये सबाल उठाया है कि सूखे से उत्पन्न . . .

श्री राम विलास पासवान : जैसे मद्रास में वाटर स्केयसिटी हुई, मैंने मद्रास का उदाहरण दिया कि वहां जो प्रोजेक्ट्स थे यदि उनको तैयार कर लिया गया होता तो आज वहां वाटर प्रोब्लम न होती। मन्त्री जी कल के लिए जवाब देंगे, और आने वाले समय के लिये कोई और जवाब देगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। निश्चित ही किया जा सकता है, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और सदन द्वारा। लेकिन इस वक्त एक निश्चित मामला है सूखे से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिये जो राहत कार्य किये जाने हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है, तो मैं अपने आपको उसी तक सीमित रखना चाहता हूँ।

श्री राम विलास पासवान : फैमीन कोड को चेंज करने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आपने जो कहा है, आपके विचारों को हमने नोट किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो बारबार कहा जाता है। कितनी बार नोट कीजियेगा।

श्री राम विलास पासवान : फैमीन कोड तो अंग्रेजों के समय का बना हुआ चल रहा है, उसको चेंज करने के बारे में क्या विचार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He wants some information about the Famine Code.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले ही कहा हमने पहले भी इस प्रकार विचार किया है, और आपने जो कहा है, We have taken note of it and we shall see what can be done.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : After the Minister's reply not much is left and I am grateful to him that when our State Government of Himachal Pradesh approached the hon. Minister for immediate relief on account of drought conditions in the State he was very sympathetic and quick as he has been conversant with the areas of our State, being himself a Minister in Punjab and he saw to it that most of the State Government's demands were immediately met.

Financial assistance to the tune of Rs. 19 crores was sanctioned to our State and it gave enough scope for generation of fresh employment and also for carrying on some works of relief.

But I want to draw the Minister's attention that the amount has not been sufficient and some more money is required on that score too. But the present notice that I gave was in relation to the current situation where snow, storms and heavy rain, etc. have been responsible for the damage to crops.

It has been reported in the Press also that Simla and the Upper reaches of Himachal Pradesh and also various parts in the State have been subjected to heavy snowfall and most of the standing crops have been destroyed. The districts of Solan and Hamirpur and other areas have been subjected to severe rains. So, on the one hand, the State has suffered—our State, Jammu & Kashmir, some areas of UP adjoining our State have suffered on account of the drought last year and in the previous months of the present year. Now, at the moment, our State is suffering, so also is J & K and so are the hill areas of UP—from heavy sleet, snow storm and heavy rain. So, immediate attention of the Government is required in this direction and through you I want to draw the attention of the House and the hon. Minister to the extensive damage being caused to the cash crops and the fruit crops and the foodgrain crops in Himachal Pradesh and request him for immediate relief on this score.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is correct in following the Calling Attention

rules. Only 3 minutes he has taken... He follows the rules.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : We act and proceed as and when we receive memorandum from the State Government regarding damage by drought or by some other natural calamity. On the earlier memorandum, we have received from the Himachal Pradesh Government, a decision has already been taken and sanction has been issued, and no other memorandum of Himachal Pradesh is pending with the Central Government. As I said earlier, we can act and proceed only when we receive a memorandum from the State Government.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: The government there is in the process of formation and the memorandum will reach you soon.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You please expedite the memorandum. Now, Shri Jai Pal Singh Kashyap. You are starting at 1.15.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देकर अपनी बात ज्यादा लम्बी नहीं करना चाहता हूँ। सरकार के पास भी सब सूचनाएँ हैं और हमारे पास भी हैं।

मामला बड़ा संजीदा है, स्थिति और गम्भीर होती जा रही है, बावजूद इसके कि करोड़ों-करोड़ों रुपया सिचाई पर, लोगों को ज्यादा अनाज देने पर, नियोजन पर खर्च किया जा रहा है। पूरे देश की स्थिति सरकार के सामने है। 10 प्रदेशों के अन्दर लोग अनाज और पानी के बगैर मर जायें और वह भी 35 साल की आजादी के बाद, तो यह कलंक सरकार पर ही नहीं पूरे देश के जिम्मेदार लोगों पर है।

सबसे बड़ी विपत्ति इस देश में पानी की वजह से होती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं पानी की वजह से ही और लाखों करोड़ों भूखे-प्यासे मर जायें, वह भी पानी की वजह से ही होता है। इससे बड़ा अभिशाप इस सरकार पर और कोई नहीं हो सकता है।

राहत कार्य आपत्ति आने पर आप करते हैं। जो दैवी आपत्तियाँ आती हैं, उनसे लड़ने के लिये, उन्हें खत्म करने के लिये आप क्या कार्य कर रहे हैं? राहत कार्य जो आप कर रहे हैं, वह अच्छे हैं या बुरे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इन दैवी आपदाओं को खत्म करने के लिये आपकी क्या योजना है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

40 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाते हैं। पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिरती है लेकिन वह सब पानी बेकार चला जाता है। बरसात का पानी इकट्ठा करने की आपने कोई योजना नहीं बनाई। आदिवासी लोगों को, आप मध्य प्रदेश, बिहार कहीं जाकर देख सकते हैं, आज 35 साल के बाद भी पीने का पानी नहीं मिलता। जब सूखे की स्थिति नहीं होती है, उस समय भी आप उनको पानी नहीं दे पाते हैं, वह लोग बरसात का पानी पीते हैं। आज उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण में भी लाखों करोड़ों लोग बरसात का पानी ही पीते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या यह अकाल की स्थिति नहीं है? आप पानी की भी व्यवस्था न कर पायें और लाखों लोग भूख-प्यास से मर जाय, तो यह क्या है?

राव साहब सदन में हर साल कहते रहते हैं कि अनाज का उत्पादन रिकार्ड तोड़ रहा है लेकिन फिर भी यह सरकार विदेशों से अनाज मंगाती हैं। 40 लाख टन अनाज हम विदेशी मुद्रा खर्च कर के मंगाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी आप अनाज और पानी के मामले में अपने को आत्मनिर्भर नहीं कर पाये हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी सरकार पर है।

जब बरसात के पानी से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा बह जाता हो और उसी पानी के बगैर पूरे मुल्क के जानवर और इन्सान प्यासे मरते हों, तो क्या उस पानी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई

लम्बी योजना है; अगर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार हर साल जो राहत-कार्य चलाती है, उसका उद्देश्य दैवी आपत्तियों को खत्म करना नहीं होता, बल्कि सरकार की मंशा सिर्फ जनता को दिलासा देने की होती है।

चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ था। उसको दुनिया के किसी मुल्क ने आज से पांच साल पहले तक अनाज का एक दाना नहीं दिया, कोई वैज्ञानिक जानकारी और साधन नहीं दिए। मगर आज वहां पर एक भी इन्सान भूखा या प्यासा नहीं मरता है। लेकिन इस देश की आधी से ज्यादा आबादी—37 करोड़ लोग—गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। उनको पानी नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। यह आजादी कैसी है! दुनिया के किसी भी मुल्क में, यहां तक कि अरब देशों जैसे रेगिस्तानी मुल्कों में भी, जहां हजारों मीलें तक रेत ही रेत है, लोग प्यासे नहीं मरते हैं। इस देश में अथाह पानी के साधन हैं, यहां पर कावेरी, महानदी, गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं, जिनमें लगातार पहाड़ों से बर्फ का पानी आता है। लेकिन सरकार उस पानी का ठीक उपयोग नहीं कर पाती है।

जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, इससे बड़ी नासमझी दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मैदान अनाज पैदा करने के लिए है। हमारे पास साधन हैं, इन्सान की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन क्या सरकार ने भुखमरी को खत्म करने के लिए कोई योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या किसी एक प्रदेश को सरकार छांट ले और बफर स्टॉक बनाने के लिए उसे अतिरिक्त सिंचाई-साधन मुहैया करे। एक उत्तर प्रदेश को वह छांट ले। अकेला उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को अनाज दे सकता है। क्या सरकार भविष्य में भुखमरी

को निपटने के लिए देश के किसी प्रदेश को प्राथमिकता देकर अनाज पैदा करने की योजना बनाएगी? दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वह कनाडा हो या अमरीका, ऐसे इलाके हैं, जहां जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है।

अगले साल भी अकाल और सूखा पड़ेगा। उससे निपटने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है? देश में सब कुछ होते हुए भी सरकार कब तक अमरीका से अनाज मंगाती रहेगी? अगर सरकार भविष्य में भा अमरीका से अनाज मंगाती रही और उसने हिन्दुस्तान की खेती के विकास को प्राथमिकता न दी, तो यह एक देशद्रोही कार्य होगा। इसका मतलब यह है कि वह देशभक्त नहीं है। अगर उसमें देशभक्ति का माद्दा हो, तो वह खेती को प्राथमिकता दे, ताकि हमारी इकानोमी में सुधार हो। अगर सरकार खेती की प्राइव्केशन को नहीं बढ़ाती, तो वह भुखमरी से कैसे निपट सकती है? नहीं निपट सकती। आने वाले समय में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार कौन सी योजना बनाने जा रही है? किसानों और खेती को सब प्रकार की छूट देकर अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना उसके पास है? लोग प्यासे न मरें, इसके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए कौन सी योजना उसके पास है? यह समस्या बहुत गम्भीर है और लगातार अधिक गम्भीर होती जा रही है।

डा० दस्तूर ने एक योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत काश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सब नदियों को जोड़ा जा सकता है। जब यह सरकार खेल-कूद पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो वह उस योजनाओं पर पैसा क्यों नहीं खर्च करती? डा० दस्तूर की योजना को कार्यान्वित करने के लिए अगर वर्ल्ड बैंक और इन्टरनेशनल मानिटरी फंड से कर्ज लेना पड़े, तो सरकार ले।

सारा मुल्क आपके साथ होगा। लेकिन खेल-कूद पर तो आप खर्चा कर दें और राज-स्थान कैनल पर खर्चा न करें इसका क्या औचित्य है? राजस्थान कैनल की जो सात अरब की योजना थी वह बढ़कर 14 अरब तक पहुंच गई है। आपने एशियाड समय पर पूरा किया और बड़े गर्व के साथ आप कहते हैं कि समय पर पूरा कर दिया लेकिन आपकी कोई भी सिंचाई की योजना समय पर पूरी नहीं हुई है। सिंचाई की योजनाओं को भी आप समय पर पूरा क्यों नहीं करते हैं? जिनके कारण इन योजनाओं में देरी होती है उन अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही भी नहीं करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो सिंचाई की योजनाएँ बनाई हैं, उनको समयबद्ध करके कब तक पूरा करेंगे ताकि प्यास और भुखमरी से लोग न मरें? दूसरे, दस्तूर योजना के बारे में सरकार की क्या योजना है, क्या प्रतिक्रिया है? कश्मीर से बंगाल की खाड़ी तक पानी बहकर नदियों के मोहानों से 60 प्रतिशत से अधिक सागर में चला जाता है उसको रोकने के लिए आपकी क्या योजना है? वही पानी उत्तर भारत को बाढ़ से भी मिटाता है तो पहाड़ों पर प्राकृतिक बांध बनाकर उस पानी का बफर स्टॉक बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद ख़ाँ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाए हैं उनमें से अधिकतर सिंचाई मंत्रालय से संबंधित हैं। आज सौभाग्य से सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर चर्चा भी होनी है। अतः माननीय सदस्य को दोबारा भाषण नहीं करना पड़ेगा और माननीय मन्त्री जी इनका उत्तर भी दे देंगे।

एक बात मुझे कहनी है कि रूरल डेवलपमेन्ट मंत्रालय की ओर से जो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम डेजर्ट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, एक्सटेंशन आफ इरीगेशन प्रोग्राम, माइनर इरीगेशन प्रोग्राम और कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

चलाए जा रहे हैं या और भी जो योजनाएँ बनाई गई हैं, जिन पर इस सदन में चर्चा होती है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जनता को प्राकृतिक आपदाओं से तथा भुखमरी से मुक्ति दिलाई जाए। इन सारी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि इन विपदाओं से, बेकारी से, भूख से, गरीबी से अपने देशवासियों को मुक्ति दिलाई जाए और इसीलिए बड़े पैमाने पर यह कार्य किए जा रहे हैं। समस्या निश्चित ही बड़ी गम्भीर है लेकिन सरकार ने भी उसी गम्भीरता के साथ उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य इसको एप्रिषिएट करेंगे।

श्री राम सिंह शाक्य (इटावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आज सारा देश सूखे से भयभीत है। तमाम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, लाखों लोग भोजन तथा रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। पाँच वर्षों से लगातार राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। 27 में से 26 जिले सूखाग्रस्त हैं।

जैसा कि “आज” राजस्थान के समाचार पत्र में दिया गया है कि 23,572 गांवों में 1 करोड़ 77 लाख से अधिक निवासी भूख से परेशान हैं और लगभग 2.5 करोड़ मवेशी हैं, जिनके लिए चारे और पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोग भूख से परेशान होकर घास और पत्तियों पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब मनुष्य घास और पत्ती खाएगा, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, गन्दा पानी पीएगा, तो निश्चित तरीके से कोई न कोई बीमारी उत्पन्न होगी। इस प्रकार जब बीमारी से मरेगा तो रिपोर्ट आएगी कि बीमारी से मर गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वास्तविकता क्या है? पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को अनाज नहीं मिलेगा, लोगों में बीमारी पैदा होगी और लोग

मरने। चूँकि बीमारी से मरे हैं, इसलिए यह खबर कभी नहीं आती है कि भूख से मरे हैं। हर प्रदेश में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन इसको दर्शाया नहीं जाता है।

सात अप्रैल को इसी सदन में हमारे साथी श्री नरसिंह सूर्यवंशी ने नियम 377 के अधीन इस सवाल को उठाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के बिडार जिले में 657 गांवों में से 250 गांवों में पीने के पानी की कमी है। इस जिले में पानी का लैवल है, वहां पर हैंडपम्प लगाकर और अन्य साधनों से पानी को निकाला जा सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में तुरन्त व्यवस्था करके पानी की व्यवस्था कर रही है? कृपया यह भी बतायें कि क्या कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु का मदुरई जिला, जो कि दूसरे नम्बर का जिला है। वहां दस लाख की आबादी है। वहां पर भी पीने के पानी की समस्या है। 1976 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोलार पेयजल योजना की मंजूरी मांगी थी, यदि सरकार ने उस योजना की मंजूरी दे दी होती और तैयारी हो जाती, तो संभवतः इस संकट में कुछ कमी आ जाती और वहां के लोगों को मदद मिलती सरकार इस तरह के कामों को लगातार टालती रहती है, जिससे आज पूरे देश में यह संकट छाया हुआ है।

इस प्रदेश के अलावा केरल और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य प्रदेशों में भी यही समस्या है। जहां राहत कार्य की बात है। सरकार जो भी राहत कार्य देती है, उसकी व्यवस्था इस तरह की है कि वह राहतकार्य, अनाज, गेहूं व चावल, उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिनको कि मिलना चाहिए। जब किसी जिले में गेहूं दिया जाता है, तो वहां के लेखापाल से रिपोर्ट मंगाई जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : तमिलनाडु की बात कर रहे हैं।

श्री राम सिंह शाक्य : मैं उत्तर प्रदेश और सब जगहों की बात कर रहा हूं। जब

रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो उसका अधिकतर हिस्सा वहां के सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग खा जाते हैं। होता यह है कि यदि 50 किलो दिया जाना है तो पांच किलो दिया जाता है और 50 किलो का हिसाब कर दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था हर प्रदेश में हो रही है। इस पर आपको ठोस कदम उठाने चाहिए।

मेरा एक सुझाव है कि गरीबों को जो अनाज बांटा जाता है, किस तरह से वह अनाज और चावल गरीबों को दिया जाय इसके बारे में एक योजना बनाई जाय। मान लीजिये, अब आगे बरसात आयेगी, बाढ़ आयेगी, तो बाढ़ या बरसात के पानी के निकास के लिये नालों की जरूरत पड़ेगी। यदि सरकार ने इन नालों के खुदवाने की कोई योजना बनाई है तो यह काम बरसात या बाढ़ के आने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। सरकार निश्चय करें कि हम यह काम तुरन्त करायेंगे और इस काम पर इन गरीबों को लगा दिया जाय। कोई बड़ा आदमी इस काम को करने के लिये नहीं जायगा, ये गरीब लोग ही इस काम के लिये आगे आयेंगे, आप उन से नालों को खुदवाने का काम कशाय्ये और बदले में उन को गेहूं और दूसरे अनाज दीजिये।

आज क्या होता है कि ये चीजें एक दम बांट दी जाती हैं, जिस से यह गरीबों को न मिल कर ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जिन को उस की जरूरत नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—क्या आप बरसात के आने से पहले ऐसी कोई योजना बना रहे हैं जिससे गेहूं गरीबों को मिल जाय, चावल गरीबों को मिल जाय, और बाढ़ के आने से पहले वहां नालों की व्यवस्था हो जाय। अगर मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करें तो मेरे विचारों में कुछ हद तक बाढ़ की समस्या का हल हो सकता है।

हमारे बहुत से साथियों के यहां खेती होती है, मेरे यहां भी खेती होती है और आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये जरूरी है कि गांवों में बिजली नियमित रूप से पहुंचाई जाय। आज होता क्या है—बिजली की व्यवस्था तो है और कहा जाता है कि 8 घण्टे के लिये बिजली आयेगी। लेकिन मैंने खुद देखा है—गांव में आधा घण्टे के लिये बिजली आती है, जैसे ही किसान उस का उपयोग करने के लिये खेत में पहुंचता है, बिजली गायब हो जाती है और पानी खेत तक नहीं पहुंच पाता है। उस के बाद किसान इन्त-जार करता रहता है कि कब बिजली आ जाय, पूरी रात उस को जागना पड़ता है लेकिन पानी खेत तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय कि जितने घण्टे भी बिजली दी जाएगी, वह उस को सही तरीके से मिलेगी तो किसान उस का उपयोग कर सकता है, समय से अपने खेतों में पानी पहुंचा सकता है और इस तरह से गेहूं तथा चावल की उपज को बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़े हुए उत्पादन से, जैसा मरे साथी ने बतलाया, उत्तर प्रदेश न केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, बल्कि पंजाब और हरियाणा की तरह सारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। सूखे के संकट के समय में देश में अनाज की कमी नहीं रहेगी और देश की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। परन्तु दुख यह है कि इस तरह की व्यवस्था की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कागज पर योजना है कि बिजली दी जा रही है, राहत कार्य चल रहे हैं, गरीबों में अनाज बांटा जा रहा है, लेकिन यदि खुद जा कर देखा जाय तो आप को मालूम होगा कि जितना कहा जाता है उतना काम नहीं हो रहा है। यदि आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा कि जब सूखा पड़ेगा तो लोगों को समझा दिया जायगा

कि तुम्हारे यहां राहत कार्य शुरू कर दिया है, बाढ़ आयेगी तो लोगों से कह दिया जायगा कि तुम्हारे यहां गेहूं और चावल भेज दिया गया है। लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें, इस तरह की योजना बनायें जिससे कि बाढ़ और सूखे के रास्ते को कन्ट्रोल किया जा सके। अगर यह कन्ट्रोल नहीं हो पाया, तो इस से कुछ नहीं बनेगा कि सूखा पड़ा तो गल्ला बांट दिया, बाढ़ आई तो गल्ला बांट दिया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष जी, सरकार की योजनाएं इसी दृष्टिकोण से बनायी जाती हैं कि इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निबटा जा सके।

राजस्थान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, खास तौर पर पीने के पानी के विषय में। पिछले वर्ष में वर्षा, शुरू होने से पहले और वर्षा शुरू होने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत कार्य में केवल पीने के पानी के लिए 24 करोड़ 26 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये, इतनी राशि का प्रावधान किया गया।

तमिलनाडू के विषय में मैंने आपको अपने लिखित वक्तव्य में भी बताया था कि उसके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है। लेकिन उन्हें अग्रिम राशि 15 करोड़ रुपये और प्रधान मंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार के बजट में केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 करोड़ 59 लाख रुपये की मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया। अब नया बजट शुरू हो गया है जिसमें ये सारे प्रावधान हैं।

माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हमारी भी वही चिंता है। नाली आदि के सम्बन्ध में आपने जो बात कही है, जो घनराशि सहायता कार्य हेतु दी जाती है उसके बारे में हम यही अपेक्षा करते हैं कि नाली खुदवाने का

काम, तालाब खुदवाने का काम इस प्रकार से किया जाए जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में जो रोजगार मिल रहा है, वहां केवल रोजगार ही न मिले बल्कि आगे काफी समय के लिए वहां नालियां और तालाब हो जाएं जिससे कि बाढ़ के दिनों में वहां से पानी गुजारा जा सके।

अनाज के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा। एन० आर० ई० पी०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिन्हें मजदूरी दी जाएगी उन्हें उनकी मजदूरी के आंशिक वेतन के रूप में एक किलो अनाज दिया जाएगा। राहत के रूप में एक किलोग्राम गेहूं उनको आंशिक वेतन के रूप में दिया जाए, यह इस कार्यक्रम में है।

किसानों को मिलने वाली बिजली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा। केन्द्रीय सरकार, समय समय पर प्रदेश सरकारों को निर्देश देती रहती है कि फसल ठीक से हो, उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा केन्द्रीय दल भी प्रदेशों को भेजे जाते रहते हैं, यही मोनेटरिंग करने के लिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : डिप्टी स्पीकर महोदय, तन्नीर तन्नीर तमिलनाडु इल्लै, तन्नीर तन्नीर राजस्थान, इल्लै। तन्नीर तन्नीर भारत इल्लै। भारत में आज कहीं भी पानी नहीं है। यह सारा गुस्सा इन्द्र भगवान पर तो है मगर इन्दिरा देवी भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही इन्दिरा देवी देश की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं।

जो उत्तर मंत्री महोदय की तरफ से आये हैं और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आये हैं, उनसे मालूम होता है कि सिंचाई मंत्रालय, खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच में खिंचाव है। इसी खिंचाव की वजह से सही रूप से इस प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सुखा और अकाल के प्रश्न पर सरकार का ध्यान जाता

तो क्या इस देश में इस तरह से फिजूलखर्ची चलती रहती? पांच स्टारी वाले होटल चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। फाइव स्टोरी होटल बनते चले जाएं और देश में कोई नोटिस न ले। एक तरफ तो लोगों को पानी और अनाज नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इन चीजों पर ध्यान न देकर के फिजूलखर्ची पर, खेलों पर, और नाच-रंग पर खर्च कर रही है। इस राशि को राहत कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए था।

योजनाओं के संबंध में आपने कुछ बातें कहीं हैं। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे। सरकार शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह समस्या कई मंत्रालयों से संबंधित है। इन समस्याओं को देखते हुए भविष्य की योजना बनाइए।

सूखे का प्रश्न बाढ़ से जुड़ा हुआ है। बरसात का मीठा पानी बहकर खारे समुद्र में मिल जाता है। नदियों को गहरा और चौड़ा करें। इनके दोनों ओर बांध बनाकर पेड़ लगाएं। उन नदियों में 2, 4, 6 या 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े तालाब बनाकर पानी इकट्ठा करें। बरसाती नहरें बनाएं। इससे जो पानी बहकर बिहार और बंगाल की ओर चला जाता है उसे वहां से डायवर्ट करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर भेजा जा सकेगा। इससे यह पानी बेकार न जाकर सिंचाई के काम में आएगा। इन बरसाती नहरों से आपको बाद में पानी नहीं मिलेगा लेकिन धान, गन्ना, जूट आदि की फसलों को इनसे लाभ हो सकता है। इसके लिए एक बहुत लम्बी योजना तैयार करनी होगी। इस समय तो आपको रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजगार न मिलने की वजह से लोग पलायन करके दूसरे शहरों

की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर रही है। और एक मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी दूसरे मंत्रालय पर डाल रहा है इसी तरह से वहां पर लोग बेरोजगारी से परेशान होकर दूसरे शहरों की ओर जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आप मृत्यु की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय पर डाल सकते हैं। जब लोग घास खाएंगे तो बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भुखमरी की सूचना देने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान और लेखापाल की है, इस तरह की व्यवस्था आपको भी करनी चाहिए। इस तरह की जिम्मेदारी गांवों के प्रधानों और लेखापालों पर डालें कि वे जानकारी एकत्र करके जिलाधीशों को दें और वे जानकारी एकत्र करके सरकार को भेजें। इससे सही स्थिति का पता लगेगा कि कहां भुखमरी है।

इसके अलावा यह भी देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायदे से चले और दवाइयां वगैरह भी वहां पर पहुंचें। दवाओं की आवश्यकता उनको अधिक होती है क्योंकि वहां पर लोग कमजोर होते हैं। बच्चों के लिए दूध और भोजन की व्यवस्था भी करनी आवश्यक है। नलकूप लगाए जाएं और जहां पर नलकूप नहीं लगाए जा सकते वहां पर जलाशय कायम करने चाहिए। पहले शासक लोग जलाशय बनाया करते थे। उसका वैज्ञानिक महत्व था। जब बाढ़ आती है तो मिट्टी की उर्वराशक्ति बह जाती है। एक इंच मिट्टी की तह बनने में हजारों साल लग जाते हैं।

अगर पानी तालाबों में जायेगा और तालाबों से पुनः सिंचाई के काम में लाया जायेगा तो तालाबों में उर्वरक शक्ति वाली मिट्टी जायेगी और पुनः खेतों में सिंचाई के साथ-साथ आ जायेगी। इससे मिट्टी समुद्र में या दूसरे

स्थानों पर नहीं जायेगी। पूरी धरती का पांच फीसदी हर गांव पंचायत में तालाब बनाकर पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें जिससे पानी सिंचाई के काम में आ सके। जब तक आप कोई लम्बी योजना नहीं बनायेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मैं उसका जानकार नहीं हूं। लेकिन चर्चाएं होती हैं कि जो यूकेलिप्टस या सफेदे का पेड़ है, उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए तो वह फायदेमन्द होता है। जहां पर पानी ज्यादा है या दलदल है तो पानी उस सतह से नीचे चला जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह पेड़ हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। पानी की सतह उससे नीचे चली जाती है और सूखे का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन, अगर है तो आज देश में इन पेड़ों का रोपण हो रहा है। आप नदियों और बांधों के किनारों पर बबूल, पीपल और फलदार वृक्षों का भी रोपण करें। यूकलीप्टस के पेड़ से पानी की सतह नीचे आ रही हो जिस से सूखे पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा वहां वृक्षारोपण को रोकने का प्रयास करे। मैं जानना चाहूंगा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है? इन्द्र भगवान तो गुस्से में हैं लेकिन इन्दिरा देवी जी का ध्यान हमारी तरफ दिलवा दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: माननीय सदस्य विषय से पलायन कर गए, उन्हें इजाजत है। मैं समझता हूं, आप मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे कि मैं विषय से पलायन करूं। माननीय सदस्य ने अपनी बात के मध्य में माननीय चौधरी चरण सिंह का अनुकरण करने के लिए कहा है। शायद, फिर वह हमसे कहने लगे कि हम गन्ने के किसानों से यह कहें कि गन्ने के खेत में आग लगा दो। इससे बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

श्री जलपाल सिंह कश्यप : आज गन्ने के किसान को 6 या 7 रुपए का भाव मिल रहा है जबकि खाद, पानी, बिजली और डीजल आदि सभी के दाम बढ़ गए हैं। उस जमाने में कम से कम ये चीजें तो सस्ती थीं। आज 13 रुपए एक बैलगाड़ी पर लग रहे हैं। . . . (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें हमारे तरीके से हमारी नीतियों और सिद्धान्तों के अनुसार ही काम करने दीजिए। ऐसा अनुकरण करने के लिए कहिए कि जिससे आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए भी पैदा हो जाए। ग्राम पंचायतों में नलकूपों और जलाशयों आदि के संबंध में जो योजना है, वह केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता के अन्तर्गत ही आती है। उसमें यही कोशिश है कि ग्राम पंचायतों में प्रभावित क्षेत्रों में जलाशय बनाए जा सकें। भुखमरी के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए हम प्रदेश सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए रखते हैं और जो कुछ सहायता करना सम्भव होता है, वह करते हैं। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या दूसरी प्रदेश सरकारों से जब भी सूचना प्राप्त होती है तो हम ग्राम पंचायतों के स्तर पर या अपने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कराते हैं कि वहां कुछ न कुछ अनाज रहे जिससे भुखमरी की स्थिति पैदा न होने पाए।

13.55 Hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Connecting Udaipur and Delhi by a Superfast train.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान राजस्थान के कश्मीर प्रदेश उदयपुर की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहां से हजारों की संख्या में लोग प्रति सप्ताह, प्रति

दिन अहमदाबाद व दिल्ली आते जाते हैं। इस प्रदेश में आवगमन के साधन वैसे ही बहुत कम हैं। तथापि रेल व्यवस्था का बिल्कुल अभाव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भी उदयपुर एवं दिल्ली का मिलाना रेल व्यवस्था से अति आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सरकार ने अभी जोधपुर से सुपर फास्ट ट्रेनों व दिल्ली से अहमदाबाद को जोड़ा है उसी तरह से उदयपुर को दिल्ली व मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर होते हुए, अहमदाबाद से सुपर फास्ट ट्रेनों से शीघ्र जोड़ा जाये।

(ii) Financial Assistance to Kerala to meet drought situation in the state.

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : Kerala is under the grip of a severe and out of 1300 villages in the State 900 have already been declared drought affected by the Government of Kerala. Never before in the history of Kerala has witnessed a drought of this magnitude. Not only that the prices of rice and other commodities have shot up, but also they are scarcely available in the market. In many villages the situation is so grave that people are not getting even drinking water.

The economy of the State is on the verge of ruin. Adding fuel to fire, the power generation has fallen steeply resulting in loss of revenues to the exchequer and fall in production in the industrial sector. All these have created an unprecedented and very serious situation demanding the immediate attention of the Central Government. If the Central Government do not rush to provide necessary assistance, the consequences will be alarming, as the situation may lead to starvation-death and spreading of epidemics.

In view of the above serious situation, the Kerala Government have asked for a special assistance of Rs. 200 crores from the Centre. This amount itself is too meagre considering the gravity and magnitude of the problem. The Chief Minister of Kerala has also met the Prime Minister and Finance Minister and made representations in this regard.

I, therefore, urge upon the Central Government to rush to provide assistance to Kerala and sanction an assistance of at least Rs. 200 crores to meet the drought situation.

(iii) Bank loans to people of Gujarat whose houses were destroyed in recent cyclone.

SHRI NAVIN RAVANI (Amreli) : With a view to bringing relief to those whose houses were damaged or destroyed during the cyclone which hit certain parts of Gujarat mainly the districts of Amreli, Bhavnagar and Junagadh, the Central & State Governments have promptly made arrangements for relief and have through the R.B.I. instructed nationalised Banks to provide housing loans to the affected persons on easy terms.

It is, however, observed that the progress of the Banks in giving loan is not at all satisfactory. In urban areas most of the applications for loans have been rejected on technical grounds. The situation in rural areas is still worse. Hardly and application for loan has been sanctioned in the rural areas.

The plight of these unfortunate people can well be realised that they with their little ones are still under the scorching sky and when rain sets in, which is not far off, their plight will be aggravated.

I need not over-emphasise the matter because the Finance Minister had personally visited the affected areas and seen for himself the sad conditions under which these people are living.

I, therefore, request the hon. Finance Minister kindly to issue necessary instructions for the grant of loans so that the relief work can be undertaken immediately.

(iv) Need to improve the functioning of telephones at Mathura, Uttar Pradesh.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : श्रीमन्, मथुरा नगर में टेलीफोन का डायल सिस्टम हो गया है। मथुरा में टेलीफोन की व्यवस्था असाधारण रूप से खराब है। अधिकतर टेलीफोन इसलिये खराब रहते हैं। मैं दो टेलीफोन

इसलिए रखता हूँ कि एक खराब होगा तो दूसरे से काम चल जायेगा। लगभग दोनों ही खराब रहते हैं। कभी दिल्ली से मथुरा बात करना चाहता हूँ तो बहुदा नहीं हो पाती। जनता को बहुत परेशानी है। वहाँ के एस० डी० ओ० टी० तो मेरे किसी पत्र का उत्तर तक नहीं देते। मैंने 24.2.83 को महाप्रबन्धक दिल्ली को पत्र लिखा। अपने 3 मार्च, 1983 के पत्र में लिखा कि उन्होंने मेरा पत्र लखनऊ के टेलीफोन महाप्रबन्धक को भेज दिया है।

मैं नहीं समझता कि मुझे क्या करना चाहिये ताकि मथुरा नगर और मेरी समस्या हल हो और यह भी पता लगे कि एस० डी० ओ० टी० मथुरा संसद सदस्य की शिकायत पर भी क्यों ध्यान नहीं देते।

कृष्ण जन्म भूमि में जनता भगवान से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करने आती है। मैं उस पवित्र नगरी की ओर से अपनी प्रार्थना सरकार से करता हूँ कि वहाँ की टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें।

14.00 Hrs.

(v) Working the Telegraph and Telecommunication services in the country.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा हुआ, चौधरी दिगम्बर सिंह जी के बाद मुझे भी उसी समस्या पर बोलना पड़ रहा है।

मैं दूर-संचार की अकार्यकुशलता को सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ। यह मेरा और अन्य अनेक व्यक्तियों का अनुभव रहा है कि जो ट्रंक-काल बुक की जाती है, उनके मिलने में काफी समय लगता है और वह ट्रंक-काल भी ट्रंककाल अधिकारियों को कई बार याद दिलाए जाने के बाद मिलती है। बहुधा ये ट्रंक-काल बिल्कुल नहीं मिलते। टेलीफोन एक्सचेंज से जब सम्पर्क किया जाता

है तो वे, जिस व्यक्ति ने काल बुक की है, उसे यह सूचना देते हैं कि लाइन खराब है। इससे काफी असुविधा तथा कठिनाई होती है, विशेष कर वह मामला जिसके लिये ट्रंक-काल का उपयोग किया जाता है, अविलम्बनीय लोक-महत्व का हो।

एक अन्य मामला जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि जब एक बार स्मरण कराये जाने पर भी वह नहीं मिल पाती तो काल को रद्द करा पाना और भी अधिक कठिन होता है।

एस० टी० डी० कालों के बारे में मैंने यह देखा है कि प्रायः टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल पाता है।

इस बारे में मैं एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मेरी आधे-घंटे-की-चर्चा के बारे में 7 अप्रैल को मेरे स्थायी पते पर लोक-सभा सचिवालय ने एक अविलम्ब ट्रंक-काल बुक किया था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ट्रंक काल के लिए चार बार स्मरण कराने पर भी वह नहीं मिल सका तथा मुझे ठीक समय पर जानकारी नहीं मिल पायी। लोक-सभा सचिवालय द्वारा 6 अप्रैल को भेजा गया टेलीग्राम भी मुझे 9 अप्रैल, 1983 की शाम को मिला।

जब सर्वोच्च सदन के सचिवालय द्वारा अथक प्रयास के बाद भी अपने सदस्यों से सम्पर्क इन माध्यमों द्वारा नहीं किया जा सकता तो साधारण जनता की दुरावस्था का आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह तार व दूर-संचार सेवाओं सम्बन्धी शिकायतों की विशेष रूप से जाँच करें और उन्हें अविलम्ब दूर करें।

(vi) Need for early re-opening of Bhaskar Textile Mills, Jharsuguda.

SHRI SATYASADHAN CHAKR-ABORTY (Calcutta South): I make the following statement under Rule 377.

The closure of Bhaskar Textile Mills, Jharsuguda from 10th January, 1983 has resulted in starvation of 3000 workers and their family members. This closure is causing deep resentment of the entire population of the area since its economy is greatly affected due to this closure. The company started from 1963-64 with investment of Rs. 35 lakhs. It earned a fabulous profit of over Rs. 3 crores till 1980-81. The owner of the company however indulged in several irregularities. When the workers were agitating for payment of bonus and the company on 1.10.82 fixed 16th October, 1982 for discussion with Jharsuguda Industrial Mazdoor Union it surreptitiously issued lockout notice on 2nd Oct, 82 though it was signed on 30th Sept. 82. Since 2nd October 1982 lockout became operative rendering thousands of workers jobless. At present it is still continuing despite repeated efforts by the Union to reopen the mill, and they demanded 1) immediate take over by NTC, opening it immediately by taking back all the workers who were on the rolls on 1.10.82, (2) payment of wages for the lock out period. Therefore, I urge the Government to take steps to meet up their just demands.

(vii) Need for providing speed boats to Custumes Collectorate of Madurai to curb smuggling.

SHRI M.S.K. SATHIYENDRAN (Ramanathapuram): Sir, the Collectorate of Central Excise and Customs at Madurai has under its jurisdiction the east coast from Rameshwaram upto near about Madras. With the duty free shops having been opened at Colombo in Sri Lanka, the smuggling along this long coast-line has gone beyond normal patrolling. Whenever the Customs officials get any information they have to approach through correspondence. the Department of Fisheries or the Naval Coast Guard for loaning speed boats to chase the smugglers. By the time the formalities are fulfilled and the boats are made available, the smugglers run away. It has become essential that the Customs Collectorate at Madurai should be provided immediately with two speed boats so that the smuggling activities are curbed effectively on the east coast. Besides, these speed boats may also stop the poaching being done by some adjoining for- countries on our territorial waters, particularly along the

east coast where the delicious prawn fish are available.

(viii) Problems of opium growers.

श्री चतुर्भुज (शालावाड) : उपाध्यक्ष महोदय, अफीम-उत्पादन कृषक की समस्याओं एवं कठिनाइयों पर केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा अफीम से प्राप्त होती है। कृषक को आज भी 130 पर के जी है लगा कर कुल 240 रुपए पर के जी मिलता है। विश्व बाजार में 10 हजार रुपए पर के जी मात्र है। अफीम उत्पादन पर तकनीकी प्रणाली पर कुल खर्चा एक बीघे पर 1000 रुपए आता है। करीब 1200 रुपए गम्भीरता आमदनी प्राप्त करता है। उर्वरक, खाद, बीज, पानी, तकनीकी मजदूरों एवं ज्ञान पर कई गुणा खर्चा बढ़ा है, लेकिन पिछले तीन वर्ष में एक भी पैसा अफीम का भाव नहीं बढ़ाया, बल्कि घटाया है। अफीम उत्पादन क्षेत्र घटाया ही नहीं गया है, बल्कि प्रकृति प्रकोप से पीड़ित फसलों को भी राहत देना उचित नहीं समझा गया है।

अतः मेरा आग्रह है कि अफीम का भाव बढ़ाया जाए। अफीम क्षेत्र कम न किया जाए। अफीम क्षेत्रों में और अफीम दी जाए। नारकोटिक्स बोर्ड में लोक सभा सदस्य लिये जाएं। लोक सभा में एक बिल इस संदर्भ में लाया जाये, जो किसानों के हितों को संरक्षण देने वाला हो।

अतः अफीम उत्पादन लाखों कृषक एवं करोड़ों मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने हेतु नारकोटिक्स नियमावली पर लोक सभा में प्रतिवर्ष विचार हो।

(ix) Increasing cases of blindness amongst children in the country

SHRI ARJUN STEHI (Bhadrak) : Sir, the high incidence of blindness caused by Vitamin A deficiency and malnutrition amongst the children estimated to be 2,50,000 in developing countries of the world and of them about 30,000 are Indians. This high

incidence was pointed out in 1981 by the National Institute of Nutrition and has been recently corroborated by independent studies by Indian Council of Medical Research. According to these, blindness among children ranged from 8.9% in Orissa to 0.6% in Gujarat, in Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal and Tamil Nadu the percentage ranged from 1.1% to 2.9%. In fact, in the International Year of Child, it was calculated that 2.5 million children were in varying daerees threatened by Vitamin A deficiency blindness.

An ambitious Central scheme for covering 125 million children at the cost of Rs. 18 crores was announced in 1981. The Institute of Nutrition has developed an oral dose of Vitamin A to be administered every six months.

However, this emphasis on administering concentrated doses of Vitamin A can have only limited effect in the country where the majority of the most vulnerable have little access to clinics. Workers at Primary Health Centres need also to be taught how to recognise the early symptoms of blindness due to deficiency. Educative compaigns will be more effective in the long run.

Therefore, I urge upon the Government to launch immediate frontal attack on blindness taking educative, preventive and curative steps to help control the increasing blindness amongst the children in the country.

14.10 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1983-84—Contd.

MINISTRY OF IRRIGATION

MR. DEPUTY SPEAKER : We now go to next item. Discussion and Voting on the Demand for Grant under the control of the Ministry of Irrigation.

The House will now take up discussion and voting on Demand No. 67 relating to the Ministry of Irrigation for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the table within 15 minutes indicating the

serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial number of cut motions moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring to the notice of the Officer at the Table without delay.

Motion Moved :

"That the respective sums not exceed-

ing the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand No. 67 relating to the Ministry of Irrigation."

*Demands for Grants, 1983-84 in respect of the Ministry of
Irrigation submitted to the vote of Lok Sabha*

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 18th March, 1983		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF IRRIGATION					
67.	Ministry of Irrigation	16,69,73,000	1,86,52,000	83,48,65,000	9,32,59,000

MR. DEPUTY SPEAKER : Prof. Rup Chand Pal to initiate the discussion.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in our predominantly agricultural economy, as it has been rightly stated in the Report of the Irrigation Ministry, agriculture plays a very important part. 70 per cent or more than that of the people of our country, directly or indirectly, are dependent on agriculture. Half or a little more than that of the national income is accounted for by agriculture. Even in respect of the foreign exchange earnings, a considerable amount is contributed from the agricultural sector. Irrigation, as all of us will agree, is the backbone of agriculture. If we look at this vital sector, the performance in this vital sector for all these years, if the least is to be said, I can say that it is in total mess.

Day in and day out the claims are made both inside the House and outside that this Government has made a phenomenal progress in different spheres of our economy. Let us have a look at the irrigation sector, such a vital sector of our economy. From the beginning of the Plan period in 1951

upto 1980, out of 206 major irrigation projects, only 30 projects have been completed. Out of 921 medium irrigation projects, 476 projects have been completed. According to the Government figures of 1980, 11 projects are spilling over from the First Plan period, 13 projects from the Second Plan period, 24 projects from the Third Plan period and 10 projects from the Annual Plan period of 1968-69. During the last 15 years, speaking on the basis of 1980 figures, the average annual increase in irrigation potential was 1 million hectares. If such a rate of progress continues, you calculate when we shall be able to achieve our ultimate irrigation potential.

There are projects that are continuing for 15 to 20 years. What is the loss suffered by us during all these years as a result of this delay? Let us take the cost escalation in respect of only a few projects. Nagarjuna-sagar project started in 1960. The estimated cost at that time was Rs. 91.1 crores and the latest estimate is Rs. 537 crores. Gandak project started in 1961. The estimated cost was Rs. 36.6 crores. Now the latest estimate is Rs. 415.81 crores.

For eight projects Nagarjunasagar Rajas-
than Canal Stage I & II, Kansbuti, Mala-
prabha, Kallada, Jawa, Gandak and Kosi
etc., the total estimated cost was Rs. 386.07
crores and now the latest estimate is
Rs. 2,144.71 crores.

Out of a target potential of 59.57 million
hectares during this period, our achievement
is to the tune of 38.98 million hectares, both
major, medium and minor taken together
i.e., 20 million hectares backlog. The short-
fall is to the tune of 33%. What is the cost
of this shortfall? According to the present
estimate, if per hectare cost is Rs. 7,000,
then just calculate. We have to bridge the
gap of this backlog of 20 million hectares.
What is the cost? It will come to
Rs. 14,000/- crores as per 1979 price base.

We are mortgaging our sovereignty and
our economy to the IMF, having a loan of
Rs. 5,000 crores and, due to your fault—I
shall come to that, to the important docu-
ments being given by important committees
—the people of this country will have to
pay Rs. 14,000 crores.

We have invested during the period 1951
to 1982, more than Rs. 15,000 crores. Now,
it is being said that we shall cover it up
during the Sixth Plan period. It is being
claimed that out of 176 major projects, 86
are likely to be completed. Out of 446
medium projects, 419 are to be completed.

What is the total outlay in the Sixth
Plan? The outlay for major, and medium
irrigation projects is Rs. 8,458 crores, and
for minor irrigation projects Rs. 1,811 crores.
We will get Rs. 1,700 crores from institu-
tional sources.

Suppose, an additional outlay of
Rs. 2,600 crores is given do you think that
this target will be fulfilled? We are hoping
against hope! We are living in a world of
illusion. Can you imagine the loss that we
have suffered till now?

The other day, the Minister of Agri-
culture was holding a press conference and,
for the first time, he admitted that our food
production is declining. It is not the admis-
sion of the Minister of Agriculture himself
only. What are your statistics? What is the
study made by the international agencies?
Instead of reaching self-sufficiency, we are
importing food. We know that you shall

say that it is all for creating buffer-stock in
our country and all that. But one interna-
tional study says that the *per capita* availabi-
lity of food in our country remains static
for the last two decades at 170 Kg per year.
Our national standard in this respect is far
below the international standard.

Do you know that, according to another
estimate made by the Planning Commission,
66% people of India do not have enough
purchasing capacity to buy food for the
major part of the year? These are not my
own statistics. This is a study made by the
Planning Commission itself. You have
yourself admitted that more than 350 million
people of our country live below poverty
line. Though in reality number is far more.
Not our statistics. At this stage I am not
going to enter into question of the manipu-
lations being made regarding the poverty-
line, etc.; I will come to that on a different
occasion. What is the loss we have suffered
in floods and drought? Leave alone the
loss of precious human lives every year,
according to your own admission, you have
spent more than Rs. 395 crores per year for
floods and about Rs. 200 crores per year on
an average for drought. And let us see what
is being said now in a very important docu-
ment submitted on 11th April. The Public
Accounts Committee examined the Planning
Commission. Where does the fault lie?
You can say that irrigation is a State subject,
water is a State subject, but the Planning
Commission is involved right from the
beginning to the end, from the stage of
investigation to sanction, monitoring and in
every respect. It is being said here that
something is wrong not with the States but
with the Planning Commission itself. I am
saying that it is in a total mess. Can you
imagine, the figures being given to Parlia-
ment, supplied by the Planning Commission,
by the Ministry, are mostly all wrong? It
has come out here. To an Unstarred
Question as to what was the irrigation poten-
tial created during the period 1975-76 to
1978-79, the Minister replied: five million
hectares. After that, during cross examina-
tion it came out that it was for less than
that—4.35 million hectares or something like
that. Even the Prime Minister was given
that figure and she made a broadcast on the
basis of that figure. Have you any correct
figure? You are fooling us, you are
fooling this House, by giving wrong

figures. Does the Agriculture Ministry agree with the figures given by the Irrigation Ministry ? Here is another example—a difference of two million hectares. And what does this '2 million hectares' mean ? According to the present estimate, the cost per hectare is Rs. 7,000/-. Everything is in a mess. If you look at the figures given by the U.P. Government regarding the ultimate potential and the figures given by the Planning Commission in the Plan document, they are different. This is published by the Government of India, Central Water Commission, it says regarding U.P. about the ultimate irrigation potential of the State as assessed by the Planning Commission and as assessed by the State Government. The Planning Commission says 25.7 million hectares and the State Government says 35.5 million hectares. Come to Bihar. There is big difference here. It is said that the ultimate irrigation potential of major and medium projects, is 6.50 million hectares ; this is as per Annexure 10.2 of the Sixth Plan document ; it is 6.50 million hectares according to the Plan document. But the State Government puts this figure as 9.23 million hectares. One figure is 6.50 million and the other figure is 9.23 million. What are you planning about ?

AN HON. MEMBER : What about West Bengal ?

PROF. RUP CHAND PAL : If the Chair gives me one hour, I can give all the figures.

Now come to utilisation. The backlog of 20 million hectares we could not raise ; we are still living in a world of illusion that we will reach the target by the turn of the century and all those things. Leave that alone. But what is there already, are you in a position to utilise ? 59 million hectares, according to their claim, are the created potential. The utilisation, according to their statistics, is to the tune of 55 million hectares. 4 million hectares are unutilised. Can it happen in any country ? How much we are losing by failing to utilise it, leave alone the question of seepage, the loss in transmission, the loss in distribution and siltation ? Siltation is a big problem, that is coming up. What is the life of these projects—big projects ? Say 80 to 100 years according to international estimate. In 25 years whatever we have achieved are getting silted.

If we come to the question of data, there are very serious things. It is being said every-time that we are in a position to utilise whatever irrigation potential has been created through minor irrigation. Whom are you hoodwinking ? Whom are you fooling ? What is the experience of the cultivators ? What is the life, what is the capability of a tubewell ? For how many hours are they working ? How many days are they working ? What is the ground-water level ? Is water available or not ? How many pumps are energised ? All these problems are there and it is being repeatedly said that we are utilising it hundred per cent. In reply to such a claim, the document says—the question was whether the Minister of Irrigation had any information about the number of tube-wells remaining out of order in a particular year ? The representative of the Ministry replies, 'We do not keep that information as to how many tube-wells are working and how many are not, but the power supply is most uncertain.' Still they conclude that in minor irrigation, in the 30 million hectares potential created, 100% is being utilised. In a country like ours had we been successful in achieving our targets according to Government statistics and admission, we would have produced 23 to 30 million tonnes more than what we produce today. What is the loss ? 23 to 30 million tonnes we are losing cumulatively. This is the end result of wrong planning, lopsided planning and misplaced priorities and it is now time—the time has come—to have a fresh look. They will say, 'We know. We are not satisfied. We have now included all these in our new 20 point programme. Now we have created a new Ministry for that purpose. Now we have given new guidelines.' But due to inter-State disputes only, projects are not being taken up for execution.

Do you have a national policy regarding water—how much of hydel, how much of irrigation, how to strike a balance, what is the opinion, the international opinion now going round regarding finding a match between the use of the two sectors ? Have you any national policy regarding the use of river waters ? Just before the discussion, it had been announced, 'We have started one National Water Resources Board with certain functions stated there to be taken up by them.' One of them is the inter-State water disputes.

I will now come to certain very important things regarding the problems being faced by the people living in the Ganga Basin. You know the problem of Ganga—that during the dry season it is not having enough water and the Calcutta port itself is being endangered day by day. 40,000 cusecs of water should be ensured to Bhagirathi and the West Bengal Assembly unanimously, all parties supporting, had taken one resolution—not once but more than once—and on the basis of that resolution, an all Party delegation came.

SHRI CHITTA BASU : Including Congress (I).

PROF. RUP CHAND PAL : Yes, yes, everyone. All Parties supported it. They unanimously passed a resolution that Calcutta port will have to be saved. Calcutta port is the life line and in our national economy it is playing a very important role. What is the step that you are going to take to save the Ganga? There were many plans earlier and many proposals were there as how to take water, transfer water from this river to that river—just to save the flow, just to augment the flow in the Ganges. Many suggestions came for the augmentation of the flow of Ganga with all the alternatives—storing of monsoon rains, ground water reserves, etc. All these proposals were there but they have not been able to find enough time to take a decision. But, Sir, it is already late and if we do not decide now and take urgent steps, the disaster may come earlier than envisaged.

After this problem of Ganga, I shall try to draw your attention to the measures being taken now. Opinion has been pressed forward and presented by several committees as also by the Public Accounts Committee of Parliament in its latest report.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please try to conclude now.

PROF. RUP CHAND PAL : I am going to conclude.

...that minor irrigation should be taken in right earnest. It is a low cost project, shorter gestation period and people can be made to get involved easily and various schemes like the IRDP, DPAP, NRDP, etc. can be easily implemented, they are labour intensive and so minor irrigation should be

taken up in right earnest. I do not say that major and medium projects will not have their use because, at times of drought and vagaries of nature, major and medium projects do play a very vital role and it is very apt and correct that we should have co-ordination between these three—minor, major and medium and that is the correct policy. But here in this respect I would draw the attention of the Government to the problems being faced by certain parts of the country including West Bengal in regard to shallow tubewells of the private farmers purchased with the institutional finance. I draw the attention of the Minister to this that under the erstwhile Small Farmers Development Agency Programme for small and marginal farmers 82% of all holdings in West Bengal are less than 2 hectare. They used to get some subsidy for the projects but with the introduction of IRDP, the criteria for selection of beneficiaries is standing in the way of sanction of this subsidy to small and marginal farmers. This point will have to be looked into that earlier SFDA has been doing something.

Another thing, that project is lying with you for a long time—West Bengal Public Tubewell Irrigation Projects. I will request you to look into that. My suggestion would be that for the consolidation of the gains already achieved by us, all ongoing projects should be tried to be completed. I do not know how it is going to be completed because I do not live in a world of illusion. According to Government estimates, more than Rs. 50,000 crores are required for completion of the balance target of about 71.42 million hectares to reach our ultimate irrigation potential of 113 million hectares.

My next suggestion will be that in a country like ours, irrigation has been given to the State sector. Right, but they should be given ample powers and financial support to complete the projects. Another thing is about the powers of the State Governments. They should have the financial authority.

When we look at the picture of achievements in certain States, we find that the irrigation potential achieved in Punjab is 80%. They are producing more food than others. There are other States (which have high density of population) who could not produce more because of deficit in irrigation potential. There are regional imbalances. So, this point should be looked into at the time

of giving Central assistance. Mr. Deputy Speaker, in your State, it has been said that enough development in irrigation has been made and there is limited scope in certain areas of irrigation. But in Bihar there is ample scope. Punjab has achieved 80%. There are other States like my own State, West Bengal. Much is yet to be done to increase the irrigation potential. There should be a feeling among the people that the Government is trying to remove regional imbalances in terms of irrigation.

Now, my last point is this. During the last Governors' Conference, a suggestion had come that water and power are the two sectors which should come under the jurisdiction of the Centre. I do not agree with it. I hold just that opposite view. Power and Water should be only with the State. The State should be adequately helped with finance and know-how. The failures which we find today are due to wrong planning and shortage of resources. The Planning Commission do not have correct. They are even supplying wrong figures to the Prime Minister who broadcasts on the basis of these figures. Agriculture Ministry has one figure. Irrigation Ministry has another figure.

Regarding productivity, is there any figure, Sir? No. From the papers with me, it is seen that there is no correct data regarding the difference in yield-per-acre between irrigated and non-irrigated area. Any layman can say that in an irrigated area the yield will be more. But the Planning Commission is unable to say anything about this difference in yield. They have not made any in depth study to find out the difference between the yields of irrigated and non-irrigated area in our country. We have to collect the right data. We have to give the correct priority, the correct perspective. There should be ample powers with the States to implement them. Government should urgently look into the colossal failure in this sector and take lessons for the future. By the turn of the century, with the growth of population, what will be the situation in the food front, we do not know. Now, Sir, my request to the Government would be that they should give serious thought to these developments. Thank you.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : By the turn of

the century would have come to power.

SHRI R.P. DAS (Krishnagar) : I beg to move :

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to implement flood Control Programme under the Sixth Plan.] (38)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to fill up the vacant posts in the Central Water Commission.] (39)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to implement the memorandum of understanding agreed to by the members of the Indo-Bangladesh joint river panel in its 23rd Meeting.] (40)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to control the hilly rivers of North Bengal and effect proper utilisation of the water and protect the region from sharp erosion.] (41)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to provide alternative jobs to persons working in Farakka Barrage Project as muster roll workers and employees.] (42)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to meet the irrigation requirements for the country as set in the last Annual Plan.] (43)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to RE. 1."

[Failure to bring more areas under irrigation by all available means in West Bengal in view of sharp increase in population in the recent years.] (44)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced to Re. 1."

[Failure to put emphasis on bringing additional areas under irrigation by efficient water management by the existing installations.] (45)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to make provision for the West Bengal Deep Tubewell Irrigation Project in the current Annual Plan.] (46)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to build up good relations between the Ganga Basin Water Resources Organisation Staff Union and the management in respect of problems arising out of transfer of employees to far away places from Berhampore Division.] (47)

SHRI CHANDRADEO PRASAD (Verma (Arrah) : I beg to move :

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to complete the work of Buxur-Koilabar embankment in Bihar.] (49)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100"

[Need for pucca lining for the hundred year old Sone Canal.] (50)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need for early completion of the Sandesh Pumping Scheme.] (51)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to provide irrigation facilities through high power pumping scheme within the Buxar-Koilabar embankment plan.] (52)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to provide irrigation facilities through high power pumping scheme for agricultural area along the Canal embankment from Sahar to Koilabar.] (53)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need for proper scrutiny of the expenditure being incurred on irrigation projects in Bihar.] (54)

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : I beg to move.

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to protect the villages like Patasia Sultanpur and other situated on the bank of Ganga in Samastipur district in Bihar, from being eroded away.] (55)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to assess the progress of irrigation projects not on the basis of expenditure but on the basis of work actually executed.] (56)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to settle dispute over sharing Sone river water in Ban Sagar Project among Bihar and other States.] (57)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to utilise all our resources for irrigation purpose in the country in general and Bihar in particular.] (58)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to stop soil erosion of cultivable land in the country in general and Bihar in particular.] (59)

"That the Demand under the Head 'Ministry of Irrigation' be reduced by Rs. 100."

[Need to provide more funds for minor irrigation and lift irrigation project in North Bihar.] (60)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to bring all the cultivable land in North Bihar under irrigation.] (61)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to construct an all purpose dam over Kosi river at Barahkshetra.] (62)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to complete Chingia bandh in Dalsingsarai Prakhnd of Samastipur district in Bihar to protect the area from the flood ravages.] (91)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to complete excavation of drainage channel to drain out flood water from the area around Tara Dhamaun in Patroi Prakhnd of Samastipur district in Bihar.] (92)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to provide sluice gate on the Ganga bandh between Jalalpur and Dhamaun in Patori Prakhnd of Samastipur district in Bihar.] (93)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to complete all projects meant to protect any area from floods well before the approaching rainy season.] (94)

“That the Demand under the Head ‘Ministry of Irrigation’ be reduced by Rs. 100.”

[Need to provide sluice gate on Mirjan nallah in Patori Prakhnd of Samastipur district in Bihar.] (95)

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI (Saidpur) ; I beg to move :

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to fully develop the means of irrigation in the country, particularly in U.P., Bihar and Madhya Pradesh.] (63)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to implement flood control programme under the Sixth Plan.] (64)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to check the damage to agriculture caused by floods every year.] (65)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to achieve the targets of irrigation potential in the country laid down in the Annual Plans.] (66)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to harness the Ganga, Yamuna and Gomti rivers for irrigation purposes.] (67)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to provide more funds for medium, minor and lift irrigation projects.] (68)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to utilize for irrigation purposes the water potential of 18,000 per cubic feet in the Ganga river.] (69)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Rs. 1.”

[Failure to extend the Sharda subsidiary canal in Eastern U.P. and Western Bihar.] (70)

“That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced to Re. 1.”

[Failure to release sufficient water into the canals of U.P.] (71)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to control devastating floods in the Ganga, Gomti, Sai and Varuna rivers every year in Varanasi, Jaunpur and Ghazipur areas of U.P.] (72)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to take steps to augment water potential of fast drying up wells in Harhua, Cholaipur, Badgaon, Chaubepur in Varansi, Ghazipur and Jaunpur districts of U.P.] (73)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100".

Need for a scientific survey and study of water in the basin of the Ganga river in Varanasi, Ghazipur and Mirzapur.] (74)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

Need to construct dams on Gomti and Sai rivers in Jaunpur for irrigation purposes.] (75)

"That the demands under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to properly and effectively use the Deokali Pump Canal, Jāmania Pump Canal, Rajmal Dam, Amora, Bsreji, Gahmar, Deval Pump Canals for irrigation purposes in Ghazipur district of Uttar Pradesh.] (76)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to further extend the lift canals and to release water in them throughout the year.] (77)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to develop the means of irrigation on the basis of command areas already determined.] (78)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to check the further deterioration in the under-ground water level in eastern districts of Uttar Pradesh Particularly Ghazipur, Varanasi, Balia, Jaunpur, Ajampur & Mirzapur.] (79)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to protect the standing crops from floods every year in Rajwadi Kainthi, Rauna Kalan, Dharhara-Nithar of Varanasi and Patna, Hathora-Hathori, Kharauna Sidhauna, Sedpur Phulwariya, Naisare, Nari Panch Dewara of Chazipur district and Sarkauni, Jalalpur Chandwak Kerakat and Ratanpur of Jaunpur district.] (80)

"That the demand under head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to provide flood relief material and other concessions to agriculturists in Varanasi, Ghazipur and Jaunpur districts of U.P.] (81)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to pay compensation for the crops damaged due to lack of irrigation facilities.] (82)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to check increasing malpractices in irrigation departments.] (83)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100"

[Need to check misbehaviour of tubewell operators and mechanics towards farmers.] (84)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100".

[Need to provide tube-wells in Varanasi, Ghazipur and Jaunpur districts of Eastern U.P.] (85)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to check erosion of thousands of acres of land every year by floods in Kaihi and Rajwari in Varanasi district and Chandvak and Jalalpur in Jaunpur district.] (86)

"That the demand under the Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100,"

[Need to provide loans for installation of pumping sets to farmers expeditiously.] (87)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to make tub-wells drains pacca in Uttar Pradesh and other parts of the country.] (88)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100."

[Need to pay Compensation to the owners of houses of the Scheduled Casters and others falling as a result of moisture caused by branch canals of Sharda tributary and main canals in Purenb, Trilochan Mahadev and Murki of Jaunpur district.] (99)

"That the demand under the head Ministry of Irrigation be reduced by Rs. 100.

[Need to check damage to crops due to inundation of thousands of acres of land by canals in Jaunpur and Ghazipur districts every year and to pay compensation to the victims.] (90)

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Mr Deputy Speaker, Sir, we are aware of the fact that our economy is an agricultural economy.

Four out of every five persons are drawing directly or indirectly their sustenance from this primary sector, namely, Agriculture. Hence the development of water resources and virrigation is the imperative need for successful and modern agriculture,

Sir, the hon. Member, who had initiated the discussion on the Demands for

Grants of the Ministry of Irrigation, was trying to rub on the wrong side by saying that everything depends on the Central Government, that is, right from the beginning of initiating the proposals for various schemes including the decision-making till their implementation and even the maintenance of those projects, he has said that the Centre is responsible. Sir, we all know that the Ministry of Irrigation at the Centre is a supervisory body and only gives directions regarding the policy matter. So, the hon. Member, Shri Rup Chand Paul, has not cared to point out the responsibilities of the State Governments regarding the maintenance of the projects. He has not said anything about how far they have succeeded in maintaining those tube-wells because they are the people who executed these projects in the State. We all know that, after Independence, specially after launching of the Five Year Plans, about 61.4 million hectares of irrigation potential have been created and it is barnt that out of it 4 million hectares of irrigation potential could not be utilised. Creation and utilisation of irrigation facilities is not only the concern of the Members sitting on this side alone but it concerns the Members on the other side also. I would like to urge upon the Government that they must see to it that whatever potential has been created on the irrigation side, that must be utilised fully in order to get the maximum return, specially at a time when we are repeatedly hit by drought in different parts of our country, so that these irrigation facilities may cover the maximum rain-fed areas and help reduce our dependence on the monsoon.

Therefore, may first request to the hon. Minister is that he should take immediate and prompt action to see that whatever projects that are still pending in the Central sector and remain to be cleared by the Centre, should be cleared immediately and this should be given the utmost importance and after the Centre's clearance, these projects must be taken up for execution and completed immediately. The Annual Report of the Ministry states that due to untimely completion of these projects, Government had to spend an enormous money on flood-relief measures as well as on drought relief measures. In this connection, I would like to point out that while replying to some

of the questions the hon. Minister had stated that when a particular project was completed there was a difference between the actual potential created and original potential projected in the project Report.

The Hon. Minister had stated something while replying to questions in the Rajya Sabha. I would like to quote few sentences from it :

“There is a lag of about 4 million hectares between the potential created, and the utilization created in irrigation. This is mostly due to lack of field channels and other on-farm development works in the Command areas of projects. In some projects, the actual potential achieved is found to be less than the original project potential. So, there is usually a lag of one year between the creation of potential and its utilization, as the reservoirs have to fill up after the completion of the project works, before being utilized.”

In this particular case, I would like to point out how our estimate differs from the original estimate that Government had made earlier, while they considered or while they cleared the project at the Central level. Similarly about the Command area, on Monday the hon. Minister had stated while replying to a question, that there had been a colossal loss due to seepage and absence of field channels and other factors. He said that an area of 7,43,740 acres of land in the Command area of irrigation projects in nine States were affected by water-logging. He has mentioned only nine States. There are also States from which there is no report. So, there must be some addition to these colossal figures.

I would like to emphasize here that unless we take follow-up measures to see that whatever irrigation potential is created in the country is utilized in the best interests of the people and the farmers, there will be no use of spending on the projects. There will certainly be colossal losses. With regard to the potential created, there should be a monitoring cell. There should be regular monitoring right from the beginning of implementation till the completion of the project. There should

also be monitoring to see how far we have utilized the potential which we have created.

In this connection, I would like to point out one aspect relating to my State. We all know that due to floods as well as brought, the loss is colossal all over the country. On Monday, I had put a question. The hon. Minister, Shri Mirdha had pointed out that there were flood control projects which states had submitted to the Centre. The Centre had also referred them to the States for their comments. There is one case in my State. Here is one flood control project, viz. the Subarnarekha Double Embankment scheme. The Centre had referred this back to the State for its comments more than a decade back, i.e. on 19.2.1971. The Centre had referred this flood control project back to the concerned State Government, viz. Orissa. The hon. Minister has stated on 11th April 1983 that they have not yet received the comments from the State.

The hon. Member from West Bengal, while he was speaking, pointed out that due to lack of follow-up measures, our projects have met this kind of a fate.

In this particular case, I must say that these flood control projects not only relate to Orissa, but there is a portion which concerns the State of West Bengal. They are also somewhere affected by these projects. They have also to send their reaction to the Centre, but they have not yet, what I have understood, sent their reaction to the Centre. Even the Orissa Government has not recommended regarding these projects. That is why, from 1971 till today, this project is still pending ; there is no action taken in this regard. There are other projects also. Here in reply (a) to the Starred Q. No. 593 dated 11.4.1983, they have mentioned that there are many projects, flood control schemes right from flood control scheme for Baitarni system (post Bhimkund dam conditions) to Bhimkund multipurpose project stage-I on river Baitarni. It concerns the State Government. They have not yet submitted their reaction. So, yet submitted their reaction. So, I would like to emphasise that there must be some time-bound programme regarding

implementation of these projects. Otherwise, it will be no use just talking, just making promises to the people that these projects will be taken up very soon or flood control measures will be taken up very soon, etc.

Similarly, there is the scheme to survey of the ground water resources of the Country, Here while replying to the question, the hon. Minister stated that this survey will be completed only after the completion of the Sixth Five Year Plan. If it takes another three years to complete this survey, then how long will they take to complete this survey, then how long will they take to have the scheme implemented for the irrigation of the area which needs immediate irrigation? In the report the hon. Minister has stated, at the Conference of the State Irrigation Ministers at Madras, they have laid stress on the on-going projects and said that on-going projects should be completed during the Sixth Five Year Plan and after it the new projects will be taken up. I support this proposal. Whatever on-going projects remain to be completed must be completed during the Sixth Five Year Plan, Otherwise, the report itself said that there will be time lost as well as there will be escalation of cost. Therefore, I request the hon. Minister to see that whatever potential we have created that should be utilized and the on-goings projects that remain to be completed must be completed in time. The government's target of creation of 3 million hectares of irrigation potential during the remaining years of the 6th Plan is really commendable. But unless follow up measures are taken up, unless at least specific and monitoring cells are created to to monitor the progress of the projects and progress of the steps taken, there will be a backlog of projects which may spill over even to the seventh Five Year Plan. Therefore, support the Demands for Grants of the Ministry of Irrigation. I request the hon. Minister to take these points into consideration. I also request him to take steps to complete at least on-going projects during this Plan itself.

14.56 Hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

श्री राम किकर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने

मुझे सिंचाई सम्बन्धी अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज किसानों तथा सरकार का दुर्भाग्य है कि इन्द्र-देव कुपित होकर पिछले एक सप्ताह से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा कर रहे हैं और ओले भी पड़े हैं। हमारी खरीफ की फसल भी चोपट हो गई थी। जायद की फसल भी जिसमें शाक सब्जी, फल एवं खाद्यान्न भी बोया जाता है, क्षतिग्रस्त हो रही है। आजादी से पूर्व सवा दो करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी जबकि 13 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती थी। 32 करोड़ हेक्टेयर में से इस समय 17 करोड़ हेक्टेयर में खेती तथा 6 करोड़ में वन हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक साढ़े 5 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई होती थी जबकि खेती 17 करोड़ हेक्टेयर में होती थी। अब तक केवल 33 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है।

मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश की शारदा सहायक परियोजना की ओर खींचना चाहता हूँ। शारदा सहायक परियोजना पर 315 करोड़ रुपए खर्च हुए और लम्बे अर्से में बनाकर पूरी की गई। उसके द्वारा 14 जिलों में सिंचाई होती है जिसमें दो जिले उत्तर के खीरी लखीमपुर और सीतापुर हैं। इसके बाद बाराबंकी है। उसके नीचे राय बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर इत्यादि 14 जिलों में सिंचाई होती है। इन जिलों को साल के सात-आठ महीने तक खासकर बाराबंकी की धरती से पानी जाता है। इन नहरों से और छोटी नहरों से सीपेज की काफी समस्या है। इन नहरों पर घाघरा से गिरिजा बराज द्वारा पानी गिराया जाता है और फिर शारदा में दूसरा बराज बनाया गया है। 28 किलोमीटर लिंक चैनल है और 260 किलोमीटर फीडर चैनल हैं। बड़ी नहर जो फीडर चैनल है, उसका 45 किलोमीटर का भाग दोनों तरफ बाराबंकी में है। इस नहर के

दाहिनी तरफ आज भी पानी की बड़ी समस्या है। पुरानी शारदा कैनल का टेल एण्ड होने के नाते दाहिनी तरफ का बहुत सा हिस्सा बिना पानी के रह जाता है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे लेकिन टेल एण्ड पर आज तक न कोई सरकार पानी दे सकी है और न आगे ही पानी दे सकने की क्षमता है। क्योंकि आज अराजकता का बोलबाला है, कुछ बड़े लोग लट्ठ, फरसा और बन्दूक लेकर खड़े हो जाते हैं और टेल एण्ड के किसानों को सींचने के लिए पानी नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह है कि पहले चौड़ी नहरें बनने से बड़ी दूर तक सिंचाई हो जाती थी लेकिन अब छोटी नहरें बनने से पानी भी दूर तक नहीं पहुंचता है। इसकी चर्चा मैंने सिंचाई एडवाइजरी कमेटी में भी की थी। यहां से उच्चाधिकारी गए थे और उन्होंने भी यह महसूस किया कि पानी की कमी के कारण किसानों को बड़ी तकलीफ है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में सर्वप्रथम रीमाडलिंग करके जो पुरानी नहरें हैं, जो टेल एंड में पड़ती हैं, उनको ठीक किया जाए तथा पानी दिया जाए। यदि नहरों से पानी देना सम्भव न हो तो उस स्थिति में वहां पर राजकीय ट्यूबेल लगाये जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त शारदा सहायक फीडर चैनल है, जिसके 112 किलोमीटर पर पूर्वी कल्याणी साइफन बना हुआ है और 118 किलोमीटर पर दूसरा पश्चिमी कल्याणी साइफन बना हुआ है। इनमें पानी निकालने की क्षमता ज्यादा है। दुर्भाग्य से जिस वक्त इंजीनियरों ने इसको बनाया, उस वक्त उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि इन दोनों साइफनों को जोड़ने वाली दोनों कल्याण नदियों को चौड़ा और गहरा बनाया जाए। यदि इसको चौड़ा और गहरा बनाया गया होता तो पश्चिम के दाहिनी तट पर जो हिस्सा पानी में डूबा रहता है, उससे किसानों को छुटकारा मिलता।

दरियाबाद एक समानान्तर नहर है, जिसमें दो नहरें पैरलल चलती है। यदि एक नहर में पानी छोड़ दिया जाता है, तो एक और सीपेज की समस्या पैदा हो जाती है। अगर बन्द कर दिया जाता है पानी, तो उसकी समस्या धीरे-धीरे घटने लगती है। इसके साथ ही साथ यदि दूसरी नहर में पानी छोड़ा जाता है, तो भी इसी प्रकार की समस्या पैदा होती है। पिछले पांच-छः वर्षों से यह सीपेज की समस्या लगातार रही है। केवल 1979 में जब उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों में भयंकर सूखा पड़ा था, तो उस साल सीपेज वाले क्षेत्र में पैदावार ज्यादा हुई थी। सीपेज की समस्या आज भी काफी भयंकर है। मेरे पास रिपोर्ट है, सीपेज के कारण जितना क्षेत्रफल प्रभावित होता है, उससे कम आंकड़े दिये जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी काफी खेती परती पड़ी हुई है, जहां पर बुआई नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां जमीन परती पड़ी हुई है और पिछले चार पांच वर्षों से बुआई नहीं की जाती है, उसका लगान माफ होना चाहिये, उनकी सिंचाई कर मुक्त होना चाहिए। जहां खड़ी हुई फसल सीपेज या नहर टूटने से चौपट हो जाती है, उसका सरकार को मुआवजा देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में लॉ. एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। वहां मजदमानी की जाती है। सारी गलत रिपोर्ट सरकार को दी जाती है। राष्ट्रीयता की भावना न तो सरकारी आदमियों में है और न आम जनता में इतनी है। देश का नेशनल करैक्टर क्या था? और अब 35 सालों की आजादी के बाद क्या है? इस पर विचार करना पड़ेगा। अकेले बाराबंकी में निचली जमीन और नहरों के कारण 585 मिलियन घन मीटर पानी की वहां क्षमता है। इस क्षमता से 1500 नलकूपों को फीड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना में 2200 नलकूपों का प्रस्ताव है। यदि

इतने नलकूप एक ही जिले में लगा दिए जाये तो और स्थानों पर उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकेगा।

शारदा परियोजना से 20 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सकती है। है। जबकि 19.23 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था जून 1983 तक हो जाएगी। शारदा सहायक परियोजना में बैराज बने हुए हैं। गोमती जल सेतु पूर्वी एशिया में अपने किस्म का एक निराला जल सेतु है। इस पर 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इससे एक बून्द पानी भी नहीं गिरता है। आप भाखड़ा नांगल को देखिए, यहां भी सीपेज ही समस्या है, लेकिन यहां आज भी एक बून्द पानी नहीं गिरता है। इसको बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। शारदा परियोजना के अन्तर्गत 13,400 किलो-मीटर लम्बी नहर है, जिसमें 7 हजार किलो-मीटर नई नहर और 6,400 पुरानी, जिसको ठीक कर के पानी चलाया जा रहा है।

मान्यवर, आज जल की जो क्षमता है उस का 40 प्रतिशत जल बेकार जाता है, जिसमें नहर के कच्ची होने या किसी अन्य वजह से या लोगों की लापरवाही की वजह से काफी पानी बरबाद हो जाता है। इस को ठीक किया जा सकता है, यदि प्लास्टिक की चादरें लगा दी जाय या जहां जमीन की सतह से ऊंची नहर है उसको पक्का कर दिया जाय तो सीपेज रुक सकता है और समस्या का समाधान हो सकता है।

आज सरकार नहर के दोनों किनारों पर ड्रेनज बना रही है, जल-निकासी के लिये, लेकिन उन ड्रेनज की सफाई नहीं करते हैं और न उन के पानी को नदी या नाले में गिराते हैं, जिस से एक जगह की मुसीबत दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। ड्रेन खोदने का नियम यह है कि ड्रेन नीचे से खोदी जाय और नहर ऊंचाई से खोदी जाय, लेकिन यहां उल्टा काम होता है। जो जूनियर इंजीनियर या उच्च अधिकार होते हैं वे ठेकेदारों से मिल कर गलत लाईनिंग लगा देते हैं, गलत जगह पर नहर को खोद देते हैं।

नतीजा यह होता है कि किसान को कोर्ट में जाना पड़ता है, वह स्टे आर्डर ले आता है और काम 10 वर्ष के लिये रुक जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को तम्बीह की जाय, उन के खिलाफ एक्शन लिया जाय। आज न जाने कितनी नहरें इस तरह से पड़ी हुई हैं, बाराबंकी में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं।

भारत वर्ष में जो जल उपलब्ध है, अगर हम उस का पूरा सदुपयोग कर सकें तो 2 करोड़ हैक्टेयर सिंचाई की एडिशनल वृद्धि की जा सकती है। मान्यवर, राजाध्यक्ष कमेटी ने कुछ ऐसी सिफारिशें की थीं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था—दो या दो से अधिक राज्यों में नहर और नदियों को लेकर जल विवाद हो तो उन को तीन महीने के अन्दर समाप्त कर देना चाहिये। अगर तीन महीने में समाप्त नहीं होते हैं तो केन्द्र को चाहिये कि वह ट्रिब्यूनल नियुक्त कर दे और ट्रिब्यूनल को भी तीन महीने में फैसला कर देना चाहिये। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि ऐसा फैसला जो हो उस के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एक और अच्छा सुझाव दिया था जो उद्योगपति अपने उद्योग घन्घे व कल-कारखाने लगाना चाहते हैं उनको अपना पैसा खर्च कर के बिजली का उत्पादन करना चाहिए, उन के लिये बिजली की व्यवस्था सिंचाई हेतु बिजली की कटौती करके नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, पिछली पांच पंच वर्षीय योजनाओं में सिंचाई के क्षेत्र में हमने क्या प्रगति की है मैं उस की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से लेकर 1956 तक 80 करोड़ रुपया का तथा 456 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करके 262 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता बनी। 1956 से 1961 के बीच 522 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और 291 लाख हैक्टेयर की क्षमता हुई। 1961 से 1966 में 909 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और

336 लाख हैक्टेयर की क्षमता हुई. 1966 से 1974 में 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और 442 लाख हैक्टेयर की क्षमता हुई। 1974 से 1978 में 3073 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई और 521 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता बनी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 137 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

कल्याणी नदी पर जनता सरकार के वक्त साढ़े-उन्चास (49.5) लाख रुपये स्वीकृत हुए थे तथा 1982 तक 22 लाख रुपये खर्च हुए। मैं उस क्षेत्र में गया था। 22 लाख में से यदि 12 लाख भी खर्च हुए हों, तो मैं समझता हूँ सही खर्च हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ एक अधिकारी थे, संजोग से उनके एक और उच्च अधिकारी लखनऊ में थे और दुर्भाग्य से उनके एक मंत्री भी सरकार में थे, नतीजा क्या हुआ? वहाँ पर 45 लाख रुपये गड़बड़ घोटाला हुआ। बाराबंकी सिंचाई विभाग में जो आज अधिकारी आये हैं उनकी कोई जिम्मेदारी उस सम्बन्ध में नहीं है। उनके पास सिवाय लीपापोती करने के और कोई चारा नहीं है।

मान्यवर, खेत और नालियों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ। सिंचाई की क्षमता तभी बढ़ सकती है जबकि खेत समतल हों नालियाँ ठीक बनी हों। किसानों में भी जागरूकता होनी चाहिए और देश में नेशनल कान्सेप्शन होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा आप से निवेदन है कि ये जाँ बत्तक कमेटीयाँ होती हैं, इनकी मीटिंग्स में रबी और खरीफ की फसल के समय खास तौर पर नहर विभाग के अधिकारियों को जाना चाहिए और पानी के महत्व को समझाना चाहिए। प्रदेश सरकारों को भी सिंचाई के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

मान्यवर, श्री केदार पांडे ने 1982 में यह कहा था कि 60 फीसदी सीपेज वाली नहरों पर प्लास्टिक की चादरें बिछायी जाएंगी। जहाँ यह समस्या है, उनमें से कुछ राज्यों में चादरें

बिछायी गयी हैं। यह चीज लाभदायक है। नहर के किनारों को भी पक्का करना चाहिए।

अभी हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक पूरे हिन्दुस्तान में 1981 तक 37 हजार, 993 नलकूप थे जिनमें 19 हजार 331 नलकूप उत्तर प्रदेश में हैं। उनमें कितने लूले और लगड़े या बीमार हैं, यह हम नहीं बता पायेंगे।

अभी वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट भी आयी है। हिन्दुस्तान भर में 22 सूबे हैं और 9 यूनि-यन टैरिटरीज हैं जिनमें से केवल 9 सूबों की रिपोर्ट आयी है जिनके मुताबिक 7 लाख 43 हजार 740 हैक्टेयर भूमि में वाटर लॉगिंग है जिसकी वजह से इतना मुकसान हो रहा है।

मान्यवर, बहुत पहले डा० के० एल० राव एक प्रसिद्ध इंजीनियर सिंचाई मंत्री थे। उनकी एक योजना थी कि गंगा को कावेरी से मिला दिया जा। 1971 में वह योजना यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम के पास भेजी गयी। वहाँ से 1973 में वह रिपोर्ट विस्तार पूर्वक बन कर आयी। वह वृहत् रिपोर्ट है और उसके मुताबिक यह काम चल सकता है। पाँच वर्ष में इसके सर्वे का काम पूरा होगा और तीस वर्ष में इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा। प्रतिवर्ष कंस्ट्रक्शन वर्क पर 11 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बारे में एक दूसरी राय यह थी कि हिमालय पहाड़ पर जब भयंकर वर्षा होगी, तभी पानी का जल प्रवाह कावेरी में अच्छा रहेगा, अन्यथा औसत भी बरसात होगी तो कावेरी में फलो नहीं रहेगा। इसके लिए पटना से दो सौ मील चलने के बाद दो हजार फीट की ऊँचाई पर एक बांध बनाना पड़ेगा और वहाँ से पानी लिफ्ट करना पड़ेगा जिस पर 7 हजार 5 सौ मेघावाट बिजली लगेगी। उसके आगे कृष्णा नदी के पास पहुँचने के बाद फिर तीन सौ फीट ऊँचा बांध बनाना पड़ेगा और पानी लिफ्ट करना पड़ेगा। इस सारे काम पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च होगी।

मान्यवर, एक दूसरी योजना दस्तूर योजना है जो कि इस से कहीं अच्छी साबित होगी। उसमें हिमालय पहाड़ से बरफ से निकलने वाली

नदियों का रावी से ले कर ब्रह्मपुत्र नदी तक नहर बनाने की बात है। उस पर बिजली की कम खपत होगी। इस योजना में दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट पर करीब नौ हजार किलोमीटर लम्बी नहर बनाई जाएगी और उसके द्वारा जो पानी अरेबियन सागर में जाता है, वह पानी तमिलनाडु और दक्षिणी पठार की तरफ ले जाया जाएगा और बोम्बे शहर को भी पीने हेतु भेजा जाएगा।

मान्यवर, आपके राजस्थान में बहुत दिनों से एक राजस्थान नहर की योजना चल रही है जो कि रुपये पैसे की कमी की वजह से क्रियान्वित नहीं हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी राय में यह योजना गंगा-कावेरी योजना से अच्छी होगी। इस नहर को यदि हिमालय पहाड़ की नदियों का पानी दिया जाए तो यह योजना बहुत कामयाब हो सकती है।

श्रीमती गुरुब्रिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) स्पीकर साहब, सँचुरी के शुरू में रायल कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा था—

Agriculture in India is a gamble on the rain

आजादी मिलने के बाद यह हम नहीं कह सकते। इंडीविजुअल के लिए हो सकता है लेकिन मुल्क में ऐसी हालत नहीं है कि हमको बाहर से मंगाना पड़े। बफर स्टॉक के लिए अलग बात है।

आप हमको यह देखना है कि किस तरह से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाने के लिये सिंचाई की खास आवश्यकता है। जब आजादी मिली उस वक़्त 20 मिलियन हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी। 1970-71 तक 38.01 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 1970-71 तक 38.01 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 1975-76 में 43.65 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और 1980-81 तक 55.60 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। अगर इसको अच्छी तरह से देखें तो पता चलेगा कि 1950-51 से 1970-71 तक एक मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष सिंचाई इक्कीज

हुई और 1970 से 1980 तक 2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष इक्कीज हुई। छठी पंचवर्षीय योजना में 3 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है सँचुरी के अंत तक 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया सिंचित करने की योजना है। यह तभी हो सकता है जब आधुनिक टेक्नालाजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। प्रधान मंत्री जी ने भी अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को प्रथम प्रायोरिटी दी है। आइडिया यह है कि फूड एण्ड फाइबर के उत्पादन को स्थिर रखा जाए और बढ़ाया भी जाए।

13.19 Hrs.

[SHRI R.S. SPARROW in the Chair]

देखना यह है कि हमारे यहां कई जगह फ्लड आता है और कई जगह सूखा पड़ता है। अब सोचने की यह बात है कि जहां फ्लड है वहां का पानी सूखाग्रस्त इलाकों में किस तरह से पहुँचाया जाए। दस्तूर प्लान के बारे में मैं बाद में कहूँगी। यह महत्वपूर्ण मामला है। इस ओर ज़्यादा तवज़ह देने की आवश्यकता है। सिंचाई को कोर सेक्टर में शामिल किया जाए। 1980 तक 55.60 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था। सिंचित क्षेत्र कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है।

दो-तीन किस्म के मेजर, माइनर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में कितनी एलोकेशन हुई है, वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1980-81 में 10,203 करोड़। इंस्टीट्यूशनल सोर्सिंग से भी हमें 1,700 करोड़ मिलने की उम्मीद है। कमान्ड एरिया डवलपमेंट के लिए भी तकरीबन 850 करोड़ रखे हैं और टोटल आउट-ले 12,750 हो जाता है। मिर्घा जी ने अपनी स्पीच में कमान्ड एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम पर ज़्यादा जोर दिया है। जो हमारे पहले मिनिस्टर थे उन्होंने दो दफा अपनी स्पीच में नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी के बारे में बताया

है। मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहती हूँ कि जो परफारमेंस बजट आपने दिया है उसमें 5000 करोड़ का प्लान बनाया है। 28 अक्टूबर 1981 के एक अखबार में मैंने देखा उसमें लिखा था "50,000 करोड़ प्लान टू टैप वाटर रिसोर्सेज।" अपने जवाब में मंत्री जी अच्छी तरह इस बारे में एक्सप्लेन कर दें जिससे हमें कुछ जानकारी हो सके। इरीगेशन और एग्रीकल्चर का सारा काम जो सेक्टर का है वह स्टेट सैक्टर को चला जाता है। इसका सारा डवलपमेंट स्टेट द्वारा ही किया जायेगा। जितने भी पालिसी प्रोग्राम्स बनते हैं, वे इरीगेशन मिनिस्ट्री द्वारा बनाए जाते हैं। देखना तो यह है कि जो हमारे पास इरीगेशन पोटेन्शियल है उसको ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार एफीशियेटली इस्तेमाल करें और जो पर-यूनिट एरिया प्रोडक्शन है वह उसके मुकाबले में ज्यादा बढ़ाया जाए। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गैप है। इस गैप को जितना हम कम करेंगे नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ जायेगा। यह गैप जो है वह इरीगेशन पोटेन्शियल में और जितना यूटिलाइज करते हैं, उसमें होता है। फ्लड्स और सूखे को देखते हुए नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी को 8 जुलाई 1982 में बनाया गया। इसमें इन्होंने नेशनल पर्सपेक्टिव फार वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट के बारे में फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके दो कम्पोनेंट्स हैं। एक तो पेनीनसुलर रिबर्स और दूसरा हिमालयन रिबर्स। यह मैं नहीं कहना चाहती कि इन दरियाओं से कम स्टोरेज किया जाए और फिर लिफ्ट इरीगेशन से पानी लाकर ड्राउट प्रोन एरियाज को दिया जाए। डा० दस्तूर की प्लान को गार-लेन्ड प्लान कहा जाता है। अभी जो मिनिस्ट्री ने कहा है वह नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फार वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट है। इनका आइडिया यह है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को कावेरी से मिलाया जाए। वेस्ट साइड या उड़ीसा के कोस्ट पर जो दरिया जाते हैं और उनमें जो बाढ़ आती है, उनके पानी को इकट्ठा करके ड्राउट

प्रोन एरियाज को दिया जाए।

उससे यह फर्क पड़ेगा कि तकरीबन 35 मिलियन हेक्टेर्स ऐडिशनल इरीगेशन पोटेन्शियल बढ़ जायेगा। मंत्री जी बतायें क्योंकि इसमें लिखा है फारफोरमेंस बजट में कि The schemes for surveys and investigations is estimated to cost about Rs. 107 crores and is expected to be completed in a period of 7 to 10 years. तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो इतना बढ़िया प्लान है इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा? तब कह सकेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर गैम्बल नहीं है रेन पर। तो कब तक इस पर मास्टरी कर सकेंगे?

दूसरे जो फ्लड कंट्रोल का प्रोग्राम है यह बहुत ही अच्छा है :

The Central Water Commission is responsible for the coordination of flood control and drainage works being carried out in the country.

और अभी अभी मैं पढ़ रही थी आपने फ्लड कार्टिग इन्टर स्टेट रिवर पर की है। चौथी प्लान में कहा है :

There are flood-prone basins of Ganga, Brahmaputra, Narmada, Tapti and Tiesta.

यह तीसरा वही है जो सिक्किम से निकलती है और coastal areas of Orissa.

इसके दो सेंटर्स आपने रखे हैं एक पटना में चीफ इंजीनियर के अन्डर और दूसरा साउथ आफ हैदराबाद। आपने उनको भी कहा है :

Hydraulic and forecasting systems are being improved and modernised. The word "modernised" is very important.

जो तमिलनाडु में कहत पड़ा है, वहां का सिस्टम इतना पुराना है जो चोला किंग्स के समय का है। तो जिस वक्त साउथ वेस्ट मानसून न हो और सिस्टम मोडर्नाइज न होने की वजह से जो इस वक्त पानी की कमी है इसको समाप्त किया जाय। तो इसका मोडर्नाइजेशन करना बेहद जरूरी है। जो स्कीम बनी है मंत्री जी इसको एक्सप्लेन कर दें।

अ—आप ब्लॉन्स बगैरह भी देते हैं फलड कंट्रोल वक्स के लिये, और उसके आगे जाकर कमान्ड एरिया प्रोग्राम है जो महत्वपूर्ण है जिससे तकरीबन ज्यादा से ज्यादा, पीडक्शन बढ़ सकता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी।

अब जो आपने माइनर इर्रिगेशन शुरू की है deep wells, boring well, deep-pipe tubewells, etc.

इसके साथ ही साथ सरफेस वाटर और स्टोरेज स्कीम, लिफ्ट इर्रिगेशन आ गया। तो मतलब यह हुआ कि :

The physical features of irrigation projects and agricultural development are closely linked.

इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना है तभी काम बनेगा। अब यह देखना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। अगर पानी पर पूरा कंट्रोल हो क्योंकि पानी कोस्टली इनपुट है एग्रीकल्चर के लिये। आपने कमान्ड एरिया प्रोग्राम में क्रेडिट भी लेने के लिए जमींदार को मदद करनी है। ऐसे ही पानी कोस्टली इनपुट है और इसकी तरफ आपको पूरी तवज्जह देनी है।

पहले जमाने में तो क्या होता था कि रेन पर किसान को डिपेंड करना पड़ता था और अगर बारिश हो गई तो अच्छा कनक पैदा हुआ, नहीं तो नहीं हुआ।

लेकिन आजकल आप सब जानते हैं कि कितना फर्टिलाइजर देना है, 5 पानी देने हैं और इतने-इतने महीने के बाद देने हैं। उसके बाद जो ग्राप मल्टी-क्रॉपिंग करना चाहते हैं, वह पानी के बगैर ही नहीं सकती है।

दूसरी चीज यह देखनी चाहिये कि ड्राउट-प्रोन एरिया से मैक्सिमम प्रोडक्शन हमने कैसे लेना है। आप लेबोरेटरी में सब टेस्ट कराते हैं और पालिसी प्रोग्राम बना देते हैं लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसे लेबोरेटरी से लड पर कैसे ले जायेंगे? मेरा एक्सपीरिएंस यह है कि जो हमारे इन्स्पेक्टर जाते हैं, उन्हें कितना पता होता है?

मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे अमदानगर में आपने लडकों को ट्रेनिंग दी है, उसको एक्सटेंड करें और इस तरह के लडके तैयार करें जो कि वाटर मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह ट्रेनिंग लें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कोर्स में भी वाटर मैनेजमेंट का कोर्स शामिल कर दें, इससे स्टेट गवर्नमेंट के पास रेडी रिक्लूटमेंट हो जाती है और यह भी नहीं होता कि सोवर स्किल्ड पीपल, सैमी स्किल्ड के वक्त पर लाये गये हैं। यह बहुत जरूरी है और केडर-वेस्ड लोगों को आप तैयार करें।

पांचवी प्लान के शुरू में आपने कमान्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसका मेन ओबजेक्टिव यही था—

“To accelerate the optimum utilisation of irrigation potential under the selected major and medium irrigation projects for increasing agricultural production.”

फार्म पर डेवलपमेंट की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैं देखती हूँ कि पंजाब तो अच्छी खासी डेवलपड स्टेट है। हम तो जब से पैदा हुए वहां बाराबन्दी के बारे में सुनते हैं लेकिन आपके कमान्ड एरिया प्रोग्राम में जो आपने रोटेशनल बाराबन्दी को जोर दिया है उसे जरूर शुरू करो। आप जो 1.5 एकड़ जमीन बाराबन्दी के नीचे लाए हैं यह मुझे समझ नहीं आती। जब हम उड़ीसा गये तो वहां हमने देखा कि कंसीलडेशन आफ होल्डिंग नहीं है। कई स्टेट ऐसी बैकवर्ड हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। पंजाब में बाराबन्दी भी है और फील्ड चैनल्स अच्छा प्रोग्राम है। 50-50 आप शेयर देते भी हैं, इससे पानी सीपेज नहीं होता। इसकी वजह से पूरा पानी लगता है और ड्रनेज की उतनी जरूरत नहीं है।

मैं आपको एक अजीब बात बताती हूँ। मेरी कांस्टीट्यून्सी फरीदकोट है उसकी तहसीलमुक्तसार है, उधर वाटर प्लानिंग हो रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट मोगा में वाटन प्लानिंग थी मैं एक कुलीग से हाल पूछ रही थी कि वहां अब

क्या हाल है। वह कहने लगे कि मोगा में पानी बहुत नीचे चला गया है। हम चाहते हैं कि कैनल ऐसे जगह हो जिससे वाटर लेवल ऊँचा आये। डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट प्रब्लम हैं। एक ही प्लान आपका आल इण्डिया के लिये है, मेरा कहना है कि यह स्टेटवाइज प्लानिंग होनी चाहिये। फर्क-फर्क प्रबलम के लिये फर्क-फर्क प्लानिंग होनी चाहिये।

मुझे खुशी है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में 76 प्रोजेक्ट हैं 16 स्टेट में और यूनियन टैरिटरी में 1 है। इसमें आपने जो इतना ध्यान दिया है, उससे हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि यह लगता है कि यह बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त आप स्टेट को बोलें कि वह इनका ख्याल रखें।

पीछे जो कान्फरेंस हुई थी कि जो 76 प्रोजेक्ट दिये गये हैं, उनको पहले खतम करो, कम्पलीट करो तो उनको कम्पलीट करते वक्त सीमेंट नहीं मिलता है। होना यह चाहिये कि जो प्रोग्राम शुरू करें, वह कम्पलीट तो किया जाये।

अब मैं पंजाब के बारे में एक दो बातें कहूँगी। थियन डैम के बारे में पंजाब के पेपर ट्रिब्यून में 21 अक्टूबर को एक आर्टिकल आया था, जिसमें नाराजगी भी जाहिर की गई थी। उसमें कहा गया था कि 1964 में इसकी लागत 69.6 करोड़ रुपए थी और 1980 में वह 469 करोड़ रुपए हो गई। मेरा ख्याल है कि अब वह 600 करोड़ रुपए हो गई होगी और अगर नहीं हुई है, तो हो जाएगी। श्री महाजन ने नागल में स्पीच देते हुए कहा था कि सातवें फाइव-ईयर प्लान में हम इसको सेंक्शन दे देंगे। मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर साहब अपने जवाब में साफ बताएं कि आया यह प्लान या कि वह यह काम शुरू कर दे। उन्होंने क्वार्टर बनाना और डिगिंग करना शुरू कर दिया था।

कोई पेपर कहता है कि उसने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, कोई कहता है कि 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यह मामला बहुत काम्प्लिकेटिड हो गया है।

इंदस वाटर ट्रीटी के तहत हमने पाकिस्तान को काफी पैसा दिया था। 1970 से रावी के सारे पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वह सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है। उस पानी से पांच स्टेट्स—राजस्थान, हिमालय प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा और पंजाब फायदा उठाएंगी। मिनिस्टर साहब इसके लिए पैसा मुहैया करें, ताकि इसको 1987 तक कम्पलीट करने का टारगेट पूरा हो सके। इससे काफी जमीन की इरिगेशन होने के साथ साथ पावर जेनरेशन भी होगा। आप जानते हैं कि पावर जेनरेशन डेवलपमेंट प्लानज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मिनिस्टर साहब साफ तौर पर बता दें कि इस डैम की क्या पोजीशन है। जब तक सेंटर इसमें एक्टिव और कीन इन्वेस्ट नहीं लेगा, तब तक इस सिलसिले में प्रोग्रेस नहीं हो सकती।

कंडी एरिया के बारे में पंजाब विधान सभा में बहुत से क्वेश्चन्ज हुए, जिनमें कहा गया कि हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश का एरिया लगता है, वहां लिफ्ट इरिगेशन से पानी आता है, लेकिन पंजाब की तरफ सूखा पड़ रहा है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है, जो सब से ज्यादा व्हीट और राइस देती है। हरियाणा भी देता है, लेकिन पंजाब सबसे ज्यादा देता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में इस बारे में बात करके कंडी एरिया में डीप ट्यूब-वेल लगाने का इन्तजाम किया जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम में जमीन को लेवल करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह हम काफी एरिया को ले सकते हैं।

जो एरिया भाखड़ा की मेन लाइन कैनल और आनन्दपुर साहब चैनल के पास है, वहां के फार्मर्ज को कहा गया था कि उन्हें पानी दिया जाएगा, लेकिन आज तक वहां कोई पानी

नहीं है। पानी पास से जाता है और किसान तरसते रहते हैं। क्या उस कैनल का पानी वहां भी देंगे या सीधे हरियाणा में ले जाएंगे? गवर्नमेंट ने प्रामिस किया कि फार्मर्ज को पानी दिया जायगा, लेकिन नहीं दिया। इसका असर बहुत बुरा पड़ता है।

कुछ थोड़े से प्लाइट्स मैं और रखना चाहूंगी। आपने एक नेशनल प्लान बनाया है, उसके बारे में मैं कह चुकी हूँ कि यह जो एप्रोच है वह एंटीग्रेटेड होनी चाहिए, पीस मील तौर पर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके रिज-स्ट्स अच्छे नहीं निकलते हैं।

हरियाणा के साउथ-वेस्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है। उस एरिया में सिर्फ ज्वार बाजरा की फसल होती थी। मुझे वहां पर भिवानी, महेन्द्रगढ़ जाने का मौका मिला। हमने देखा है स्प्रिंकलर सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है जिसका जवाब नहीं है। एल्यूमिनियम के सेट्स और एच० डी० पी० के पाइप्स लगे हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है। फार्मर्स ने 250 सेट्स खरीदे हैं और दस हजार फार्मर्स उसका फायदा उठा रहे हैं, उन दोनों एरियाज में। उसमें पावर भी कम लगती है।

एक बात और मैं जानना चाहूंगी। पहले एक आर्टिकल आया था कि अगर प्लास्टिक को यूज किया जाए तो रिजर्वियर में सीपेज कम होगा और कैनल्स में भी सीपेज कम होगा जिससे एग्रीकल्चर को बहुत फायदा पहुंचेगा। मैं जानना चाहूंगी कि यह एक्सपेरिमेंट कैसा रहा है?

इसके अलावा मैं मिनिस्टर साहब से राजस्थान की लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में भी जानना चाहूंगी। मिनिस्टर साहब राजस्थान के हैं। (व्यवधान) हमने कल अखबार में पढ़ा था कि प्रधान मंत्री जी कौंसिल की चेयरमैन बनी हैं और उसमें 41 मेम्बर होंगे। उसमें चीफ मिनिस्टरस होंगे और 8 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे।

एक माननीय सदस्य : एम पीज नहीं होंगे ?

श्रीमती गुरबिंद कौर ब्रार : एम पीज को भी अगर मिनिस्टर साहब ले लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे उनको सही एक्सपीरिएन्स बता सकेंगे। उन्होंने बताया है कि कौंसिल की मीटिंग तो एक दो दफा ही होगी लेकिन उसका यह फायदा होगा कि एक ही जगह पर बैठकर सारे सवाल का हल निकाला जा सकेगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कीम बनाने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी बात है। पैसे की व्यवस्था तो होती ही रहेगी। चेयरमैन साहब इशारा कर रहे हैं कि बन्द करो लेकिन मैं सोच रही हूँ चन्द बातें और कह दूँ तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बाकी लोगों को भी बोलना है। आप खत्म कीजिए।

श्रीमती गुरबिंद कौर ब्रार : इन्टर स्टेट जो मामले हैं, रावी-व्यास वाटर का आपको पता ही है। पंजाब की तरफ भी आपको ध्यान देना है। वह छोटी स्टेट है, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा गेहूँ भी हम ही आपको देते हैं। फायदा हो या न हो, लेकिन हम गेहूँ की काश्त ही ज्यादा करते हैं।

जो इन्टरनेशनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, बंगलादेश के साथ या नेपाल के साथ मिलकर हमें हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब चेयरमैन साहब बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : अब आप थैंक यू कह दीजिए।

श्रीमती गुरबिंद कौर ब्रार : अच्छी बात है थैंक यू।

श्रीमती कृष्णा साहू (बेगसराय) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा सिंचाई विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज सिंचाई विभाग की चर्चा कृषि विभाग के साथ नहीं हो रही है, बल्कि सिंचाई विभाग

पर हम लोग अलग से विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश में जल स्रोत बहुमूल्य एक प्राकृतिक देन है। यह ईश्वर की ओर से एक ऐसा वरदान है, जिस वरदान के आधार पर हम पूरे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जबकि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है, उनके लिए यह वरदान के रूप में सिद्ध नहीं हो रही है, बल्कि अभिशाप के रूप में सिद्ध हो रही है।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के समक्ष कुछ अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं कोई बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात नहीं करना चाहती हूँ। जनता का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ हमारा दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं से जमीन वंचित है। योजना आयोग के अनुसार भी सिंचाई की क्षमता का उपयोग जितना हमें करना चाहिए था, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, सिंचाई परियोजनाओं में जितनी हमारी पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी से भी हम लाभ नहीं उठा सके हैं। इसके साथ-साथ जो कृषि प्रधान प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार तथा पश्चिम बंगाल—ऐसे राज्यों में जहाँ पर कि भूमिगत जल के विशाल भंडार हैं, इनकी छानबीन करने में भी हमारी गति धीमी रही है। समुचित लाभ न उठाने का यह परिणाम है, इसका आशय है कि 1979-80 में सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य के ऊपर 321.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वर्ष 1981-82 में यह घाटा बढ़कर 421.6 करोड़ रुपए का हो गया है। सिंचाई की योजनाएँ वर्षों-वर्षों से हमारे देश के राज्यों में लंबित पड़ी हुई है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो 20 बरस के बाद वह जवान हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी ही है। बीस वर्ष

के बाद भी ये योजनाएँ अपने शैशव अवस्था में ही लंबित हैं। इन प्रोजेक्ट्स से जो लाभ होना चाहिए था, वह लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से जनता में काफी रोष व्याप्त है। भारत सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रायः सभी राज्यों में योजनाओं के निर्माण कार्य की पूर्ति में आवश्यकता से अधिक विलम्ब हुआ है। इसके फलस्वरूप लागत योजना में अप्रत्याशित वृद्धि होती जा रही है। इस संबंध में मैं एक-दो उदाहरण पेश करना चाहती हूँ हमारे बिहार में एक बहुत पुरानी योजना है—मोकामा बरहड़िया टाल योजना इस योजना के बारे में सन 1980 से सदन में अपने विचार व्यक्त करती आ रही हूँ। सरकार का ध्यान आकर्षित करती आ रही हूँ। यह योजना 1958 के आसपास शुरू हुई, लेकिन आज भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की जाती है, संसद में या विधान सभा में, बात जब उठती है ऐसा लगता है कि गाड़ी को झटका लगा। वह चलती है, रुकती है बहुत धीमी गति से। 1958 में वह प्रारम्भ हुई और उसके बाद 1970 में श्री के. एन. राव, तत्कालीन सिंचाई मंत्री, उसको देखने के लिए गए थे। सारी जमीन का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को रखा जिन को बिहार सरकार और भारत सरकार के, दोनों के, समन्वय से पूरा करना था। वह 1970 में गये थे, उनके बाद 1975 में सिंचाई सचिव गये और 1975 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। सभापति महोदय, इसकी कहानी अनन्त है, जितना कुछ कहा जाए कम है। लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि आज 1983 में भी हम विशेष प्रगति नहीं कर सके हैं। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ—410वर्ग मील में यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है तो आज जो बीस सूत्री कार्यक्रम की हम चर्चा करते हैं और जिस में सिंचाई को प्राथमिकता देने की बात की गई है, हम

दाल के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह पूरा एरिया दाल का भण्डार हो सकता है, न सिर्फ बिहार को, बल्कि सारे देश को दाल दे सकता है। उस जमीन की उर्वरा शक्ति के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है— अभी तक यही चल रहा है कि वहां कमेटी बने या यहां कमेटी बने। भारत सरकार कहती है कि बिहार सरकार जाने और बिहार सरकार कहती है कि भारत सरकार से पैसा मिले तब हम करें। कहने का मतलब यह है कि हमारी निरीह जनता दो सरकारों के बीच में ही पिसती जा रही है और जनता से हम लोगों को जो बुरा-भला सुनना पड़ता है, वह अलग बात है।

दूसरी समस्या कटाव की है कुछ शब्द मैं कटाव के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। मुझे याद है—इस की चर्चा भी संसद में 1980 से हो रही है। कटाव से लोग तो मरते ही हैं, गांव के गांव बरबाद हो रहे हैं। इस से हमारी मिट्टी की जो क्षमता है, सिंचाई व कृषि की जो क्षमता है, वह समाप्त होती जा रही है। हमारे बिहार की स्थिति कुछ ऐसी है, यद्यपि यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है, लेकिन हमें कहना पड़ता है, क्योंकि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जनता के प्रति एक ही कर्तव्य है, हमारी एक ही सरकार है आज नहर प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ रहा है। सोन नहर या कमला नहर को लेकर कहा जाता है कि 10 लाख एकड़ में निश्चित सिंचाई की व्यवस्था है और वह जमीन धान के लिये सबसे उत्तम है। परन्तु वास्तविकता क्या है—क्या पांच लाख एकड़ में भी सिंचाई होती है? जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं वे तो लम्बित हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी योजनायें हैं वे भी आज कारगर नहीं हो सकती हैं। देश अन्य प्रान्तों में जो खेती योग्य जमीनें हैं वहां भी आज विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 48 प्रतिशत

से 92 प्रतिशत की सिंचाई क्षमता है, लेकिन बिहार में सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ है—केवल 25 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का स्रजन हो पाया है।

जो केन्द्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी बिहार राज्य की जो मिट्टी है वह चावल की खेती के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हैं, लेकिन उस का भी प्रति एकड़ उत्पादन दूसरे प्रान्तों के मुकाबले बहुत कम है। जैसे उड़ीसा में 419 किलोग्राम प्रति एकड़ चावल पैदा होता है, बंगाल में 461 किलोग्राम प्रति एकड़ पैदा होता है, लेकिन बिहार में 323 किलोग्राम प्रति एकड़ पैदा होता है। इस लिये कार्य-निष्पादन की दृष्टि से हम पीछे पड़ गये हैं और इसी से हमारे यहां क्षेत्रीय विषमता पैदा हो गई है। इसलिये जब हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और देश की आर्थिक समृद्धि इसी पर निर्भर करती है तो हमारा सुझाव यह है कि जो वाटर-मैनेजमेंट की समस्या है यह राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय दृष्टि से इस को हल करने के लिये इस पर विचार करना चाहिये। यह भी बार-बार होता है कि यह सेंट्रल सैक्टर में है, यह स्टेट सैक्टर में है, इसके लिये, मिर्चा साहब, यदि कानून में संशोधन भी करना पड़तो करना चाहिये छोटी योजनायें यदि स्टेट को करनी हैं, तो उसे करने दीजिये। लेकिन बड़ी योजना जिनका कि भारत सरकार जिम्मा लेती है, उनको उसीको करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम एक ही का उत्तरदायित्व होना चाहिए। बिना किसी का उत्तरदायित्व फिक्स किये यह काम ठीक नहीं होगा। कितने आयोग बिठाये जाते हैं। कृषि आयोग, बाढ़ आयोग, सिंचाई के लिए, सारे आयोग ही आयोग बिठाये जाते हैं। लेकिन सब का यह कहना है कि देश में चार सौ मिलियन हैक्टयर मीटर जो वर्षा होती है उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उपयोग होना चाहिए। उस पानी का हम ऐसा उपयोग करें जो राष्ट्रीय नीति के आधार पर हो।

क्योंकि खर्च तो हो ही जाता है, पानी भी निरर्थक बह जाता है उसी तरह से हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपये पानी के समान बह जाते हैं और बाढ़ और सूखे से हम लोग जूझते ही रहते हैं।

1982-83 में बाढ़ और सूखे से 14 अरब की क्षति हुई थी जबकि पिछले वर्ष के लिए 1132 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। यह 82-83 की वार्षिक रिपोर्ट सिंचाई विभाग की हमने देखी है। उस के अनुसार विशेष प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1953 से लेकर 1983 तक 365 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक नुकसान हुआ। सब से अधिक नुकसान 1455 करोड़ रुपये का 1978 में हुआ। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब इतनी राशियाँ खर्च होती हैं, तब उस पर जो एक्सपेरिमेंट ही न किया जाए कि यहाँ होगी व वहाँ होगी। आप एक नेशनल वाटर अथारिटी बनाइये। या जो भी आपको करना हो उसके फंक्शंस डिफाइन कीजिए। देश की जो तमाम बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए एक अथारिटी होना चाहिए। और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो इर्रिगेशन पोर्टशियलिटी है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल होना चाहिए। इस सदर्भ में हमारी प्रधान मंत्री ने भी बहुत चिंता व्यक्त की है। अभी जो पब्लिक सैक्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। यह बहुत चिंता का विषय है। इसी सम्बन्ध में मैंने अखबारों में देखा है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ है जैसा कि पहले हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा कि इस परिषद से राष्ट्रीय नीति निर्धारित होगी या जो नदी बेसिन हैं, उनकी भी योजनाएँ बनकर प्रतिवेदन आयोगें जिनपर कि भारत सरकार विचार करेगी। हमें आशा है कि इस

से सिंचाई के विकास में हर प्रकार की उन्नति होगी। चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मामला हो, या उनके कोऑर्डिनेशन का सम्बंध हो, या जमीन के नीचे हमारे जल स्रोत हों। उन सब पर विचार कर, कोऑर्डिनेशन कर एक नीति बनेगी। इस से हमें सफलता मिलेगी।

हर वर्ष 60 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट होती है। एक फारेस्ट फार्मिंग प्रापर्टी इन इंडिया किताब है। उसी में यह देखने को मिला है कि 50 वर्षों में, जितने हमारे जंगल हैं, उनमें से 9 करोड़ हैक्टेयर जंगल काट दिये गये हैं और भारी मात्रा में जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी का कटाव भी साथ-साथ होता जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 6 सौ करोड़ टन मिट्टी बह जाती है या उड़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष 60 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन हमारा देश गंवा रहा है। यह गंभीर विषय है।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए भी बहुत दुःख होता है कि राज्य में जो सिंचाई विभाग हैं, उनकी व्यवस्था और रख-रखाव पर इतनी राशि खर्च होती है जो कि नहीं होना चाहिए। इस विभाग में जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके दैनिक भत्ते और वेतन पर भी काफी राशि खर्च होती है। हमारे बिहार राज्य में 18 चीफ इंजीनियर हैं। उनके साथ-साथ उनका जो काफिला है, उनके साथ जो काम करने वाले हैं, उन सब पर प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानती हूँ कि एक कांस्टीच्युएँसी में 24 डिविजन काम कर रहे हैं और जितना कामा होना चाहिए, उतना काम नहीं हो पाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सारे विषय स्टेट के हैं।

16.00 Hrs.

इसको देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से कानूनों में संशोधन किए जाएं जिससे

इन स्कीमों को देखकर कोई एक जलनीति बनाई जा सके। जल से संबंधित डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। 20-25 वर्ष से जो योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं पहले उनको पूरा किया जाए। इसके बाद नई योजनाओं को लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री चांद्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, आप तो एक व्यवसाय से संबंध रखते हैं लेकिन आपका प्रदेश ऐसा है जो सारे देश को गेहूँ, चावल और आलू दे रहा है। यहां पर वैज्ञानिक खेती होती है। आप सिंचाई के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिंचाई के बगैर वैज्ञानिक खेती नहीं हो सकती। सफल खेती के लिए सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता है। हमको ऐसा लगता है कि इसके महत्व को सरकार ने बहुत कम आंका है। जितना ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिये था, विगत वर्षों में उतना ध्यान नहीं दिया गया है। शासकवर्ग की जिम्मेदारी थी कि वह इसके महत्व को सही रूप में आंकता। देश में ज्यादा सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये था।

इस देश में अभी तक 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है और 70 प्रतिशत क्षेत्र में पैदावार वर्षा पर निर्भर कर रही है। बरसात की अनिश्चितता की वजह से सारा उत्पादन नष्ट हो रहा है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, जहाँ वर्षा अधिक होती है, सभी जगह सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों कि जमीन की आर्द्रता कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है। इस तरह से जहाँ बरसात अधिक होती है वहाँ पर भी हम पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए वैज्ञानिक खेती के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंच-

वर्षीय योजनाएं बनाई गईं। 1951 से इनको लागू किया गया। 1951 से लेकर 1976 तक साढ़े चार पंचवर्षीय योजनाओं में हमें क्या प्रतिफल मिला। इस अवधि में एक मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष ही सिंचाई व्यवस्था की जा सकी। इससे अधिक कभी नहीं बढ़ाई जा सकी। इसको अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी। ज्ञातव्य है कि सरकारी नीति के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक 113 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हो जाना चाहिए। काम की गती को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया सकता। यह ठीक है कि 1977 के बाद से यह रफतार 2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। इस रफतार को और बढ़ाने की आवश्यकता है। गांव-गांव में जब तक समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। यह ठीक है कि देश ने व्यवसायों में कुछ उन्नति की है।

आपके पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों के गांवों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। दूसरे राज्य भी ज्यों के त्यों ऐसे ही पड़े हुए हैं। 1977 के बाद सिंचाई क्षमता हले की तुलना में लगभग दुगुनी हो गई। लेकिन इसकी सीमा अब तक पचास प्रतिशत से अधिक नहीं गई है। क्या बाकी पचास प्रतिशत हम इस शताब्दी में पूरा कर सकेंगे और अगर कर सकेंगे तो कितनी? तीन-चार मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी इसकी जरूरत पूरी हो सकेगी अन्यथा नहीं।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर पानी है और जमीन के नीचे भू-गर्भ में भी अथाह जल प्रवाहित हो रहा है। इसको अगर निकालने की व्यवस्था की गई होती तो यह सिंचाई कार्य हो सकता था लेकिन यह नहीं हो सका। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार देश में 128 मिलियन हेक्टेयर जल

है। यहां भूमिगत जल की भी कमी नहीं है। समूचे उत्तर भारत में जमीन के नीचे जो जल प्रवाहित हो रहा है वह लगभग 27 मिलियन हैक्टेयर है। इसको जुटाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है लेकिन कारगर नहीं हो रही है। आपको यह मालूम है कि देश में कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र लगभग दो सौ मिलियन हैक्टेयर है। यदि आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उत्पादन होता या हो तो यह जो भू-तल में पानी है इसको निकाला जा सकता है। लेकिन विद्युत की हालत इस देश में बहुत ही खराब है। नीति के अनुसार 31,535 मेगा-वाट उत्पादन होना चाहिए था। लेकिन मात्र 122,925 मेगा यूनिट ही हो सका है। क्षमता से लगभग आधा ही इसको कह सकते हैं। क्षमता का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। यह तो देश में विद्युत की स्थिति है। राज्यों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। एक दो राज्यों की हालत अच्छी कही जा सकती है लेकिन अन्य राज्यों की बहुत ही खराब है।

बिहार में कुल 173 लाख हैक्टेयर भू-भाग है जिसमें 115 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। उपलब्ध साधनों से साढ़े 92 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1982 तक 52 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकी। वास्तव में इतनी भूमि की भी सिंचाई नहीं हो सकी और न हो रही है। मुख्य मंत्री ने वहां अपने बजट भाषण में जो कहा है, वह नहीं हो रहा है।

आज के खबर में आया है कि 150 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है, जबकि 954 मेगावाट का लक्ष्य है और वहां उत्पादन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइये कि हालत बहुत ही खराब है। बिहार में जो भूतल जल है यानी नलकूप, लिफ्ट इर्रिगेशन वहां 75 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं। जिस

प्रदेश में 75 प्रतिशत नलकूप खराब हों और बिजली समय से न मिले तो किसान क्या करेगा? किसान की बहुत ही दयनीय हालत है। कहीं नलकूप को बिजली नहीं मिलती, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, मीटर नहीं है, स्विच नहीं है, चालक नहीं है, इस तरह से 75 प्रतिशत नलकूप खराब हैं। समूचे बिहार राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में पूरी व्यवस्था फेल कर गई है। इस बिहार को देखकर सरकार ने निर्णय किया है कि आधे नलकूपों को बिहार सरकार रखेगी और आधे नलकूपों को पंचायतों और जिला परिषदों को दे देगी। जिला परिषदें भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। सारे का सारा पैसा खा जायेंगे। ऐसी हालत में उनका देना तो हंसी वाली बात है। बजट भाषण में बिहार के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जहां काफी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को नकारा नहीं जा सकता है। मतलब यह है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार है। दरअसल जो पैसा आप दे रहे हैं या कमीशन आदि से स्वीकृत योजनाओं के अधीन पैसा जाता है उसका 75 प्रतिशत भ्रष्टाचार में जा रहा है। इंजीनियर्स लेते हैं, ठेकेदार लेते हैं, और राजनीतिक लोग भी अच्छे नहीं हैं। ऐसी जब हालत हो तो 25 प्रतिशत में किसी भी प्रदेश में क्या काम होगा?

मेरे क्षेत्र में गंगा जल प्रवाहित हो रहा है, अथाह जल है। बक्सर से लेकर पूरे बिहार राज्य में सिर्फ एक जगह इनका हाई पावर पम्पिंग सैंट था बक्सर के पास, वह भी पिछले दिनों बाढ़ में बह गया। फिर 1,2 मुंगेर में है। यह व्यवस्था हो सकती थी कि पानी को लिफ्ट करके छोटी नहरें बना करके आसपास के 5,7 जिलों के किसानों को पानी देते जिससे किसान सम्पन्न हो सकते थे। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न राज्य सरकार और न केन्द्रीय सरकार। पूरे भोजपुर जिले को बाढ़ से सुर-

क्षित करने के लिये 1972-73 में एक योजना बनी। यह बक्सर-कोइलवर तटबन्द योजना 165 किलोमीटर लम्बी है जिस पर अपार धन खर्च हो रहा है लेकिन कुल मिलाकर लगभग 65 प्रतिशत कम इसमें हुआ है।

आप अनुमान लगाइये कि 72-73 में जिसकी स्वीकृति मिली और काम शुरू हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसे 1978 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। बांध लगा हुआ है, बाढ़ आती है और उसमें घुस जाती है। बाढ़ को सौटने में देर लगती है, महीनों बाढ़ के पानी में वह इलाका डूबा रहता है। भ्रष्टाचार का तो आपको वहां पता ही है जो पैसा मिलता है, वह खर्च हो जाता है। पैसा कहां खर्च होता है लोगों को पता नहीं चलता। आपने पानी में डूबे हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिये बांध की व्यवस्था की हुई है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मेरा सिंचाई मंत्री जी से आग्रह है कि इसको शीघ्र इस साल पूरा कराइये नहीं तो बाढ़ से फिर वही हालत होगी जो विगत वर्षों में होती रही है।

165 किलो मीटर का घेरा जो आप देख रहे हैं, उसमें लिफ्ट से पानी डलवाइये गंगा से, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था हो सके। किसान कहते हैं कि यह बेकार व्यवस्था है, बाढ़ आती थी तो कम-से-कम रबी की फसल तो होती थी, खरीफ की नहीं होती तो ना सही। आपने व्यवस्था की थी कि दोनों फसलें हों, हम पानी वहां देकर इसकी व्यवस्था करेंगे और इसके बीच में एक मूंग की दाल की भी फसल हो जायेगी, लेकिन इन तीन फसलों की खेती हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था वहां नहीं हो सकी है। यह सब पैसा बेकार जा रहा है। इससे लगभग 40-50 करोड़ रुपयों के बीच हर वर्ष बाढ़ में क्षति हो रही है और सिंचाई भी नहीं हो रही है। इसको आप शीघ्र करवाने का कष्ट कर।

सिंचाई के लिये केन्द्र में अनेकों बोर्ड बने

हुए हैं जो हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतको बहुत सफलता क्यों नहीं मिल रही है। केन्द्रीय जल आयोग बहुत बड़ा है, हजारों लोग इसमें काम करते हैं पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। ये लोग देश को ही नहीं विदेशों को भी देखते हैं। आप विकासशील देशों को तो देख रहे हैं, लेकिन अपने देश का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अपने देश में क्या हो रहा है, यह अच्छी तरह से देखते तो आज यह हालत नहीं होती कि विगत 35 वर्ष के बाद भी आज हमको विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ रहा है। आज इन पदाधिकारियों में विदेश जाने की होड़ लगी हुई है। इनके पदाधिकारी विदेश जाने के भूखे हैं, इनका हिन्दुस्तान के काम की ओर ध्यान नहीं है। न देश का काम हो रहा है न विदेश का काम हो रहा है।

सिंचाई व्यवस्था के लिए और इसके सम्बन्ध में बहुत सी संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे, केन्द्रीय भूमिगत जल और विद्युत अनुसंधान-शाला, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सोन नदी आयोग, जल और विद्युत सलाहकार सेवाएं, बाढ़ नियंत्रण अनुसंधान, वेतवा नदी बोर्ड, नवदा नियंत्रण प्राधिकरण ब्रह्मपुत्र सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वानसागर नियंत्रण बोर्ड, बांड, माही नियंत्रण बोर्ड आदि। हम यह नहीं कहते कि इन संस्थाओं को क्यों बनाया है। लेकिन उनसे काम लिया जाए। दरअसल वे काम नहीं कर रही हैं। वे सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं।

मैं अपने क्षेत्र में एक दो मुद्दों को और आपके सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने 110 वर्ष पहले सोन नदी पर सोन कैनाल का निर्माण किया था, जिससे पटना, गया, भोजपुर और रोहतास जिलों के अधिकांश हिस्से की सिंचाई होती थी। कुछ समय से इस नहर का जल आधा हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध बन गया है और मध्य प्रदेश में वानसागर योजना बन रही है। वे दोनों ऊपर

का पानी ले रहे हैं और सोन का जितना पानी इस नहर को मिलता था, वह नहीं मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले से जो योजना बनी हुई है, वह क्षतिग्रस्त न हो। इस बारे में कुछ उपाय किए जा सकते हैं।

इन नहरों में जहाँ टेल-एंड, बहुत पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ सोन नदी में कहीं कहीं स्वतः पानी जमीन से निकल रहा है, जैसे डेडुआ में। वहाँ पर हाई पावर पंपिंग सेट से अगर पानी को नहर में उछाल दिया जाए, तो नीचे टेल-एंड तक सिंचाई हो सकती है। इस बारे में हमने कई बार लिखा-पढ़ी की है। बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को संचिका भेजी है कि इस योजना को स्वीकृति प्रदान की जाए।

भोजपुर जिला, जो पूरे बिहार को खिलता था, आज खुद भूखों मर रहा है। वहाँ सूखे की स्थिति है। बिहार के जिस इलाके में सबसे ज्यादा धान की फसल होती थी, वह इलाका आज पानी के बगैर जल रहा है। खरीफ की फसल नष्ट हो गई और रबी की फसल भी नष्ट हो रही है। आज उसको पानी की जरूरत है, लेकिन पानी नहीं है। चूँकि सोन नहर को सोन नदी से आधा ही पानी मिल रहा है।

पटना जिले में पालीगंज से लेकर पटना तक जो बांध लगा हुआ है, उस बांध के दाहिनी तरफ पानी देने से बहुत अच्छी खेती हो सकती है। वह बड़ी अच्छी उपजाऊ जमीन है, लेकिन पानी के अभाव में अच्छी खेती नहीं हो सकती है। भोजपुर जिले में भी सोन नदी के किनारे किनारे बांध लगे हुए हैं। उनके बाएँ बाजू पर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। वहाँ पर भी हाई पावर पंपिंग सेट लगाया जाए, लेकिन यह सब निर्भर करता है विजली पर।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है, उनके बारे में वह कार्य शीघ्र करें।

श्री मती ऊषा वर्मा : सभापति महोदय,

मन्त्री जी ने जो मांगें चर्चा के लिए सदन के समक्ष रखी हैं, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारी सरकार की ओर से सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएँ लागू की गई हैं। इसके बावजूद हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हैं जिससे सरकार का भी नुकसान होता है और जनता का भी नुकसान होता है। कभी बाढ़ और कभी सूखे से भूमि ग्रस्त रहती है। इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज लाखों लोगों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और दूसरी ओर जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से कायवाही की जानी चाहिए और राज्यों को यह आदेश जाने चाहिए कि हर जिले का सर्वेक्षण कराकर वहाँ राहत कार्य आरम्भ किए जायें।

अब मैं अपने क्षेत्र की ओर भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगी। हमारे जिला लखीमपुर-खीरी में सात नदियाँ हैं जो कि तराई के इलाके को बर्बाद किए हुए हैं। सिंचाई के अतिरिक्त तबाही का साधन भी उन नदियों के द्वारा पैदा हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार सरकार को लिखा है, सन् 1980 से बराबर लिखती आ रही हूँ कि वह इलाका सीपेज से ग्रस्त है। जो नहरें वहाँ से निकाली गई हैं उनमें ही वहाँ की काफी जमीन पड़ गई है। कुछ भूमि तो कैनाल्स में चली गई और कुछ भूमि ऐसी है, जिस पर हमेशा तीन-चार फुट पानी भरा रहता है। मेरे क्षेत्र में तीन-चार विधान सभाई क्षेत्र आते हैं। शारदा सहायक परियोजना जो बनी है, उसके कारण सीपेज की बड़ी समस्या है। इस परियोजना का उद्गम लखीमपुर-खीरी जनपद ही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 28 किलोमीटर लिंक चैनल हैं और पोषकनहर 35 किलोमीटर हैं। लखीमपुर से सीतापुर, कैनाल निकाली गई हैं, जिसके कारण लाखों बीघा भूमि में सीपेज की समस्या गम्भीर रूप से विद्यमान है। इसके कारण

लाखों परिवार भुखमरी से ग्रस्त हैं। सैकड़ों गांवों में सीपेज के कारण मकान तक नष्ट हो गए हैं। मनुष्य एवं पशु भी अनेक बीमारियों के शिकार हो गए हैं। मनुष्यों को 8-8 फुट पानी से होकर नाले पार करने होते हैं। जाड़े के मौसम में तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। बहुत से मनुष्य एवं पशु अपंग हो गए और बीमारी से ग्रस्त हैं। काश्तकारों के पास भी कोई काम नहीं है मैं सरकार के समक्ष यह सुझाव रखना चाहती हूं कि सीपेज की समस्या को दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जायें। जैसे कि सीतापुर में डिवीजन बनाया गया है, उसी प्रकार से जिला लखीमपुर में भी एक सीपेज डिवीजन की स्थापना की जाए। वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं एवं लेखपालों आदि को लेकर इसका सर्वे कराकर समाधान के उपाय किए जायें।

सिचाई विभाग की तरफ पुलियों का निर्माण किया जाना चाहिए। जो जमीन काश्तकारों के सीपेज से बेकार पड़ी हुई है, उन जमीनों के ऊपर लगान बन्धा हुआ है, उस जमीन पर अब तक जो लगान लिया गया है, उसको वापिस किया जाना चाहिए। किसी भी काम के लिए हम लोगों को यह बताया जाता है कि हम केन्द्र सरकार से कहेंगे, जब हमें पैसा मिलेगा, तब हम उस काम को करेंगे। सीपेज की समस्या के लिए वहां के मुख्य मंत्री जी से मिली थी। इसके लिए जवाब दिया जा रहा है कि कच्ची नालियां बनाई जा रही है, जिससे सीपेज की कुछ समस्या कम हुई है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप पैसा नालियों को बनवाने में बर्बाद मत कीजिए। जब एक बार नाली को खोदा जाता है, तो उसमें बाल भर जाता है, जिससे समस्या फिर वही बनी रहती है। मेरा सुझाव है कि नालियां बनवाने के बजाय आप नहरों को पक्का कर दीजिए। सीपेज की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी और जमीन पर भी खेती की जा सकती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जमीन का जो उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को हर जिले में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जो लोग बेकार हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीनें देकर रोजगार के लायक बनाया जाना चाहिए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को जमीनों के पट्टे दिए गए थे, उनको यह पता नहीं है कि उनकी जमीन कहाँ पर है। जमीन का पता नहीं है, फिर भी उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सुविधायें हम 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लोगों को दे रहे हैं, वह भी उनको नहीं मिल पाती हैं। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो सुविधायें जिन लोगों के लिए हैं, वे उनको मिलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सत्यनारायण जटिया : (उज्जैन) : सभापति महोदय, कविवर रहीम ने कहा था—“रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून”। सृष्टि को चलाने के लिए पानी बहुत बड़ी जरूरत है। सृष्टि के बहुत बड़े हिस्से में पानी है। किन्तु धरती पर जहाँ पानी नहीं है, वहाँ परेशानी है। को परेशानियां दूर हों, इसलिए सरकार योजनायें बनाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी योजनायें बनाई हैं, जितने बाढ़ से बचाव के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, कोई भी कार्यक्रम अपनी निर्धारित अवधि में, जिस समय तक उसे पूरा होना चाहिए, वह पूरा नहीं हुआ है। और जितनी लागत का अनुमान किया गया था, उस में भी वह काम पूरा नहीं हुआ। इस का मतलब यह है कि सिचाई के काम को जिनना महत्व

देना चाहिए, उतनी ही उपेक्षा की गई और उसी का यह परिणाम है कि आज हमें परेशानी उठानी पड़ रही है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं पानी पीने के लिए भी चाहिए। हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था पानी पर निर्भर करती है। पानी पर हमारी कृषि का उत्पादन निर्भर है, पानी पर बिजली का उत्पादन निर्भर है। मैं आप की जानकारी के लिये जो हमारी योजनायें बनती हैं उन का कुछ थोड़ा सा हिसा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ—जब हमारे यहाँ योजना बननी शुरू नहीं हुई थी उस समय जो बिजली हम पानी से पैदा करते थे वह कुल बिजली के उत्पादन का 33 प्रतिशत थी। जब हमारी पहली योजना खरम हुई तो यह प्रतिशत बढ़ा—35 प्रतिशत हुआ। दूसरी योजना के अन्त में 41 प्रतिशत हुआ, तीसरी योजना के अंत में 46 प्रतिशत हुआ, लेकिन उस के बाद चौथी योजना के अन्त में यह कम होकर 42 प्रतिशत हो गया। पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 41 प्रतिशत रह गया और मार्च, 1983 में जो साल खत्म हुआ है उस के जो आंकड़े सामने आये हैं उन में यह गिर कर 37 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब है कि देश में सिंचाई में हम पिछड़ रहे हैं, कृषि उत्पादन में पिछड़ रहे हैं साथ ही बिजली के उत्पादन में पिछड़ रहे हैं। इस लिए भी देश की प्रगति के लिये पानी और बिजली जो मूलभूत आधार है तथा जिन का बीस सूत्री कार्यक्रम में भी उल्लेख है—उस को पूरा करने के लिये हम कितना आगे बढ़ सके हैं यह इन आंकड़ों से सदन के सामने साफ हो गया है।

जो भी योजनायें हम बनाते हैं तथा उन को पूरा करने के लिये जिस धनराशि की व्यवस्था हम करते हैं यदि नियत अवधि में हम उस पैसे को खर्च न करें तो उस का भार आगे की योजनाओं पर पड़ता है। 1951 से 1982 तक हम ने सिंचाई की योजनाओं पर कुल धनराशि 15047 करोड़ रुपये खर्च की है।

हमारे देश में पानी के आधार पर सिंचाई की क्षमता का लक्ष्य 113 मिलियन हेक्टेयर है। इस के लिये हम ने कुछ लक्ष्य तय किये थे, योजना में कुछ कार्यक्रम तय किये थे हमने तय किया था कि 59.57 मिलीयन हेक्टेयर हम बड़ी और मीडियम योजनाओं से सिंचित करेंगे। बड़ी से 29.10 तथा छोटी से 30.47 मिलियन हेक्टेयर और 29.10 छोटी योजनाओं से प्राप्त करेंगे। लेकिन मिला क्या? आज तक जो लक्ष्य एचीव किया है—वह 38.98 मिलियन हेक्टेयर बड़ी से मध्यम से 18.98 है और छोटी योजनाओं से 20 मिलीयन हेक्टेयर का लक्ष्य एचीव किया है। इस का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य में 33 प्रतिशत पीछे रह गये। जितनी हमारी सिंचाई होनी चाहिए थी उस से 33 प्रतिशत कम हुई। इस का सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ा है और यही कारण है कि हमें खाद्यान्न के लिये विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। हम ने पिछले वर्ष भी मंगवाया और शायद इस वर्ष भी मंगवाना पड़े। एक कृषि प्रधान देश के लिये खाद्यान्न का आयात निश्चित रूप से बड़े शर्म की बात है।

इस के कारण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हम जितना पीछे रह गये हैं उस को एचीव करने के लिये 1980 की कीमतों के आधार पर अब 50 हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। यदि हम ने समय के अन्दर काम को पूरा कर लिया होता तो यह जो अधिक पैसा हम को 113 मिलियन हेक्टेयर को एचीव करने के लिये खर्च बचाया जा सकता था। अब एक हेक्टेयर सिंचाई के लिए हमें सात हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हमारे देश में पैसे की क्या स्थिति है? हम विदेशों से कर्जा भी लेते हैं। कर्जा लेने के बावजूद भी देश की प्रगती नहीं होती। हजारों करोड़ रुपये का कर्जा आज हमारे ऊपर है। हमारे देश की जो स्थिति है उसमें उसका सारा भार आम जनता और खेतों में काम करने वाले किसानों पर पड़ता है।

हमारी 205 बड़ी योजनाएं हैं, जिनमें से 1980-81 तक 29 योजनाएं पूरी की गयी हैं। मध्यम दर्जे की 916 योजनाएं हैं जिनमें से 478 योजनाएं हमने पूरी की हैं इस प्रकार से हम कितनी सिंचाई योजनाओं में पिछड़े हुए हैं। ये सारे आंकड़े रख कर मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश है। हमें अपने देश को समृद्ध करने की दृष्टि से काम करना चाहिए जिस से आने वाले समय में हम अपने देश की खाद्यान्न की मांग को पूरा कर सकें। बाढ़ के पानी से जो तबाही होती है उस से बचाव के लिए हमें प्रभावी योजनाएं बनानी चाहिए।

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सिंचाई योजना पर शीघ्र कार्य करना जरूरी है। उसमें इतना पानी है कि उस से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का सारा हिस्सा हराभरा हो सकता है। इस सारी योजना को पूरा करने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय मध्यप्रदेश सरकार सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती रहती है। 1981 में चम्बल आयकर विकास योजना भेजी गई थी। 1979 में रोहर योजना भेजी गई थी मध्यम दर्जे की योजना गेज टैंक परियोजना 1981 में भेजी गई जो कि दस सातों में पूरी होनी है। लेकिन अभी तक इन योजनाओं पर स्वीकृति नहीं मिली है। मैं आप से कहता हूं कि सारी योजनाओं की स्वीकृति मिले। जो योजनाएं स्वीकृत हो कर अब तक पूरी हो जानी चाहिए थीं उनका काम भी 15 साल विलम्ब से चल रहा है। ऐसी योजनायें तबा और बर्ना योजनाएं हैं। राजस्थान के अन्दर झालावाड़, मनीहरथाना, गागरिन योजनाएं हैं जिन पर कि 15-20 सालों से सर्वे का काम नहीं हो पाया है। कोटा में जो मुंगेर योजना बनी है, उस पर भी सर्वे होना चाहिए।

इन सारी बातों को कहते हुए मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि हमारे देश की समृद्धि

सिंचाई पर निर्भर करती है। हमारे देश में सिंचाई के जो स्रोत हैं उनका दोहन करना होगा। जो हमारा अण्डर गाऊण्ड वाटर है, जमीन के ऊपर पानी है और आसमान में जो पानी (मानसून) है, अगर हम तीनों पानी को मिला कर योजनाएं बनाएं तो निश्चित रूप से हमारा देश सम्पन्न होगा, हमारा किसान सम्पन्न होगा। हमारे कृषि प्रधान देश का जो हरित क्रांति का सपना है वह सपना साकार होगा।

यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

DR. MAHIPATRAY M. MEHTA (Kutch): Sir, Mine is the story of sweat, sorrow and tears. We export sweat and blood and import the highest amount of foreign exchange for this Government. Why has this happened? This has happened because we cannot produce anything. Why can we not produce anything? It is because, as rightly pointed out by the previous speaker, we have been deprived of water. It is not as if water is not there, but we have been deprived of it.

The constituency from which I come occupies a unique position in the whole world. It is a land where there are at present only one million people. Nearly 2 million people have already left that place to earn their livelihood, just for earning a piece of bread.

Once this constituency of mine was a part of the country, and the river Indus was flowing through it. It was a very rich and fertile part of the country at that time, having communication with all over the world. But unfortunately, about a century ago, some earthquake came, and land came up in between the Indus and my constituency, which is called Alla Bundh. From that day, the sad story of my constituency has started. It has become today the most drought-prone area in the whole country. If the highest number of droughts have affected any part of the country, then it is my unfortunate constituency. That is way I have taken this opportunity today as a last resort to appeal to the Union Government, through you, so that at least justice may be done to that

area. Sir, I do not seek any favour. We have never sought any favour from any body in the whole of our lives. As I have told you already, we have exported blood and sweat, but we have never begged.

On the floor of this august House, I would like to point out that soon after Independence, in the very first year after our Independence, that is, in 1948, there was a drought in that part of the country. Panditji had gone at that time to Pakistan to meet the Prime Minister of Pakistan, Mr. Liaquat Ali Khan. Our Congress Committee had written a letter to him to plead with Pakistan that since we were in the Indus basin, we had our claim on the Indus waters, as was the case before Partition and as was the position in prehistoric days when water used to flow from there to our area. Panditji did take up the matter with Mr. Liaquat Ali Khan. But unfortunately, they had fognd a document in which the Chief Irrigation Engineer of the then princely State had on behalf of the Ruler given in writing that Kutch had no claim on the Indus river waters. Therefore, with all the sorrow in his heart, Panditji informed me that in view of that letter, we could not claim any waters from the Indus. At the same time, our border near Chand Bet was also in dispute, Panditji immediately took the claims from it, and in the very first Plan, the Rajasthan Canal was envisaged up to Kutch and extending to Kandla. That Plan is still there in writing. If, as originally envisaged, the Rajasthan Canal had been fed with waters from the Himalayan rivers in the Northern India, it would have served the purpose of the Ichchogil canal at that time. We had three important and definite purposes in view to solve the three main problems of India at that time. The first problem was food scarcity, which was could have solved by irrigation from the waters in this canal. The second was the problem of defence against Pakistan. This canal would have given us a waterway giving a clear opening to Punjab to the sea and it would also have given an opening to Rajasthan to the sea. If only this would have been done, the history of India would have been different. But unfortunately, the Rulers of Gujarat and the people who were at the helm of affairs at that time did not pay any attention to this matter.

I had myself gone at that time to Shri Morarji Desai who was our supreme leader, and I urged that somehow we must get the benefits of the Rajasthan Canal under any circumstances. But he told me that I should not shout about Rajasthan Canal because we would be getting the Narmada waters.

The result was that we were deprived of the Indus waters first and then we were deprived of the benefits of the waters from the Rajasthan Canal also. Now, the only hope that remains for us is the Narmada project. With all tears and sorrow in my heart, I beg to say here that because we are numerically small in this great democracy, we have been deprived today of even our basic necessities.

When the Khosla Commission was appointed, Gujarat fought its case at the cost of Kutch. Banni was a unique pasture land at that time in the whole of India. It was rich in cattle, especially cows. I remember that after Independence, Pandit Nehru had sent Mr. Datar Singh, the then Agricultural Adviser to the Government of India to visit that area. He was very happy to look at it, because that was a land which could come up uniquely in the whole country, because it had 85,000 cows of the same colour and the same height and of the best species in the whole world. He was mad after it. He even wondered how it was that that area was being neglected. And yet what is the condition today? Mr. Avtar Singh met me some time in 1973, and he asked me what the condition of Banni was. I said that not a single stone had turned, on the contrary the whole cattle had perished. When I said this, he was taken aback. I told him that it was not for me to reply but it was for the Government on which we had all the time depended, which happened to be the Congress Government at that time. I had no other reply to give to him. Today, there are not even 1000 cows there. Most of them have perished: it was a case of almost total perishing. You may ask what the reason for it is, and whether after Independence, this is the way in which backward areas should have been treated. I would only point out that it was only two months ago, that even the basic necessity of drinking water was supplied. A pipeline had been envisaged with an expenditure of nearly Rs. 2 crores, and after a good

deal of shouting, it was constructed and the drinking water was supplied to that area only about two months ago.

I would further point out that when the Narmada case was fought before the Khosla Commission, it was at the cost of Kutch that arguments were put forward before it. If only sufficient water supply could have been assured to this beautiful area of Banni, which is a lowlying area about 680 sq. miles in extent, it could have given rice and wheat not only to the whole of Gujarat but to some part of India too. A picture was filmed at that time about what one acre of land would yield if it were supplied with water. Mr. Chawla, one of the members of the Khosla Commission had come to Kutch at that time. Fortunately, he was from Hosiarpnr in Punjab. When he saw Banni, I asked him laughingly, 'Mr. Chawla what do you think of Hosiarpur during the pre-canal days'. He immediately said 'Dr. Sahab, it was just like this area before. But today it is supplying the best wheat to the whole of India. I am sure this part will also come up likewise'.

The Gujarat Government had submitted various reports to the Khosla Commission I would request the Central Government to go through those reports. In the second report submitted by the Gujarat Government in 1963, they had stated if the height of the Navgaon dam or Sardar Sarovar was only 425 feet, and the canal had a height of 300 feet with a slope of one foot every mile, and 100 million hectare feet of water were given then more than half a million acres of land of Kutch would be irrigated. And the Khosla Commission award gave 20 per cent of total water, whereas we had asked for 25 per cent because the area of Kutch was about 25 per cent of that of Gujarat.

It is pertinent to mention here that about hundred years ago, several thousands of people had died because of drought conditions. Even recently, during the period 1960-70, there had been eight continuous years of drought. You can understand what drought in one year means. Drought in the second year is more serious. Drought in the third consecutive year is still more serious. There has been a continuous chain of eight years of drought in that area. And yet what is our record? The people of

Kutch and the farmers of Kutch, not through water but through their sweat produced 32,000 tonnes of wheat. What I want to point out thereby is that the people there are ready and willing to work. But the question is whether the necessary infrastructure is there. Unfortunately, it is only those with the loudest voice or those who can wield political influence or money power can get these things. This is how corruption rules most in our country, and plans are subjected thus to political decisions.

The Khosla Commission's report as well as the award made by them were disputed. The Prime Minister took it upon herself of give a judgment on the Narmada dispute. We were very happy that here was a person whose father had visited Kutch so many times, who herself had seen the Kutch area so many times, and naturally, she would render justice to our area, but unfortunately what happened was that a tribunal was appointed to go into the matter further. If you refer to the judgment of the tribunal you would find that they have stated that the height of the Navgaon dam should be 450 feet, and if water is there in it even up to a height of 465 feet, Kutch can get more than five lakhs acres irrigated as giving their report, the tribunal has stated that the even height of the canal would be 300 feet.

The Gujarat Government had demanded 1 million acre-feet of water with provision for evaporation. The tribunal had given 90 million acre feet after evaporation which was exactly what they had demanded and not a drop less. Unfortunately, Gujarat government did not represent Kutch before the tribunal. Therefore, the tribunal has stated that only 6% water would be given to Kutch as against 20% awarded by the Khosla Commission. There were several other ambiguities in the award. So, the case was referred back to the tribunal. They revised their earlier report and gave a report saying that the sole authority was given to the States to distribute whatever quantity had been allotted to them within their State area. Thus, this becomes a State subject. The tribunal has given power in the hands of the States to distribute the waters and to decide how much water should be distributed and where.

Sir, as I said, I do not seek any favours. But I am only pleading for natural justice. When one fights a case and gets an award on the basis of particular points, one is bound to fulfil those points first, because the award has been obtained on the basis of those points only. Therefore, if the Gujarat Government has fought the case on this basis that if Kutch requires, water would be given to it, then I would say that it becomes their moral duty and indeed the primary duty of the Centre also to see that the people of Kutch are given proper justice. Unfortunately, today, it has become a land of widows, old and handicapped persons, because all the intelligent people have gone out of that land.

17.00 Hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER
in the Chair)

As I have said already, and as has been pointed out rightly by some of my hon. friends who have spoken earlier, we are not using properly our manpower also we have a huge manpower in India today, but do you know how many man-hours we are losing at present? Similarly, we have vast resources, but how much of it are we actually using? We are using, for instance, only 14 per cent of our river waters. If only we utilise our water resources fully we can irrigated thousands and millions of acres of land. So far as Kutch is concerned, whose area is nearly one-fourth of that of Gujarat, we can settle an equal number of people there, the people who have gone out can be brought back, or at least the younger generation which is living there may not have to go outside for earning their bread if only justice is given to them.

How are we to get justice? I know how we can get it. I may remind you of what happened in 1956 when the integrated bilingual Bombay State was formed. The same question arose at that time because there were six units at that time, Kutch, Saurashtra, Gujarat, Vidarbha, Marathwada and Maharashtra. If some part of it suffered from injustice, where could one shout about it? Panditji—I can never forget him for the whole of my life, and his sense of giving judgment to people—without

asking anybody from Gujarat, immediately said that development board under Art. 371 (2) would be set up for all those six units if they felt it necessary. But let me all you with all the anguish and pain in my heart that this constitutional right of mine has been denied to me till now. Even the proper channel through which we can approach is denied to us. Therefore, there seems to be no prospect of our getting justice anywhere. The then Home Minister had declared in this august House, and the then Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Om Mehta had declared in the other House on this matter, and yet this constitutional right has been denied to us.

Again, in 1977, while inaugurating the Assembly session in Gujarat, the Governor had declared that he had received an Order from the President to that effect. But, with all the sorrow in my heart, let me tell you that Order, even before it was fulfilled was revoked and today we are without anything.

That is why I want to make this appeal to the hon. Minister. Even the agency through which we can take up this issue has been denied to us. Whom should we approach? Where are we to go? Do you want us to speak the same language as Punjab or Assam is doing today? Sir, we are not people of that type. As I have told you, we have exported our sweat and blood, but we have never spoken in such language or shouted for such things. Therefore, do not expect us or indeed the people of India to use such language. But what do we find. Unfortunately, it is the Government that teaches these things. You may go to any State, the Congress-I administered States, and I would say with all the sorrow in my heart that the greatest discontent, the greatest infighting amongst them, and the greatest mismanagement anywhere is found there, the greatest injustice, the greatest corruption, the greatest law and order problem, and the greatest indignity to womenfolk who are raped day and night is there, besides bank robberies and everything else.

That is why, on the floor of this House, I ask this question to the hon. Minister through you. I am not just requesting, but

but I am asking a question. If they do not give justice, then just as we have fought during all these generations...*(Interruptions)*

SHRI RAM PYARE PANIKA : It is not correct to say like that.

DR. MAHIPATRAY M. MEHTA : My hon. friend is not the Chairman. Mr. Chairman is there. Why should my hon. friend insult the Chair. The Chair is there to tell me. Let my hon. friend sit down.

(Interruptions)

I want to point out to the hon. Minister that so much injustice is being done, and therefore, let us do something to the people who deserve justice, not favour. Let what the Gujarat Government had given in writing to the Khosla Commission before the matter went to the tribunal, be fulfilled. Let those old terms be first fulfilled. That is all that I would like to say.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : There are some hon. Members who speak rarely ; and there are some other hon. Members like Mr. Vyas who are not satisfied, even though they speak frequently.

SHRI NITYANANDA MISRA (Bolan-gir) : Mr. Deputy Speaker, Sir : We all know that irrigation plays a very vital and crucial role in agricultural production. Out of all the factors which contribute to improvement of agriculture, irrigation has got a special place. And it is irrigation which makes the maximum contribution. We may have better technology for agricultural production. There may be larger input of fertilizers. There may be intensive cultivation ; and you may use hybrid and improved seeds. But unless there are irrigation facilities, all these factors cannot improve agricultural production. Increased agricultural production will be possible only if there is irrigation. So, irrigation plays a very crucial role in improving agriculture, and it has been given the importance that it deserves.

Sufficient funds have been allocated for the improvement of irrigation, for increasing our irrigation potential. Actually, we have increased our irrigation potential to the extent of nearly 2.4 million hectares of land every year during the last 3 or 4 years. But, unfortunately, in spite of the fact that we

have increased our irrigation potential, our agricultural production has not increased correspondingly i.e. proportionately. If we take the last 4 or 5 years, we must have increased our irrigation potential by nearly 10 million hectares of agricultural land ; but the increase in agricultural production has not been to the tune of nearly 25 million to 30 million tonnes, taking into consideration the fact that for every irrigated hectare of land, there should be an additional production of 3 to 4 tonnes. So, it is a very serious matter ; and we will have to analyse and find out the reasons why this increase in irrigation potential is not reflected in additional increase in agricultural production.

The increase in irrigation potential has not been reflected in the adequate increase in agricultural production. This is a very important and a very serious matter. It has been proved that in spite of the fact that we have increased our irrigation potential, we have not been able to fully utilize our irrigation facilities, as a result of which, our agricultural production has not increased. Therefore, I think it is high time that we should shift emphasis from increasing the irrigation potential to the fullest utilisation of the irrigation of the irrigation facilities that are made available to the farmers. This is a very important aspect which deserves our serious consideration.

It is also high time that we should seriously think of having an organisation consisting of people who have got specialised and technical knowledge about water management. Our farmers lack knowledge about better practice, about better method of utilization of irrigation facilities, as a result of which there is no equitable distribution of water. Then we do not have sufficient amount of knowledge about the best water management and cropping pattern as a result of which irrigation facilities which are made available to the farmers are not being utilized in the best manner possible. That is the reason why this aspect deserves the attention of the Ministry of Irrigation, and greater emphasis should be laid on this sector.

The other day, there was discussion about waterlogging because of seepage of water. This is a very important problem.

We provide irrigation facilities so that agricultural production will increase, but it is really a contradiction that because of irrigation facilities certain lands are being waterlogged and the seepage has not been checked. Of course, lining of the canals is absolutely necessary for the purpose, if seepage is to be checked; and for that, colossal financial resources are required; and that is why there appears to be some reluctant, some hesitation on the part of the State Governments to invest sufficient amount for the purpose. But it is absolutely necessary that this waterlogging which is a very important problem should be checked, because the most fertile land, the most productive low land is being very severely affected by that. If this lining is done, whatever might be the cost, then we shall also be able to check this wastage of water and coverage under irrigation would also increase, because water wastage has been checked. Therefore, I request the Ministry of Irrigation to pay sufficient amount of attention to this problem and also give sufficient amount of financial assistance to the States who want to undertake this work, who are not able to do it at present because of paucity of funds.

We have observed from experience that when a new irrigation project comes up and irrigation facility is extended to the farmers, it takes a long time for the farmers to adopt a new technique of agricultural production in the irrigated area, because the whole technology of production becomes completely different. Our farmers are habituated to rain-fed conditions and when they get irrigation facility, they use probably excess water, which is also harmful to agricultural production. Therefore, it is necessary that they should be taught the new technique of cultivation which is relevant to the conditions of irrigation.

We have observed that there are many irrigation projects, which have been carried on from the First Five Year Plan and some from the Second Five Year Plan and still they are on-going projects. Some of the Members of the opposition have thrown the blame on the Irrigation Minister for this delay. I think, it is completely unjustified because a number of irrigation projects had been taken up before the old ones were completed on our insistence. Just

now, my hon. friend from Kutch has made a fervent appeal for a project in his area. Likewise, all of us have been making fervent appeals. As a result, a number of projects had been taken up and the old on-going projects could not be completed in time. Though they were projected to be completed within a specified time, it could not be done because of constraint of resources. If the Irrigation Ministry is blamed for this, I think it is not justified. A time has come when we should realise that the old projects, which are on-going projects, should be completed within a very short period of time, because we have invested colossal amounts of money on them and we are not getting any return out of that. The agriculturists also are not getting any benefit. The escalation of the cost is so high that the present estimate is probably five to ten times of the original estimate.

In the field of irrigation, there is a necessity of consolidation plan, as in the Railways we have got the rehabilitation plan where we pay sufficient amount of attention to basic and fundamental problems. So in the field of irrigation we should have a consolidation plan so that sufficient attention can be focused on utilisation of water and use of irrigation facilities and completion of old projects, which have been going on for a long time. This is a very tough and hard task.

Uptil now we find that there have been very big projects which are being implemented at a huge cost. Of course, there are so many advantages in them. But at the same time, I request the hon. Minister to shift the emphasis to small and medium projects so that the return on the investment can be obtained very quickly and the farmers can utilise the benefit of the irrigation facility very early.

The constraint of resources that we have got will not be felt so much because the expenses of the small irrigation schemes will be comparatively very small. We have got thousands of small streams and rivulets throughout the whole country. If the water resources can be harnessed by erection of some diversion weir then we can have colossal amount of benefit by spending a very small paltry sum. We have experience that for irrigation one acre of

land, we have to spend something like Rs. 300 to Rs. 400/ or Rs. 500, and then during the time of drought we can get sufficient irrigation. When there is acute scarcity of water, when the rain fails us, when we face drought conditions, at that time these small irrigation schemes help us immensely. Therefore, if the emphasis is shifted to small irrigation projects and minor irrigation projects, then it will benefit our farmers very much, quick execution can be ensured and with little resources we can provide irrigation to vast acreage of land.

I shall take this opportunity to speak a few words about the position of irrigation in my own constituency.

MR. DEPUTY SPEAKER : You should have started from your constituency.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : He started from his constituency. From Bolangir he is now in Delhi.

SHRI NITYANANDA MISRA : In our State we have got the problem of flood in the delta region and the problem of drought in the hill region where the tributaries of Mahanadi and other big rivers are lying. So, these two problems are, in fact, only one problem that is, the problem of irrigation. Because in the tributary region there is no irrigation project, that is why the excess flood water runs into Mahanadi and plays havoc in the region. Therefore, it is absolutely necessary that in order to check flood in the coastal area, there must be irrigation projects which should be undertaken in the tributary region of the big river so that our problem of drought can be solved which is a perennial problem because we face drought conditions almost every year. It might be of interest to you when I mention that in my constituency only 5 per cent of the total cultivated area gets irrigation facilities and the rest 95 per cent of the land is totally dry and rain fed and entirely dependent on the rains and because of that there is economic disparity and nearly 90 per cent of the farmers and agricultural labour are below the poverty line and they are extremely poor. My area is the poorest area in the State and the whole of the State itself is the poorest in the whole of the country. We have got water sources, we have got a number of tributaries. In my constituency there are six tributaries of

Mahanadi but the water sources are not being tapped. There has not been any irrigation project in my constituency as a result of which this has been a vast expanse of dry and arid zone, semi-desert zone, without irrigation facilities. The living condition of the people is very very low and the economic condition is also very bad.

As I stated, 90 per cent of the people are below the poverty line. Therefore, I would request the Irrigation Minister to pay special attention to those areas, which are economically backward, undeveloped, but which have plenty of water resources, which can be tapped, which can be harnessed, and there is scope for a number of irrigation projects. In that way, we shall be benefited and, at the same time, this will check the floods in the coastal areas, in the delta region, which will be of great service to them also.

Every year flood plays havoc in the coastal areas as a result of which human lives are lost, colossal amount of property is lost and serious damage is caused to the crop, which affects the food production. Therefore, I would appeal to the Minister once again to pay attention to this most backward area, the most undeveloped area, which comprises my constituency.

Then I would like to touch another point. We have been observing that between the urban area and the rural sector there is economic disparity, because there has been investment of resources in the urban areas, but there has not been proportionate investment of resources in the rural sector, as a result of which the people in the rural areas are extremely poor and poverty-stricken. Consequently, there is always a tendency for the people of the rural areas to migrate to urban centres of growth. We can have small scale industries in the villages, but they will not be economically viable and they will not help the economy at all. There is only one way of improving the rural sector, and that is by having irrigation projects and providing irrigation facilities to the rural sector. That is the only way in which the economic disparity between the urban centres of growth and the rural areas can be removed. Therefore, from this point of view also, there is every necessity to give importance, prime importance, to

irrigation and allocate sufficient amount of funds for the improvement of irrigation so that in the irrigated area people will have sufficient employment, three times the employment, because they will be growing three crops every year with irrigation facilities. In this way, we can solve their unemployment problem and the economic disparities between regions can be eliminated.

***SHRI ERA MOHAN (Coimbatore):**
Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Irrigation for 1983-84.

I whole heartedly welcome that for the first time the Irrigation Ministry has got an independent entity and talented Shri Ram Nivas Mirdha has been entrusted with the charge of this vital Department. I am sure that his inherent dynamism will get reflected in the activities of this Ministry.

In our country 1130 lakh hectares are capable of being brought under irrigation. During the past 32 years 50% of the land has been covered by irrigation facilities. The Ministry has expressed the hope that by AD 2000 their remaining 50% of land will be covered by irrigation. I welcome this assertion contained in the Ministry's Annual Report. If during the coming 17 years the remaining 50% land is to be covered by irrigation then the Ministry has to pay special attention and endeavour ceaselessly to achieve this laudable objective. I am compelled to voice a discordant note because many times we find that there is wide gap between word and deed, the uncovered bridge between what is contained in the report and what is done outside, which has inhibited the nation's progress according to our Plan targets. Irrigation is the basis for our agricultural efforts. As our economy is agricultural economy, we have to lay great emphasis on irrigation.

During the Sixth Five Year Plan, a sum of Rs. 10,203 crores has been allocated for major, medium and minor irrigation. By the end of 6th Plan it is expected that 140 lakh hectares are likely to be brought under irrigation. It is worthwhile mentioning

here that from 1951 to 1982 we have invested nearly Rs. 10081 crores on major and medium irrigation projects. But our efforts have been nullified by the occurrence of floods in the North and drought in the South at monotonous intervals. According to the information furnished in the Annual Report a sum of Rs. 11,630 crores has been the loss the country has suffered on account of such recurring floods from 1953 to 1982. In 1982-83 26.17 crores of people have been afflicted by drought and about 429 lakh hectares have been affected by drought. You can imagine the magnitude of the problem of floods and drought and the losses that the country is suffering year after year.

Here I would like to highlight the need for intensive efforts for exploiting the irrigation potential of our country. In our country out of 1430 lakh hectares being cultivated, 1050 lakh hectares are rainfed land. This comes to 73% of total cultivated land. This land produces nearly 42% of the total food grains produced in our country. It is no exaggeration to say that our agriculture is monsoon agriculture. Though we have increased irrigation facilities, yet we have not created irrigation facilities to the extent of achieving self-sufficiency in foodgrains production. I will substantiate this by saying that so far we have not utilised even 50% of available waters for irrigation during the past 32 years. We cannot blame the nature for our abject poverty. We have failed to utilise the nature's bounty for the good of the people.

Cauvery Water dispute, Yamuna Water dispute, Mahi Water dispute, Narmada Water dispute, Kanhai Water dispute—I can go on enumerating the unresolved interstate river water disputes which have proved the greatest hindrance in implementing expeditiously irrigation projects. These river water disputes among the States have inordinately delayed the execution of irrigation projects with the inevitable consequence of escalation in costs. Similarly, we have not utilised the waters of west-flowing rivers in our country. The Central Planning Commission constituted a Committee to study this issue. I know that this Com-

mittee has submitted its report. The Irrigation Ministry had also constituted a Committee and I am told that the report of this Committee has also been presented to the Government. The Centre has also constituted a Committee of Technical Experts of both Tamilnadu and Kerala Governments to study this issue of utilising the waters of west-flowing rivers. I understand that this Committee is still to start its work. The other two Committee have submitted their Reports. If the Government does not take any action on the recommendations of these Committees, why should such Committee be constituted, why should public money be wasted on them? It is really criminal to waste public money if the Government does not take any action on the Reports of such Committees. I demand that the hon. Minister should say something about this in his reply to the Debate.

Without Cauvery waters and without the waters of west-flowing rivers, Tamil Nadu will soon become another Thar desert of Rajasthan. Such a situation is fast approaching in Tamil Nadu. The Irrigation Commission submitted its report some ten years ago. I would like the hon. Minister of Irrigation to apprise the House of the action taken so far on the recommendations of the Irrigation Commission. I am constrained to remark that such inordinate delay impede the Government's effort in creating further irrigation facilities.

Sir, only the other day the Hon. Minister replied to a question in this House that about 60 lakh hectares have been afflicted by water-logging on account of which several hundreds of crores of rupees have been lost. I would like to know from the hon. Minister of Irrigation what steps the Government have taken to reduce the problem of water-logging in our country. We cannot afford to waste 60 lakh hectares of cultivable land every year.

I have to regretfully point out that the Centre seems to surrender to violence and the just demands of the people are swept under the carpet. I do agree that Punjab may go into the grip of extremists if Ravi-Beas water agreement is not re-opened. The Home Minister has announced that this Agreement between Punjab, Himachal

Pradesh, Haryana and Rajasthan would be reopened soon for the benefit of the people of Punjab. I would only stress the fact that before Tamil Nadu starts burning, the Centre should also find a solution to the Cauvery Waters dispute.

The Inter State Water Disputes Act, 1956 and the River Boards' Act 1956 have been passed by the Parliament deriving authority from Article 262 of the Constitution and also under Entry 56 of the Union List of our Constitution. In other words the Government of India has got constitutional authority to intervene in river-water disputes among the States. But so far none of the inter-State river water disputes has been settled. They have been allowed to sore the relations between the States. The perpetuation of such inter-State river water disputes proves that the Centre has not exercised its authority in resolving them. The Centre cannot say that they are helpless and these disputes are such imponderables beyond the competence of the Government of India. They are not so difficult as is being bruited about. The river waters should be declared as national asset under the Constitution and a permanent solution must be found for these disputes. Then only the nation can make meaningful progress. When the Centre can come to an amicable agreement with Pakistan and Bangla Desh in the sharing of river waters, I am surprised why the inter-state river water disputes should be prolonged in this manner. I am sure that our dynamic Minister of Irrigation will solve all of them during his term of Office.

Sir, I would like to refer to Vaigai Seeramaippu Project in Tamil Nadu which was implemented by the D.M.K. Government in Tamil Nadu. My hon. friend Shri M.S.K. Satyendran, sitting nearby me will vouch safe for it. He knows the present condition of this project. Some years ago there was unprecedented flood in Vaigai which breached the banks of the canals feeding the land in East Ramanathapuram District. The scheme was implemented with financial assistance from the Centre. But, now the present AIADMK Government has not taken any interest in repairing these canals just because this scheme was implemented by the D.M.K. Government in Tamil Nadu. Consequently

the people in East Ramanathapuram District are suffering for want of water. I demand that the Central Government should intervene in this matter and ensure that the people of East Ramanathapuram district are saved from extinction by repairing the breached canals here.

Sir, I would like to stress the point that only when Pandiyaru and Ponnampuzha scheme is implemented, the chronically drought-afflicted areas of Palladam and Avinashi in Coimbatore District will get some water of cultivation. Similarly, the Anamalayar and Idliyar originate in Kerala, run through Tamil Nadu and then enter Kerala before they join the sea.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It can be called Idly-Sambar river. When Sambar is poured on the Idly it becomes a river.

SHRI ERA MOHAN : Sir, the Parliament can give that new name. Presently, the waters of these rivers are being wasted. If they are utilised for irrigation, then nearly 2 lakh hectares of land in this portion of Tamil Nadu will become fertile. I suggest that this scheme should be implemented expeditiously in the interest of the people of Tamil Nadu. Similarly, the Palani Kudiraiaru scheme should be taken up for expeditious implementation. A high-level Commission was constituted for the D.V.C. project. I demand that such a high-level Commission should be constituted for the Cauvery Valley project. This Commission should not be just name-sake commission. It should be an active supervisory body with adequate authority to take on-the-spot decisions in the interest of the project.

Sir, the neighbouring State of Karnataka has constructed reservoirs on Kabini, Haringi and Hemavathi which are the tributaries of Cauvery. This has depleted the water supply into Cauvery. The Karnataka Government did not take the permission of the Central Planning Commission to complete these projects. The people of Tamil Nadu have been denied their legitimate share of Cauvery waters. Tamil Nadu has been done the greatest injustice. When the Chief Ministers' Conference was convened in Delhi recently, the Tamil Nadu Chief Minister could not be seen.

SHRI S.T.K. Jakkayan (Periakulam) : The Tamil Nadu's representative was here.

SHRI ERA MOHAN : This was Chief Ministers' Conference. The Chief Minister of Tamil Nadu did not attend this meeting. When Tamil Nadu is burning, it is not proper for him to absent himself from this important meeting.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : The Chief Minister did send his representative to this meeting.

MR. DEPUTY SPEAKER : He only says that the Chief Minister of Tamilnadu did not attend the meeting. He has got every right to say that.

SHRI M. KANDASWAMY: (Tiurchengode) : At that time the Chief Minister of Tamil Nadu was attending a wedding function.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : He is giving false information.

SHRI M. KANDASWAMY : I am not giving false information. He considered the marriage of an actress more important than the Conference of Chief Ministers convened to consider the Cauvery waters issue.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : Sir, this is wrong.

MR. DEPUTY SPEAKER : You need not defend the Chief Minister. He is making only a statement of fact.

SHRI ERA MOHAN : This is Chief Ministers' Conference. We have been discussing Cauvery waters for years in the Parliament. We have been discussing it in Tamil Nadu. The Thanjavur District, commonly called as the Granary of Tamil Nadu, is greatly affected. Yet the Chief Minister of Tamil Nadu did not feel any sense of responsibility. The Central Government should have summoned him to be present for this important meeting.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : He should not say so, Sir. The top leaders like the Chief Minister and the Prime Minister can send their representatives. He is not wrong.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not criticising the Chief Minister. He only says that he did not attend the meeting of Chief Ministers. As a citizen of India and as a resident of Tamil Nadu he has the right to say so. He has not said anything offensive against the Chief Minister, Thiru M.G. Ramachandran. He says that the Chief Minister of Tamil Nadu should have realised responsibility as the Chief Minister.

SHRI ERA MOHAN : Sir, the new Member probably does not know that this issue has been discussed any number of times in this forum and outside.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : The leader has every right to depute his representative if he is not in a position to come. I have got the right to intervene when something wrong is being said.

MR. DEPUTY SPEAKER : You refer to this in your speech. Please do not interrupt him unnecessarily.

SHRI ERA MOHAN : The Tamil Nadu Chief Minister has no time to attend to such important national jobs. His attention is always on the Poes Garden now. The fate of Tamil Nadu depends upon the early settlement of Cauvery waters issue. I suggest that our hon. Minister of Irrigation should immediately convene a Conference of the Chief Ministers of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry and find a permanent solution to this long outstanding problem. Before the district Thanjavur, called the granary of Tamilnadu, becomes an arid zone, and before the people of Tamil Nadu become victims of starvation, the hon. Minister of Irrigation should find a solution to the Cauvery waters dispute. With these words, I conclude my speech.

श्री बीरबल (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ एक विशेष समस्याओं के बारे में सिचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

गंगानगर जिले में गंग कैनल करीब 50 बरस से चल रही है। 2750 क्युजेक की यह नहर अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले रही है क्योंकि पीछे पंजाब के हिस्से में बुरी तरह से

क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। इस नहर की मरम्मत का काम शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये।

मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाये ताकि भाखड़ा एरिया के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके।

राजस्थान कैनल एरिया में 75 के बाद जो अन-कमांड जमीन को पानी दिया गया था, जो आबपाशी रजिस्टर में भी दर्ज है, मगर अब इनको पानी नहीं दे रहे हैं, सो दिया जाये।

राजस्थान कैनल एरिया में बने पक्के खालों की कमी को पूरा कर के, आज से पहले की रकम का जो ब्याज है, वह माफ किया जाये।

राजस्थान कैनल एरिया में भूमिहीनों को जमीन दी जाए और हरिजनों के लिए 35 परसेंट का रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। हरिजनों को 1968 और 1969 में जो जमीन एलाट हुई थी, वह कागजों में कमांड है और मौके पर अनकमांड है। इसलिए फलासिफिकेशन करके जो जमीन लेवल के हिसाब से अनकमांड हो उसकी कीमत अनकमांड के हिसाब से ली जाये।

पूरे प्रदेश में जमीन को कहीं भी नीलाम न कर के भूमिहीनों में बांटा जाये।

राजस्थान कैनल एरिया में जो काश्तकार 1955 से पहले के हैं, उनसे थोड़ा प्रशासनिक खर्चा लेकर सीलिंग सीमा तक खातेदारी दी जाए।

नोहर कैनल का काम शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए। सिद्धमुख नहर का काम भी चालू किया जाए।

हनुमानगढ़ में खाद का कारखाना लगाया जाए। जितनी खाद वह कारखाना पैदा करेगा, वह पूरी की पूरी इसी जिले में खपत हो सकती है, क्योंकि वह पूरा जिला सिंचित एरिया है और कारखाने की एक्वायरशुदा जमीन भी वहां पर मौजूद है।

श्री मनोराम बागडी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, कहने और सुनने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ।

ऐसा मालूम होता है कि पानी की जगह अब खून बहाया जाएगा। भारत में बाढ़, सूखे और अकाल का कारण पानी है। लेकिन इस वक्त ऐसी नीति है, जो भाइयों को आपस में लड़ाती है और पानी की जगह खून बहने लगता है। अगर नदियों के बारे में फौसले कायदे-कानून से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किये जाते, तो आज की स्थिति पैदा न होती कि पंजाब और हरियाणा में और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लड़ाई हो रही है। 1976 में फैसला हो गया। वह एवार्ड मान लिया गया। उसको न मान कर 1981 का एवार्ड प्रधान मन्त्री ने दिया। उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया। उसके बाद पानी का सवाल खालिस्तान तक पहुँच गया और इन्सानियत पर चोट लगी। पानी के इन सब झगड़ों को मिटा देना चाहिए। एक ही मुल्क में पानी और जमीन के बंटवारे में लड़ाई और गोली का इस्तेमाल देशद्रोह है। उसका फैसला अदालत और कानून से होना चाहिए।

जो पक्की नालियाँ बनाई जाती हैं, उनका पैसा किसानों से क्यों लिया जाता है? दुकानदार अपना माल बेचता है, वह माल का पैसा ले लें। इतना बेईमान दुकानदार नहीं देखा, जो दुकान बनाने की कीमत भी खरीदार से वसूल कर लेता है। पक्की नालियों का पैसा किसानों से नहीं लेना चाहिये।

मैं नहीं चाहता कि मद्रास और दिल्ली में कोई फर्क हो। इस फर्क को मिटा देना चाहिए, वरना देश के लिए नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। मद्रास में पीने के पानी की किल्लत है। अगर कहीं दिल्ली में होती, तो इस समस्या का हल निकल गया होता। क्या यह सरकार है या ऐसा टोला है, जिसकी कोई समस्या नहीं

है? जब प्यास लगती है, तब वह कुँआ खोदता है। यह तो पागलपन है। पानी ले जाने के लिए यह सरकार रेलगाड़ी चला रही है। 15 दिन पहले क्यों नहीं? दुबई, कुवैत जहाँ पीने का पानी होता नहीं है, वहाँ भी पानी पहुँच जाता है। आप हरियाणा और पंजाब को, भाई-भाई को लड़ाना चाहते हैं जहाँ एक घर में पत्नी हिन्दू और खाविन्द सिख या पत्नी सिख और खाविन्द हिन्दू। अगर कोई मुजरिम है लड़ाने वाला तो वह सिर्फ सरकार है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इन तीनों बातों को समझ ले। 1976 का एवार्ड लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया जाए। राजस्थान अकाल से ग्रस्त है। गाय पाँच रुपए में और बैल 10 रुपए में बिक रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं। यह बीमारी बहुत बढ़ गई है, इसका तुरन्त इलाज नहीं है लेकिन सरकार कोशिश करे जिससे कि यह मामला हल हो सके। बिजली और पानी का इलाज निकालना चाहिए। जमीन के नीचे जो पानी है उसको भी निकाल कर बंटवारा होना चाहिए। सिर्फ आकाश के भरोसे पर कोई देश रहे और यहाँ पर सरकार भी रहे तो ऐसी सरकार के रहने का अख्तियार नहीं है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, some Members from this side and also from that side want to speak today because they will not be available here on Friday. I would, therefore, call such of these Members who have expressed their desire to speak today, and to that extent we will have to extend the time of the House...

AN HON. MEMBER : Upto 7.00.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not so much. We may have to extend by 30 minutes or so. Such of those Members whose names are here and who will not be available on Friday may send their names. Each hon. Member will take only 5 minutes. The Minister will reply on Friday. Now I call Mr. D.P. Yadav.

श्री डी० पी० यादव (मुँगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सिचाई मंत्रालय की माँगों पर

बहस कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सिंचाई मंत्रालय का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत संजीदा, बोले कम और करे ज्यादा—ऐसा व्यक्ति है। श्री राम निवास मिर्घा जी को मैं जानता हूँ, वे गृह राज्य मंत्री थे, जितने भी टेढ़े से टेढ़े सवाल होते थे, वह सब मिर्घाजी के माथे सौंपे जाते थे और वे बड़े ठण्डे दिल से, बड़ी चतुराई के साथ, उनको हल कर लेते थे।

बीस सूत्री कार्यक्रम का पहला आइटम सिंचाई ही है। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि किस तरह से आप इस देश की सिंचाई की समस्या को हल करेंगे। पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी की रिपोर्ट आई है जिसके पेज 24 पर लिखा है कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन सी स्कीम्स बनाई गई थीं। मन्त्री जी उसको आप गहराई के साथ देखें और सोचें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 211 मीडियम इरिगेशन स्कीम्स टेकअप की गईं और 208 पूरी हुईं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 115 टेकअप की गईं और 112 पूरी हो गईं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 74 ली गईं और 64 पूरी हो गईं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 104 ली गईं लेकिन 41 ही पूरी हुईं। उसके बाद घटती गई। पंचम पंचवर्षीय योजना में 375 ली गईं लेकिन 21 ही पूरी हुईं। चतुर्थ, पंचम और छठी योजनाओं में मीडियम सिंचाई योजनाएँ पूरी नहीं हुईं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि पहले के जो इंजीनियर थे उनमें ज्यादा देश भक्ति थी।

18.00 Hrs.

लेकिन जो नए इंजीनियर्स आए हैं, उनको निश्चित रूप से काम से कम मतलब है और अर्थ-संग्रह से ज्यादा मतलब है। इस बात को मैं साफ-साफ मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ। प्राइस एसक्लेशन के बारे में किसी

ने कहा था कि वह पांच गुना बढ़ती है। मेरे ख्याल से यह गलत है। मेरे पास अपने बिहार राज्य के और सारे देश के आंकड़े हैं जो सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हैं। मेरे ख्याल से कोई भी सिंचाई योजना ऐसी नहीं है, जिसमें 5 से 15 गुना की वृद्धि न हो। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं इसमें खामियाँ हैं। यह खामियाँ कौसी हैं, वह आप किसी बड़े शहर के मुख्यालय में जाकर देखिए। बड़े-बड़े इंजीनियरों के दस-दस, बीस-बीस लाख के मकान बने हुए हैं। वे मकान इस देश के गरीब लोगों के पेट को काट कर बनाए गए हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय में एक ऐसा सेल होना चाहिए, जो यह देखे कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके कितने मकान हैं और बैंकों में कितनी पूंजी जमा है। सगे-संबंधियों की बैंकों में कितनी पूंजी है। इन सब की एन्वयरी होनी चाहिए। तब जाकर आपको पता लगेगा कि सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में क्या बिलम्ब होता है। सिंचाई योजनाओं के लिए अत्यधिक पैसा दिया गया। राष्ट्र ने समझा पैसे का आवंटन करो, ताकि हमारा काम आगे बढ़ेगा। इंजीनियरों ने समझा योजनाओं की राशि काम के लिए नहीं आगे के लिए है। मैं उदाहरण देकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ कि किस-किस योजना में कितना-कितना पैसा बर्बाद हो चुका है।

मैं आपको एक, दो उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार राज्य के सिंचाई मंत्री श्री उमेश्वर प्रसाद वर्मा जी का पत्र मेरे पास आया है। उनकी ईमानदारी और निश्चलता और नेक-नीयता पर कोई भी दाग नहीं है। वह व्यक्ति निश्चल और ईमानदार है। वे लिखते हैं—'मेरा पूर्ण प्रयास है कि स्थिति में सुधार हो और काम आगे बढ़े। वास्तव में अनेक कठिनाइयाँ ऐसी हैं, जिन पर शीघ्रता से काबू पाना संभव नहीं हो पा रहा है।' इसका मतलब यह है कि वे भी लाचार हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की कमजोर आवाज उनके मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। स्थिति बिगड़ी हुई है, तो यह एक ऐसा मौका है जिस पर आपको

दृढ़ता काबू पाना होगा। इसमें केवल आप से ही समन्वय स्थापित कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको प्राइस एसक्वेशन का देना चाहता हूँ। वे महरना योजना की स्वीकृति सिचाई विभाग ने सन् 1973 में दी। 62 लाख 61 हजार रुपये स्वीकृत हुआ। इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन नौ करोड़ हो गया। 62 लाख की योजना और 9 करोड़ पर चली गई। मिर्धा जी, 15 गुना नहीं हुआ, तो और क्या हुआ। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यह समस्या क्यों पैदा हो रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कमेटी बीस सूत्री कार्यक्रम की थी, जिसमें चीफ इंजीनियर ने जो कहा है, वह मैं पढ़ना चाहता हूँ। सरकार का आदेश ऐसा है कि बाहर के व्यक्ति को बहाल नहीं कर सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी के पास आशुलिपिक नहीं है। नक्शों के लिए ड्राफ्ट मैन नहीं हैं, बल्यू-प्रिन्टर नहीं है—सब व्यवस्था डगमगा उठी है। ऐसी परिस्थिति में सिचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लक्ष्य के अनुरूप कैसे प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति मुंगेर जिले की ही नहीं, समूचे बिहार की स्थिति डगमगाने लगी है। यह चीफ इंजीनियर कह रहा है, जबकि इर्रिगेशन टैक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। भरी सभा में मंत्री की मौजूदगी में यह कहा जाए की व्यवस्था डगमगा रही है। एक तरफ 15 गुना दाम बढ़ा चीफ इंजीनियर की असावधानी के कारण या वैस्टेड इन्टरेस्ट के कारण, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि व्यवस्था डगमगा रही है।

कहीं-न-कहीं कुछ दोष है और उसको ढूँढना होगा।

मैं आपको बतलाऊँ कि किस प्रकार से पैसा लूटा जा रहा है। एक एकजीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने पूछा कि आप ने प्रेशर रिलीज बल्ब 16 लाख 3 हजार रुपये का खरीदा है, यह काम में कब आयेगा। वह 17 नवम्बर, 1981 को लिखते हैं—

“It is very difficult for the undersigned to say about the specific date by which the pressure release valve will be utilised.”

अब 1983 गुजर रहा है, उसका उपयोग कब होगा इस का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि उसको किसी मकसद से खरीदा होगा, वह कैसा मकसद है.....

एक माननीय सदस्य : कमीशन के लिए खरीदा होगा।

श्री डी० पी० यादव : जो भी हो। मिर्धा जी, असलियत में जाना होगा। केनाल बनाइये, गारलेड केनाल बनाइये, डा० के० एल० राव की योजना को लाइये, हमारा मकसद यही है कि काम होना चाहिए। वाटर कमीशन में हमारे पास अच्छे-से-अच्छे इंजीनियर हैं, बढ़िया से बढ़िया टैक्नालाजिस्ट हैं। डिजाइन उन पर छोड़िये। काम की गहराई में जाइए। असल कारण क्या है—एक योजना यहां से पास करते हैं, अगर कलैक्टर की इच्छा नहीं है या एकजीक्यूटिव इंजीनियर से समन्वय नहीं हुआ, जमीन एक्वायर करने में देरी हुई परिणाम यह हुआ कि कास्ट दुगनी हो गई। इसलिए जो भीतर की बात है उसका समन्वय किया जाय।

इस समय सेन्ट्रल वाटर कमीशन में जो काम हो रहा है उसे केवल सिविल इंजीनियर्स कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस में कुछ सोशल-साइन्डिस्ट्स, कुछ इकानामिस्ट्स, कुछ जीयो फिजिसिस्ट्स, कुछ जीयोलाजिस्ट्स, इस तरह के लोगों का भी परमानेंट एडवाइजर्स रखिए। जीयोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया में से कुछ लोगों को एडवाइजर्स के रूप में रख लिया जाय। इस में कोई हर्ज नहीं है।

योजना की जियोलाजिकल इंजीनियरिंग एसपेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं होती है। योजना पास हो जाती है। 8-10 साल तक रिपोर्ट तैयार नहीं होती है क्यों डायरेक्टर, जियोलाजी कलकत्ता में बैठा है, काम मुंगेर में हो रहा है, एकजीक्यूटिव

इन्जीनियर को फुरसत नहीं है कि वह बात करे, प्लान रेडी नहीं है, ड्राफ्ट रेडी नहीं है, काम नहीं हो रहा रहा है। इस तरह से पैसा बरबाद हो रहा है, सारी व्यवस्था डगमगा रही है। सारे सुविधा भोगी पद-स्थापित लोग मोज-मजा उड़ा रहे हैं, लेकिन ज्योलाजिकल इंजीनियरिंग की स्टडी नहीं हो रही है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

इधर राज्य सरकारों में यह देखने में आ रहा है कि सिंचाई के लिए बहुत से विभाग हो गये हैं। केन्द्र में "काडा" सिंचाई मंत्रालय में है लेकिन बिहार में "काडा" यानी कमाण्ड डेवलपमेंट आथारिटी कृषि मन्त्रालय में है। ट्यूबवेल एग्रीकल्चर के साथ है, माइनर इर्रिगेशन एग्रीकल्चर के साथ है, कुछ पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलीफ के नाम पर बांटा जाता है जो कलैक्टर के पास चला जाता है। एक तरह समन्वय का अभाव है। मल्टीप्लिसिटी के कारण आप के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

आपके पास सभी रिपोर्ट्स हैं इर्रिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, फलड कंट्रोल कमीशन की रिपोर्ट है। एलड कंट्रोल कमीशन की रिपोर्ट पर आप के मंत्रालय ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। डाउट-प्रोन-एरिया का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा है—फलड-प्रोन एरिया का प्रोग्राम भी चलाइये। मैं निवेदन करूंगा कि करीब 40 लाख हेक्टेयर जमीन फलड-प्रोन एरिये में आती है, उसकी रक्षा के लिए कोई उपाय लगाइए।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा आइ० आइ० टी० हो, बी० एस० आइ० हो या नेशनल फोटो इन्टरप्रेंटेशन सर्वे आफ इण्डिया हो, इन तमाम एजेन्सियों को समन्वित रूप में लगाइए जिससे हमारा माइक्रो-लेवल-प्लानिंग एरियावाइज हो सके। किसी वाटर-शेड-एरिया में मान लीजिए 5 लाख एकड़ जमीन है तो उस का माइक्रोलेवल-प्लानिंग होना चाहिए चाहे इस में आइ० आइ० टी०, को लगाना पड़े,

ये जो हमारे यहां आइ० आइ० टी०, ज्योलाजिकल, सर्वे आफ इंडिया, नेशनल फोटो इन्टर प्रिंटेशन सर्वे आफ इंडिया, रिमोट सेंसिंग आरगेनाइजेशन को हमारी एजेंसियां हैं परन्तु उपयोग हम सिंचाई के क्रियान्वयन में नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए।

महाराष्ट्र की एक योजना के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। वहां चन्द्रपुर और भंडारा दो जिले हैं। उन दो जिलों के लिए कोशी खुद प्रोजेक्ट है। लेकिन यह प्रोजेक्ट सेंट्रल वाटर कमीशन में पड़ा हुआ है या प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है। इस योजना के कार्यान्वयन न होने से वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप इसको दिखवा लें और जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट बना कर इसकी सेक्शन हो जाए। यह बड़ी कृपा होगी।

आपने 90 ड्राफ्ट प्रोन एरियाज का रिपोर्ट तैयार किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत उपयोगी रिपोर्ट है। इसको कंसाइज रूप में तैयार करवाइए और आम लोगों में वितरित करवाइए। जिससे कि इसका उपयोग हो और आम लोगों को इसकी जानकारी हो। अगर ऐसी रिपोर्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स का बन जाए तो काफी फायदा होगा। यह जो बोल्यूम है, यह बड़ा उपयोगी है।

अन्त में आपको एक बात और कहना चाहता हूं। अभी बी० एस० सी० इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिकेनिकल इंजीनियरिंग आदि का कोर्स अलग है। आप मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन के टैक्नीकल डिविजन से बातचीत कर एक नया कोर्स सिंचाई इंजीनियरिंग के लिए भी तैयार करवाइए। मैं अपने को दोषी मानता हूं कि जब मैं खुद शिक्षामंत्री था उस समय यह आइडिया मुझे नहीं आया और यह कोर्स मैं खुद तैयार नहीं करा सका। नए सिरे से एक कोर्स इर्रिगेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए होते

हैं, मिकेनिकल और सिविल इंजीनियर होते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हुआ आपकी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Mr. Deputy-Speaker, Sir, being aware of the fact that Demands for Grants of the Ministry of Irrigation debated at the moment under the shadow of sledge and hammer blow and after the Report of the Public Accounts Committee which was laid on the Table of the House only day before yesterday, I will not try to add to the discomfiture of our friend, Mr. Ram Niwas Mirdha because he has borne every burden of his predecessor. But I hope that he will remember the corrective measures suggested by the Public Accounts Committee. For want of time, I shall not go into the details of the Report. But I would like to point out one thing which is taken place in his Ministry. Sir, once bitten, twice shy, and that is what is happening in his Ministry. About the target in regard to the irrigation potential, this year, I find nothing concretely has been spelt out. It has been mentioned like this that 3 million hectares 'should'.....but whether that is the target or not has not been stated anywhere. I heard one Congress-I Member referring to it as 3 million and we also took it that this target figure was 3 million for 82-83. But only now I find that quietly it was again brought down. But certainly this year's (i.e. 82-83) target has been shown as 2.35. That means, now the actually the figure is different, and not the 3 million which is being taken in general. I want to raise this point, because if this figure of million remains something which is only being talked about, there is no possibility of fulfilling the 8th five-year plan. I would like him to spell out the target for 1983-84.

Secondly, I think there is a big declaration, viz. "Under the New 20-Point Programme, increase in the irrigation potential has been given the highest priority." This is a very lofty declaration; but if my mathematics has not gone wrong, I find that compared to last year's revised budget, this year's estimate is only Rs. 12 crores extra. Am I right, Mr Mirdha? So, with Rs. 12 crores extra, does he really believe that there is any earthly possibility

of reaching that 3 million; and is that the reason to keep all this nebulous? Naturally, I will have to vote against the Grant, if not for any other reason, because of this totally illusory grant—I would have to vote against it for this reason, apart from others, because this is creating an illusion.

I have some more observations to make, but I will not go into them in detail for want of time I will try to go at the speed of Milkha Singh, and try to cover some of the very urgent problems of my State which, I am sure, you will allow me to do.

MR. DEPUTY SPEAKER: Why not like Valasamma?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: One problem is there which pertains not only to my State, but also to others. It is about the actual utilization of irrigation potential. There, everybody has pointed out that this is the most important thing. It is about the Command Area Development Programme, and in which the field channels are one of the most important things.

Here, in this performance budget, figures have been given about the target of constructing field channels, and the fulfilment of these targets. Many States, including my own, have not been able to keep pace with the targets.

MR. DEPUTY SPEAKER: Prof. Rup Chand Pal has dealt with it. You speak only about such of those points which he has not touched upon.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I am trying not to deal with those points. If I do it, I will do so, only to add.. some new points.

About field channels, we are not in bad company. There are many States, including Maharashtra, which have failed very heavily, in fulfilling the targets. There are many States which have not been able to do anything. I am glad that a decision has been taken that in the new projects in the command area, the project will bear the cost of field channels, at least a big chunk of it. But it seems to me very funny. The old projects where field channels are not there, money in the projects has already been sunk; and it is there that the return must come first. So, it is those old projects

which should have been the first to take to this, viz. that the field channel cost should be borne by the project itself. Otherwise, the actual utilization will go on as it is going. So, I would particularly request the Irrigation Ministry, and also demand of the Planning Commission, that if they have said so many lofty things, let them come out with it, that in those old projects, the field channel costs will be borne by the projects, and not by individual farmers who are not yet prepared for it, for which we are losing a lot of potential. This is a problem not only of our State, but also of others. That is why I say this emphatically.

Secondly, there is some other thing about which not only our State, but all other States are also concerned. A part of it has already been raised by Mr. Pal. I am supplementing him. The hon. Minister, Mr. Mirdha has been very kind to write a reply to my 377, about this question of subsidy to the small and marginal farmers, for sinking their own shallow tube wells. I have his letter dated 9th April, 1983, which is very diplomatically couched, though I do appreciate that diplomacy. He says, as far as this question of development is concerned this question is receiving attention. How? The last paragraph of his letter reads as follows :

“Under the IRDP, with the new criteria of giving benefits annually only to 600 of the families below the poverty line in a block, it has been apprehended that subsidy in minor irrigation schemes may not be available on the same scale as was hitherto to all small and marginal farmers under the Small Farmers Development Agency Programme till October 1980. Accordingly, a separate scheme for giving subsidies to the small and marginal farmers for minor irrigation schemes is under the active consideration of the Ministry of Agriculture and the modalities of the scheme are being worked out.”

It is not only a question of relaxing that provision which is very important, but increasing the quantum of subsidy to the small and marginal farmers at the rate of 50 per cent—that is what we think—is a necessity and without that no amount of active consideration will meet the situation.

There are certain very serious problems. Regarding Farakka Barrage, you know, there is a very serious problem of erosion of that Ganges. We are losing land and are adding it to Bangladesh, as the situation stands, because the other side is getting land. But let them have it. I do not grudge. But a very serious situation has been created due to erosion. It has come within 300 yards of the railway line and within one km. of the feeder channel. It means that unless this erosion is immediately and effectively checked, both the railway line and the feeder channel will be threatened as also the entire Farakka Barrage, including the Calcutta Port, and international complications will be created. For that, Centre has taken some responsibility, but that is not enough at this is a border region and there is a serious problem. On this question, I implore the Central Government to take much bigger responsibility with regard to checking erosion in Farakka Barrage.

There is another international question with international complications. It is the Teesta Project. That is the only source of water in a big way in North Bengal. Its estimate is Rs. 250 crores. But what is going on at the moment? This year, Rs. 23 crores have been allotted by the West Bengal Government for it. Our government's source is very limited. Even then, they have given Rs. 23 crores. But the rate at which it is being built, it will take 10 years; and if it takes 10 years, then by that time, for sharing of the water of the Teesta Project, there will be commotion in international relations, unless we go quickly and complete this project much earlier. Then there will be another connecting problem. Therefore, I again implore on this question that some loan assistance should be secured urgently so that this Project can be completed quickly and effectively. It is not only our State, but these are connected with the international question. I also hope that in any case need of extra water will be adequately protected.

Now, I come to Subernarekha Project which is having inter-State significance also. As far as this Project is concerned, it is still waiting technical clearance, whose barrage we are supposed to build, it is awaiting

technical clearance. But technical clearance alone will not do. I am glad that Bihar and Orissa Subernarekha Dam Project has been cleared. I understand that the World Bank's assistance has been negotiated for that. I request the Minister to play a very active role in getting our barrage technically cleared and also arrange to get some facility for loan.

Coming nearer home, resuscitation of Rupnarain river is very necessary. It is by the side of my constituency, it is feeding Haldia to some extent. There are floods in this river every time. If this is the situation of Rupnarain today, it is not the working of our State Government, either the Congress or the present Government. It is because of the construction of three Railway bridges on it consecutively in a short span of space. Due to that Rupnarain has no capacity to bear more water. It is virtually smothered. That being the case, I implore that the question of resuscitation of Rupnarain be taken up on a different plain. Let this question be examined by the Poona Institute, so that this can be taken up in future.

Unless Mirdhaji fights strongly to get more finance, all these estimates will again go into a situation where another Public Accounts Committee will come out with a sharp criticism. I hope, he will avoid that situation.

SHRI BHUBANESHWAR BHUYAN (Gauhati) : While I am supporting the Demands for Grants relating to the Ministry of Irrigation, I would like to draw the attention of the Minister of Irrigation to Assam, through you.

You know that Assam is a land of plenty of water and now it is known as a land of perennial floods. The river Brahmaputra, which used to be the hopes and aspirations of the people of Assam, has, of late, turned into a river of sorrow. In this connection I would like to mention that in China a river Howangho, is called by the name River of Sorrow. Now the Chinese Government has turned that river into a river of hopes and aspirations of the people of China. I am sorry to say that since independence the Congress has ruled this country with a little interlude when Janata Party was in power, but it has failed to turn Brahma-

putra into a river of hopes and aspirations for the people of Assam. Assam failed to receive the due attention that it ought to have in the hands of the Government, it being a border State of India. That is why, the people of Assam have lost almost all faith in the Government of India and in the major political parties of India. The consequence is that the whole of Assam is burning today. If we think that it is only the people of that State who are responsible for that, it is not correct. The Centre has a duty to consider that aspect. I would like to inform you that it is not merely Assam but the entire eastern region is burning. You are getting its evidences every now and then. It is pouring into our ears that you are getting reports. Why this is so ? Because the entire eastern region has not been attended to during this period.

I would like to mention that Assam, although it is a land of plenty of water, yet it suffers from drought conditions. Particularly during the winter, it suffers from the scarcity of water. As a consequence of this, although the land of Assam is more fertile than the rest of India, yet it remains uncultivated, untenured. As a consequence, Assam, that used to be the granary of East in the past, has become a deficient area even in matters of food-stuffs. So, the Department of Irrigation has a lot to do. There are every potentialities of harnessing this Brahmaputra river. Of course, I offer my thanks to the Government of India for constituting a Brahmaputra Flood Control Commission but up to this date this Commission failed to do any perceptible work so far as controlling of the river Brahmaputra is concerned except erecting a few dams to protect the erosion on the banks of the river Brahmaputra. As a consequence of these things and as a result of this lack of irrigation projects in Assam, the whole of Assam is suffering from shortage of food-stuffs at present. The lack of any proper planning for the development of this State so far as irrigation is concerned, is also another important factor to be noted. So, in this respect I take this opportunity to appeal to our Irrigation Minister through you to prepare and execute on war-footing certain plans of irrigation schemes for the whole of the State, particularly with reference to the thickly populated areas of Kamrup district, areas of the Nowgong district, Darrang district and

Goalpara district. These are the most thickly populated areas. In Palebary in Kamrup district, although there was a scheme framed for the irrigation, the deep-well scheme, but for want of necessary funds that had to be suspended. I request that the said scheme may kindly be revived within a very short time.

Furthermore, there are sore areas. One big sore area, known as Kalachar, can be irrigated with a little device of having some canals dug out to the interior part of sore. Easily that char can be turned into a most highly cultivated land and we can expect a far better result in the field of agriculture. As you know the agriculture, particularly the scientific agriculture requires the first and foremost attention in irrigation. In the entire southern part of the Kamrup district, tracing from Gauhati to the border of Goalpara town in the Goalpara district, there is ample scope for irrigation. If these lands are irrigated, then it will definitely yield better crops and it will provide better activities to the people.

In the end, I would request that in the light of the recent happenings, if we want that we should be something for quelling all this agitation, all these disturbances, not only in Assam but in the entire eastern region, I think we can have three things to be done simultaneously. The first and foremost thing is that we should curb the lawlessness, wherever it may be, with an iron hand. Secondly, as far as Assam is concerned, detection of the foreigners is the first and foremost thing, which should be started. Simultaneously, there should be development in all respects, so far as Assam is concerned.

If we have to go in for the development of Assam, then the first and foremost requirement is irrigation, because the State must be made self-sufficient, so far as food production is concerned. Then only the Government of India, or we in Assam, will be able to go in for further progress and development, so far as industries and other scientific processes are concerned. So, my humble request to the Minister of Irrigation is to consider all these aspects and give us whatever we can. I hope that within a short time he will initiate further schemes of irriga-

tion, so far as Assam is concerned.

With these words, I support the Demands for Grants relating to this Ministry.

*SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periakulam) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Irrigation for 1983-84.

I am glad to say at the very outset that the Central Government has realised the importance of irrigation in our developmental activities and has given independent status to this Ministry for the first time. I am also happy that this has been put under the charge of capable Minister, Shri Ram Nivas Mirdha. Sir, I know that he played a significant role in the successful holding of 9th Asian Games in our capital. I am sure that he will be able to find a lasting solution to the pending inter-state river water disputes during his term of office. Here he has to use all his latent talent in curbing an early solution to this problem affecting the nation's progress. I am sure he will meet with success in his laudable efforts.

Sir, the National Floods Control Programme was initiated in 1954 and upto March 1982, some steps have been taken to control the floods in about 120 lakh hectares. Some 400 lakh hectares are susceptible to recurring floods year after year. The annual loss due to recurring floods and drought in our country is estimated to be Rs. 1000 crores on an average. I would like to know from the hon. Minister the action taken on the recommendations contained in the Report of National Floods Commission.

Sir, the only lasting solution to the recurring floods in North and drought in South is the linking of Ganges in North with Cauvery in Tamil Nadu. If this is done, then India will be supplying foodgrains to the entire world. Recently the hon. Prime Minister has stated that this scheme has been taken up by the Centre for detailed examination. I would like to suggest that the Government of India should seek financial assistance from the World Bank and the Asian Development Bank for implementing this scheme, which will transform the entire nation.

As has been pointed out by the hon. Member from Tamil Nadu, under Article 262 of our Constitution and under item No. 56 of the Union List in the Seventh Schedule of our Constitution, the Government of India has enacted the Inter-State Water Disputes Act, 1956 and the River Boards Act, 1956. But, unfortunately, the Government of India has so far not chosen to exercise its constitutional authority in settling these inter-state water disputes. Though 'water' is in the State list, yet the Centre has been empowered to act in the interest of the nation so far inter-state river water disputes are concerned. In 1974 the Cauvery Waters Agreement between Karnataka and Tamil Nadu came to an end. If at that time, the then D.M.K. Chief Minister, Thiru Karunanidhi had taken prompt action for a fresh agreement, this critical situation could have been averted.

SHRI M. KANDASWAMY : I want to know what the present Chief Minister of Tamil Nadu has achieved during the past 5 years.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN : Our Chief Minister is trying to get things done what his predecessor could not achieve.

SHRI ERA MOHAN : Mr. Kandaswamy is asking whether the present Chief Minister has achieved anything tangible during the last five years of his rule.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN : I would like to emphasise that if the D.M.K. Chief Minister, Thiru Karunanidhi had taken steps as soon as the Cauvery Agreement came to an end, the things would have taken a different shape.

SHRI ERA MOHAN : You ask your Party General Secretary Shri P.V. Shanmugham, who was then a colleague of Shri Karunanidhi as to what steps the Chief Minister Karunanidhi took in regard to Cauvery Water dispute.

SHRI M. KANDASWAMY : What has your Chief Minister done in this matter ? He is interested in attending the marriage of an actress. He is not interested in attending the meeting of the concerned Chief Ministers convened for the specific purpose of discussing the Cauvery water disputes.

SHRI ERA MOHAN : Your Chief Minister has done this so far.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : Sir, the way in which the proceedings are going on, you can see that it is against the parliamentary dignity and decorum.

MR. DEPUTY SPEAKER : He can express his views. If you do not agree with him, you can oppose him on some other occasion. But this kind of interruption will not help. He has got every right to express his views. The parliamentary etiquette demands that there is no such unnecessary interruption.

SHRI ERA MOHAN : Sir, let him give his views. But he should not mislead the House.

SHRI M. KANDASWAMY : The present Chief Minister is not at all interested in a thing except attending the marriage of an actress. He is interested in everything else excepting the Chief Ministers' Conference.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already said that. He can say his point of view.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN : I would like to repeat with all the force at my command that if in 1974 itself, after the Cauvery Water agreement lapsed, the then Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Karunanidhi, had taken immediate steps for a fresh agreement, the things would not have become so bad as they are now.

MR. DEPUTY SPEAKER : Why are you repeating the same ? You go to the next point.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, yesterday you said that the Members should have absolute freedom.

MR. DEPUTY SPEAKER : I am asking him not to repeat it.

SHRI ERA MOHAN : Sir, he is misleading the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Jakkayan, please do not repeat the same point. Please go to the next point.

SHRI ERA MOHAN : Sir, he is misleading the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please sit down. I am not permitting you. Sometimes you all think that you are in the Tamil Nadu Assembly. You forget that you are in Parliament. You have to settle your disputes in Tamil Nadu and not here. Mr. Jakkayan, you have already mentioned what you wanted to say. Come to the next point. Your time is also up. Please conclude.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, he is speaking something interesting.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Jakkayan, please come to the next point.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN : Even after nine years, the Central Government has not taken keen interest in resolving the Cauvery water dispute between Tamil Nadu and Kerala.

Without the express sanction of Planning Commission, the Karnataka Government have constructed huge reservoirs on Kabini, Haringi and Hemavati, the tributaries of Cauvery which has depleted the supply of water into Cauvery. The State Government of Karnataka has invested Rs. 230 crores under 'Non-Plan Head'. This is real injustice being perpetrated on Tamil Nadu. Without the waters of Cauvery, Tamil Nadu will become the arid Zone like Thar desert of Rajasthan. The hon Minister of Irrigation should intervene and exert his good offices in resolving Cauvery water dispute so that the people of Tamil Nadu are saved from extinction.

The Central Government did take so much pains in concluding the Ravi-Beas agreement between Punjab, Haryana and Rajasthan. In the interest of northern States the Centre has also successfully concluded river water agreement with Pakistan and Bangla Desh. I wonder whether the Central Government has taken similar interest in the settlement of inter-state water disputes like Cauvery water dispute. The very fact that even after nine years the Cauvery water dispute is not yet resolved shows the step-motherly approach of the Central Government towards Tamil Nadu. There cannot be a better example to prove my contention. I

demand that at least now the ebullient Minister of Minister will exert himself in this direction and find a solution to this issue soon.

Many of the west-flowing rivers in South originate in Tamil Nadu and go through Kerala before they join the sea. Kerala does not require all this water. This has been amply proved by the Irrigation Commission in its report. 67 TMC of water of these four west-flowing rivers is surplus to Kerala according to the Irrigation Commission. If that is diverted towards Tamil Nadu, then the dry lands in Ramnathapuram, Madurai and Tirunelveli Districts will become fertile. There is no chance for having any major irrigation project in Tamil Nadu. Tamil Nadu has also utilised all the available underground water. There are 8 lakh pumpsets in Tamil Nadu. Tank irrigation has also come to an end with the failure of two monsoon rains last year. All the tanks have dried up. The only hope is the diversion of waters of the west-flowing rivers. If this scheme is implemented, then Bodinayakanaur, Kombai, Thevaram, Nakalapuram, Andipatti and Sedapatti in my Periakulam Parliamentary constituency, which are traditionally backward areas, will get water for cultivation. One lakh acres of land will become fertile with the implementation of this scheme to divert the waters of westflowing rivers. Similarly, if water from Kallar scheme is diverted to Tamil Nadu then the acute drinking water scarcity in the growing city of Madurai will be resolved for ever.

I know that it will take many years for implementing Ganga-Cauvery link up Scheme. At the initial stages, Godavari-Krishna-Cauvery can be linked. I understand that nearly 70% of Godavari water is going waste into the sea.

If Tamil Nadu dries up, it is not going to help the neighbouring States. It is not the problem of a few people only. It is a problem of the people of India. I appeal to the hon. Minister that he should not allow Tamil Nadu to be wiped out from the map of India. He should give succour to the people of Tamil Nadu by exercising his authority to solve Cauvery water dispute. Before I conclude, I demand that the national rivers should be declared as national assets which should be utilised for the good of the people of India as a whole.

With these words, I conclude my speech. I thank you very much, Sir, for the opportunity given to me.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Bheekhabhai.

You may finish your speech in five minutes.

SHRI OSCAR FERNANDES (Udipi) : The hon. Member who spoke just now have raised some important issues...

(Interruptions)

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। साथ ही साथ मैं सिंचाई मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वे मुलझे हुए सिंचाई मंत्री राजस्थान में भी रहे हैं। सेंट्रल वाटर पावर कमीशन को इस-लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने डी. पी. ए. पी. की योजनायें बनाई हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। दोनों जिले आदिवासी हैं। दोनों जिले शैड्यूल एरिया में हैं। दोनों जिलों में हमेशा अकाल और सूखा पड़ता है। दोनों जिले इस प्रकार के हैं कि शैड्यूल एरिया के अतिरिक्त ट्राइबल एरिया के अन्दर भी आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बांध बांध दिया है। जो गुजरात ने बांधा है, माही नदी पर। उस बांध का नाम कनाड़ा बांध है। इस कनाड़ा बांध से डूंगरपुर जिले को कोई फायदा नहीं होता है और बांसवाड़ा जिले को फायदा होता है और वहाँ पर सागर बनने से ओर भी फायदा होगा। लेकिन मुझे कहना यह है कि इसका उद्घाटन आज से 20 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तीस टाइम उसकी कास्ट बढ़ चुकी हैं। माही सागर में रहने वाले जो इंजीनियर हैं, वे बीस साल से वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने वहाँ अपनी प्रापर्टी बना ली है। अपने घर बना लिए हैं और वे वहाँ रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग गांधी सागर गए, फिर गांधी सागर से राना प्रताप सागर गए और वहाँ से फिर कोटा बंराज में गए। सबसे

पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जांच आयोग कायम किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चले कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया है और कितना सीमेंट तथा लोहा ब्लैक मार्केट में दिया है और कितनी संपत्ति उनकी बैंकों में जमा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले हैं। डूंगरपुर जिले के लोगों को इस बांध से प्रभावित होना पड़ा है। गुजरात सरकार ने इसको कमांड एरिया में भी नहीं रखा है। 1966 के एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि पानी बाड़मेर और जालौर को दिया जाए, इसको गुजरात सरकार ने मना कर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह पानी आप वहाँ नहीं देना चाहते हैं तो डूंगरपुर को उससे क्यों वंचित किया है? उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं। उनकी जमीन चली गई, मंदिर चले गए, सड़कें चली गई। गुजरात सरकार ने उनको न कमांड एरिया में लिया है और न ही उनको बसाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार के साथ फिर करार करना चाहिए। 1966 के एग्रीमेंट में रद्दीबदल करनी चाहिए। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे इसकी जांच करें और यह बतायें कि मैं कहाँ तक सत्य हूँ। कितनी सम्पत्ति बनाई है और कितना पैसा जमा है, इसका आप कंटागोरिकली जवाब दें।

दूसरी बात मैं राजस्थान नहर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। राजस्थान नहर का शिलान्यास हमने पं० गोविन्द बल्लभ पंत से सन् 1958 में करवाया था। इस परियोजना के जो ड्रीम करने वाले थे, श्री कंवर सेन, उन्होंने एन्विसेज करके काण्डला तक ले जाने का प्लान बनाया था जैसा कि श्री मेहता ने, जोकि गुजरात से आए हैं, बताया है। राजस्थान कनाल को आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से माही नदी की जो योजना है उसको भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर पूरा किया

जाना चाहिए। इसके अलावा सागवाड़ा और खांडू में नगरीय भूमि के आवंटन में जो अनियमितताएँ हुई हैं उसकी भी जांच करवाई जानी चाहिए। इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि डूंगरपुर जिला जोकि सबसे ज्यादा गरीब है वहाँ पर लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहाँ पर सिंचाई के कोई स्रोत नहीं है अतः लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा पानी पहुँचाया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा मेरा एक प्वाइन्ट यह भी है कि माही के सम्बन्ध में इंजीनियर्स ने कह दिया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की इरीगेशन मिनिस्ट्री तकनीकी और प्रशासनिक जांच करवाए। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है डूंगरपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे ज्यादा भूमि डूब में चली जाए लेकिन उसके बाद भी वहाँ पानी न मिले, बिजली न मिले, यह घोर अन्याय है। वह आदिवासी इलाका है, उनको जंगलों में बसाया गया है। इसके लिए गुजरात सरकार पर दबाव डाला जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और साथ ही मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि बैकवाटर के सम्बन्ध में गुजरात सरकार के साथ तीसरा करारनाम किया जायेगा ताकि गरीब जनता जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके प्रति न्याय हो सके। इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, आने वाली जेनरेशन्स इसका जवाब देंगी।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए समय दिया।

सर्वप्रथम मैं अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने

सिंचाई मंत्रालय का काम एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा है जो बहुत समझदार और प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो घरती की प्यास और घरती के बेटों की पानी की प्यास को समझते हैं और एक-एक बूंद पानी के महत्व को समझते हैं और उसे किस तरह से बचाना चाहिए, इसको भी वे समझते हैं। इन्होंने ही राजस्थान के अन्दर सिंचाई मंत्रालय का काम संभाला था। इस से इस मंत्रालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि प्रधान मंत्री का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसका पहला सूत्र सिंचाई है। इसीलिए सोच समझ कर ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्री राम निवास जी मिर्धा को सिंचाई मंत्रालय का काम सौंपा है। वे बड़ी चतुराई से इस कार्य को सम्पन्न कर रहे हैं।

मैं राजस्थान के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण तीन भागों में विभक्त हो जाता है। उसका एक पश्चिमी भाग है जो कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है जहाँ पर कि मीलों तक कुछ नजर नहीं आता, कोई तालाब देखने का नजर नहीं आता। राजस्थान का एक हिस्सा वह जिसके बारे में भीखाभाई जी बता रहे थे। वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। राजस्थान का तीसरा हिस्सा अलवर और भरतपुर का है। यह इलाका आज जरखेज है, उपजाऊ है। एक हिस्सा राजस्थान का कोटा है। जहाँ कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पानी उपलब्ध कराया गया, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये हैं और उसका विकास किया गया।

जिस इलाके से मैं आता हूँ वह इलाका न रेगिस्तानी है, न उपजाऊ है और न अनुपजाऊ है। इसके लिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि रावी-व्यास के सिलसिले में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना दृष्टिकोण रखा है उसको माना जाए। उसको राजनीतिक दबाव में आ कर काटा न जाए।

हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद से सिंचाई के वृहत् और मध्यम प्रोजेक्ट तैयार किये गये

हैं। राजस्थान इतना बड़ा प्रांत है लेकिन उस प्रांत के लिए अभी तक जल की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। अगर वहां जल व्यवस्था हो जाती है तो अकेला राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान को खिला सकता है और पूरे हिन्दुस्तान में उससे और भी विकास कार्य चल सकते हैं। राजस्थान में चूँकि पानी का अभाव है और रेगिस्तान है, इसलिए हम वहां कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी बड़ी स्थिति खराब है।

हमारे राजस्थान के बारे में जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं सबने राजस्थान नहर की बात कही है। राजस्थान नहर योजना एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। यह एक राष्ट्रीय योजना है और इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर ही विचार किया जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को इतने लम्बे अर्से तक लटकाये रखना उचित नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से पैसा दिया जाना चाहिए। इस से हजारों हजार मील जमीन, जहां पर कि रेगिस्तान में पेड़ तक नहीं उग सकते हैं, उस जमीन को पानी मिलने से वह इलाका जरखेज और उपजाऊ हो जाएगा। यह इलाका देश के लिए बहुमूल्य इलाका बन जाएगा। आपने गंगा-नगर के बारे में देखा। वह भी रेगिस्तानी इलाका था लेकिन वहां पानी के साधन होने के कारण वह इलाका भी जरखेज हो गया है। इसी तरीके से हम पूरे रेगिस्तान को जरखेज बना सकते हैं। अगर आप वहां यह राजस्थान नहर योजना को पूरा कर दें तो वह सारा इलाका भी जरखेज और उपजाऊ बन जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोयले, सीमेंट, पैसे का जो भी आपको इंतजाम करना हो वह राजस्थान के लिए करें। माननीय सिंचाई मंत्री जी को इस कार्य को टोप प्रायोरिटी के आधार पर पूरा करना चाहिए।

19.00 Hrs.

अब मैं अपने जिले टोंक के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इसके बारे में मैं पहले

ही बता चुका हूं कि यहां पर न तो ज्यादा रेगिस्तान है और न ही ज्यादा पहाड़ हैं। यहां पर जमीन न ज्यादा उपजाऊ है और न ज्यादा अनुपजाऊ है। यहां पर अगर थोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो सकता है। हमारे जिले में बनासा नदी को दो जगह बांधा गया है। मेरे जिले बीसलपुर में भी इसको बांधने की योजना पिछले दिनों से चल रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया गया है और इसको सेंट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा गया है। इस परियोजना का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इससे पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। घरती के लिए तो आप पानी देने में देर कर सकते हैं पर लोगों को पीने का पानी देने में आप देर नहीं कर सकते। लोग मर जाएंगे। मेरे क्षेत्र में अजमेर जिले में केकड़ी स्थान है। यहां का मैंने पिछले दिनों दौरा किया था। यहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बनास नदी के किनारे कुएं खोदे हुए हैं और वहां से पानी एक्सप्लायट करके अजमेर जिले को पिलाया जा रहा है। इससे हमारे जिले में कुओं के पानी का लेबल बहुत कम हो गया है। कुओं में पत्थर फेंकने से आवाज से पता लगता है कि कुओं में पानी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए पीने के पानी का शीघ्र इंतजाम किया जाए। मैंने कई गांवों का दौरा किया। साबर, चोसला, पनराहेड़ा, पीपड़ाज, कादेड़ा, मोलक्या, कालेड़ा, मालेड़ा, नासरदा, कासी आदि गांवों में भारी संख्या में लोगों ने इस बात की मांग की कि हमारे यहां पानी खारा हो गया है और मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। पूरे इलाके के लोगों की बीसलपुर बांध की मांग है। इसको टाप प्रायोरिटी दी जाए और सेंट्रल वाटर कमीशन से इसको शीघ्र क्लीयर कराया जाए। इसको शीघ्र तैयार करवा कर पीने के पानी की ओर सिंचाई की व्यवस्था की जाए।

राजस्थान सरकार ने मुझे बताया है कि इसमें थोड़ी देर हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप चंबल से पानी दे सकते हैं। वहां से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा पानी दिया जाए जिससे अजमेर जिले में पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

कोटा जिला मेरे जिले के नजदीक है। यहां पर नहरों के किनारे-किनारे खार जमा हो गया है। खेतों में अधिक मात्रा में पानी देने से जमीन में नमक की मात्रा अधिक हो गई है। इससे खेती को नुकसान हो रहा है। इसके लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए। पानी का उप-युक्त ढंग से इस्तेमाल किया जाए और मेरे इलाके के पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : सिंचाई मंत्री श्री राम निवास मिर्धा जी से अभी जान-पहचान हुई है। जैसा कि श्री यादव जी ने कहा है और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि उनकी कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठा में मुझे विश्वास है। मैं पहली बार लोक सभा में आया हूं इसलिए मंत्री महोदय को जानने का मौका मिला है यद्यपि मैं इनका नाम बहुत दिनों से सुनता था। मैं अपने क्षेत्र के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। बक्सर से कोइलवर तक गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर तटबंध बनाया गया जिससे भोजपुर जिले की तो बाढ़ से सुरक्षा की गई परन्तु इसका भयंकर दुष्परिणाम आज सारन जिले के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गंगा के दक्षिण में तट-बंध बन जाने से अब बाढ़ की भयावह धारा उत्तर की ओर मुड़कर सारन जिले को बरबाद कर रही है। प्रति वर्ष घन-जन की अपार क्षति हो रही है। इससे कोई त्राण नहीं है। 1980 से बार-बार कहकर में थक गया परन्तु अभी तक बिहार सरकार के सिंचाई अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे सारन जिले को बरबादी से

बचाने के लिए गंगा के उत्तरी किनारे पर गंगा के दक्षिणी किनारे की तरह तटबंध का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए, उत्तरी किनारे पर तट-बंध का निर्माण परम-आवश्यक है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री स्वर्गीय श्री केदार पान्डेय जी, 23 सितम्बर 1983 को बाढ़ की भयंकर विनाशलीला देखने के लिए छपरा गये थे। और, सोनपुर से छपरा रेल द्वारा यात्रा कर रेलवे लाइन के दोनों किनारों पर बाढ़ से उत्पन्न कृत्रिम महासागर का दृश्य देखा था। मकान की छतों पर और रेलवे लाइन पर 20-25 दिनों से बाढ़ पीड़ित शरणार्थियों को देखकर ममहित थे। उन्होंने जगदम कालेज छपरा में छपरा के गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकों की सभा में बाढ़ विभीषिका की चर्चा करते हुए सिसवन से सोनपुर तक गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबंध के निर्माण के लिए पहली किश्त में चार करोड़ रुपये के आवंटन की तत्काल घोषणा की थी। और, सभा में आश्वासन दिया था कि भारत सरकार सारन के नागरिकों की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये इस प्रस्तावित तट-बंध में जितनी भी राशि लगेगी, उसका आवंटन करेगी। अब श्री मिर्धा जी को अपने पूर्ववर्ती सिंचाई मंत्री के अधूरे काम को पूरा करने के उत्तरदायित्व को निभाना है। छपरा के बारे में दूसरा एक और निवेदन करना चाहता हूं। छपरा की उत्तर जल निकासी योजना स्वर्गीय श्री प्रभुनाथ सिंह, मंत्री, स्वर्गीय श्री दीपनारायण सिंह, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री बिहार, स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री-बिहार, स्वर्गीय श्री बनारसी लाल सिंह, भूतपूर्व सिंचाई विभागीय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर पांच लाख की यह जल निस्सरण योजना अब दो करोड़ की बन गयी है। कुछ पैसा खर्च भी किया गया है। केवल कागज पर योजना बनती है। उसके आकार और प्रसार केवल कागज पर ही होता है। वह कभी जमीन पर नहीं उतरती जिससे सारन जिले के छपरा सदर

और जलालपुर प्रखंड के लोगों को खेती करने का सुअवसर नहीं मिलता और घर में अन्न लाने का सौभाग्य शायद ही कभी मिल पाता है क्योंकि खेती के समय खेत में पानी जमा होता है। सारन जिले के गड़खा, दरियापुर, परसा, अमनौर और सोनपुर प्रखंडों को बाढ़ से बचाने के लिए उस क्षेत्र की सुखमन, माही, गोगरी आदि बरसाती नदियों में तटबन्ध होना अत्यावश्यक है। जिसकी व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी। तीन वर्ष पूर्व गण्डक विभाग की जल निकासी इकाई, गण्डक योजना विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालिका अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के साथ मैं भी स्थल का निरीक्षण करने गया था। उन्होंने विनाश की गंभीरता को देखकर अविलम्ब इन नदियों पर तटबन्ध का निर्माण कराने के लिए कदम उठाने का अपना संकल्प सुनाया था। परन्तु, अभी तक इस दिशा में तनिक भी काम नहीं हो सका। आगामी बरसात में गंगा नदी के तटबन्ध, छपरा के उत्तर में जल निकासी योजना और माही, सुखमन, गोगरी नदियों में तटबन्ध के अभाव में सारन के नागरिकों का दिल बाढ़ की विभीषिका और विनाशलीला

की कल्पना से थर-थर कांप रहा है। क्या हमारे नए कर्मठ सिंचाई मंत्री श्री राम निवास मिर्धा जी हमारे जिले के लोगों को बाढ़ से आतंकित और प्रकम्पित नागरिकों को सुरक्षात्मक कदम उठाकर सही मायने में आश्वस्त करेंगे कि भारत सरकार सारन जिले के नागरिकों को अब बाढ़ से प्रताड़ित नहीं होने देगी? प्रो० डी० पी० यादव और श्री भीखा भाई जी ने इंजीनियर के माल बनाने, घर बनाने और सरकारी कोष का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और उसकी जांच की मांग की है, उसका मैं भी हार्दिक समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों का मैं प्रबल समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to reassemble at 11.00 a.m. on Friday, April 15, 1983.

19.10 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 15, 1983/ Chaitra 25, 1905 (Saka).